राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 16 मई • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

आप सभी लोगों को कुछ समय और कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप हर समय सभी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते।
-अब्राहम लिंकन

भरमा नहीं सकेंगे अब

झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के जरिए आम आदमी को प्रलोभन देकर पैसा बनाने वाली कंपनियों को स्वप्रमाण-पत्र जारी करना होगा। यह दावा गलत हुआ तो हर्जाना चुकाना होगा। उनके खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई भी होगी। रामदेव की कंपनी पतंजली के भ्रामक विज्ञापन मामले के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। मंत्रालय द्वारा ऐसी प्रणाली और पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें विज्ञापनदाता स्व-प्रमाणपत्र अपलोड करेगा। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस बाबत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिनके तहत कंपनियों को अपने उत्पादों और वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने की गरज से भ्रामक विज्ञापनों से बचने की सलाह दी गई है। भ्रामक विज्ञापनों को

करने वाली चर्चित हस्तियों को भी इस झूठ में शामिल माना जाएगा। यह व्यवस्था अगले महीने से लागू हो जाएगी। दावा गलत सिद्ध होने पर मुकदमा दायर होगा तथा मुआवजा भी देना होगा। हैरत नहीं होनी चाहिए कि अदालत के कड़े रुख के बाद संबंधित मंत्रालय और व्यवस्था चेत रही है। वरना तो अपने यहां गोरापन बढ़ाने वाली क्रीम तकरीबन 54 सालों से भ्रामक विज्ञापनों के सहारे ही बिकती रही हैं, जिनका सालाना रेवेन्यू 2400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बताया जा रहा है। ऐसे ही बच्चों की लंबाई बढ़ाने या हड्डियां मजबूत करने का दावा करने वाले तमाम प्रोडक्ट्स से बाजार अटे पड़े हैं। स्वास्थ्यवर्धक पेयों के मामले में भी कुछ ऐसा ही मंजर है, जिनका बाजार 7500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बताया जा रहा है। ताजगी बढ़ाने और भीषण गरमी से राहत देने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स का बाजार 5700 करोड़ रुपये का है, जिनमें शक्कर की मात्रा घातक स्तर तक होने की चेतावनी जब-तब चिकित्सक देते रहते हैं। देश में हर ग्यारहवां शख्स डायबिटीज की चपेट में है। मगर इन सब चीजों का प्रचार जोर-शोर से साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है। मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के खिलाफ कहीं कोई आवाज उठी भी तो तूती की तरह दब जाती है। इसके लिए स्पष्ट तौर पर सरकार और उसके मंत्रालय जिम्मेदार हैं जिन्हें जनता को भ्रामक प्रचार से बचाने के सख्त कदम उठाने थे। इस बात का फायदा उठाते हुए भ्रामक प्रचार और विज्ञापन के बल पर चांदी कूटने वाली कंपनियां बेखटके रहीं। अब हालांकि बहुत देर हो चुकी है। स्व-प्रमाणपत्र जैसी गाल बजाने वाली व्यवस्था देकर पीठ थपथपाने की बजाय गुणवत्ता मानक सख्ती से तय किए जाएं।

उम्मीद का वोट

भारत के मुकुट कश्मीर के श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान लोकतंत्र में आस्था की कहानी बयां कर रहा है। अपने बेहतर भविष्य की उम्मीदों को लेकर घरों से निकले मतदाताओं ने पिछले 28 वर्षों के मतदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार तीन फीसद मतदान हुआ जबकि 2019 में 14.43 और 2014 में 25.86 फीसद मतदान हुआ था। 1996 में 40.94 फीसद मतदान हुआ था और यह वह समय था जब आतंकवादियों और अलगाववादियों ने चुनाव के बहिष्कार की अपील की थी, लेकिन सेना की मदद से लोग मतदान केंद्रों पर आने में समर्थ हुए थे। लेकिन इस बार श्रीनगर के लोग बेखौफ होकर घरों से बाहर आए और मताधिकार का प्रयोग किया। जम्मू-कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद यह पहला आम चुनाव है। दशकों से यहां लोग चुनाव बहिष्कार, आतंक और हिंसा के डर से घरों से बाहर नहीं निकला करते थे। लेकिन अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के

बाद चुनाव बहिष्कार की राजनीति इतिहास बन गई है। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र का दायरा पांच जिलों और 18 विधानसभा क्षेत्रों तक फैला है। हैरानी की बात यह है कि पुलवामा और शोपियां जैसे आतंकवादियों के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार मतदान अधिक हुआ। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के गंदरबल, बड़गाम, पुलवामा, शोपियां और त्राल जैसे इलाकों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है जो एक नया ट्रेंड दर्शाता है। इसका साफ संकेत है कि कश्मीर घाटी के लोग अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के समर्थन में हैं। यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतार लगी हुई थी। इससे यह भी साफ होता है कि यहां के लोगों ने विरोध के पक्ष में नहीं, बल्कि उम्मीद के पक्ष में वोट किया है। श्रीनगर में शांतिपूर्ण मतदान का होना और लोगों का उत्साहपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का यह भी अर्थ नहीं है कि यहां के क्षेत्रीय दलों और केंद्र सरकार के बीच विश्वास बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोक सभा के बाद विधानसभा के चुनाव में भी लोग इसी तरह उत्साह से वोट करते नजर आएंगे।

कटाक्ष/ सहीराम

चुनाव में क्या-क्या चाहिए

चुनाव में क्या-क्या सामान चाहिए-इसकी सूची तैयार हो रही थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जमाने में शादी-ब्याह में हलवाई सामान लिखवाता था या फिर पूजा के लिए पंडित जी सूची दिया करते हैं कि जजमान जरा यह सामग्री मंगवा लेना। तो चुनाव के लिए क्या-क्या चाहिए इसकी सूची तैयार हो रही थी। एक कर्मठ कार्यकर्ता ने बड़े उत्साह से कहा-जी, रैली के लिए के लिए लोग चाहिएंगे, टेंट चाहिएगा, माइक-वाइक...उपस्थित लोग उसकी बात पर हंस पड़े। बेचारा समझ ही नहीं पाया कि उसने क्या बेवकूफी कर दी। नेता जी ने गंभीर होकर कहा कि देखो, यह सब तो चाहिए ही चाहिएगा और क्या चाहिएगा यह बताओ? गहन चिंतन शुरू हुआ। एक वरिष्ठ ने कहा-जी मंदिर तो चाहिएगा ही। हां, पर मंदिर के दर्शन तो हमने पहले ही करा दिए न। इससे अच्छा तो अधूरा ही था जी। चुनाव में काम तो आता हमेशा की तरह। मंदिर को लेकर हुई थोड़ी जल्दबाजी पर अफसोस करने के बाद एक और वरिष्ठ ने कहा-जी, देखो हिन्दू तो हमारे पास हैं, थोड़े मुसलमान चाहिएंगे। उनका क्या करेंगे-विरोध हुआ। नेता जी हंसे-बिल्कुल। वे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। दस साल से उन्हीं के भरोसे तो सारी टीवी डिबेट चलाई हैं, सारे चुनाव लड़े हैं। लेकिन उन्हें हमेशा की तरह उस पाले में ही रखना। जी वो नहीं होते तो हमारा क्या होता! एक और वरिष्ठ ने संतोष प्रकट किया। फिर कांग्रेस का घोषणापत्र चाहिएगा। सब लोग हतप्रभ। वो क्यों चाहिए? नहीं वो नहीं चाहिए। उसका हमारा अपना संस्करण चाहिए। हमारी टीकावाला। अच्छा-अच्छा समझ गए। इसके साथ पाकिस्तान भी चाहिएगा। अच्छा हुआ जो वो बन गया, वरना हमारा क्या होता, पता नहीं। और हां, एक चार कमरे वाला घर, एक मंगलसूत्र और दो भैंस भी चाहिए। जी वो क्यों चाहिए? अरे कांग्रेस के घोषणापत्र को उदाहरण सहित समझाना पड़ेगा न। और क्या चाहिएगा जी? और-और...चिंतन जारी था...और हां, अंबानी और अडानी भी चाहिए। वो तो हैं ही जी, हमारे पास। नहीं, हमें थोड़ी देर के लिए उन्हें उस पाले में खड़ा करना होगा। तो क्या उनकी सहमति चाहिए। जरूरत क्या है, वो असहमत क्यों होंगे। उनके साथ दो-चार टैंपो चाहिए और कुछ बोरियों में काला धन चाहिएगा। बाकी बाद में देखेंगे।

जनता को भा रही जुगलबंदी

मोदी-योगी

राजेश मणि

लोकसभा चुनाव में मोदी-योगी की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दोनों नेता अपने-अपने भाषण में एक-दूसरे का खूब बखान भी कर रहे हैं। गजब का सामंजस्य चल रहा है। इसके पीछे की पूरी पटकथा लिखी हुई है। यह सभी जानते हैं कि दिल्ली तक पहुंचने में उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे महत्त्वपूर्ण और सर्वाधिक होता है। इस नाते लोक सभा चुनाव 2024 की पहली सभा मोदी ने उत्तर प्रदेश में ही की और शायद अंतिम सभा भी उत्तर प्रदेश में ही होगी। चुनावी सभा के दौरान मोदी योगी की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं, और उससे भी अधिक योगी मोदी की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। यह सामंजस्य देखने को खूब मिल रहा है। चुनावी सभा, रोड शो, रैली में जहां दोनों पहुंच रहे हैं, वहां विशाल भीड़ इकटठा हो रही है।

मोदी बार-बार कहते नजर आ रहे हैं कि योगी जी मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने माफिया राज को खत्म कर दिया है और योगी यह कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी, अबकी बार 400 पार। यहां तक ही नहीं, जब राम मंदिर की बात आ रही है तो योगी बार-बार मोदी को श्रेय दे रहे हैं जबकि यह भी सभी जानते हैं कि योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए रात-दिन एक कर दिया था। बार-बार अयोध्या जा कर मॉनिटरिंग करना, आत्मबल बढ़ाना, विरासत और विकास की बातें खूब हो रही हैं। लोक सभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और गिनी-चुनी सीटों को छोड़ दिया जाए तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 65 से ऊपर सीटें भाजपा के पास रहेंगी और इसका श्रेय सीधे तौर पर योगी को जाता है। केंद्र की योजनाओं और प्रदेश की योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे मुलाकात और बूथ लेवल कार्यकताओं का लाभार्थियों से सीधा संपर्क बना हुआ है। इसी नाते मोदी भी योगी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। पूरे देश में चुनावी सभा में जिस तरह से योगी की डिमांड हो रही है, वह अपने आप में एक उदाहरण है। स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें जनता हर जगह चाह रही है। उत्तर प्रदेश के बदलाव को बखूबी लोग अपनी जुबां से बयां कर रहे हैं। गोरखपुर का बदलाव भी योगी के कद को बढ़ा ही नहीं रहा है, बल्कि आसपास की लोक सभा सीटों को एक संदेश भी दे रहा है।

कानून व्यवस्था तो जैसी यूपी की है, शायद ही किसी अन्य प्रदेश की हो। अपराध और अपराधी यूपी से गायब हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कहीं गुंडा टैक्स नहीं चलता। दंगों, कर्फ्यू, रंगदारी, अपहरण, डराना-धमकाना उत्तर प्रदेश से सब समाप्त हो चुका है। इन सभी मुद्दों को लेकर दोनों नेता चर्चा करते नजर आ रहे हैं।

प्रथम चरण के चुनाव के बाद जिस तरह से पूरी भाजपा टीम को और मजबूती से लगाया गया है, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में एक नया संदेश देना चाहती है भाजपा। चार जून को लोक सभा चुनाव के परिणाम आने के बाद योगी का कद

और बढ़ेगा। योगी विरासत और विकास की बातों के साथ-साथ अपनी पुरानी छवि, फायर ब्रांड हिन्दूवादी नेता की, को कायम रखे हुए हैं। उसी तौरतरीके से उनका चुनावी भाषण भी हो रहा है। बल्कि चुनावी भाषण को छोड़ दिया जाए तो योगी ने अपने नियमित भाषण में बड़ा ही परिवर्तन किया था, तकनीकी और विकास की बारे अधिक होती रहती थीं। लोक सभा चुनाव के ऐलान के बाद राज्यवार स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी योगी को वरीयता दी गई। यह अपने आप में संदेश पहले ही दे दिया गया कि केंद्र के पांच शीर्ष नेताओं के बाद छठे नम्बर पर योगी का ही नाम है। कानून व्यवस्था सख्त रखने के चलते दूसरे राज्यों में योगी की खूब चर्चा होती है। हार्डकोर हिन्दुत्व वाली छवि भी उनके कद को बढ़ाती है। जुगलबंदी इस तरह हो गई है कि योगी गोरखपुर आएंगे तो बाबा गोरखनाथ की पूजा करने के बाद ही अपने कमरे में जाते हैं। मोदी ने काशी में जिस तरह से कल रोड शो किया वह देखने लायक था। भगवामय कशी नजर आ रही थी। बाबा विश्वनाथ, गंगा मइया, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय सभी जगह पूजन-अर्चना, माल्यार्पण मोदी ने किया। रोड शो के दौरान जिस तरह दोनों नेता अभिवादन करते चल रहे थे, सब की जुबान पर मोदी-योगी चल रहा था। योगी भगवाधारी हैं ही मोदी भी भगवा कुर्ता और भगवा गमछा के साथ रोड शो कर रहे थे। लोगों को यह जुगलबंदी खूब भा रही है। कल मोदी ने अपने नामांकन के दौरान भी योगी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो लोग योगी जी को केवल बुलडोजर के नाम से बदनाम करते हैं, वे कान खोल कर सुन लें। जिस तरह से योगी ने यूपी में औद्योगिक विकास किया है, आजादी के बाद विपक्षी सरकारें इतने वर्षों में नहीं कर पाईं। मैं काशी का सांसद भी हूं, और मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि योगी जैसे व्यक्ति मेरी टीम में हैं। चुनावी सभा के दौरान योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 'एक जिला एक उत्पाद' का मिशन पूरे देश में नया सम्मान पैदा कर रहा है।

यह निरंतर दोनों नेताओं में देखने को मिल रहा है एक-दूसरे की तारीफ करना। योगी चुनावी सभा में कह रहे हैं कि मोदी का साथ है तो आज गन्ने के मूल्य से लेकर सुरक्षा, विकास, समृद्धि की बातें हो रही हैं। जिस तरह से दोनों नेता अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर आर्थिक विकास से जोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से इसे धर्म में आस्था के साथ-साथ आर्थिक समृद्धि के रूप में भी देखा जा रहा है। लाखों श्रद्धालुओं का प्रति दिन आना अपने आप में विकास को गति दे रहा है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं। दोनों की जोड़ी अयोध्या के बारे में मंचों से बोल रही है। योगी कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि अब उत्तर प्रदेश में अयोध्या-मथुरा-काशी सहित सभी हिन्दू तीर्थस्थलों में भक्तों की भारी भीड़ बढ़ रही है जिसके कारण निवेश बढ़ रहा है।

योगी कहते हैं 'सबका साथ सबका विकास' का जो मोदी का सपना है, वह मोदी की गारंटी के रूप में पूरा हो रहा है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया का नेतृत्व करने वाला नया भारत बन कर खड़ा हुआ है। अब देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दिशा में जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश में गुंडों की मनमानी की जगह विकास की योजनाएं चल रही हैं। डबल इंजन की सरकार समस्याओं का समाधान दे रही है। मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। कहा जा सकता है कि लोक सभा चुनाव 2024 में मोदी-योगी की जुगलबंदी ही सबसे प्रभावी रही। दोनों का एक-दूसरे के साथ गजब का सामंजस्य दिख रहा है। जनता की भी मांग इसी जोड़ी की रही।

> मोदी कहते नजर आ रहे हैं कि योगी जी मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने माफिया राज को खत्म कर दिया है और योगी कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी, अबकी बार 400 पार तक ही नहीं, जब राम मंदिर की बात आ रही है तो योगी मोदी को श्रेय दे रहे हैं जबकि सभी जानते हैं कि योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए रात-दिन एक कर दिया था। बार-बार अयोध्या जा कर मॉनिटरिंग करना, आत्मबल बढ़ाना, विरासत और विकास की बातें खूब हो रही हैं

- भारत में तंबाकू का सेवन करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है
- केपीएमजी-एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज की नई रिपोर्ट-ह्यूमन-सेंट्रिक अप्रोच टू टोबैको कंट्रोल-के मुताबिक, भारत में 27 प्रतिशत वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं
- रिपोर्ट में कहा गया है कि तंबाकू नियंत्रण के लिए एक व्यावहारिक रोडमैप बनाया जाना जरूरी है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

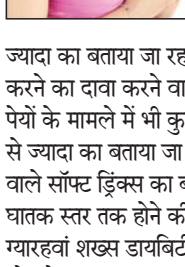

हर महान क्रांति से पहले हमेशा वैचारिक क्रांति होती है। भारत आज वैचारिक क्रांति के इसी दौर से गुजर रहा है।

पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू
@mkatju

खतरनाक हो सकती है अनदेखी

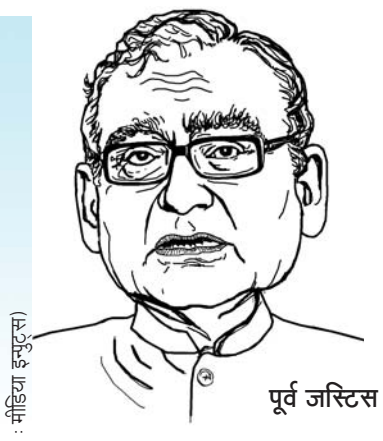

डेंगू | **योगेश कुमार गोयल**

अन्य घातक बीमारियों के साथ-साथ डेंगू भी ऐसी गंभीर बीमारी बन चुका है, जिसके जोखिम को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। प्रति वर्ष डेंगू के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है यानी डेंगू जानलेवा बीमारी है। प्रायः जून-अक्टूबर के दौरान डेंगू के सर्वाधिक मामले सामने आते हैं। डेंगू को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विशेष थीम के साथ हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस 'डेंगू रोकथामः सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी' विषय के साथ मनाया जा रहा है। डेंगू से बचाव को लेकर सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। 2018 में भारत में एक लाख से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, 2023 में डेंगू के मामलों की संख्या करीब ढ़ाई लाख थी।

माना जाता है कि अक्टूबर के बाद रात के तापमान में गिरावट आने पर डेंगू के मच्छर स्वतः खत्म हो जाते हैं, लेकिन समय के साथ-साथ स्थिति खतरनाक होती जा रही है और डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का प्रकोप सर्दी के मौसम में भी अब शांत नहीं होता। मौसम में बदलाव के बावजूद सर्द मौसम में डेंगू के सैकड़ों मरीज सामने आने लगे हैं। डेंगू से पीड़ित को प्रायः तेज सिरदर्द होता है और लगातार बुखार आता है, जो 100 डिग्री के आसपास रहता है लेकिन डेंगू के मरीजों के मामलों में कुछ समय से यह चिंताजनक स्थिति भी देखी जाने लगी है कि बहुत से मरीज ऐसे भी सामने आते हैं, जिनमें बुखार तथा सिरदर्द जैसे लक्षण नदारद होते हैं, और शारीरिक कमजोरी तथा प्लेटलेट्स कम होने जैसे लक्षण ही देखने को मिलते हैं। सिर्फ थकान और कमजोरी की शिकायत करने वाले मरीजों में डेंगू की पहचान करना मुश्किल होता है। रक्त जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर ही डेंगू की पुष्टि की जा सकती है। डेंगू के लक्षणों में इस बड़े बदलाव को लेकर किए गए अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि एडीज मच्छर के वायरस और स्ट्रेन में बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि चिकित्सक इस बदलाव को जानलेवा नहीं किंतु चिंताजनक अवश्य मानते हैं।

वायरस संक्रमण के कारण डेंगू होता है, जो मादा

एडीज मच्छर के काटने से होता है। केवल मादा मच्छर में ही डेंगू का वायरस होता है और यह मच्छर दिन में ही काटता है। एडीज मच्छर के काटने के 3-5 दिनों बाद डेंगू के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वायरस संक्रमण श्वेत रक्त कोशिकाओं पर धावा बोलता है, जिससे पीड़ित की रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हो जाती है। प्लेटलेट्स कम होने पर शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इलाज सही मिले तो स्थिति जल्द नियंत्रित हो सकती है अन्यथा डेंगू जानलेवा साबित हो सकता है। जब डेंगू अपनी खतरनाक अवस्था में पहुंचता है तो रोगी की प्लेटलेट्स बेहद कम हो जाती है, रक्तचाप तेजी से नीचे गिरता है और शरीर के अंदरूनी अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। डेंगू के प्रमुख लक्षणों में लगातार बुखार रहने के साथ-साथ सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण देखे जाते हैं। बुखार के साथ नाक बहना, खांसी, आखों के पीछे दर्द, त्वचा पर हल्के रैशेज, भूख कम होना, कमजोरी जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं और कुछ लोगों में लाल और सफेद निशानों के साथ पेट खराब होने, जी मिचलाने, उल्टी आने जैसे लक्षण भी सामने आते हैं।

व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद आज भी बहुत से लोग यही मानते हैं कि डेंगू का मच्छर नालियों या दूषित जल में ही पनपता है जबकि वायरसजनित यह खतरनाक बीमारी साफ-सुथरे पानी में पनपने वाले एडीज मच्छरों के काटने से फैलती है। डेंगू के मच्छर प्रायः मानसून के बाद ठहरे हुए साफ पानी में पैदा होते हैं। प्लास्टिक के ड्रमों, टंकियों इत्यादि में पैदा होते हैं। कूलर में पानी भरे रहने पर उसमें भी पनप जाते हैं। अभी तक डेंगू के इलाज के लिए कोई दवा, एंटीबॉयटिक या टीका उपलब्ध नहीं है, अतः इसका उपचार इसके लक्षणों का इलाज करके ही किया जाता है। बचाव के लिए स्वच्छता और सजगता पर विशेष जोर दिया जाता है क्योंकि जितना मुश्किल डेंगू के संक्रमण से खुद को बचाए रखना है, उससे भी मुश्किल डेंगू होने के बाद उससे पूरी तरह उबरना है। अपने घर के आसपास साफ-सफाई रखें। पानी की टंकियों को अच्छी तरह बंद करके रखें। अगर किसी स्थान पर पानी जमा होने से रोकना संभव नहीं है तो उस जमा हुए पानी में पेट्रोल अथवा केरोसिन तेल डालें। घर में ऐसे टूटे-फूटे डिब्बे, टायर, बर्तन, बोतलें इत्यादि न रखें जिनमें पानी भरा रहता हो। कूलरों, गमलों, फूलदानों या ऐसे ही अन्य पात्रों का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें। घर के खिड़की-दरवाजों पर बारीक जाली लगवा कर घर में मच्छरों के प्रवेश को बाधित करने का प्रयास करें। रात को सोते समय ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर के अधिकांश हिस्सों को ढंक सकें।

नेतृत्व | **डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी**

महाभारत के युद्ध से पहले रणभूमि पर भयभीत दुर्योधन को देखकर 'कौरव पक्ष के वृद्ध, तेजस्वी और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष प्रेरित करने के लिए सिंह की दहाड़ के समान ऊंची शंख-गर्जना की। जब भीष्म ने दुर्योधन को द्रोणाचार्य के पास खड़ा देखा तो उन्हें लगा कि दुर्योधन पांडव सेना को देख कर चिंतित और हैरान है। पितामह को स्थिति की गंभीरता का अहसास तब हुआ जब दुर्योधन भीष्म की रक्षा के लिए सेना से अनुरोध कर रहा था। उन्होंने तुरंत भांप लिया कि यदि सेना को दुर्योधन की पीड़ा दिख गई तो सेना का मनोबल गिर जाएगा। इस समय पितामह को अपना प्रभाव दिखाना आवश्यक लगा। युद्ध की घोषणा होते ही उन्होंने क्षण की भी देरी किए बिना सिंह की भांति जयघोष करके प्रधान सेनापति का कर्त्तव्य निभाया। इस प्रचंड शंखनाद से सब युद्ध के लिए सज्ज हो गए। इस अवसर पर पितामह में एक कुशल नेता का गुण देखने को मिलता है। कुशल नेता कठिन चुनौती में भी अपनी टीम में साहस का संचार करके परिणाम बदल सकता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान और टैंक मिले थे। एक समय पाकिस्तान ने हवाई ताकत और जमीनी टैंक के गोलों से कहर बरसा दिया था। जैसलमेर की सीमा पर लड़ रहे हमारे 90 जवानों के लिए वह रात भयानक थी। पाकिस्तान के 2000 सैनिक टैंकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर आगे बढ़ रहे थे। रात को वायुसेना से मदद मिलना संभव नहीं था। सेना असमंजस में थी। लेकिन कठिन समय में मेजर कुलदीप सिंह ने सेना में ऊर्जा भर दी। उनके नेतृत्व का बड़ा असर हुआ। उन 90 भारतीय सैनिकों ने मातृभूमि के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए कमर कस ली। भयंकर युद्ध हुआ। हमारी छोटी संख्या ने बड़ी पाकिस्तानी सेना को एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने दिया। सुबह वायु सेना ने तो पाकिस्तानी सेना का नाश्ता ही बना दिया। इस प्रकार, महंत स्वामी महाराज कहते हैं, अब हमें सोचना है-परिवार में मुखिया के रूप में, कार्यालय में अधिकारी के रूप में अनेक लोग हमारा अनुगमन करते हैं। क्या हम उनका मनोबल बढ़ाते हैं? या...?, हां, नेता-मुखिया तो हम बन गए, परंतु क्या सही नेतृत्व कर पाते हैं?

रीडर्स मेल

मकड़जाल में पाकिस्तान

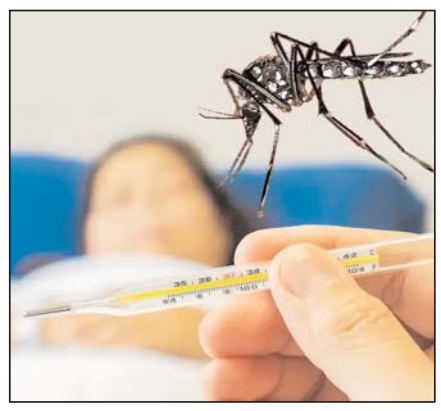

जिस देश की माली हालत नाजुक हो उस देश की सरकार को न जाने क्या-क्या निर्णय लेने पड़ते हैं। अब देखिए न हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया की हालत से गुजर रहा है। शायद इसीलिए वहां की सरकार कर संग्रह बढ़ाने के लिए समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर सख्ती से पेश आ रही है। कुछ दिन पहले संघीय राजस्व बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों की बिजली और गैस की आपूर्ति काटने के लिए कर कानूनों में संशोधन करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया था। पिछले महीने देश के कर संग्रह निकाय, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को डिफॉल्टरों के पांच लाख से अधिक सिम ब्लॉक करने का आदेश दिया था। आदेश को चुनौती देते हुए दूरसंचार कंपनी के वकील ने तर्क दिया कि यह निर्णय संविधान का उल्लंघन है। देखना होगा कि पाकिस्तानी हुक्मरान आगे क्या कदम उठाते हैं क्योंकि यह सब सख्ती सरकार खुद से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश पर उठा रही है। नहीं उठाएगी तो मुद्रा कोष ऋण देना बंद कर देगा। मतलब पाकिस्तान सरकार 'आगे कुआं पीछे खाई' के मकड़जाल में फंस गई है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

टूटते परिवार, जिम्मेदार कौन

दुनिया भर में परिवार का महत्त्व समझाने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 1993 से अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। हर वर्ष 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। बेशक, इस दिवस की शुरुआत विदेश से हुई है, लेकिन हमें दूसरे देशों की अच्छी बातों को ग्रहण करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और न ही तर्क देना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हमारे देश की परंपरा नहीं है। परिवार का महत्त्व क्या है, इसकी अहमियत हमारे देश में बहुत ज्यादा है। इंसान की प्रथम पाठशाला घर-परिवार होती है। घर-परिवार के संस्कार और माहौल ही बच्चे के अच्छे-बुरे चरित्र का निर्माण करते हैं। परिवारों की टूटन से देश में कई समस्याएं पैदा हुई हैं, जो विकास में बाधा हैं, और देश में अनैतिक कामों का बढ़ना, बच्चों का गलत राह पर चलने का कारण भी परिवारों में अनैतिक पतन है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मुफ्त के वादे बड़ी बाधा

मायावती ने कहा है कि आपको जो मुफ्त अन्न मिल रहा है, यह लोगों की कमाई का ही अंश है। भाजपा वाले इसे अपने पास से नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक मोदी ही दहाड़ कर पांच किलो अनाज की गारंटी का वादा कर रहे हैं। चुनाव के समय नेताओं के मुफ्त के वादे लोगों को लुभाते हैं। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये वादे बड़ी बाधा हैं। महाभारत का प्रसंग है जब कौरव लड़ाई में हार गए तब द्रोपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से सवाल किया, 'जब कौरव मेरा चीर हरण कर रहे थे तो आप चुप थे। गुरु द्रोण ने कहा : 'मैंने कौरव राजा का नमक खाया था। विरोध कैसे करता।' आप सक्षम होते हुए भी मोदी सरकार का नमक खा रहे हैं। वास्तव में मुफ्त के वादों से लोगों को जागरूक होने का समय आ गया है।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 272
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दस किलो अनाज

अनेक लोगों के लिए चुनाव विचारधारा, समस्या और मुद्दों को परखने का मौका है, तो बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर बस यह जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा? इसी कड़ी में भाजपा की घोषणा है कि आने वाले पांच वर्ष तक 80 करोड़ लोगों को पांच किलो अनाज मुफ्त मिलता रहेगा, इससे आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने घोषणा की है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार अगर बनी, तो पांच के बजाय दस किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेसवार्ता में यह महत्वपूर्ण घोषणा की है। मतदान के चार चरण बाद की गई इस घोषणा का आने वाले तीन चरणों पर अब क्या असर होगा, यह देखने वाली बात है। क्या ऐसी घोषणा इंडिया ब्लॉक की ओर से पहले नहीं हो सकती थी या क्या किसी आशंका की वजह से अब घोषणा की गई है? वजह चाहे जो हो, इस वादे का महत्व है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से की गई थी और अब यह योजना सभी राजनीतिक दलों या सरकारों के लिए मजबूरी बन गई है।

विपक्ष में ऐसे लोग भी हैं, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आलोचक रहे हैं। दो वजहों से इस योजना को निशाने पर लिया जाता है। पहली वजह बताई जाती है, लोगों को रोजगार चाहिए, मुफ्त अनाज नहीं। दूसरी, जब देश में गरीबों की संख्या घट गई है, तब वे कौन 80 करोड़ लोग हैं, जिन्हें मुफ्त अनाज की जरूरत पड़ रही है? वैसे, इसमें शक नहीं कि इस योजना की शुरुआत 2020 में एक साल के लिए हुई थी, मगर अब पांचवां साल शुरू होने वाला है। यह योजना देश की एक सफलतम योजना है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो इसका लाभ ले रहे हैं। महामारी का असर पीछे छूट गया है, पर वास्तव में ज्यादातर लाभार्थी यह नहीं चाहेंगे कि यह योजना बंद हो जाए। अतः इंडिया ब्लॉक ने अगर पांच किलो मुफ्त अनाज को दस किलो करने का वादा किया है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हां, इंडिया ब्लॉक अगर यह घोषणा पहले करता, तो शायद उसे ज्यादा सियासी लाभ मिलता।

चुनावी शोर में यह नहीं भूलना चाहिए कि देश पर कितना कर्ज हो गया है। मुफ्त घोषणाओं में लगी हर पार्टी को अर्थव्यवस्था के प्रति सजग रहना होगा।

यह बात अलग है कि मुफ्त अनाज योजना का आर्थिक दबाव देश और उसके लोगों पर ही पड़ेगा। मुफ्त की योजनाओं को शुरू करना और चलाते रहना आसान नहीं है। अगर मुफ्त देना इतना ही आसान होता, तो तमाम राज्य सरकारें दिल्ली सरकार की तरह मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा दे रही होतीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही दिल्ली की सीमा में किसी का बिजली बिल शून्य आता है, तो उससे बमुश्किल पचास कदम दूर उत्तर प्रदेश में चार हजार रुपये! मतलब, मुफ्त योजनाएं असंख्य लोगों के लिए जरूरत और सियासी मजबूरी हैं, पर उनमें तार्किकता होनी चाहिए। मुफ्त योजनाएं अच्छी होती हैं और अच्छी लगती भी हैं, पर उनका असर जब महंगाई के रूप में लौटता है, तब नाराजगी नहीं होनी चाहिए। आज हर पार्टी को पता है कि देश पर कितना कर्ज है और घोषणाओं में लगी हरेक पार्टी को अर्थव्यवस्था के प्रति सजग रहना होगा। साल 2022 की बात करें, तो भारत पर जीडीपी के हिसाब से 81 प्रतिशत ऋण था, जबकि जापान पर 260.1 प्रतिशत और अमेरिका पर 121.3 प्रतिशत। ऋण तब बुरा नहीं है, जब उसका सदुपयोग सुनिश्चित हो। ऋण हो या मुफ्त की योजनाएं, अगर देश खुशहाल हो रहा हो, तो स्वागत है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 16 मई, 1949

भारत के साथ रहना हितकर

नई दिल्ली, १५ मई। आज शाम काश्मीर के प्रश्न पर पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा शेख अब्दुल्ला के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई। ज्ञात हुआ है कि विराम-संधि के संबंध में काश्मीर कमीशन के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श हुआ और यह संभावना है कि भारत कमीशन के इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के बारे में अपनी असमर्थता प्रकट करेगा।

नई दिल्ली पहुंचने के बाद शेख अब्दुल्ला से कई अधिकारियों तथा गैर-सरकारी लोगों ने उस मुलाकात के बारे में पूछा है जो कि शेख साहब ने एक ब्रिटिश पत्रकार से की थी और जिसमें यह सुझाव रखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा के अन्तर्गत काश्मीर एक स्वतंत्र राज्य बन सकता है। काश्मीर के नेता ने कहा है कि जब ब्रिटिश पत्र-प्रतिनिधि मुझसे मिला तो कतिपय वैकल्पिक योजनाओं की चर्चा हुई। शेख साहब ने कहा है कि हमारी स्थिति अपरिवर्तित है- दूसरे शब्दों में हम चाहते हैं कि काश्मीर भारतीय संघ में शामिल हो और हमारा विश्वास है कि राज्य की जनता के लिए यही सबसे हितकर उपाय है। शेख अब्दुल्ला ने विश्वास प्रगट किया है जनमत लेने पर काश्मीर भारत में शामिल होने के पक्ष में ही मत देगा।

नेहरू जी का प्रस्ताव स्वीकृत : नई दिल्ली, १५ मई। आज शाम विधान परिषद् के कांग्रेस दल की एक बैठक हुई और उसमें नेहरू जी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि विधान परिषद् भारत के राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने के निर्णय को मंजूर कर ले। प्रस्ताव में तीन संशोधन रखे गये थे किन्तु कोई भी स्वीकार न हुआ। नेहरू जी ने बाकायदा कोई भाषण तो नहीं दिया किन्तु संशोधनों के पेश होने पर जो बहस हुई उसका उत्तर दिया। प्रधानमंत्री को कोई नई बात तो कहनी नहीं थी, क्योंकि रेडियो पर अपने भाषण में तथा पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में वह राष्ट्रमंडल में बने रहने के लाभों पर पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। जातीय प्रश्न के संबंध में उन्होंने कहा कि यह तो राष्ट्रमंडल में न उठाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाना चाहिए। सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की कि विधान परिषद् की बैठक सुबह ८ बजे से १२ बजे तक हो। यह सुझाव कल १० बजे सुबह रखा जायेगा और आशा है कि विधान परिषद् इसे स्वीकार कर लेगी।

पाकिस्तानी कब्जे में नाराज कश्मीरी

सुशांत सरीन | सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

पाकिस्तान में 'कश्मीर' को कोई सांविधानिक दर्जा हासिल नहीं है। हमने हमेशा जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना है, जबकि वहां पीओके को लेकर ऐसी सोच नहीं है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के दिन-ब-दिन बिगड़ते हालात किसी एक घटना की उपज नहीं हैं। अभी वहां जो जन-विद्रोह चल रहा है, उसके बीज पिछले डेढ़ साल के घटनाक्रमों में छिपे हैं। पिछले साल की शुरुआत में सब्सिडी हटाने के कारण आटे के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए थे, तब भी लोग आक्रोशित हुए थे। मगर स्थिति जैसे-तैसे संभाल ली गई। इसके बाद मई के आसपास बिजली के बिल को लेकर वे मुखर हुए। उनका आरोप था कि पीओके में बना मंगला बांध 1,500-2,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है और उत्पादन-दर ढाई से तीन रुपये प्रति यूनिट है, पर उपभोक्ताओं से 50-60 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल वसूला जाता है। इस आंदोलन ने पूरे पाकिस्तान को उद्वेलित कर दिया और बिजली-शुल्क में कटौती की मांग मुल्क के हर कोने से उठने लगी। इसे भी पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बड़ी मुश्किलों से संभाला, लेकिन लोगों में गुस्सा बना रहा।

पीओके के अवाम की इस नाराजगी को अवामी एक्शन कमेटी ने आकार दिया। यह कोई सियासी तंजीम नहीं है, बल्कि इसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं। वास्तव में, पीओके में नेताओं के लिए अब कोई जगह बची ही नहीं। यहां मुख्यधारा के राजनीतिक दल तो अप्रासंगिक हैं ही, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में तोड़-फोड़ के बाद यहां एक खिचड़ी सरकार काम कर रही है, जिसकी हैसियत न इस्लामाबाद में है और न स्थानीय लोगों के मन में। अवामी एक्शन कमेटी की मांग ऐसे में प्रासंगिक बन गई। उसने आटे और बिजली-बिल के साथ-साथ कुछ राजनीतिक मुद्दों को भी अपने चार्टर में जगह दी। छात्र संघों की पुनर्बहाली, सरकारी अफसरों या निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं का अंत, चुनाव, संपत्ति टैक्स आदि मसलों को भी इसने उठाया। हालांकि, उसका मुख्य जोर आटा और बिजली बिल पर ही रहा, इसलिए माना जाता है कि ताजा विरोध-प्रदर्शन आर्थिक मुद्दों से जुड़ा है और यदि हुकूमत महंगाई का तोड़ निकाल लेती है, तो हालात संभल सकते हैं।

मगर इस पूरे मामले में जो बात अलग से नजर आई, वह है लोगों का आक्रोश। यह संभवतः पहला मौका था कि वे इस कदर नाराज हुए। राजधानी मुजफ्फराबाद तक निकाले गए 'लॉन्ग मार्च' को रोकने के फौजी उपायों ने इस आग में घी डालने का काम किया। इसीलिए हमने पुलिस वालों की पिटाई देखी, सड़कों पर यातायात अवरुद्ध होते देखा और सरकार-विरोधी नारेबाजी सुनी। बेशक, स्थानीय सुरक्षा बलों का खौफ आम लोगों में पहले भी नहीं था, मगर इस्लामाबाद के रेंजर्स से वे टकराते नहीं थे। मगर इस बार रेंजर्स से भी प्रदर्शनकारियों ने दो-दो हाथ किए।

एक तर्क यह दिया जा रहा है कि पीओके की नई पीढ़ी अपने बुजुर्गों की तरह नहीं सोचती। दरअसल, पुराने जमाने के कश्मीरी पाकिस्तान के अधीन रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तानी पंजाबियों के इशारे पर चलते हैं, कभी आवाज नहीं उठाते और भारत को अपना दुश्मन समझते हैं, मगर वहां के नौजवान पीओके का वाजिब हक लेने के लिए मुखर हैं। पाकिस्तान सरकार के प्रति भी उनका नजरिया अलग है और वे मानते हैं कि टैक्स लेने के बावजूद संसदीय प्रतिनिधित्व से उनको दूर रखना गलत है। इस पीढ़ी को भारत के जम्मू-कश्मीर का विकास भी लुभाता है।

पाकिस्तान में 'कश्मीर' को कोई सांविधानिक दर्जा हासिल नहीं है। अपने यहां भी अनुच्छेद 370 था, पर हमने हमेशा जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना है, जबकि पाकिस्तान में पीओके को लेकर ऐसी सोच नहीं है। उसके मुताबिक, यह ऐसा क्षेत्र है, जिसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है और इसका निर्धारण 'यूएन रिजॉल्यूशन' या संयुक्त राष्ट्र की दखल से होगा। यहां का अपना संविधान है, मगर उसका पाकिस्तान से सांविधानिक जुड़ाव नहीं है। यहां आर्थिक गतिविधियां नाममात्र की हैं, रोजगार के साधन सीमित हैं। हां, पाकिस्तान का इस पर नियंत्रण है, इसलिए यहां चुनाव कराए जाते हैं और लोगों को पासपोर्ट दिया जाता है, पर उनको पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिलती। यहां के लोग नेशनल असेंबली (संसद) के लिए वोट नहीं कर सकते और न ही ऊपरी सदन में उनका कोई नुमाइंदा है। नेशनल फाइनेंस कमीशन का कुछ हिस्सा इसको जरूर मिलता है, पर इसमें भी इसका अमल-दखल नहीं है।

यही कारण है कि मौजूदा हालात संभाल लिए जाने के बावजूद कहा जा रहा है, पीओके के लोग कोई भी रुख अख्तियार कर सकते हैं। वैसे, पाकिस्तान के सभी सरहदी इलाकों में ऐसा हो रहा है, फिर चाहे वह बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या गिलगित-बाल्टिस्तान। सभी क्षेत्रों में पाकिस्तानी हुक्मरानों से नाउम्मीदी दिख रही है और रियासत से अवाम का सामाजिक रिश्ता टूट रहा है। लिहाजा, जैसे-जैसे रियासत कमजोर होगी, इस तरह के आंदोलन तेज हो सकते हैं। चूंकि पीओके में हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, इसलिए इसका यह संदेश भी जा सकता है कि अगर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल सकें, तो अपनी बात मनवा सकते हैं। ऐसा कभी इमरान खान ने भी कहा था कि हम 30-35 हजार लोग यदि सड़कों पर आ जाएं, तो पाकिस्तानी जनरलों की सलवारें गीली हो जाएंगी। जाहिर है, अलग-अलग इलाकों में चल रहा आंदोलन पाकिस्तान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है।

यहां चुनौती भारत के लिए भी है। अगर पीओके में हालात बहुत बिगड़ते हैं और लोगों का पलायन भारतीय कश्मीर में होता है, तो उनके साथ हमारी सत्ता क्या बर्ताव करेगी? क्या 'राइट टु रिटर्न' यानी उनको वापस भेजने का कोई कानूनी प्रावधान हमारे यहां है? इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर को हम अपना हिस्सा मानते हैं, तो वहां के नागरिकों के साथ हमारा सुलूक क्या होगा या उनको क्या अधिकार दिए जाएंगे? और, अगर वहां के लोग भारत के साथ जुड़ने की मांग शुरू करते हैं, तो किस तरह हम उन्हें मदद कर सकेंगे? क्या भारत वहां कोई कार्रवाई करेगा या वहां के अलगाववादियों की सहायता करेगा या हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएगा- यह भी हमारी एक अन्य चुनौती होगी।

सवाल यह भी है कि पीओके का हंगामा यदि अन्य सरहदी इलाकों में फैलता है, जैसा हमने पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान में देखा था, तब हमारा रुख क्या होगा? ऐसे में, अभी इन विरोध-प्रदर्शनों पर नजर बनाए रखना ही उचित है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

शहरों में लोगों पर क्यों गिरने लगे विशालकाय होर्डिंग

के के पाण्डेय | प्रोफेसर, अर्बन मैनेजमेंट, आईआईपीए

अपने देश में कई लोग बड़े-बड़े होर्डिंग या सूचना-पट्ट की ओर शक की निगाह से देख रहे होंगे। देश की व्यावसायिक राजधानी कहलाने वाले महानगर मुंबई में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हुई है और 74 घायल हुए हैं। यह विशालकाय विज्ञापन-पट्ट 120 फुट का था, जबकि इतने बड़े पट्ट या होर्डिंग लगाने को मंजूरी नहीं है। देश के अलग-अलग राज्यों, शहरों में होर्डिंग का आकार अलग-अलग तय है। हालांकि, ऐसे शहर भी हैं, जहां होर्डिंग को लेकर स्थानीय नियम-कायदे तय नहीं हैं।

मुंबई में जो त्रासद हादसा हुआ है, वह साफ तौर पर स्थानीय निकायों और रेलवे की लापरवाही को दर्शाता है। मुंबई जैसे महानगर में प्राथमिक जिम्मेदारी तो बीएमसी की है, पर बीएमसी ने रेलवे को और रेलवे ने बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। देखने की बात है, बीएमसी ने रेलवे या आरोपियों को दो साल बाद नोटिस भेजा है। इस होर्डिंग की शिकायत भी तब हुई, जब होर्डिंग के सामने आ रहे पेड़ों को काटा जा रहा था। आखिर बीएमसी को इस गलत होर्डिंग तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा? क्या बीएमसी की स्थानीय निगरानी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है? नियमों को तोड़कर होर्डिंग लगाने वाले क्या इतने ताकतवर हो गए हैं कि रेलवे और बीएमसी के अधिकारी उनके खिलाफ कदम नहीं उठा पा रहे हैं?

मुंबई में होर्डिंग गिरने का जो त्रासद हादसा हुआ है, वह साफ तौर पर नगर निकाय और रेलवे की लापरवाही व उदासीनता को दर्शाता है।

यह हादसा हमारी व्यवस्था की कमी का नतीजा है। इतने विशाल होर्डिंग लगाने से पहले मृदा परीक्षण होना चाहिए था, निर्माण सामग्री व निर्माण को परखना था और फिर लगातार सुरक्षा जांच की जरूरत थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह लापरवाही नई नहीं है और हमारे ज्यादातर शहरों में व्याप्त है। सबको याद होगा मोरबी सेतु हादसा। गुजरात में सेतु टूट गया था, वहां भी सुरक्षा जांच या सेफ्टी ऑडिट का काम नहीं हुआ था। निगम के तहत आने वाले ऐसे ढांचों की समय-समय पर जांच की व्यवस्था होनी ही चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है।

सामान्य तौर पर ही देख लीजिए, हमारे शहरों में जो फुटपाथ हैं, वह बुजुर्गों या दिव्यांगों के अनुकूल नहीं होते हैं। अच्छा कहलाने वाले शहरों में भी सड़कों या फुटपाथ की देखरेख पर्याप्त नहीं है। जरूरी सुविधाओं की परख नियमित रूप से होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। मिसाल के लिए, कुछ वर्ष पहले तिरुवनंतपुरम के नगर निगम ने विशेष अभियान चलाकर जांच की और शहर में 54 हजार होर्डिंग को गलत पाया। शहरों में होर्डिंग लगाकर विज्ञापन शुल्क वसूला जाता है। नगरीय निकायों की अन्य स्रोतों से आय घटी है और वे होर्डिंग इत्यादि से ज्यादा कमाने के उपाय करते रहते हैं। विज्ञापन शुल्क को हटाया तो नहीं जा सकता और न होर्डिंग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, पर इसके नियम-कायदे स्पष्ट होने चाहिए। एक बार जो प्रक्रिया तय हो जाए, तो उसकी पूरी पालना करनी चाहिए। निकाय विज्ञापनों के जरिये कमाई करे, पर सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न करे। शहर के तय और सुरक्षित स्थानों पर ही विधिवत होर्डिंग लगाए जाएं। अवैध या गलत होर्डिंग को हटाना चाहिए।

केंद्र सरकारों को भी होर्डिंग संबंधी दिशानिर्देश तय करने चाहिए और अलग-अलग राज्यों में अपने हिसाब से दिशानिर्देश लागू करने चाहिए। जैसे पहाड़ी राज्यों के दिशा-निर्देश अलग हो सकते हैं। अवैध होर्डिंग के खिलाफ लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और नगर निकायों को निगरानी के काम में आम लोगों की मदद लेनी चाहिए। जैसे बेंगलुरु में निकाय ने लोगों से कहा कि वे होर्डिंग के फोटो खींचकर भेजें। ऐसा होने से फायदा यह है कि अवैध होर्डिंग की जांच की जा सकती है या असुरक्षित होर्डिंग के बारे में शिकायत समय रहते सामने आ सकती है। अभी निगरानी का अभाव है, जिससे नगर निकाय को आर्थिक नुकसान के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी होती है। अभी मुंबई में क्या हुआ, आम लोगों पर ही मुसीबत टूट पड़ी। आम लोग अगर सजग होते, तो यह नौबत ही नहीं आती। लोग अगर चाहें, तो मिलकर कहीं से भी असुरक्षित या अवैध होर्डिंग को हटवा सकते हैं। शहरों में विशालकाय होर्डिंग की संख्या बढ़ती चली जा रही है, अतः अपने स्तर पर शहरों के नीति नियंताओं को नियम-कायदे बना लेने चाहिए। श्रेष्ठ तरीका ऐसा होना चाहिए कि निकायों को कमाई भी हो और शहरवासियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मनसा वाचा कर्मणा

संन्यासी और गृहस्थ

बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या आध्यात्मिक साधना केवल संन्यासी लोगों के लिए है? बिल्कुल नहीं। संन्यासी और गृहस्थ, दोनों आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं। इनके बीच के मूलभूत अंतर को समझना होगा। पारिवारिक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। संन्यासी का एक ही कर्तव्य रहता है। गृहस्थ को परिवार का प्रतिपालन करना होता है और उसका दूसरा कर्तव्य है- अखंड वैश्विक मानव समाज के कल्याण के लिए कुछ करना। ऐसे में, उसे संतुलित रूप से काम करना होगा। यदि कोई व्यक्ति महीने में दस हजार रुपये कमाए और उसमें से आठ हजार दान कर दे, तो उसके परिवार में दुर्व्यवस्था पैदा होगी। घर अभाव में रहेगा और परिजनों में लड़ाई होगी। उसे परिवार की समुचित देखभाल और मानव कल्याण के बीच मात्रात्मक संतुलन बनाना होगा।

भगवान शिव की एक कथा है। एक दोपहर भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी से कहा, 'देवि, मुझे भोजन तो कराएं।' पार्वती जी ने कहा, 'आप घर-गृहस्थी की भी कुछ खबर रखते हैं? केवल एक से दूसरे श्मशान घूमते रहते हैं। आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि आज चूल्हा ही नहीं जला। घर में कुछ था ही नहीं, इसलिए रसोई नहीं बनी।'

शिव जी ने पूछा, 'कुछ दिनों पहले भिक्षा मांगकर जो मैं बहुत सारा चावल-दाल लाया था, वह कहां गया?' पार्वती जी ने उत्तर दिया, सब समाप्त हो गया है। थोड़ा सा ही था। भंडारगृह में जो थोड़े से चावल थे, उसे गणेश के चूहे ने जलपान कर लिया।' यह कहानी मानव जीवन की है, लेकिन भक्तों को समझाने के लिए भगवान का मानवीकरण करके लोग कहानियां बना लेते हैं। इससे समझने वाली बात यह है कि घर-संसार चलाने के लिए जरूरी सामान का इंतजाम तो करना ही होगा। छोटे और बड़े संसार, दोनों के बीच एक संतुलन रखना होगा। यह संतुलन गृहस्थ का कर्तव्य है, संन्यासी का नहीं। संन्यासी के पास जो कुछ भी आएगा, वह सोलह आना संसार को दान कर देगा। यही उसका कर्तव्य है।

मनुष्य को सभी अवस्थाओं, सभी उम्र में धर्म की साधना करनी चाहिए। सभी लोग अपने-अपने कर्तव्य करते जाएं। यह जो अति साधारण पृथ्वी है; यह जो धूलि की धरणी है, इसी पर स्वर्ग को उतार लाना संभव है। किसी अन्य स्वर्ग की खोज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग-नरक जैसी कोई अलग दुनिया नहीं होती। इसी धरती पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। जब हम कर्तव्य-कर्म को सभी के हित के साथ जोड़ देते हैं, तो उससे मिलने वाला आनंद स्वर्ग का सुख देता है। जहां कोई किसी को प्रताड़ित करता है, वहां नरक जैसा वातावरण बनने लगता है। इसलिए कहा गया है, समान व संतुलित भाव से अपने आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक कर्तव्य का पालन करते रहो।

जब हम कर्तव्य-कर्म को सभी के हित के साथ जोड़ते हैं, तो उससे मिलने वाला आनंद स्वर्ग का सुख देता है। जहां कोई किसी को प्रताड़ित करता है, वहां नरक जैसा वातावरण बनने लगता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

शेखर कपूर | फिल्म निर्देशक

यह ब्रह्मांड अराजक नहीं, लयबद्ध है। मगर महादेव के तांडव की तरह यह लय इतनी तीव्र है कि इसके विश्लेषकों को अव्यवस्थित लगती है। अब भगवान शिव के तांडव का हिस्सा बनने का एकमात्र रास्ता तो उनके साथ एकाकार होना है।

महिला क्रिकेटरों का कहीं जिक्र नहीं

बधाई तो बनती है! राधा यादव बनीं प्लेयर ऑफ द सीरीज। बात बांग्लादेश में खेली गई पांच मैचों की ट्वंटी-20 क्रिकेट शृंखला की है, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम को 5-0 से पराजित कर दिया। इस शृंखला में कुल 10 विकेट लेकर हीरो बनीं राधा यादव, जिनको आखिरी मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। मगर इन सबमें मुख्य बात यह है कि पुरुष खिलाड़ियों की एक जीत पर हर तरफ से बधाइयों का तांता लग जाता है, लेकिन इन महिला क्रिकेटरों की ऐतिहासिक जीत को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। यह वाकई शोचनीय मसला है। खैर, इतनी जल्दी कहां समाज में कोई बदलाव आता है। यहां बेटियां हर रोज खुद को साबित करने में लगी हैं। देखते हैं, कब तक हमारा समाज इस बात को मानता है!

आर्यन रनवी, टिप्पणीकार

उनको भी पूरा सम्मान मिले

बेहतरीन खेल दिखाया भारत की बेटियों ने बांग्लादेश में। पांच मैचों की सीरीज में उन्होंने सभी मैच भी जीते व क्रिकेटप्रेमियों के दिल भी। मगर यह चिंतनीय विषय है कि हमारे देश के क्रिकेटप्रेमियों का इस ओर ध्यान नहीं गया। यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि अभी देश में आईपीएल चल रहा है, लेकिन क्या जितना प्रेम हम पुरुष क्रिकेटरों से करते हैं, उतना ही स्नेह महिला खिलाड़ियों को भी नहीं मिलना चाहिए? आखिर उनकी जीत भी तो राष्ट्र की जीत है और वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती धमक का संकेत है! एक सच्चा क्रिकेटप्रेमी यह नहीं देखता कि जीतने वाला खिलाड़ी महिला है या पुरुष। अगर उस खिलाड़ी ने देश का नाम रोशन किया है, तो उसे हाथोंहाथ लिया जाना चाहिए। मगर महिला क्रिकेटरों को यह नसीब नहीं हुआ। कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि देश अभी आम चुनाव में व्यस्त है, इसलिए इस ओर ध्यान नहीं गया। मगर हम देख रहे हैं कि आईपीएल मैचों के दर्शकों की संख्या करोड़ों में है और मीडिया में भी उसे पूरी जगह मिल रही है। इस पूरे मामले में बीसीसीआई का रवैया समझ से परे नजर आया। उसने ऑनलाइन लाइव कमेंट्री के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि इस सीरीज में आशा शोभना का ऐतिहासिक डेब्यू हुआ, हरमनप्रीत कौर ने अपना 300वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला, शेफाली वर्मा ने 100वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला और शेफाली व स्मृति मंधाना की जोड़ी महिला टी-20 मैच में भारत के लिए दो हजार रनों की साझेदारी करने वाली पली जोड़ी बनी। साफ है, हर मोर्चे पर महिला खिलाड़ियों की अनदेखी की गई, जो कतई उचित नहीं है।

सुजीत कुमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

महिला टीम से बेरुखी

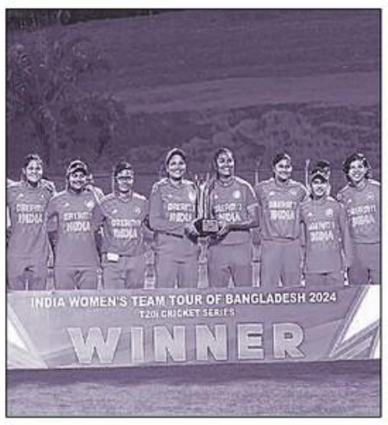

पुरुष खिलाड़ियों के समान सुविधा

यह सही है कि भारत में लंबे समय से महिला खिलाड़ियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन बीते कुछ समय से लैंगिक समानता लाने के कई प्रयास किए गए हैं, जो सराहनीय हैं। इनमें सबसे जरूरी प्रयास समान वेतन का है, जिसकी घोषणा करते हुए बीसीसीआई के सचिव ने कहा था, हम अनुबंधित बीसीसीआई महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की नीति लागू कर रहे हैं। अब पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए मैच फीस समान होगी, क्योंकि लैंगिक समानता के एक नए युग में भारतीय क्रिकेट प्रवेश कर रहा है। इसी तरह, 'वीमेंस प्रीमियर लीग', यानी डब्ल्यूपीएल की शुरुआत भी महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। डब्ल्यूपीएल का आगाज पिछले वर्ष हुआ था और इस साल फरवरी-मार्च में इसका दूसरा संस्करण खेला गया। इसका एक बड़ा फायदा यह हुआ है कि इसने देश की महिला क्रिकेटरों के सपने को नए पंख दिए। अब कई खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं और उनको प्रदर्शन के हिसाब से उचित पारिश्रमिक भी मिल रहा है।

रही बात बांग्लादेश शृंखला की, तो देश में आईपीएल और आम चुनाव साथ-साथ चल रहे हैं। किसी भी अन्य क्रिकेट शृंखला से महत्वपूर्ण आईपीएल के मैच माने जाते हैं, इसी तरह आम चुनाव भी पांच साल में एक बार होने वाला सबसे अहम आयोजन है। ऐसे में, यह आरोप गलत है कि मीडिया महिला खिलाड़ियों की अवहेलना कर रहा है। हां, इन दोनों आयोजनों के मुकाबले उनको कम सुर्खियां मिल रही हैं, क्योंकि मीडिया में जगह की भी एक सीमा होती है। रही बात बीसीसीआई की, तो संस्था के सचिव ने खुद कहा है कि देश में महिला क्रिकेट जोर-शोर से बढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कि इसे पुरुषों के मुकाबले कम तवज्जो मिल रही है। अलबत्ता, बीसीसीआई ने अपना ज्यादा ध्यान महिला क्रिकेट पर लगाया है और यह उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, क्योंकि इसका स्तर पुरुष खेल के समान ऊंचा करना है। यही कारण है कि महिला खिलाड़ियों की मैच फीस भी बढ़ाई गई है और उनकी कमाई भी अब पहले के मुकाबले ज्यादा हो रही है। इसीलिए सिर्फ एक शृंखला से किसी संस्था को कठघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। परिस्थिति के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। हां, अभी महिला खिलाड़ियों के लिए माहौल कुछ अलग है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनको कोई कमतर आंका जा रहा है। इसलिए इस मसले पर बेजा विलाप नहीं होना चाहिए।

सुष्मिता, टिप्पणीकार

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

मुम्बई हादसा : एक्ट ऑफ गॉड नहीं

आम आदमी की कोई कीमत नहीं होती। सरकारों और प्रशासन के लिए लोगों की मौतें महज एक संख्या होती हैं। आप जितना भी कह लें कि आम आदमी के लिए सरकारें हैं, संस्था है, व्यवस्था है, मगर सत्ता की गलियां इनके लिए नहीं होतीं। आम आदमी की सुनवाई कहीं नहीं होती। चुनावों के दौरान भी भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते आम आदमी की मौत कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनती। मुम्बई में सोमवार को आई तेज आंधी के दौरान घाटकोपर में एक पैट्रोल पम्प के पास लगाया गया 100 फुट से ज्यादा लम्बा बिलबोर्ड गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हो गए। क्या इस हादसे को एक्ट ऑफ गॉड माना जाए। क्योंकि हादसे की वजह तेज आंधी बताया जा सकता है। यह एक्ट ऑफ गॉड नहीं है बल्कि बृहन मुम्बई महानगर पालिका (बीएमसी), राजकीय रेलवे पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। इस हादसे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी है। बीएमसी ने मुम्बई की एक मुख्य जगह पर लगे इस बिलबोर्ड को अवैध करार दिया है जिसे लगाने के लिए कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी। जबकि जीआरपी की ओर से यह कहा गया है कि इस विशाल होर्डिंग को लगाने की अनुमति दिसम्बर 2021 में तत्कालीन जीआरपी कमिश्नर ने दी थी। जिस पैट्रोल पम्प के ऊपर यह बिलबोर्ड गिरा उसका संचालन जीआरपी पुलिस आयुक्त कल्याण निधि संगठन द्वारा किया जा रहा था।

शहरों और महानगरों में आम आदमी एक रेहड़ी और खोमचा भी लगा ले तो तुरंत स्थानीय निकाय और पुलिस उसका सामान जब्त करने के लिए पहुंच जाती है। बिना रिश्वत दिए कोई आम आदमी किसी चौराहे पर रेहड़ी भी नहीं लगा सकता। मुम्बई जैसे महानगर में जहां किसी इलाके में फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों के वैध-अवैध होने के संबंध में प्रशासन को पूरी जानकारी रहती है वहां विशालकाय बिलबोर्ड कैसे खड़ा हो गया इसकी जानकारी बीएमसी को न हो यह हैरानी की बात है।

इस बिलबोर्ड के बारे में कुछ माह पहले ही शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि यह बिलबोर्ड लगाने के लिए पेड़ों के तनों में छेद करके जहर डाला गया था ताकि वे सूख जाएं और होर्डिंग दिखाने में बाधा न आए। बीएमसी आमतौर पर अधिकतम 40X40 फीट के आकार का बिलबोर्ड लगाने की अनुमति देती है। हालांकि अवैध बिलबोर्ड गिरा है उसका साइज 120X120 फीट था यानि यह बिलबोर्ड लगभग 15000 वर्ग फीट का था। बीएमसी ने केवल होर्डिंग लगाने वाली कम्पनी को नोटिस देकर खामोशी धारण कर ली थी। होर्डिंग लगाने वाली कम्पनी ने 2022 में 6.14 करोड़ में लाइसैंस हासिल किया था। जबकि उसने अभी तक लाइसैंस फीस की बकाया राशि भी नहीं दी है। बीएमसी हर साल महानगर में होर्डिंग लगाने के लिए 1000 से अधिक लाइसैंस देती है। पिछले वर्ष बीएमसी को कुल 179 करोड़ का राजस्व मिला था, जिसमें 100 करोड़ के लगभग होर्डिंग एजैंसियों से प्राप्त हुआ था। महानगरों में होर्डिंग लगाने के ठेकों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। होर्डिंग एजैंसियां लाइसैंस हासिल कर अपनी मनमानी करती हैं और जगह-जगह अवैध होर्डिंग लगाकर कम्पनियों से धन लेती हैं और करोड़ों के वारे- न्यारे करती हैं।

शहरों और महानगरों में आम आदमी एक रेहड़ी और खोमचा भी लगा ले तो तुरंत स्थानीय निकाय और पुलिस उसका सामान जब्त करने के लिए पहुंच जाती है। बिना रिश्वत दिए कोई आम आदमी किसी चौराहे पर रेहड़ी भी नहीं लगा सकता। मुम्बई जैसे महानगर में जहां किसी इलाके में फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों के वैध-अवैध होने के संबंध में प्रशासन को पूरी जानकारी रहती है वहां विशालकाय बिलबोर्ड कैसे खड़ा हो गया इसकी जानकारी बीएमसी को न हो यह हैरानी की बात है। जिस होर्डिंग एजैंसी के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू की गई है उसका मालिक 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुका है और उस पर बलात्कार और छेड़छाड़ का मामला चल रहा है। इसके अलावा उस पर 21 मामले ऐसे चल रहे हैं जिनमें से अधिकतर अवैध होर्डिंग लगाने के हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 14 लोगों की मौत हुई उन लोगों के परिवारों के आंसू कौन पोंछेगा। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना पति। मृतकों में आटो चलाने वाले युवा भी थे और मजदूरी करने वाले लोग भी थे। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी जान की कीमत 5-5 लाख रुपए लगाई है लेकिन क्या इससे उनके जीवनभर का दर्द कम हो जाएगा। समूचा प्रशासन हादसे के बाद जितनी सक्रियता दिखा रहा है वह इतनी सक्रियता पहले दिखाता तो आम लोगों की जान नहीं जाती। ऐसे हादसों की वजह जगजाहिर है। क्या सम्बन्धित विभागों को यह नहीं पता कि मुम्बई में बारिश, तूफान के चलते लोग ऐसी जगहों पर इकट्ठे हो जाते हैं, जहां पर होर्डिंग लगाना खतरनाक हो सकता है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि ऐसी जगहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग भ्रष्टाचार के चलते ही उग आते हैं। मुम्बई के इस हादसे से सबक लेने की जरूरत है। अगर सम्बन्धित विभागों ने समय रहते अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई होती तो शायद यह हादसा टल सकता था। महाराष्ट्र सरकार ने यद्यपि अब मुम्बई में लगे अवैध होर्डिंग हटाने का फरमान जारी कर दिया है लेकिन यह सब जानते हैं कि सरकारों के लिए आम आदमी की कीमत कुछ भी नहीं है।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

NewsPaperPaid

नारी की गरिमा खतरे में...

जब देश में कहीं पर भी एक नारी की गरिमा खतरें में नजर आए,
तो इस बात से नारी की वर्तमान स्थिति का अंदाजा लगाएं,,
फिर कैसे भारत देश पुनः विश्व गुरु का दर्जा पाए,
जब दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के देश में नारी चींटी की तरह रौंदी जाए...।।"

गीता पाढा

लू से होने वाली मौतों में से सबसे ज्यादा 20 फीसदी मौतें भारत में हुई

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दुनिया भर में प्रति वर्ष 1.53 लाख से अधिक मौतें भीषण गर्मी या लू के कारण होती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 20 फीसदी मौतें भारत में होती हैं। एक अध्ययन से यह जानकारी मिली।पिछले 30 वर्षों से अधिक के आंकड़ों के आधार पर यह अध्ययन किया गया। भारत के बाद चीन और रूस का स्थान है, जिनमें से प्रत्येक में क्रमशः लगभग 14 फीसदी और आठ फीसदी मौतें भीषण गर्मी से जुड़ी होती हैं।मोनाश विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में पाया गया कि लू से जुड़ी मौतें गर्मी से संबंधित सभी मौतों का लगभग एक तिहाई और वैश्विक स्तर पर कुल मौतों का एक प्रतिशत है।शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि हर साल गर्मियों में होने वाली कुल 1.53 लाख अतिरिक्त मौतों में से लगभग आधी एशिया में और 30 प्रतिशत से अधिक यूरोप में होती हैं। इसके अलावा, सबसे बड़ी अनुमानित मृत्यु दर (जनसंख्या के अनुपात में मृत्यु) शुष्क जलवायु और निम्न-मध्यम आय वाले क्षेत्रों में देखी गई। अध्ययन 'पीएलओएस मेडिसिन' में प्रकाशित हुआ है।शोधकर्ताओं ने लिखा है, ''1990 से 2019 तक गर्म मौसम के दौरान, लू से संबंधित अतिरिक्त मौतों के कारण प्रति वर्ष 1,53,078 मौतें हुईं। इस तरह प्रति दस लाख निवासियों पर कुल 236 मौतें हुईं।'' अध्ययन के लिए, शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन स्थित मल्टी-कंट्री मल्टी-सिटी (एमसीसी) सहयोगात्मक अनुसंधान नेटवर्क के आंकड़ों का इस्तेमाल किया।

केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत के बाद...

मर्यादाएं
चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के 'असाधारण महत्व', का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का यह तर्क रद्द कर दिया कि अंतरिम ज़मानत देने से राजनेता आम आदमी की तुलना में लाभकारी स्थिति में पहुंच जाएंगे और इससे ग़लत संदेश जाएगा। अदालत का यह भी कहना था कि बेशक उन पर गम्भीर आरोप हैं पर उन्हें दोषी नहीं पाया गया। कोई ज़ब्ती नहीं हुई। पर अदालत ने यह शर्त लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और किसी फ़ाईल पर दस्तख़त नहीं करेंगे। अर्थात जहां अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत से राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के कारण उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहने पर सवालिया निशान लग गया है। अगर वह कोई सरकारी कामकाज नहीं निपटा सकते तो मुख्यमंत्री बने रहने का औचित्य नहीं रहता। ईडी का तर्क है कि चुनाव प्रचार में शामिल होना मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर सामान्य लोगों को ज़मानत नहीं मिलती तो नेताओं को देना समानता के क़ानून के शासन के खिलाफ है। ईडी का तर्क भी वज़नदार है।

अब क्या इसी आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अंतरिम ज़मानत मिलेगी कि वह भी प्रचार कर सकें? 13 मई वाला चरण तो गुजर गया पर अभी वहां तीन चरण और बाक़ी हैं और हेमंत सोरेन की प्रचार में मौजूदगी से काफ़ी अंतर आ सकता है। क्या तेलंगाना की के.कविता, जो भी शराब घोटाले के कारण अंदर है, को भी ज़मानत मिलेगी? अर्थात यह फ़ैसला बहुत बहस को आमंत्रित करेगा पर यह फ़ैसला लोकतंत्र को मज़बूत करने की तरफ बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरह चुनाव की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उससे बहुत ग़लत संदेश गया था। ईडी का इस्तेमाल केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ करने को देश में पसंद नहीं किया गया है।

2014 के बाद राजनेताओं के खिलाफ ईडी की कार्यवाही में चार गुना वृद्धि हुई है, जिनमें 96 प्रतिशत विपक्ष के नेता हैं। ईडी की कारगुज़ारी पर एक विशेष अदालत यह चेतावनी दे चुकी है," अगर इतिहास से कोई सबक़ सीखना है तो यह कि मज़बूत नेता, क़ानून, और एजेंसियां आम तौर पर उन नागरिकों को काटने के लिए लौटती हैं जिनके संरक्षण का उन्होंने प्रण लिया होता है"। अरविंद केजरीवाल को मिली इस ज़मानत से कुछ हद तक जिसे लैवल प्ले ग्राउंड कहा जाता है, वह बहाल हुआ है। एक बार फिर न्यायपालिका की संविधान के संरक्षक के रूप में भूमिका रेखांकित हुई है। देश की जनता नहीं चाहती कि एक-एक कर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाए।

हम मज़बूत सरकार और मज़बूत विपक्ष दोनों चाहते हैं। हम आज़ाद मीडिया चाहते हैं। न ही इसे पसंद किया गया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बैंक खाते चुनाव से पहले फ्रीज करने की कार्रवाई की गई। चुनाव लोकतंत्र की धड़कन है और जनता नहीं चाहती कि एक पक्ष को ज़बरदस्ती वैंटीलेटर पर डाल दिया जाए। इसलिए यह अच्छी बात है कि एक लोकप्रिय नेता को चुनाव प्रचार की इजाज़त मिल गई है। परिस्थिति विशेष थी, जो बात माननीय न्यायाधीशों ने भी मानी है। इस राहत से विपक्ष और केजरीवाल दोनों का मनोबल बढ़ेगा। दिल्ली में चुनाव 25 मई को है और पंजाब में 1 जून को। हैरानी की बात है कि अरविंद केजरीवाल छोटी सी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं पर जिस तरह दिल्ली के उपराज्यपाल से उनका टकराव चल रहा है और सरकारी एजेंसियां उनके पीछे लगी हैं उससे तो यह प्रभाव मिलता है कि भाजपा केजरीवाल को भावी ख़तरा समझती है जिसे वह शुरू में ही मसलना चाहती है।

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 62 आप के पास ज़रूर हैं पर लोकसभा की सात की सात सीटें भाजपा जीतने में सफल रही है। अर्थात दिल्ली की जनता विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग-अलग मापदंड रखती है फिर भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा प्रतिद्वंद्वी क्यों समझा जाता है? क्या घबराहट है कि दिल्ली में आप-कांग्रेस का गठबंधन उलटफेर न कर दे? अरविंद केजरीवाल से एक और तकलीफ़ है, वह राहुल गांधी नहीं हैं। इस बार तो राहुल गांधी ने ज़बरदस्त चुनौती दी है और प्रियंका गांधी विशेष तौर पर आक्रामक और प्रभावी हैं, पर इस परिवार के खिलाफ ग़लत-सही कहने को भाजपा के पास बहुत कुछ है। वह 'डायनॉस्ट' अर्थात उच्च वंश से सम्बन्धित है। कांग्रेस के पूर्व शासन की ग़लतियों को उन पर थोपा जा सकता है। राहुल गांधी को नरेन्द्र मोदी 'शहज़ादा' कहते हैं, अमित शाह 'राहुल बाबा'। पर ऐसी कोई संज्ञा ज़मीन से उठे और दस साल की अल्पावधि में दिल्ली और पंजाब में पैर जमाने वाले अरविंद केजरीवाल के बारे इस्तेमाल नहीं की जा सकती। दिल्ली के जेएनयू के पोलिटिकल साईंस के प्रोफ़ेसर नरेन्द्र कुमार का कहना है, "इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा का लम्बे समय का लक्ष्य विपक्ष को बिल्कुल मामूली बनाना है...केजरीवाल भविष्य के लिए गम्भीर ख़तरा हैं"। विचारधारा को एक तरफ़ रख लोगों की मूलभूत समस्याओं पर केन्द्रित रहने के प्रयास ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया है। बिजली, पानी, मुहल्ला क्लीनिक, अच्छे स्कूल आदि प्रदान कर उन्होंने अपना आधार बढ़ाया है। अब रिहा होने के बाद उन्होंने ग़रीबों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बेहतर सरकारी स्कूल, हर गांव में क्लिनिक का वादा किया है। सारा ध्यान कल्याणकारी योजनाओं पर है। न ही उनके बारे यह कहा जा सकेगा कि वह 'राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवा देगें'। हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल पर किसी तरह के तुष्टिकरण का आरोप भी नहीं लग सकता। वह भगवंत मान को लेकर राम मंदिर के दर्शन भी कर आए हैं। अर्थात् केजरीवाल के खिलाफ कहने को बहुत कुछ नहीं है। कई तो यह भी मानते हैं कि एक दिन वह भाजपा और कांग्रेस दोनों का विकल्प हो सकते हैं। आख़िर ज़मीन से जुड़े नेता हैं और लोगों की नब्ज पहचानते हैं।

उन्होंने स्पष्ट तौर पर धारा 370 हटाए जाने, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। पर यह आगे की बात है। इस समय तो वह इस कथित शराब घोटाला में फँसे हैं जिस पर न्यायालय का फ़ैसला आना बाक़ी है। अन्ना हज़ारे की 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आन्दोलन से निकले अरविंद केजरीवाल का उभार प्रभावशाली रहा है। उस आन्दोलन के वह एकमात्र लाभार्थी हैं। 10 साल में उन्होंने अपने पैर जमा लिए हैं। उन्हें हवा का ताज़ा झोंका समझा गया, कुछ नए विचार और नई कार्यशैली सामने आए। वह तो नरेन्द्र मोदी के गुजरात में 2022 के चुनाव में 12 प्रतिशत वोट और 2 सीटें जीतने में सफल रहे हैं। इसके बाद आप को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया। केजरीवाल ने स्थापित राजनेताओं का विरोध कर खुद को स्थापित किया था। शीला दीक्षित को तो जेल में डालने की धमकी दी थी। पर अब वह बदले हैं। वह नीली वैगन-आर वाले केजरीवाल नहीं रहे। जो नए साथी राज्य सभा में लिए गए हैं उनमें से संजय सिंह को छोड़ कर मुसीबत की घड़ी में किसी ने भी साथ नहीं दिया। सब डर के मारे या तो विदेश भाग गए हैं या छिप गए हैं। जिस तरह सड़क पर उतर कर तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन करते हैं उससे आप के सांसद तो कोसो दूर भाग गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ज़रूर पूरा साथ दे रहे हैं। अंतरिम ज़मानत अरविंद केजरीवाल की समस्याओं का अंत नहीं है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि केस का क्या बनता है? इस दौरान वह लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे पर क़ानून की लड़ाई तो अदालत में ही लड़ी जाएगी। उनकी ज़मानत ईडी के लिए धक्का जरूर है पर यह क्लीन चिट नहीं है। वह सख्त पीएमएलए क़ानून के नीचे जेल भेजे गए हैं पर एक रुपए का काला धन बरामद नहीं हुआ। जब तक उन्हें स्थाई ज़मानत नहीं मिल जाती तब तक उनकी मुसीबतें ख़त्म नहीं होंगी।

सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर चुनाव न होते तो अंतरिम ज़मानत न मिलती। आप का भी वही हाल हैं जो बसपा, सपा, जदयू, बीजेडी, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस जैसी एक व्यक्ति पर आधारित पार्टियों का है। अगर बड़े नेता को कुछ हो गया तो पार्टी भटक जाती है। सब कुछ अपने इर्द गिर्द समेटने की क़ीमत चुकानी पड़ती है। नवीन पटनायक की बीमारी के कारण उड़ीसा में बीजू जनता दल अब अनिश्चित दौर में प्रवेश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता ने कुछ भूमिका निभाने की कोशिश की थी पर यह प्रभाव सही नहीं कि आम लोगों पर आधारित पार्टी भी एक परिवार तक सिंकुड़ कर रह गई है। सुनीता केजरीवाल आप के 40 स्टार प्रचारक की सूची में दूसरे नम्बर पर रखी गई है। दूसरी राबड़ी देवी बनाने के प्रयास को पसंद नहीं किया जाएगा। वैसे भी अभी उनकी पार्टी बहुत छोटी है।

विपक्ष में वह कांग्रेस का मुक़ाबला नहीं कर सकते जो सारे देश में फैली है। अमित शाह ने भी कटाक्ष किया है कि जो पार्टी केवल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसके नेता सारे देश में बिजली मुफ्त करने का वादा कर रहे हैं। विपक्ष के नेता की भूमिका पर अब राहुल गांधी का अधिकार बनता है जिनकी स्वीकार्यता बहुत बढ़ गई है।

प्रधानमंत्री मोदी की सिख गुरुओं के प्रति आस्था

सिख सियासत
सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सिख गुरु साहिबान के प्रति आस्था के चलते ही सिख समुदाय के लम्बे समय से लटकते हुए मसलों का समाधान निकलता दिख रहा है हालांकि अभी

भी गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी, गुरुद्वारा डोंगमार सिक्किम जैसे मसले हैं जिनके लिए उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में उनका भी कोई समाधान निकल पाएगा। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में आपातकाल के समय कई महीनों तक पंजाब में सिख समुदाय के बीच सिखी वेषभूषा धारण कर रहे थे। जिस दौरान उन्होंने गुरु साहिबान के जीवनकाल और सिख इतिहास की जानकारी हासिल की। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिला के मंच से देशवासियों को दिये संदेश में साफ किया था कि अगर गुरु तेग बहादुर साहिब ना होते तो इस देश का नक्शा आज कुछ और ही होता, ना हिन्दू धर्म होता और ना ही हिन्दुस्तान। मगर अफसोस कि आज तक देशवासियों को उन जालिम लोगों का इतिहास पढ़ाया जाता रहा जिन्होंने जुल्म की इन्तहा करते हुए इस देश में केवल एक ही धर्म रखने की बात की, मगर गुरु साहिबान और सिखों की शहादतों की दास्तान किसी ने बताने की सोची ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साहिबजादों की शहादत को ''वीर बाल दिवस'' के रूप में मनाकर देशवासियों को बताया कि गुरु गोबिन्द सिंह जी के साहिबजादे कौन थे और उन्होंने शहादत क्यों और किसलिए दी थी।

गुरु गोबिन्द सिंह जी की जन्म स्थली पटना साहिब जहां सिखों का दूसरा तख्त मौजूद है मगर देश की आजादी से लेकर आज तक 77 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा इस पवित्र स्थल के दर्शन तक करना मुनासिब नहीं समझा गया। 1979 में इन्दिरा गांधी यहां जरूर गई, मगर उस समय वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थी। पद पर रहते हुए नरेन्द्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वयं तख्त पटना साहिब के दर्शनों की इच्छा जाहिर की और इतना ही नहीं पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ सिर पर दस्तार सजाकर, प्रशादि और रुमाला साहिब लेकर तख्त पटना साहिब नतमस्तक हुए, अरदास करते हुए ग्रन्थ साहिब के समक्ष चौर साहिब की, लंगरहाल में जाकर लंगर की सेवा निभाई और सिख संगत से मिले भी। मैं तो स्वयं को भी सौभाग्यशाली मानता हूं जो मुझे इन क्षणों का साक्षी बनकर सभी दृश्यों को देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री के आगमन को कुछ लोग राजनीतिक रंग देते हुए इसे सिखों की वोट हासिल करने के लिए की गई कार्यवाही बता रहे हैं मगर शायद उन्हें इस बात का अन्दाजा ही नहीं है कि पूरे पटना में मात्र कुछ हजार ही सिख वोट होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा का मानना है कि इससे प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी को नहीं बल्कि सिख समुदाय को समूचे राष्ट्र में लाभ मिलेगा और जो लोग अभी भी सिखों को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं उनकी सोच में बदलाव निश्चित तौर पर आयेगा। आयोग के पूर्व चेयरमैन तरलोचन सिंह का कहना है कि ऐसे प्रधानमंत्री का समुचे सिख समुदाय को शुक्रगुजार होना चाहिए जहां सिख प्रधानमंत्री ने भी अपने 10 साल कार्यकाल के दौरान जाने की सोच नहीं रखी वहां मौजूदा प्रधानमंत्री ने जाकर समूचे सिख कौम को गौरवान्वित किया।

तख्त पटना साहिब कमेटी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सफलता और लम्बी आयु के लिए श्री गुरु ग्रन्थ साहिब का अखण्ड पाठ भी रखवाया गया था जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री शामिल हुए और अरदार की। कमेटी के प्रधान जगजोत सिंह सोही, महासचिव इन्द्रजीत सिंह सहित समूची कमेटी के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा 3 राष्ट्रपति, 18 कैबिनेट मंत्रियों सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री भी नतमस्तक हुए। वैसे तो इस तख्त की इतनी महानता है कि जो भी राजनेता यां प्रशासनिक अधिकारी पटना पहुंचता है वह तख्त साहिब के दर्शनों के लिए स्वयं खिचा चला आता है।

खालसा पंथ की माता साहिब कौर जी

गुरु गोबिंद सिंह जी ने माता साहिब कौर जी को खालसा पंथ की माता होने का गौरव बख्शिश किया था। समूचा पंथ गुरु गोबिन्द सिंह जी को पिता और साहिब कौर जी को माता के रूप में मानता आ रहा है। इतिहास बताता है कि माता जी गुरु जी से मिलने के पश्चात उन्हें अपना पति मान चुकी थी मगर गुरु गोबिन्द सिंह जी पहले से ही शादीशुदा थे जिसके चलते उन्होंने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। माता जी के परिवार वालों की अपील पर गुरुजी उनके आनंदपुर में रहने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए बिना, इस शर्त पर स्वीकार किया था कि माता साहिब देवा के साथ संबंध आध्यात्मिक होगा, शारीरिक नहीं। आज लोग साल में एक दिन मदर्स डे मनाकर महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश करते हैं मगर सिख धर्म में महिलाओं को हमेशा ही उच्च स्थान दिया जाता रहा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिन्द सिंह जी ने महिलाओं को सम्मान दिया। आज भी सिख समाज उसी परंपरा को निभाता आ रहा है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि साल में एक दिन नहीं बल्कि पूरा साल महिलाओं को माता, बहन, बेटी के रुप में सम्मान दें।

गुरु के सिख का जज्बा

गुरु के सिख में जजबा स्वयं ही आ जाता है जिसका ताजा उदारहण 10 वर्षीय जसप्रीत सिंह में देखने को मिला। पिता की मौत के बाद मां भी चली गई मगर बच्चे ने अपनी ही नहीं बड़ी बहन की पढ़ाई और परवरिश के लिए पिता द्वारा चलाई जा रही छोटी सी रेहड़ी को पुन: शुरू किया। सुबह स्कूल, दोपहर ट्यूशन करते हुए शाम को रेहड़ी पर खड़े होकर गुरु नानक के किरत करो के सन्देश पर पहरा देते हुए काम करने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बड़े-बड़े व्यवसाई, बालीवुड अभिनेता और नेतागण उसकी मदद के लिए आगे आए हैं मगर बच्चे का साफ कहना है कि वह ''गुरु गोबिन्द सिंह जी का पुत्र है'' इसलिए हिम्मत नहीं हारेगा, जब तक शरीर में जान है मेहनत करेगा। लालच में आकर किसी से बिना वजह मदद भी नहीं लेगा। स्थानीय विधायक जरनैल सिंह के द्वारा जसप्रीत के लिए रेहड़ी के स्थान पर एक सुन्दर सा कार्ट बनवा दिया जिसमें खड़े होकर जसप्रीत अब अपने काम को आगे बढ़ा रहा हैं। उसकी सभी से एक ही अपील है कि अगर आप मदद करना चाहते हैं उसके कार्ट पर आकर रोल खाईये। सलाम है गुरु साहिब के इस लाडले बच्चे को जसप्रीत जैसी खुद्दारी हर सिख में होनी चाहिए।

खेतड़ी खदान हादसे में हिंदुस्तान कॉपर के मुख्य सतर्कता अधिकारी की मौत

जयपुर, (पंजाब केसरी): राजस्थान के नीम का थाना जिले में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की खेतड़ी स्थित एक खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से उसमें फंसे 15 लोगों में से 14 को बुधवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया जबकि हादसे में मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यह हादसा मंगलवार रात को उस समय हुआ जब करीब 8:00 बजे निरीक्षण के दौरान लिफ्ट की केबल टूटने से लिफ्ट नीचे गिर गई और उसमें सवार 15 व्यक्ति फंस गए।

कई घंटे चले बचाव अभियान में बुधवार दोपहर तक चौदह लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि एचसीएल की कोलकाता से आई सतर्कता टीम और अन्य लोगों को मंगलवार रात एक पिंजरा (कैज) के जरिए शाफ्ट से नीचे उतारा जा रहा था, तभी इसकी केबल टूट गई, जिससे वे 1,875 फुट की गहराई पर फंस गए। राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक अनिल पालीवाल ने बताया कि खेतड़ी स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में हुए हादसे कारण उसमें फंसे 15 व्यक्तियों में से 14 को एसडीआरएफ व कंपनी की बचाव टीम ने अभियान चला सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे का शव बरामद किया गया। पांडे ने पिछले साल जून में एचसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार संभाला था।

एचसीएल ने एक बयान में कहा, '14 मई को शाम करीब 7.30 बजे राजस्थान के खेतड़ी नगर स्थित खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (एचसीएल की एक इकाई) की कोलिहान तांबा खदान में एक हादसा हुआ। दिल्ली में खान सचिव वीएल कांता राव ने कहा कि घटना की जांच के आदेश दिये जाएंगे। राव ने संवाददाताओं से कहा, मैं कुछ महीने पहले उसी लिफ्ट में था। सब कुछ अच्छा था... हम जांच कराएंगे और पता लगाएंगे कि क्या हुआ।

एसडीआरएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पालीवाल ने बताया कि एसडीआरएफ तथा कॉपर लिमिटेड के बचाव दल ने मंगलवार देर रात लगभग तीन बजे संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। टीम कमांडर रवि वर्मा नौ जवानों तथा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बचाव टीम को लेकर दूसरी लिफ्ट एवं 'रेस्क्यू रोप' की सहायता से घायलों तक पहुंचे। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और 'इंप्रोवाइज्ड स्ट्रेचर' और 'रेस्क्यू रोप' की मदद से उन्हें 64 मीटर स्तर पर बेस तक लाया गया और फिर खदान के वाहनों से बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया गया।

पुलिस ने बताया सबसे पहले बचाव टीमों ने तीन गंभीर घायलों को बाहर निकाला। उसके बाद पांच व्यक्तियों को और अंत में सभी सात व्यक्तियों को बाहर निकाल कर अस्पताल भिजवाया। साथ ही मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे के शव को बाहर निकाला गया। इस अभियान में बचाव टीम ने केसीसी इकाई प्रमुख जीडी गुप्ता, कोलिहान खदान उप महाप्रबंधक एके शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक विद्युत विनोद सिंह शेखावत, सहायक उप महाप्रबंधक मैकेनिक एके बेरा, मुख्य प्रबंधक खदान अर्णय भंडारी, सहायक उप महाप्रबंधक यशोराज मीणा, सहायक उप महाप्रबंधक विजिलेंस वी.भंडारी, फोटोग्राफर विकास पारीक, वरिष्ठ प्रबंधक (अनुसंधान) निरंजन साहू, सुरक्षा अधिकारी करण सिंह, प्रबंधक प्रीतम सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक खदान रमेश नारायण सिंह एवं कर्मचारी हरसी राम तथा भागीरथ को निकालने में सफलता हासिल की है।

14 लोगों को बचाया

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

CMYK

संपादकीय

नई दिल्ली, गुरुवार 16 मई 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

पुरकायस्थ की रिहाई : आज़ाद खयाली को राहत

प्रसिद्ध न्यूज़ पोर्टल न्यूज़क्लिक के संस्थापक व प्रधान सम्पादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अमान्य करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरन्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। उन्हें पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम- यूएपीए के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। उन्हें चीन की ओर से दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि पुरकायस्थ एवं न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने देश की सम्प्रभुता को बाधित करने एवं देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिये चीन से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, जिसे 'टेरर फंडिंग' कहा जाता है। पुलिस के मुताबिक भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखलंदाजी के उद्देश्य से न्यूज़क्लिक ने पीपुल्स एलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्यूलरिज्म के साथ मिलकर कथित रूप से साजिश की थी। इस आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 9000 पृष्ठों का आरोप पत्र एवं कई उपकरण साक्ष्य के रूप में पेश किये थे, जिनमें मोबाइल, कम्प्यूटर आदि शामिल थे। उल्लेखनीय है कि अमित चक्रवर्ती इस वर्ष की जनवरी में सरकारी गवाह बन गये थे जिसके कारण उन्हें 6 मई को जमानत मिल चुकी है। न्यूज़क्लिक की ख्याति व्यवस्था के खिलाफ मुखर होकर खबरें देने वाले पोर्टल की है।

जस्टिस बीआर गवई एवं जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश देते हुए कहा साफ किया कि पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के पीछे के आरोप आधारहीन व अमान्य हैं क्योंकि गिरफ्तारी के समय उन्हें इस का आधार नहीं बताया गया था। वैसे इस मामले में दिल्ली पुलिस दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है इसलिये पुरकायस्थ की रिहाई ट्रायल कोर्ट के जमानत नियमों के तहत हुई। उन्हें जमानत बॉन्ड भरने के लिये कहा गया है। उनके वकील अर्शदीप खुराना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि वे पहले से कहते आये हैं कि यह गिरफ्तारी अवैध है।

पुरकायस्थ की रिहाई उन सभी लोगों एवं संगठनों के लिये राहत की बात है जो स्वतंत्र विचारों एवं अभिव्यक्ति की आजादी में भरोसा करते हैं। इनमें अनेक विचारक, लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वैसे तो यूएपीए का यह कानून 1967 में अस्तित्व में आया था जो केन्द्र सरकार को कठोर शक्तियां प्रदान करता है। इसमें 2008 में एक संशोधन लाकर यह नियम बनाया गया कि अगर मामला प्रथम दृष्टया सत्य महसूस होता है तो आरोपी को जमानत देने से इंकार किया जा सकता है। 2019 में केन्द्र सरकार ने इसमें एक और महत्वपूर्ण संशोधन लाकर इसे अधिक कठोर बना दिया है। इस कानून का इसलिये मानवाधिकार संगठन विरोध करते रहे हैं क्योंकि यह लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। किसी के भी वक्तव्यों या कामों को देशविरोधी अथवा उकसाने वाली कार्रवाई बतलाकर उसकी गिरफ्तारी आसान है। जमानत मिलनी कठिन है जो न्याय के अधिकार का भी हनन है। इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों से सम्बन्धित लोगों के खिलाफ भी किया जाता है। इतना ही नहीं, संगठनों के अलावा व्यक्तियों पर भी यूएपीए लागू करने का नियम बनाया गया। अभियोजन के मानकों का इसमें अभाव होने के कारण इसके दुरुपयोग की गुंजाइश बहुत ज्यादा है; और वह जमकर हो भी रहा है। पीयूसीएल ने वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके अनुसार इस नियम की सफलता की दर बहुत कम है। इसमें बताया गया था कि 2016 से 2020 के बीच हुई गिरफ्तारियों में 3 प्रतिशत से भी कम को सज़ा मिली थी।

मौजूदा सरकार द्वारा यूएपीए का दुरुपयोग करने की भरपूर शिकायतें मिलती रही हैं। आजाद खयाल लोगों एवं संगठनों ने इस आधार पर भी इस कानून का विरोध किया है क्योंकि इसके जरिये सरकार अपने विरोधियों व आलोचकों की आवाज़ दबाती है। बड़ी संख्या में वकील, नेता, लेखक-पत्रकार, सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्ता इसके तहत गिरफ्तार किये गये हैं। कई तो लम्बे समय से जमानत पाने के लिये संघर्षरत हैं। यह भी पाया गया है कि सरकार या सरकार में बैठे लोगों के विरूद्ध बोलने या पृथक विचार रखने वालों को लम्बे समय तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ाया जाता है। जमानत आसानी से मिलती नहीं और फैसले भी खूब लम्बे खिंचते हैं। बरी होने के पहले आरोपी अपना लम्बा समय जेलों में बिता देते हैं। सरकार में बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने को भी देशविरोधी गतिविधि या कार्रवाई बतलाकर आधारहीन व गैरकानूनी तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।

पिछले दस वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासनकाल में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी है। आरोप है कि अपने आलोचकों को वह इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करने में संकोच नहीं करती। 2021 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके पहले 7 वर्षों में 10552 लोग इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार हुए लेकिन दोष सिद्धी हुई केवल 253 के खिलाफ। अनेक प्रतिष्ठित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला गया। पत्रकारों की भी एक लम्बी सूची है जिन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यूज़क्लिक के ही सलाहकार सम्पादक गौतम नवलखा भी इनमें शामिल रहे। सरकार विरोधी विचार तो दूर, व्यवस्था की पोल खोलने वाली या उनमें खामियों का खुलासा करने वाली खबरें छापने के कारण भी कई पत्रकारों को इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। जहां तक आतंकवाद में संलिप्त व्यक्तियों एवं संगठनों से जुड़े लोगों की बात है, तो उन्हें सज़ा दिलाने से किसी का विरोध नहीं, पर इसका इस्तेमाल वैचारिक विरोधियों के खिलाफ करना गलत है। लोकतंत्र में सरकार का विरोध जायज है।

राहुल की राह पर राजनीति से उम्मीदें

दुनियादारी

■ **सर्वमित्रा सुरजन**

देश की जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकारों की पैरोकार शबनम हाशमी ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं, उनके दूसरे हाथ में एक डलिया है और उन दोनों के साथ उनका पालतू कुत्ता भी घास पर टहल रहा है। इस तस्वीर में राहुल और सोनिया गांधी के बीच प्यार और ममत्व का वही जज्बा नजर आ रहा है, जो किसी भी मां-बेटे के बीच स्वाभाविक तौर पर होता है। शबनम हाशमी ने इस तस्वीर के साथ एक कैप्शन लिखा है, जो काबिले-गौर है। सुश्री हाशमी ने लिखा कि छप्पन इंच की नहीं एक ऐसी छाती चाहिए जिसमे मोहब्बत हो। जो अपनी मां से मोहब्बत करता है वह सब से मोहब्बत करने का जज़्बा रखता है। यह बेहद ही खूबसूरत और नेचुरल फोटो है। और जिनको छप्पन इंच का शौक़ है उनकी फोटो देख कर लगता है ज़बरदस्ती माँ के साथ बैठा दिया है।

इस कैप्शन में 56 इंच की छाती और मां के साथ जबरदस्ती बिठाने वाला तंज किस पर किया गया है, इसके अलग से खुलासे की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अब तो भारत का बच्चा-बच्चा जानता है कि अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में श्री मोदी ने कैसे जन्मदिन या अन्य अवसरों पर अपनी मां के साथ तस्वीरें खिंचाई हैं। कभी वो उनके पैरों में बैठे हैं, कभी उनके हाथ से प्रसाद खा रहे हैं। हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी घर, कुछेक अपवादों को छोड़कर मांएं अक्सर अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार से दुलारती और खिलाती हैं। इस जज्बात को किसी प्रचार की आवश्यकता कभी नहीं रही। लेकिन नरेन्द्र मोदी अपनी राजनीति को चर्चा में बनाए रखने के लिए कई बार अपनी मां को बीच में ले आए। अमेरिका में उन्होंने इस बात पर आंसू बहाए थे कि उनकी मां को दूसरों के घर बर्तन मांजना पड़ता था। भारत में उन्होंने नोटबंदी के फैसले के बाद एक तस्वीर में दिखाया था कि उनकी मां भी नोट बदलने के लिए कतार में खड़ी हुईं। जबकि वे प्रधानमंत्री की मां हैं, तो उन्हें आम लोगों की तरह कतार में लगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर ऐसा हुआ, और इसकी बाकायदा तस्वीरें खींची गई, जिसका राजनीतिक मकसद अपने आप जाहिर हो गया। जब श्री मोदी की मां बीमार थी और अस्पताल में आईसीयू में थी, तब वे उनसे मिलने गए और वहां भी उनकी तस्वीरें खींची गईं। इस तरह माता और संतान के बीच के रिश्ते का राजनीतिकरण भी श्री मोदी ने मुमकिन कर दिखाया।

तीन दिन पहले ही रविवार को जब दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा था, तब नरेन्द्र मोदी प.बंगाल में एक सभा कर रहे थे और वहां उन्हें दो लोगों ने उनकी मां के साथ उनका एक चित्र उन्हें भेंट किया। जिस पर आभार प्रकट करते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया मदर्स डे मना रही है, लेकिन भारत में तो हम 365 दिन मां की पूजा करते हैं। दुर्गा, काली और भारत मां की पूजा करते हैं। इसके बाद अपने भाषण में उन्होंने संदेशखाली की घटना का जिक्र छेड़कर टीएमसी पर हमला किया। इस पूरे चुनाव में कई बार नरेन्द्र मोदी नारी शक्ति का जिक्र कर चुके हैं। महिला उत्पीड़न पर विरोधियों को घेर चुके हैं। मगर मणिपुर पर वे कुछ नहीं बोल रहे हैं और बोलेंगे भी नहीं। क्योंकि उनकी अपनी मां हों या मातृ शक्ति, श्री मोदी के लिए वे राजनीति के औजार से अधिक कुछ नहीं हैं। मंगलवार को श्री मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया। यहां भी 2014 में उन्होंने मां गंगा वाला जुमला उछाल कर लोगों की भावनाओं का दोहन किया था। इस बार उनके नामांकन के एक दिन पहले 13 मई को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर द प्रोटैगनिस्ट नाम के यूज़र ने पोस्ट लिखी है कि उन्हें पता चला है कि उनकी मां को दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है। क्योंकि नरेन्द्र मोदी वहां नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस यूजर ने लिखा है कि मेरी 52 बरस की मां इस कायर के लिए खतरा हैं। बता दें कि इस यूज़र को दो दिनों से अपनी मां के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था और इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें अब खबर मिली अपनी मां के हिरासत में होने की। इस पूरी घटना का कारण और उसका सच शायद कुछ दिनों में बाहर आए, लेकिन नरेन्द्र मोदी देवी शक्ति, मातृ शक्ति की बात क्यों करते हैं और किस तरह उन महिलाओं का अपमान करते हैं, जो उनके विरोध में हैं या विरोधी खेमे में हैं, यह सच अनेक अवसरों पर उनके बयानों से जाहिर हो चुका है।

> **सोनिया गांधी उनकी मां हैं, तो उनके साथ दुलार भरी तस्वीर का आना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन पूरे देश में कई महिलाओं की (हर उम्र और वर्ग की) वैसी ही स्नेह भरी तस्वीरें बीते सालों में सामने आई हैं। इसलिए मौजूदा राजनैतिक, सामाजिक परिदृश्य में देश में प्यार, उदारता और कल्याणकारी माहौल बनाने की उम्मीद राजनीति की उस राह पर चलकर ही पूरी हो सकती है, जो गांधीजी की राह है, जो राहुल गांधी की राह है।**

बहरहाल, शबनम हाशमी ने राहुल और सोनिया गांधी की तस्वीर में नजर आ रहे स्वाभाविक प्रेम और सुंदरता की तारीफ तो की ही है, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह आज और प्रासंगिक हो जाता है। शबनम हाशमी ने अपने राजनैतिक रुझान और कांग्रेस के बारे में अंग्रेजी में लिखा है कि 1976 में मैं जब कॉलेज में दाखिल हुई तो पहली राजनैतिक भागीदारी आपातकाल के विरोध में हुई। इसके बाद 1989 में मैंने कांग्रेस से जुड़े गुंडों की वजह से अपने भाई सफदर हाशमी को खोया। लेकिन 2002 के बाद मैंने गुजरात में कांग्रेस को करीब से देखा। राहुल गांधी ने मुझे उम्मीद दी है। हजारों किमी की यात्रा और लाखों लोगों से संवाद के बाद अब राहुल एक बदले हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे उम्मीद दी है कि मानवता से भरे समाज निर्माण का सपना संभव है। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि इस समाज से प्यार, कल्याण और उदारता अभी खत्म नहीं हुई है। मैं उम्मीद करती हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, विमर्श, चर्चा और मतभिन्नता को साथ लेकर चलते हुए कांग्रेस राहुल की राह पर आगे बढ़ेगी।

शबनम हाशमी ने पूरी साफगोई से अपनी बात रखी है कि उनका रुझान हमेशा से कांग्रेस की तरफ नहीं था, लेकिन राहुल गांधी में उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही है। शायद यही राहुल गांधी की ताकत है। या यह भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने राजनीति के जिस तरीके को अपनाया है, यह उसकी ताकत है। गांधीजी इसी ताकत के साथ अंग्रेजों से लेकर देश के राजनैतिक दिग्गजों के सामने खड़े होते थे। जिस वजह से उनसे कट्टर मतभिन्नता रखने वाले भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। राहुल गांधी, गांधी नहीं हैं, लेकिन आज के दौर में उन्होंने देश में वही उम्मीद भरी है, जो एक वक्त में गांधी के कारण गुलाम भारत में आम लोगों में भर गई थी।

शबनम हाशमी ही नहीं, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद जैसे अनेक नेता, जो कांग्रेस या गांधी परिवार से मतभेद रखते थे, राहुल गांधी के लिए स्नेह और आदर प्रदर्शित कर चुके हैं। यह उसी मोहब्बत की दुकान का नतीजा है, जिसे राहुल गांधी पूरे देश में खोलने के लिए पैदल निकल पड़े थे। सोनिया गांधी उनकी मां हैं, तो उनके साथ दुलार भरी तस्वीर का आना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन पूरे देश में कई महिलाओं की (हर उम्र और वर्ग की) वैसी ही स्नेह भरी तस्वीरें बीते सालों में सामने आई हैं। इसलिए मौजूदा राजनैतिक, सामाजिक परिदृश्य में देश में प्यार, उदारता और कल्याणकारी माहौल बनाने की उम्मीद राजनीति की उस राह पर चलकर ही पूरी हो सकती है, जो गांधीजी की राह है, जो राहुल गांधी की राह है।

चुनाव में जलवायु परिवर्तन

■ **कुलभूषण उपमन्यु**

संयुक्त राष्ट्र संघ' की 'विश्व मौसम विज्ञान संस्था' ने एशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बात सामने आई है कि वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रभाव एशिया में विश्व औसत से ज्यादा पड़ रहा है। इस क्षेत्र के कई देशों में आज तक का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जिसके कारण इस महाद्वीप में 2023 में 90 लाख लोग बाढ़ों और तूफानों से प्रभावित हुए हैं, दो हजार लोग काल का ग्रास बने हैं। जलवायु परिवर्तन ने बाढ़, सूखे और तूफानों की घटनाओं को न केवल बढ़ाया है, बल्कि उनकी भयावहता को भी बढ़ाया है जिसका दुष्प्रभाव वहां के समाजों, अर्थ-व्यवस्थाओं, और मानव जीवन पर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के मुख्य सूचकों, जैसे - जमीनी तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र के जलस्तर के बढ़ने से बिगड़ती हुई स्थिति का पता चल रहा है। 1960-1990 के दौर के मुकाबले तापमान वृद्धि की दर लगभग दुगनी हो गई है। 2023 में जहां एक ओर सूखा पड़ा वहीं दूसरी ओर भयानक बाढ़ें आईं। लू के कारण 100 लोगों की मौत हो गई और सिक्किम का तीस्ता-3 बांध बाढ़ की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया। इस दुर्घटना में 100 लोग अपनी जान गंवा बैठे।

> **इतनी चिंताजनक स्थिति के बाबजूद वर्तमान चुनावों में यह मुद्दा जनता के बीच महत्वपूर्ण नहीं बन सका है। पर्यावरण से जुड़े दिवसों पर चेतना रैली निकालने, कुछ अच्छे-अच्छे नारे लगाने, भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने या ज्यादा-से-ज्यादा चुनावी घोषणा-पत्रों में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े वादे उछालने तक हम सीमित होते जा रहे हैं। राजनैतिक दल भी जन चेतना जगाने के इस मौके का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।**

बढ़ते तापमान के कारण इस तरह की घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। भारत और बांग्लादेश में लू की संभावनाओं में 30 गुणा वृद्धि की आशंका पैदा हो गई है। एशिया के तेज़ गति से बढ़ते तापमान के चलते इसके ग्लेशियर भी खतरे में पड़ गए हैं। मुख्य 22 ग्लेशियरों में से 20 में भारी नकारात्मक बदलाव हुए हैं, यानि ग्लेशियरों के पिघलने की गति तेज़ हुई है। तापमान वृद्धि से समुद्र का जल भी ज्यादा गर्म हो रहा है जिसके कारण भारी बारिश और समुद्री तूफानों का खतरा बढ़ा है। पिछले चार दशकों में अरब सागर में समुद्री तूफानों की संख्या में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है और तूफानों की घातकता भी बढ़ी है।

जुलाई और अगस्त 2023 में हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से हुई तबाही का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है जिसको भारत सरकार ने आपात स्थिति घोषित किया था। इन स्थितियों से निपटने के लिए आपदा प्रबन्धन के विषय में भी काफी कुछ करने की जरूरत पर रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। हालांकि भारत ने इस विषय में कुछ मानकों पर अच्छी प्रगति की है, फिर भी काफी कुछ किये जाने की जरूरत है। पूर्व-चेतावनी व्यवस्था में सुधार करके आपदाओं से होने वाली हानि को 30 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

रिपोर्ट में आर्थिक असमानता के चलते जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के और ज्यादा चिंताजनक होने की बात कही गई है। जाहिर है, बढ़ते तापमान का प्रत्यक्ष डंक उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है या जिन्हें दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है या किसान, जिनकी फसल खुले में ईश्वर भरोसे रहती है। उनके लिए जलवायु-अनुकूलन व्यवस्था खड़ी करना भी संभव नहीं होता। बढ़ते तापमान से फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा पैदा होने की संभावना बढ़ सकती है।

इस दिशा में जलवायु की विपरीत स्थितियों को झेलने में सक्षम फसलों की किस्मों पर ज्यादा शोध और प्रचार-प्रसार की जरूरत है। इस दिशा में पुराने समय में प्रचलित फसलों कोदों, रामदाना, स्वांक, बाजरा आदि का प्रचार-प्रसार करके अच्छी पहल की जा रही है, किन्तु कार्बन उत्सर्जन करने वाली उर्जा उत्पादन तकनीकों और बड़े प्रोजेक्टों, खनन परियोजनाओं के कारण वनों के विनाश से कार्बन प्रदूषण की चुनौतियां यथावत बनी हैं और बढ़ भी रही हैं। पिछले 15 वर्षों में भारतवर्ष में 3 लाख हेक्टेयर वनभूमि का उपयोग इस तरह की बृहदाकार योजनाओं के लिए बदला जा चुका है और यह क्रम सतत जारी है।

इतनी चिंताजनक स्थिति के बाबजूद वर्तमान चुनावों में यह मुद्दा जनता के बीच महत्वपूर्ण नहीं बन सका है। पर्यावरण से जुड़े दिवसों पर चेतना रैली निकालने, कुछ अच्छे-अच्छे नारे लगाने, भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने या ज्यादा-से-ज्यादा चुनावी घोषणा-पत्रों में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े वादे उछालने तक हम सीमित होते जा रहे हैं। राजनैतिक दल भी जन चेतना जगाने के इस मौके का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आम मतदाता निजी आर्थिक लाभ से ज्यादा सोचने को तैयार नहीं है इसलिए राजनैतिक दल भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते हैं।

हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से यह मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है, किन्तु हम प्राकृतिक आपदा का बहाना गढ़कर आत्म-संतुष्टि कर लेते हैं या खुद को धोखा देते रहते हैं, जबकि हम सब समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव निर्मित गलतियों का नतीजा है। फिर भी हम न तो आत्मसंयम से अनावश्यक वस्तुओं, पदार्थों के उपयोग से बचना चाहते हैं न ही सरकारों के सामने अपनी पर्यावरण विषयक चिंताओं को रखकर दबाव बनाकर नीतिगत बदलाव की मांग रखना चाहते हैं। सरकारें विकास को 'सकल घरेलू उत्पाद' से नापकर आगे बढ़ती हैं, उन्हें पर्यावरण जैसे मुद्दे लुभावने नहीं लगते।

दुनिया भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर टालमटोल करते हुए, शर्माते हुए थोड़ा-बहुत कार्य करती रहती हैं। जब आपदाएं आती हैं तब कुछ गंभीरता दिखाई देती है, लेकिन धीरे-धीरे प्रकृति के ऊपर दोषारोपण करके उसे भी भूल जाती है। इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही इस मुद्दे पर कुछ लक्ष्य अपने-अपने चुनावी घोषणा-पत्रों में रखे हैं, किन्तु पिछले अनुभव के आधार पर ज्यादा आशा नहीं जगती है।

शिमला में 2009 में 'जलवायु सम्मेलन' हुआ था जिसमें हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए कुछ लक्ष्य तय किये गए थे, किन्तु दोनों प्रमुख दलों को पर्याप्त समय मिलने के बाबजूद इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो सकी। वैश्विक स्तर और हिमालय के स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौती के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के चलते अब समय आ गया है जबकि इस मुद्दे पर आम जनता और राजनैतिक दलों को चुनावी राजनीति के केंद्र में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लिया जाना चाहिए, ताकि सरकार गठन के बाद इस मुद्दे पर समुचित कार्य किया जा सके और सरकारों की जवाबदेही भी तय हो।

(लेखक हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष हैं।)

पावन प्रसंग

आत्ममूल्यांकन:व्यक्तित्व विकास का साधन

हमारी रुचि और प्रवृत्ति सदा दूसरों के जीवन में ताक-झांक करने की रहती है। हम प्राय: दूसरों का मूल्यांकन किया करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम दूसरों के बराबरी करने लगते हैं- जिससे मानसिक विकार पैदा होते हैं। अच्छा हो कि हम दूसरों की जगह स्वयं का मूल्यांकन करें। स्वयं का मूल्यांकन या आत्मविश्लेषण एक ऐसा दृष्टिकोण होता है, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता के बिना अपने व्यक्तित्व को समझ सकता है।

स्वयं का मूल्यांकन करे बिना हम प्रगति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह एक सच्चाई है कि वास्तविक मूल्यांकन होना ही स्वयं का मूल्यांकन है। क्योंकि व्यक्ति सही मायने में केवल अपने आप को ही जानता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू, व्यवहार, प्रवृत्ति एवं भाव को दूसरे गुणों से ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है।

मानसिक विचारों के बचाव के लिए जरूरी है कि समय-समय पर हम स्वयं का आकलन करते रहें। शरीर से जुड़ी कोई परेशानी होती है तो अकसर हमें उसके बारे में पता चल जाता है। मसलन, बुखार आता है तो बदन तपने लगता है। चोट लगती है तो दर्द होता है, लेकिन मानसिक बीमारियों की गिरफ्त में हम कब फंस जाते हैं, यह हमें पता ही नहीं चलता।

आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन के जरिए मानसिक समस्याओं की पहचान की जा सकती है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या को निशानदेही के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी आदतों पर गहराई से गौर करना। जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व व व्यवहार के बारे में विचार करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचें तो हमें कुछ क्षण रुककर उन्हीं कसौटियों पर खुद के व्यक्तित्व को भी आंकना चाहिए।

मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कई जटिल अंतरवैयक्तिक और सामाजिक प्रक्रियाओं के गत्यात्मक पहलुओं पर निर्भर करता है, लेकिन यदि व्यक्ति चेतना के स्तर पर थोड़ा प्रयास करे तो खुद को मानसिक तौर पर स्वस्थ रख सकता है। खुद को दूसरों की तुलना, जलन, चिढ़न, लालच जैसे भाव लगातार इंसान के चिंतन का हिस्सा बने रहने पर उसकी मनोदशा के महज हिस्से की तरह लगते हैं।

एक तय सीमा तक इन भावों की मौजूदगी नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन जब हम इस तरह के मनोभावों के प्रति बाध्यता महसूस करने लगें व चाहकर भी इस तरह की मनोदशा से बाहर न निकल सकें तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अच्छाई-बुराई में विभेद न कर पाने वाली मानसिक स्थिति हमें मानसिक असंतुलन की ओर ले जाती है- जिसकी परिणति के रूप में मानसिक रोग एवं मनोविकार जैसे अवसाद, उन्माद और उद्दंडता जन्म लेते हैं। आमतौर पर दूसरों के मूल्यांकन एवं विश्लेषण करने वाले लोग नकारात्मक पहलुओं का ही मूल्यांकन करते हैं और असंतुलित मानक तय कर दूसरों को खुद के साथ तुलना करने लगते हैं।

युग निर्माण योजना

आपके पत्र

स्वस्थ भारत की राह में रोड़ा है कुपोषण

देश में जब विकसित भारत की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा था, उस समय यह महसूस किया गया होगा कि स्वस्थ भारत के बिना विकसित भारत का आकार बेमानी है। यही कारण है कि आज विकसित भारत के नारा से पहले स्वस्थ भारत का नारा दिया जाता है। दरअसल यह स्वस्थ भारत का नारा देश के नौनिहालों को केंद्र में रख कर गढ़ा जाता है क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो हम समृद्ध देश की संकल्पना को साकार कर पाने में सक्षम होंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में भारत के बच्चे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे कुपोषण मुक्त और स्वस्थ हैं? हालांकि सरकारों की ओर जारी आंकड़ों में कुपोषण के विरुद्ध जबरदस्त जंग दर्शाया जाता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अभी भी हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं और 5 पांच तक की उम्र के अधिकतर बच्चे कुपोषण मुक्त नहीं हुए हैं।

वर्ष 2022 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें दौर के दूसरे चरण की जारी रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण की तुलना में मामूली सुधार हुआ है लेकिन अभी भी इस विषय पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। भारत में अभी भी प्रतिवर्ष केवल कुपोषण से ही लाखों बच्चों की मौत हो जाती है। करीब 32 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषण के कारण अल्प वज़न के शिकार हैं। जबकि 35 ।5 प्रतिशत बच्चे कुपोषण की वजह से अपनी आयु से छोटे कद के प्रतीत होते हैं। वहीं करीब तीन प्रतिशत बच्चे अति कम वज़न के शिकार हैं। दरअसल बच्चों में कुपोषण की यह स्थिति मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिलाएं एनीमिया की शिकार पाई गई है। जिसका असर उनके होने वाले बच्चे की सेहत पर नज़र आता है।

वास्तव में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की यह स्थिति भयावह है जिसे दूर करने के लिए एक ऐसी योजना चलाने की ज़रूरत है जिससे गर्भवती महिलाएं और बच्चों को सीधा लाभ पहुंचे। इस कड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्त्ता और सहायिका सराहनीय भूमिका अवश्य निभा रही हैं। लेकिन इस बात पर भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भूख और कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए 1975 में शुरू किया गया आंगनबाड़ी अपनी स्थापना के लगभग पांच दशक बाद भी अब तक शत प्रतिशत अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर सका है?

घर की आमदनी कम होने के कारण महिलाओं को गर्भावस्था में संपूर्ण पोषण उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिसका असर जन्म के बाद बच्चों में भी नज़र आता है। वह स्वयं एनीमिया की शिकार हैं। वहीं 35 वर्षीय अनिल गमेती बताते हैं कि वह गांव के बाहर चूना भट्टा पर दैनिक मज़दूर के रूप में काम करते हैं। जहां उनके साथ उनकी पत्नी भी काम करती है। लेकिन गर्भावस्था के कारण अब वह काम पर नहीं जाती है क्योंकि उसे हर समय चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने शरीर में पोषण और खून की कमी बताया है। अनिल कहते हैं कि पहले मैं और मेरी पत्नी मिलकर काम करते थे तो घर की आमदनी अच्छी चलती थी। लेकिन गर्भ और शारीरिक कमज़ोरी के कारण अब वह काम पर नहीं जा पा रही है। ऐसे में घर की आमदनी भी कम हो गई है। अब उन्हें चिंता है कि वह पत्नी को कैसे पौष्टिक भोजन कैसे खिला सकते हैं?

प्रिया कुमारी, अजमेर राजस्थान

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव,
(पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

संपादकीय

उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। -सुभाष चंद्र बोस

भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने से चारधाम यात्रा के दौरान कुछ लोगों के मरने की खबर निश्चित रूप से दुखद है। प्रशासन को जहां भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सक्रियता दिखानी होगी, वहीं श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि नवंबर तक चलने वाली यात्रा के लिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।

थोड़ा धीरज रखिए

अक्षय तृतीया के दिन दस मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से शुरू हुई और बारह मई को बदरीधाम के कपाट खुलने के बाद पूरी तरह संचालित हो रही चारधाम यात्रा पर भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने से सरकारी व्यवस्थाएं तो ध्वस्त हुई ही हैं, यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि यात्रा के पहले तीन दिन में ही पिछले वर्ष की तुलना में 61 फीसदी (केदारनाथ में 67 फीसदी) ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके थे। आलम यह है कि पहले पांच दिनों में ढाई लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, जबकि 27 लाख से ज्यादा अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। जबकि पिछले साल पहले पांच दिनों में महज 52 हजार लोग ही पहुंचे थे। पारिस्थितिक रूप से अस्थिर उच्च हिमालयी क्षेत्र में एकाएक इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने से हालत यह हो गई है कि हरिद्वार से आगे बढ़ते ही कई किलोमीटर लंबे जाम में लोग बीस से पच्चीस घंटों तक फंसे रहे और अब तक दस लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। परेशान हाल लोग प्रशासन की बदइंतजामी को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। मगर नहीं भूलना चाहिए कि सरकार के जो भी इंतजाम थे, वे 2023 में यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखकर किए गए थे। कई लोग तो बगैर रजिस्ट्रेशन भी पहुंच रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस वर्ष करीब 80 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या स्थानीय बुनियादी ढांचा इसको संभालने के लिए तैयार है। 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चारधाम राजमार्ग विकास योजना, जिसे चारधाम ऑल वेदर सड़क परियोजना भी कहा जाता है, की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना। सिर्फ चारधाम ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण इस परियोजना में पिछले वर्ष उत्तरकाशी के सुरंग हादसे से भले कुछ देरी हुई, लेकिन अब यह पूरा होने के कगार पर है। इसके अतिरिक्त

चारों धामों को जोड़ने वाली रेलवे की चारधाम परियोजना के भी अगले वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है। लिहाजा आने वाले वर्षों में इस यात्रा में निश्चित ही दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन फिलहाल चारधाम यात्रा के जो निराशाजनक दृश्य दिख रहे हैं, उनसे निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को तो अतिरिक्त सक्रियता दिखानी ही होगी, लोगों को भी समझना होगा कि यात्रा नवंबर तक चलेगी, ऐसे में, किसी तरह की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।

जैव विविधता का मूल्य समझें

हाल ही में जैव विविधता दिवस चुपचाप बीत गया, लेकिन उसके मूल्य को तभी समझा जा सकता है, जब हम ऐसे परिदृश्य पर विचार करें, जहां जीवन केवल एक ही प्रजाति के रूप में हो। ऐसा जीवन अनिश्चित-सा होगा और ऐसे में पृथ्वी कभी भी दुर्भिक्ष या किसी महामारी के कारण जीवन-विहीन हो सकती है।

वीर सिंह

जैव विविधता के गॉडफादर के रूप में लोकप्रिय अमेरिकी पारिस्थितिकी विज्ञानी थॉमस ई. लवजॉय की एक मार्मिक टिप्पणी है, 'जैविक विकास की अंतिम विडंबना यह हो सकती है कि मनुष्य के मस्तिष्क के माध्यम से आत्म-समझ प्राप्त करने के तुरंत बाद जीवन ने अपनी सबसे सुंदर रचनाओं को नष्ट कर दिया होगा।' जीवन की विविधता के मूल में एक मूलभूत सत्य निहित है : जगत में सबकुछ अंतर्संबंधों से बंधा है। जैव विविधता जीवन के स्थायित्व और चिरंजीविता के केंद्र में है, किंतु जैव विविधता के योग से भी परे अस्तित्व से आलोक से सराबोर जीवन स्वयं में नैसर्गिक विकास (इवोल्यूशन) की एक मनोरम गाथा का प्रतीक है। जैव विविधता ही जीवन की नैया की खेवनहार है। जितनी अधिक जैव विविधता, उतना ही अधिक जीवन का उत्कर्ष, उतना ही प्रबल जीवनगामी पृथ्वी का ब्रह्मांड में साम्राज्य!

जैव विविधता जीवन की शाश्वतता की अनंत कथा है। जैव विविधता प्रकाश की जीवंत कहानी है, जिसे सूर्य का प्रकाश प्रकाश-संश्लेषण के माध्यम से जीवन ऊर्जा के अनंत रूपों में खिलकर आकाशगंगाओं को सुनाता है। प्रकाश की सृजनात्मक क्षमता असीमित है। पेड़-पौधों के पर्णहरित से अठखेलियां कर प्राकृतिक विकास के नवाचारों के झरोखे खोलता प्रकाश अनंत जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों को निरंतर पोषित करता है। जीवन कथा को अमर बनाए रखने के लिए समय की धारा के साथ नई प्रजातियां और उनके आनुवंशिक रूप जीवन को समृद्धि और आनंद का उपहार देते रहते हैं।

एक बहती नदी के समान ऊर्जा जीवन के विभिन्न माध्यमों से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। पदार्थ निष्क्रिय होता है, ऊर्जा क्रियाशील। पदार्थ की क्रियाशीलता ऊर्जा के कारण ही होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिशीलता का स्रोत ऊर्जा ही है। मुक्तावस्था में ऊर्जा विध्वंसक रूप ले सकती है, जिसे एन्ट्रॉपी कहते हैं। असंख्य जीव-वाहिकाओं में प्रकाश

संश्लेषण के माध्यम से प्रवेश कर सौर ऊर्जा एक रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करती है। सभी जीवधारियों का व्यवहार और उनके कार्य-कलाप उसी ऊर्जा की रचनात्मक अभिव्यक्तियां हैं। मुक्तावस्था में यही ऊर्जा अराजक हो सकती थी। ऊर्जा जीवन की जितनी विविधता में क्रियाशील होगी, उतनी ही सृजनशीलता और संतुलन की अवस्था में होगी।

इसी प्रकार, पृथ्वी की भी ब्रह्मांड के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रह्मांड की एन्ट्रॉपी को नियंत्रित कर एक ब्रह्मांडीय संतुलन स्थापित करना ही जैव विविधता-भरी पृथ्वी का अनुष्ठान है। पृथ्वी पर जीवन केवल पृथ्वी का ही नहीं, ब्रह्मांड का एक उपादान है। पृथ्वी का उदय ब्रह्मांड के विकास की अनवरत यात्रा का एक लक्ष्य रहा होगा। ब्रह्मांड में 'बिग बैंग' की घटना से कालांतर में पृथ्वी-रूपी अमृत निकला, जैव विविधता जिसकी बूंदें हैं!

ऐसे परिदृश्य पर विचार करें, जहां जीवन केवल एक ही प्रजाति के रूप में हो। ऐसा जीवन निरा अनिश्चित-सा होगा और ऐसी दशा में पृथ्वी कभी भी दुर्भिक्ष या किसी महामारी के कारण जीवन-विहीन हो सकती है। जीवों की घनी विविधता ने ऐसी संभावनाओं को क्षीण कर दिया। जीवन की स्थिरता, गतिशीलता और निरंतरता उसकी विविधता पर निर्भर है। जैव विविधता जीवन को जलवायु संबंधी अनियमितताओं के प्रति लचीला बनाती है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम जीव समुदायों को पोषित करती है। विविधता स्वयं जीव समुदाय के लिए अस्तित्व का कारक है। जैव विविधता का समृद्ध भंडार जैव-रासायनिक चक्रों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है और जैवमंडल के जीवन-निर्वाह को संरक्षित करती है।

जैव विविधता हमारे जिंदा ग्रह को जीवन-शक्ति प्रदान करती है। इस अद्भुत विविधता के जागरूक प्रबंधक के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन के बहुरूप दर्शन को संरक्षित करना हमारा परम दायित्व है। पारिस्थितिक दार्शनिक हेनरिक स्कोलिमोस्की ने अस्तित्व संरक्षण के लिए जैव विविधता के आंतरिक मोल पर जोर देते हुए मानवता और प्रकृति के बीच गहन अंतर्संबंध को गहराई से स्पष्ट किया है। जीवों के पारस्परिक तालमेल और मानव सहित संपूर्ण जीवन के अस्तित्व के लिए जैव विविधता जीवन के मूल सार का प्रतीक है।

जैव विविधता जीवन की रचनात्मकता की असंख्य अभिव्यक्तियों को दर्शाती है, जिसमें प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्र और आनुवंशिक विविधता का समृद्ध स्पेक्ट्रम सम्मिलित है और जो हमारे ग्रह पर स्वयं हमारी प्रजाति के अस्तित्व के पहले से निवास करते हैं। स्कोलिमोस्की की पारिस्थितिक दर्शन की अंतर्दृष्टि हमें जैव विविधता को केवल दोहन किए जाने वाले संसाधन के रूप में नहीं, वरन एक पवित्र विरासत के रूप में समझने के लिए प्रेरित करती है। सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय रेडवुड तक, प्रत्येक जीव पारिस्थितिक संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जीवन की जटिल प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं। स्कोलिमोस्की की दृष्टि में, जैव विविधता जीवित पृथ्वी की परम आत्मा का प्रतीक है, जिसके बल पर हमारा जैव मंडल जीवन-शक्ति और संतुलन के साथ स्पंदित होता है।

अभूतपूर्व पर्यावरण चुनौतियों के युग में जैव विविधता जीवन के अस्तित्व की कुंजी है। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है और पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है, पारिस्थितिक दर्शन से मिला ज्ञान हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्तों को फिर से जागृत करने और पारिस्थितिक प्रबंधन के प्रतिमान को अपनाने का आग्रह करता है। जैव विविधता से भावी पीढ़ियों के लिए सुख, समृद्धि और संतोष की विरासत सुनिश्चित होती है।

हेनरिक स्कोलिमोस्की का पारिस्थितिक-दर्शन अस्तित्व के ब्रह्मांडीय स्पंदन के भीतर जैव विविधता के मोल का गहरा प्रमाण प्रस्तुत करता है। जैव विविधता को एक पवित्र विरासत के रूप में अपनाकर हम अपने ग्रह पर संपूर्ण जीवन के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक रास्ता बना सकते हैं।

-प्रो. एमेरिटस, पर्यावरण विज्ञान, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

जीवन धारा

एपीजे अब्दुल कलाम

रचनात्मक व्यक्ति कुछ न कुछ करने की इच्छाशक्ति से प्रेरित होता है। आप जो भी करते हैं, वह आपके कौशल और ताकत का हिस्सा बन जाता है, जो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

बिना इच्छाशक्ति के जीवन कैसे बढ़ेगा

सभी मनुष्यों के भीतर तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली हमारी प्रेरणाएं, दूसरी प्रवृत्तियां और तीसरी इच्छाशक्ति। ये तीनों शक्तियां मिलकर जीवन को आगे ले जाने का काम करती हैं। इनमें भी इच्छाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यह तस्वीर कुल मिलाकर वैसी ही बनती है, जैसे एक धनुर्धर के कंधे पर लटका तरकश का तीर, जो हमारे भीतर की प्रेरणा और आवेग का प्रतिनिधित्व करता है। तीरंदाज ने अभी-अभी अपने धनुष से जो तीर छोड़ा, वह उसकी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और तीर छोड़े जाने वाला वह क्षण विशेष उस तीरंदाज की इच्छाशक्ति के साथ कुछ करने की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। हो सकता है कि वह तीर न चलाने का फैसला भी कर लेता। इस प्रकार प्रकृति वह चीज है, जिसे न तो बदला जा सकता है और न उसके प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इच्छाशक्ति अनुसार कुछ करने की आजादी हमेशा रहती है। अगर प्रेरणा और नजरिया पहले से मौजूद है, तो हम इच्छाशक्ति से क्या नहीं कर सकते! व्यक्ति की स्थिति के ये दो पहलू- प्रवृत्ति और इच्छाशक्ति, कैंची के दो हिस्सों की तरह होते हैं। एक हिस्सा इच्छाशक्ति से कार्य करने की स्वतंत्रता है, तो दूसरा हिस्सा प्रेरणा और सहजवृत्ति को बताता है। जब दोनों हिस्से साथ चलते हैं, तो कैंची अपना काम करती है। आप कैंची के सिर्फ एक हिस्से से कपड़ा नहीं काट सकते। इसी प्रकार, किसी कार्य के लिए प्रेरणा, वृत्ति और इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता जरूरी हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। प्रत्येक विचार, भावना, इच्छा और कर्म एक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो अच्छा और बुरा, दोनों ही प्रभाव हम पर डालती है। इसलिए हम अपनी परिस्थितियों, आंतरिक प्रेरणाओं और प्रवृत्तियों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया कैसे करें, कैसे इनमें सामंजस्य बिठाएं, यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। रचनात्मक व्यक्ति कुछ न कुछ करने की इच्छाशक्ति से प्रेरित होता है। आप जो भी करते हैं, वह आपके कौशल और ताकत का हिस्सा बन जाता है, जो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

इन सब के साथ एक और जो बात आती है, वह है हमसे होने वाली गलतियां। मैं आपसे कहता हूं कि गलतियां होना कोई बुरी बात या अपराध नहीं है। गलतियों से ही हम सीखते हैं, गिरकर उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप कई सफल लोगों को यह खुलासा करते देखेंगे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी एक गलती बड़ा कारण रही। अगर वह गलती नहीं होती, तो शायद कामयाबी हासिल नहीं होती। लोग यह सोचकर गलती करने से डरते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सही मायने में देखें, तो गलतियां हमारी यात्रा का हिस्सा हैं। ये हमारी जीवनयात्रा को सुधारने और आगे ले जाने का एक जरिया भी बनती हैं। गलतियां ही हमें बताती हैं कि हमारे भीतर ज्ञान की कमी कहां है। अगर हम ज्ञान बढाएं, मानवता के रास्ते पर चलें, जीवन और व्यवहार में लचीलापन रखें और समझदारी का परिचय दें, तो फिर गलतियों के लिए जगह ही कहां रह जाएगी!

गलतियों से ही सीख मिलती है

सूत्र

यदि हम गलतियां करना बंद कर देंगे तो हम सीखना बंद कर देंगे। गलतियों के बारे में खूबसूरत बात यह है कि हम उन्हें हमेशा सुधार सकते हैं। गलतियां हमें एक सीमित दायरे से बाहर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आपने जो गलती की, वह आपका निर्णायक कारक नहीं है, बल्कि आप उससे कैसे सीखते हैं और कैसे उबरते हैं, यह आपको परिभाषित करता है।

स्मृति

नोबेलजयी कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का 13 मई को निधन हो गया। प्रस्तुत है, उनकी स्मृति के अंश...

हम गरीब थे, लेकिन हमारे आसपास हमेशा किताबें थीं

मुझे इस विश्वास के साथ बड़ा किया गया कि सबसे बुरी चीज 'अपने ऊपर ध्यान देना' है या 'खुद को स्मार्ट समझना' है। यह नियम हमारे जैसे देहाती लोगों के लिए था, शहरी लोगों के लिए नहीं। मैंने हमेशा एक स्वीकार्य और निजी जीवन जीने की कोशिश की और ज्यादातर मैं ऐसा करने में सफल रही।

मेरी मां इसका अपवाद थीं, हालांकि शुरू में ही वह पार्किंसंस रोग का शिकार हो गई थीं। मेरी मां अब भी मेरे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनका जीवन बहुत दुखद और अन्यायपूर्ण था। वह बहुत बहादुर थीं। उन्होंने सात साल की उम्र से ही मुझे स्कूल में रविवार को काव्य पाठ करने लायक बनाने के लिए संघर्ष किया। मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती थी, जो कॉलेज जाती हो। कॉलेज जाने वाले लड़के भी बहुत कम थे। मुझे केवल दो वर्षों के लिए छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन तब मैं एक लड़के से प्रेम करने लगी थी, जो मुझसे शादी करना चाहता था और मुझे वेस्ट कोस्ट ले जाना चाहता था। अब मैं हर समय लिख सकती थी। लिखने का इरादा मेरा तभी से था, जब मैं घर पर रहती थी। हम लोग गरीब थे, पर हमारे आसपास हमेशा किताबें रहती थीं। ऐसा नहीं था कि घर के काम या बच्चों के कारण मैं लिख नहीं पाती थी। मैंने जीवन भर घर का काम किया है। हमारे समाज में एक नियम था कि जो महिलाएं लिखने जैसा कुछ अजीब काम करना चाहती थीं, उन्हें गलत माना जाता था और उनकी उपेक्षा की जाती थी। हालांकि मैंने ऐसा किया और ऐसी कई महिलाएं मेरी दोस्त बनीं, जो मजाक करती थीं और छिप-छिपकर पढ़ती थीं। हमने बहुत अच्छा समय बिताया। वास्तव में समस्या मेरे लेखन में ही थी, जो अक्सर अच्छा नहीं होता था। मैं सीखने के दौर से गुजर रही थी। सौभाग्य से उसी समय इस बात का बड़ा शोर मचा कि हमारा कनाडाई साहित्य कहां है। टोरंटो में कुछ लोगों का ध्यान मेरे असहज लेखन पर गया। उन्होंने मेरी मदद की। मैंने अपने लेखन में हमेशा अपने जीवन के कुछ अंशों का उपयोग किया है। कहना चाहिए कि *द व्यू फ्रॉम कैसल रॉक* मेरे अपने परिवार की ही कहानी है। लेखन की शुरुआत में मैंने उन चीजों के बारे में लिखा, जो मुझे हैरान करती थीं-मृत्यु, प्रेम, हर तरह की चिंताएं, जो हमें जीवन भर भ्रमित करती हैं। जीवन के बारे में लिखने से मेरे लिए जीना सहज हो गया। हालांकि मैं अब भी हैरान हूं, मुझे एहसास है कि जो प्रश्न हम पूछते हैं, वे हमारे द्वारा दिए गए उत्तरों की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प हैं। मुझे यकीन है कि मेरी कहानियों में सामाजिक और राजनीतिक सामग्री है, कम से कम उन शब्दों के व्यापक अर्थ में। जाहिर है कि प्रत्येक मानवीय क्रिया का कोई न कोई राजनीतिक आवेग और सामाजिक परिणाम होता है। लेकिन मैं अपने काम में इन उद्देश्यों की व्याख्या पाठकों या आलोचकों पर छोड़ना चाहूंगी। मुझे अपने साहित्य में किसी संदेश का पैबंद लगाना पसंद नहीं है।

एलिस मुनरो
(10.07.1931-13.05.2024)

शुरू में मैंने उन चीजों के बारे में लिखा, जो हैरान करती थीं-मृत्यु, प्रेम, चिंताएं, जो जीवन भर भ्रमित करती हैं। जीवन के बारे में लिखने से मेरे लिए जीना सहज हो गया।

आंकड़े

विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई

अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के बीच विनिर्माण उद्योग में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आया है।

ऑटोमोबाइल	25%
ड्रग्स एवं फार्मा	12%
गैर-पारंपरिक ऊर्जा	12%
धातुकर्म	9%
रसायन	9%

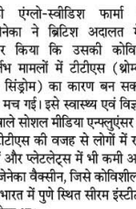

नोट-रसायन में उर्वरक शामिल नहीं है। स्रोत : DPIIT

अंतर्यात्रा

सच को लाख छिपाओ, वह छिप नहीं सकता है। एक न एक दिन सामने आ ही जाता है।

सामने आई सच्चाई

एक राजकुमारी को संगीत की शिक्षा देनी थी। वीणा-वादन और संगीत के लिए दूसरे राज्य के राजकुमार उदयन उपयुक्त थे। राजा ने कूटनीति से उन्हें बुलवा लिया। पर राजा दोनों को एक-दूसरे से संपर्क नहीं करने देना चाहता था। इसलिए दोनों के बीच में पर्दा लगा दिया। उदयन से कहा गया कि राजकुमारी दृष्टिबाधित है और राजकुमारी को बताया गया कि उदयन कुष्ठ रोग से पीड़ित है।

शिक्षा शुरू हुई और कई दिनों तक यह क्रम चला। एक दिन उदयन संगीत का अभ्यास करा रहा था। राजकुमारी बार-बार गलतियां कर रही थी। उदयन ने कई बार टोका, फिर भी राजकुमारी उसके स्वरों को पकड़ नहीं सकी। उदयन ने नाराज होकर कहा, कितनी बार बता दिया, फिर भी ध्यान नहीं देती हो। आखिर दृष्टिबाधित जो हो। राजकुमारी ने भी आवेश में कहा-जरा संभलकर बोलो, तुम्हारी तरह कुष्ठ रोगी नहीं हूं। उदयन ने सोचा, मैं कुष्ठ रोगी तो नहीं हूं, फिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों कहा? राजकुमारी ने भी इसी तरह सोचा कि मैं दृष्टिबाधित नहीं हूं, फिर उदयन ने क्यों कहा? सच्चाई जानने के लिए दोनों ने पर्दा उठाया, तो पाया कि दोनों में कोई दोष नहीं है। आवरण हटते ही दोनों के सामने सच्चाई आ गई। इसलिए कहा जाता है कि सच को लाख छिपाओ, वह छिप नहीं सकता है। एक न एक दिन सामने आ ही जाता है।

संकलित

आज का इतिहास

2013 में इंसानी भ्रूण से स्टेम सेल निकालने में सफल

इतिहास में 16 मई का दिन एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ दर्ज है। दरअसल 2013 में 16 मई के दिन अमेरिकी वैज्ञानिकों को इंसानी भ्रूण के क्लोन से पहली बार स्टेम सेल निकालने में सफलता मिली थी। मेडिकल की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ी सफलता माना गया, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सी लाइलाज बीमारियों जैसे पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रीढ में चोट और आंखों की रोशनी के इलाज की दिशा में लाभ होने की उम्मीद जगी। 1911 में कलकत्ता (अब कोलकाता) में बने तल्लाह वाटर टैंक का निर्माण पूरा। इसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहैड वाटर टैंक कहा गया था। 1920 में फ्रांसीसी स्वतंत्रता सेनानी, सेनापति जॉन ऑफ आर्क को संत की उपाधि दी गयी। 1974 में इज.राइल के लड़ाकू विमानों ने सात फलस्तीनी शरणार्थी शिविरों और दक्षिणी लेबनान के गांवों पर बम दागे। इन हमलों में 27 लोग मारे गए और 138 अन्य घायल हुए।

जोखिम तो हर टीके में होते हैं

टीकों के बारे में ईमानदार संवाद के साथ जनता को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था उन्हें निराश नहीं करेगी।

पत्रलेखा चटर्जी | स्वास्थ्य

जैसे ही एंग्लो-स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश अदालत में यह स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कुछ दुर्लभ मामलों में टीटीएस (थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम) का कारण बन सकती है, भारत में खलबली मच गई। इसे स्वास्थ्य एवं विज्ञान की कम समझ रखने वाले सोशल मीडिया एन्फ्लुएंसर ने और तेजी से बढ़ाया। टीटीएस की वजह से लोगों में रक्त के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स में भी कमी आती है। ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे कोविशील्ड नाम दिया गया था, को भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया और बेचा था।

चूंकि देश में इन दिनों चुनावी मौसम है, इसलिए अचानक ही यह मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच

राजनीतिक खेल का हिस्सा बन गया। एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से अपने कोविड-19 टीके को वापस मंगवाने की पहल की। लेकिन यह मुद्दा खबरों में बना हुआ है। थाईलैंड के अनुसार देश भर में दी गई 4.87 करोड़ खुराक में से केवल सात मामलों में टीटीएस के संदिग्ध मामले पाए गए, जो खतरे की दर को कम दर्शाता है।

भारत में इसके प्रति घबराहट का एक मुख्य कारण घरेलू राजनीति है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया, जो मुख्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा। अब सत्ताधारी पार्टी को घेरने वाले सोशल मीडिया एन्फ्लुएंसर और विपक्षी नेता एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विवाद में कूदकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। अब तक हम जानते हैं कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के दुष्प्रभाव बहुत ही दुर्लभ हैं। 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी इसका समर्थन किया। अप्रैल 2021 में डब्ल्यूएचओ ने कहा था, 'नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वैक्सजेवरिया और कोविशील्ड टीकों के साथ टीटीएस का जोखिम नगण्य जान पड़ता है। ब्रिटेन के आंकड़ों से पता चलता है कि टीका लगवाने वाले दस लाख वयस्कों में से चार मामलों में टीटीएस का जोखिम था। यानी ढाई लाख पर एक मामला, जबकि यूरोपीय संघ में यह दर अनुमानित रूप से एक लाख पर एक मामला है। कोविड-19 टीकाकरण के बाद टीटीएस जोखिम को लेकर देशों को इसके हानि-लाभ का विश्लेषण करना चाहिए, जो स्थानीय महामारी विज्ञान, टीकाकरण के लिए लक्षित आयु वर्ग और वैकल्पिक टीकों की उपलब्धता पर विचार करता हो। इन दुर्लभ दुष्प्रभावों के जोखिम में भौगोलिक आधार पर भिन्नता हो सकती है। इसलिए सभी देशों में टीटीएस के संभावित मामलों का आकलन महत्वपूर्ण है।' साक्ष्यों से पता चलता है कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने के कुछ दिनों या हफ्तों बाद टीटीएस के लक्षण सामने आते हैं, न कि वर्षों बाद। यदि वैज्ञानिक समुदाय को कोविशील्ड वैक्सीन के संभावित दुर्लभ दुष्प्रभावों के बारे में पता था, तो फिर लोगों में इतनी दहशत क्यों है? इसका मुख्य कारण है कि टीका संबंधी प्रभावी संदेश के प्रसार के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। प्रत्येक टीके के कुछ जोखिम होते हैं, लंबे समय से प्रचलित टीके के भी। लेकिन गंभीर दुष्प्रभाव दुर्लभ हैं। इसके अलावा दुष्प्रभावों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने का तंत्र भी पारदर्शी नहीं था और टीकाकरण के बाद के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना प्राथमिकता में नहीं था। इससे गलतफहमी पैदा हुई। हम चिंताओं को नकार नहीं सकते। कोविशील्ड समेत हरेक टीके के दुष्प्रभाव होते हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लोगों का विश्वास कायम करना जरूरी है, जो टीकाकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य का आधार है। भारत में कोई संगठित टीका विरोधी आंदोलन नहीं है, फिर भी भारत को पोलियो मुक्त होने में कई दशक लगे। मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में छोटे बच्चों में टीका लगवाने को लेकर आपत्ति थी। उनके भय को दूर करने के लिए काफी प्रयास करने पड़े थे।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 90 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

चुनाव विमर्श

अत्यधिक गिरावट

चुनाव में प्रतिद्वंद्वी विरले ही एक-दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वर्तमान चुनाव विमर्श में अत्यधिक गिरावट आ गई है। यदि वर्तमान आईपीएल व लोकसभा चुनाव में ज्यादा मनोरंजक विकल्प चुनना हो तो संभवत: लोकसभा चुनाव को पहला स्थान मिलेगा। चुनाव जीतने के लिए नए-नए व्यंग्य तलाशने, ओछी टिप्पणियां करने, परिवारी सदस्यों पर भद्दे आरोप लगाने, अप्रिय अभियान चलाने तथा कीचड़ उछालने जैसे काम जारी हैं। सामान्य चुनाव की तुलना में इस चुनाव के ज्यादा आक्रामक व क्रूर होने के करण सोशल मीडिया राजनेताओं के ऐसे वीडियो से भरा है जो गली के गुंडों को भी शर्मिन्दा कर देंगे। उदाहरणार्थ, भाजपा की मंडी से उम्मीदवार कंगना रनौत को अनेक गालियां सुननी पड़ीं जिनमें से अनेक इतनी भद्दी हैं कि उनका उल्लेख तक नहीं किया जा सकता है। चिन्ताजनक बात है कि पार्टियों के 'स्टार प्रचारकों' ने भी सभ्यता को हवा में उड़ा दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा विपक्षी दलों के नेताओं, खासकर कांग्रेसी नेताओं के बीच बहुत तीखी बहस हुई है। मोदी ने विपक्षी नेताओं पर 'कायर और पाकिस्तान से भयभीत' होने के आरोप लगाए हैं, जबकि कांग्रेस ने उनको 'कार्पोरेट का मुहरा' कहा है। कांग्रेस ने दुष्टतापूर्वक यह आरोप भी लगाया है कि यदि वे इस बार भी जीत गए तो भारत में फिर कोई चुनाव नहीं होंगे। इस प्रकार के वार्तालाप से न केवल गहन राजनीतिक ध्रुवीकरण रेखांकित होता है, बल्कि इससे चुनाव प्रचार के गिरते मानक भी स्पष्ट होते हैं। मोदी द्वारा लगाए आरोप भाजपा द्वारा तैयार विमर्श के अनुरूप हैं जिसके चलते वह स्वयं को राष्ट्रीय सुरक्षा की संरक्षक मानती है। ऐसी टिप्पणियां भले ही मतदाताओं के एक वर्ग को आकर्षित करें, पर वे राजनीति में जहरीला ध्रुवीकरण पैदा करती हैं। विपक्ष पर पाकिस्तान के प्रति नरमी का आरोप लगा कर मोदी अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपमानित कर भावनात्मक रूप से अपना समर्थन बढ़ाना चाहते हैं।

दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा सरकार की नीतियों को 'बड़े बिजनेस घरानों' के पक्ष में बताने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार विपक्ष की रणनीति स्वयं को आम आदमी के हितों के पैरोकार की तरह पेश कर मोदी को कार्पोरेट हितों का प्रतिनिधि बताने की है। लेकिन बिना समुचित प्रमाण के ऐसे आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास घटाते तथा मतदाताओं का और ध्रुवीकरण करते हैं। यह तथ्य भी है कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बार-बार बिना किसी आधार के तानाशाह होने का आरोप लगाता रहता है। इन आरोपों को प्रचारित करने के तरीके खासकर चिन्ताजनक हैं। चुनाव प्रचार में व्यक्तिगत हमले, चरित्र हनन तथा भड़काऊ बयानबाजी आम हो गए हैं। नीतिगत मुद्दों और प्रशासन पर विमर्श करने के बजाय पार्टियां भावनायें और घृणा भड़काने में लग गई हैं। चुनाव प्रचार के गिरते मानक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले गहरे ढांचागत मुद्दों का संकेत देते हैं। धन बल के प्रभाव, फर्जी खबरों और दुष्प्रचार के बढ़ने तथा संस्थागत नियंत्रण व संतुलन प्रक्रिया में कमी से ऐसा माहौल बना है जो नकारात्मक अभियान तथा ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहा है। सोशल मीडिया के विस्तार के कारण विभाजनकारी लफ्फाजी का प्रभाव और विस्तार कई गुना बढ़ा है। दुर्भाग्य से निर्वाचन आयोग इन 'बड़बोले नेताओं' पर लगाम लगाने में विफल रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम सबकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि नेता 'लक्ष्मण रेखा' न पार करें। मतदान के दिन हम सब ईवीएम का बटन दबा कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं।

चुनाव में अनुमानों का दौर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी बार विजय के अनुमानों के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक मतभेदों, पालाबदल व मतदाताओं की तुलनात्मक निष्क्रियता से अनिश्चितता का आयाम बढ़ा है।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारत में चल रहे वर्तमान लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी बार विजय के अनुमानों के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक मतभेदों, पालाबदल व मतदाताओं की तुलनात्मक निष्क्रियता से अनिश्चितता का आयाम बढ़ा है। अनेक अन्य देशों की तरह भारत में भी राजनीतिक पार्टियां अक्सर आधिकारिक चुनाव परिणाम आने के पहले से ही अपनी विजय का दावा करने लगती हैं। वास्तव में स्वयं को विजेता के रूप में प्रदर्शित करना उनकी राजनीति का अंग है। वर्तमान लोकसभा चुनाव भी उनके लिए एक अन्य राजनीतिक घटना की तरह हैं। हालांकि, राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव को बहुत महत्व दे रही हैं क्योंकि इसमें अनेक पार्टियों के साथ ही उनके अनेक राजनेताओं का भविष्य भी दांव पर लगा है। इस प्रकार वर्तमान लोकसभा के चुनाव परिणाम उन पर गहरा और व्यापक असर डालेंगे। देश के वर्तमान राजनीतिक और चुनावी परिदृश्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी-भाजपा ने अपनी विजय की घोषणा करते हुए कहा है कि चुनाव परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुरूप होंगे।

विपक्षी दलों का अनुमान इसके विपरीत है। उनका कहना है कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि, राजनीतिक दलों के परस्पर विरोधी दावों के बीच वास्तविक परिणाम अनिश्चित हैं। इससे राजनीतिक परिदृश्य में 'सस्पेंस' या कौतूहल का आयाम जुड़ गया है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में मतदान सात चरणों में होगा जिसमें से चार चरण पूरे हो गए हैं। मतदान के बाकी तीन चरण 20 व 25 मई तथा 1 जून को पूरे हो जाएंगे। मतदान के इन चरणों का 4 जून को घोषित होने वाले चुनाव परिणामों पर व्यापक असर पड़ेगा।

हालिया जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इन चुनावों में अभूतपूर्व व असाधारण ढंग से तीसरी बार विजय की आशा है। जनमत सर्वेक्षणों के बाद बहस अब केवल इस बात पर हो रही है कि भाजपा अपने संसद सदस्यों की संख्या बढ़ाने में सफल होगी अथवा उसमें थोड़ी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत अनेक भाजपा नेताओं का दावा है कि भाजपा-नीत राजग को इस चुनाव में लोकसभा की 543 सीटों में से 400 से अधिक पर सफलता प्राप्त होगी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि राजग ने पहले तीन मतदान चरणों की 283 सीटों में से 200 पर विजय प्राप्त कर ली है। भाजपा के इन अनुमानों को इस परिदृश्य में देखा जाना चाहिए कि अतीत में केवल 1984 में एक बार कांग्रेस पार्टी को 400 सीटें पाने में सफलता मिली थी। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार समर्थन की कोई स्पष्ट लहर न दिखने के कारण राजनेताओं को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा ने लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्यत: पांच रणनीतियों पर काम किया है। उसने चुनाव मैदान में सेलेब्रिटी उम्मीदवार उतारे हैं ताकि जनता में उनके आकर्षण का लाभ उठाया जा सके। इसके साथ ही उसने अपना हिंदू जनाधार मजबूत किया है, अल्पसंख्यक समुदायों से संपर्क मजबूत किए हैं तथा ऐसे क्षेत्रों में हिंदू मतदाताओं को अपने साथ लाने की खास रणनीतियां बनाई हैं जो विपक्ष शासित या उनके प्रभाव वाले राज्यों में रहते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से भाजपा ने 'मोदी करिश्मे' का प्रयोग करने का प्रयास किया है। भाजपा ने पिछले दस साल में सचेतन व सुनियोजित ढंग से मोदी की ऐसी 'छवि' बनाई है जो विपक्षी नेताओं पर भारी पड़े। इसके जवाब में कांग्रेस तथा उसकी सहयोगी पार्टियों ने अपने रणनीतिक कदम के रूप में हिंदू समाज की गरीब और हाशियाकृत जातियों को साथ लाने और उनमें अपना जनाधार मजबूत करने के प्रयास किए हैं।

वर्तमान चुनाव के अब तक हुए मतदान के चार चरणों में पिछले 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। निर्वाचन आयोग ने कुछ महानगरीय शहरों में कम मतदान प्रतिशत पर चिन्ता प्रकट की है जिससे हाईटेक शहरों में मतदाताओं में गंभीर उदासीनता स्पष्ट होती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मतदान परिणाम प्रभावित करने में हर मतदाता की बड़ी भूमिका होती है। अतीत पर गौर करें तो इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सी.पी. जोशी को केवल एक वोट से चुनाव में पराजय मिली थी। मजेदार बात है कि उनकी पत्नी और बेटी विजय के लिए प्रार्थना कर रही थीं और इस कारण वोट नहीं डाल पाई थीं। इससे पता चलता है कि चुनाव में एक वोट का भी कितना महत्व होता है। इस उदाहरणसे इस तथ्य को भी महत्व मिलता है कि केवल एक वोट भी चुनाव परिणाम बल सकता है। वर्तमान चुनाव में मतदान के पहले चार चरणों में देश के कुछ हिस्सों में भारी गरमी के कारण मतदान प्रतिशत में संभवत: कमी आई है। हालांकि, अधिक मतदान को आमतौर से 'सत्ता-विरोधी' लहर का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कम मतदान से भी कभी-कभी सत्तारूढ़ दल को नुकसान हो सकता है क्योंकि ऐसे में स्थानीय मुद्दे मतदान परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा का उद्देश्य भारत के 6 राज्यों में अपनी स्थिति सुधारना है। इनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल शामिल हैं। लेकिन उसे यहां क्षेत्रीय दलों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो राज्य चुनावों में वर्चस्व स्थापित कर समग्र रूप से चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। एक हालिया रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव परिणामों के अनुमान में अनिश्चितता की बात कही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदी में 'एक्स' पर संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों पर हमले कर रहे हैं जिससे संकेत मिलता है कि मोदी की कुर्सी हिल रही है। सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि पहले दो मतदान चरणों के बाद भाजपा की हालत खराब हुई है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति मुख्यत: समाज कल्याण व आर्थिक सशक्तीकरण को केन्द्र में लाना है। इससे वह मतदाताओं की प्राथमिक चिन्ताओं पर ध्यान केन्द्रित कर उनके बड़े वर्ग को प्रभावित करना चाहती है। यदि मतदाताओं का समर्थन मिले तो इससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के समक्ष मुख्य चुनौती अपने सदस्यों को एकजुट रखना है। मोदी के उभार के बाद राज्यस्तरीय नेताओं समेत अनेक नेता भाजपा में चले गए हैं। भाजपा ने उनमें से कुछ को टिकट भी दिए हैं। देखना होगा कि मतदाता इन दलबदलुओं पर क्या फैसला देते हैं।

कांग्रेस में आंतरिक मतभेद वर्तमान समय में गंभीर चिन्ता का विषय हैं। विरोधी दलों से उनके संबंधों के आरोप निष्ठा पर सवाल लगाते हैं। इससे पार्टी की एकता प्रभावित हो सकती है जिसका नतीजा वर्तमान चुनाव में प्रदर्शन पर पड़ेगा। इसलिए पार्टी में ऐसी घटनाओं पर नजर रखना तथा चुनाव संभावनाओं की बेहतर समझदारी जरूरी है। 2016 से 2020 के बीच कांग्रेस के 170 विधायक और 7 राज्यसभा सदस्य पार्टी छोड़ चुके हैं। इससे पार्टी में भ्रम तथा नेताओं की निष्ठा पर संदेह पैदा हो रहा है। इन आरोपों से कांग्रेस के इन नेताओं के बारे में मतदाताओं की समझ बदल सकती है। दलबदल की परिघटना से दूसरी गैर-भाजपा पार्टियां भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। भारत के सट्टा बाजार ने अनुमान लगाया है कि भाजपा को 330 से 335 सीटों के बीच मिल सकती हैं। इस पर एक रुपये का सट्टा लगा है। इसके साथ ही भाजपा की सीटें 350 होने पर 3 रुपये का तथा 400 पार जाने पर 12-15 रुपये का सट्टा लगा है। इसी प्रकार राजग के 400 सीटें पार होने पर 4-5 रुपये का सट्टा लगा है। ये अनुमान चुनाव परिणामों पर बाजार का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हैं जिसका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ सकता है।

हालांकि, निवेशकों द्वारा अपनी बोलियां घटाने के कारण शेयरबाजार मंगलवार को 1.5 प्रतिशत गिर गया। इससे कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि भाजपा को शायद उतनी सीटें न मिल सकें जिनका पहले अनुमान लगाया गया था। लेकिन इतना अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि मोदी निश्चित रूप से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भले ही भाजपा और राजग की सीटें 400 पार हों या नहीं। ऐसे में 4 जून को चुनाव परिणाम आने तक सस्पेंस बना रहेगा जब पता चलेगा कि मतदाताओं ने किसे पसंद किया है।

फिल्मोत्सवों की ब्रांडिंग का असर

> फिल्म महोत्सव ग्लैमर, करिश्मा, फैशन और सेलिब्रिटी भागफल को चित्रित करते हैं जो दर्शकों के बीच एक अनोखी हलचल पैदा करते हैं।

चैतन्य के प्रसाद
(लेखक,स्तम्भकार हैं)

किसी भी ब्रांडिंग अभ्यास की सफलता लक्षित दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव और प्रभाव, उत्पादों की दृश्यता, रिकॉल वैल्यू और अभियानों, लॉन्च, घटनाओं और रुझानों और शैलियों की विस्तृत श्रृंखला के दर्शकों के साथ गहरा संबंध है। इसी तरह, किसी दृश्य मंच पर ब्रांडिंग विचार या रणनीति के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है, जहां आंखें सफलता का पैमाना तय करती हैं। ऐसे ग्लैमरस सर्किट और इकोसिस्टम पर ब्रांडिंग के मूल्य, तीव्रता और प्रभाव को समझने के लिए आज फिल्म महोत्सव एक आदर्श इकोसिस्टम है।

सिनेमा के क्षेत्र में, जहां रचनात्मकता वाणिज्य से मिलती है, फिल्म महोत्सव जीवंत केंद्र के रूप में काम करते हैं जहां कहानी कहने की संस्कृति के साथ मिलती है, कलात्मकता उद्योग के साथ जुड़ती है और समुदाय सिल्वर स्क्रीन के लिए साझा प्यार के आसपास बंधते हैं। सिनेमाई योग्यता के प्रदर्शन से परे, ये त्यौहार शक्तिशाली ब्रांडों में विकसित हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग पहचान और आकर्षण है। कान्स की चकाचौंध से लेकर वेनिस फिल्म महोत्सव की विरासत तक और बर्लिन के महानगरीय आकर्षण से लेकर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (टीआईएफएफ) की बौद्धिक पेचीदगियों और भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) की भव्यता तक, ब्रांडिंग रणनीतियां ये त्योहार संस्कृति, अर्थशास्त्र और राजनीति के अंतर्संबंध की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं।

फिल्म महोत्सव ग्लैमर, करिश्मा, फैशन और सेलिब्रिटी भागफल को चित्रित करते हैं जो दर्शकों के बीच एक अनोखी हलचल पैदा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कान्स, बर्लिन, आईएफएफआई और टोरंटो ने एक अद्वितीय ब्रांड पहचान विकसित की है जिसने ब्रांडिंग क्षेत्र में कहानी और दृश्यता कथा को गढ़ा और आकार दिया है। त्यौहार अपनी नवोन्वेषी विघटनकारी प्रवृत्तियों के लिए जाने जाते हैं जो अद्वितीय आउट ऑफ द बॉक्स ब्रांडिंग की ओर ले जाते हैं। किसी भी फिल्म महोत्सव की हलचल एक अद्वितीय अभिन्न संबंध और सिनेमा को परिभाषित करने वाली आर्क लाइट और ब्रांडिंग बनाने वाले रंगों, रंगों और छवियों के बीच संबंध बनाती है। फिल्म महोत्सवों में ब्रांडिंग भागफल का एक अध्ययन महोत्सव क्षेत्र में ब्रांडिंग के विचारों, अवधारणाओं और मूल्यांकन के बदलते पहलुओं का प्रतिबिंब दर्शाता है। 4सी = रचनात्मकता, संस्कृति, सामग्री और संगति ब्रांडिंग और फेस्टिवल सर्किट के बीच अभिन्न संबंध को रेखांकित करती है।

यह रचनात्मक दिमागों, कहानीकारों, वर्णनकर्ताओं और प्रेरणादायक चर्चा करने वाले प्रमुखों का एक आदर्श संगम है। हर त्यौहार में ब्रांडिंग के कुछ खास पल होते हैं, जो दर्शकों के दिमाग पर छाप छोड़ते हैं और भावी उपभोक्ताओं और सिनेमाई उत्कृष्टता के समर्थकों पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। त्योहारों पर अवसर असीमित हैं।

कान्स, बर्लिन, आईएफएफआई और टोरंटो अपने फिल्मांकन संस्कृति झुकाव, कथाकार के मूल्यों और कहानी कहने की युक्तियों के साथ ब्रांडिंग प्लेटफार्मों और विचारों को एकीकृत करते हैं। इन त्योहारों में एक माध्यम के रूप में ब्रांडिंग ने सॉफ्ट पावर गतिशीलता और समीकरणों को मजबूत किया है जिससे बेहतर दृश्यता, उत्पाद मूल्य, सकारात्मक धारणा बढ़ी है और आउटरीच और नेटवर्किंग के अवसर बढ़े हैं। प्रौद्योगिकी ब्रांडों का एक विचार उत्पाद प्रदर्शन का एक और स्तर सामने लाता है। इंटरएक्टिव अनुभव और मार्केटिंग आउटरीच। प्रत्येक प्रमुख त्यौहार ने अपने संस्करणों में तकनीकी उपकरणों के साथ ब्रांडों की छवि, पहचान, प्रभाव, इंटरैक्शन और इंटरफ़ेस को मजबूत किया है, जिससे स्थानों पर एक अद्वितीय उत्पाद पहचान और स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रत्येक प्रमुख फिल्म महोत्सव, चाहे वह कान्स, टीआईएफएफ, वेनिस, बर्लिनले या आईएफएफआई हो, अपने व्यक्तित्व और मूल्यों को व्यक्त करने के लिए अपने ब्रांडिंग तत्वों के लिए सावधानीपूर्वक एक खाका तैयार करता है। अपने ग्लैमर के लिए प्रसिद्ध कान्स में रेड कार्पेट पर पाल्मे डी%ओर ट्रॉफी और मशहूर हस्तियों का चित्रण शामिल है, साथ ही एक परिष्कृत लोगो डिजाइन भी शामिल है जो अक्सर कान्स समुद्र तट को दर्शाता है। त्योहार का काला, सुनहरा और लाल रंग संतुलन, प्रतिष्ठा और उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है।

इस बीच, टीआईएफएफ फिल्म रीलों, विविध दर्शकों और टोरंटो स्थलों को प्रदर्शित करने वाली गतिशील आइकनोग्राफी के साथ विविधता को अपनाता है, जो लाल, नीले और पीले जैसे जीवंत रंगों से पूरित होता है जो ऊर्जा, रचनात्मकता और समावेशिता को दर्शाता है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल, अपनी समृद्ध विरासत के साथ, रियाल्टो ब्रिज या सेंट मार्क स्क्वायर जैसे वेनिस के स्थलों के शास्त्रीय चित्रण का विकल्प चुनता है, साथ ही एक परिष्कृत लोगो डिजाइन भी होता है जो वेनिस की कालातीत सुंदरता का सार दर्शाता है। आईएफएफआई सौंदर्यात्मक रूपांकनों और परिदृश्यों, पारंपरिक लोगो डिजाइन और नारंगी, लाल और सुनहरे रंगों के साथ-साथ शांत नीले और हरे रंग के प्रदर्शन के साथ भारतीय सिनेमा का जश्न मनाता है जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। इन ब्रांडिंग तत्वों के माध्यम से, प्रत्येक त्योहार अपनी मान्यताओं को संप्रेषित करता है, दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करता है और वैश्विक फिल्म उद्योग के भीतर इसके महत्व को मजबूत करता है।

फिल्म निर्माताओं के लिए, किस उत्सव में अपना काम प्रस्तुत करना है, यह न केवल आयोजन के सम्मान और प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, बल्कि उनकी कलात्मक दृष्टि और कैरियर लक्ष्यों के साथ इसके संरेखण पर भी निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान चाहने वाला एक फिल्म निर्माता कान्स या बर्लिनले की ओर आकर्षित हो सकता है, जबकि फिल्मोग्राफी की विस्तृत और विविध श्रेणी का समर्थन करने वालों को वेनिस या टीआईएफएफ में घर मिल सकता है। इस तरह, फिल्म महोत्सवों की ब्रांडिंग फिल्म निर्माताओं के करियर की दिशा और समग्र रूप से फिल्मों की सांस्कृतिक बारीकियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है।

आप की बात

कांग्रेसी भविष्यवाणी

आम चुनाव के बारे में कांग्रेसी भविष्यवाणी जनता को कतई हजम नहीं हो रही है। राहुल, प्रियंका, सोनिया व पार्टी अध्यक्ष खड़गे कह रहे हैं कि यदि इस बार चुनाव में नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से विजयी होते हैं तो वह देश में चुनाव प्रक्रिया खत्म कर देंगे। कांग्रेस कह रही है कि आज संविधान एवं लोकतंत्र खतरे में हैं। ऐसी भविष्यवाणी वह कांग्रेस कर रही है जिसने आपातकाल के दौरान पूरे देश को बंधक बना लिया था, संविधान में मनमाने ढंग से 44वां संविधान संशोधन कर जनता के मूलाधिकार छीन लिए थे तथा पूरे देश को जेल में बदल दिया था। कांग्रेस समझती है कि देश की जनता वे दिन भूल गई है जब कांग्रेसी नेता इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया के नारे लगाते थे। भारत की जनता व खासकर युवा पीढ़ी अच्छी तरह जानती है कि नेहरू-गांधी परिवार ने अपने को ही बार-बार भारत रत्न समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव में हराने की सारी तिकड़में लगाईं तथा उनका पोर्टेट तक लोकसभा में नहीं लगने दिया। कांग्रेस की ऐसी भविष्यवाणी जनता को डराने और भ्रमित करने के लिए है, लेकिन संभवत: वह स्वयं अपने 138 साल के जीवन में आज जितनी भयभीत है, उतनी भयभीत पहले कभी नहीं थी।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

बदहाल पाकिस्तान

देश की माली हालत नाजुक होने पर सरकार को अजीब निर्णय लेने पड़ते हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इन दिनों आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया की हालत से गुजर रहा है। इसीलिए सरकार करसंग्रह बढ़ाने के लिए समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर सख्ती से पेश आ रही है। पाकिस्तानी संघीय राजस्व बोर्ड ने रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों की बिजली व गैस आपूर्ति काटने का निर्णय लिया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। पिछले महीने उन लोगों के पांच लाख से अधिक सिम ब्लॉक करने का आदेश दिया था जो टैक्स नहीं दे रहे थे। लेकिन एक टेलीकॉम कंपनी की याचिका पर अदालत ने 27 मई तक इसके खिलाफ स्थगन आदेश जारी कर दिया है। देखना होगा कि पाकिस्तानी हुक्मरान अपने देश के अमीरों से टैक्स वसूली के लिए आगे क्या कदम उठाते हैं। ये सारे कदम सरकार ने आईएमएफ के आदेश पर उठाए हैं। अगर आईएमएफकी बात नहीं मानी तो वह कर्ज देना बंद कर देगा। पाकिस्तान में आम जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है और कई जगह विद्रोह पर आमादा है। ऐसे में पाकिस्तान लगातार बदहाली और विखंडन के कगार पर पहुंच रहा है।

–जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

चाबहार समझौता

चाबहार पोर्ट समझौता भारत और ईरान के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता है। इसके माध्यम से भारत और ईरान के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और अफ़ग़ानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के लिए नए रास्ते खुलेंगे। लंबे समय से भारत सरकार इस समझोते के लिए प्रयासरत थी। आखिरकार हमारे प्रयास रंग लाए और हमारी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति एक बार फिर सफल हुई। इस समझौते के बाद जहां समुद्र में भारत की ताकत बढ़ेगी वहीं समुद्री परिवहन भी सुगम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान को किनारे छोड़कर समुद्री आवागमन का एक नया मार्ग हमें मिल जाएगा। चीन भी इस समझौते से जरूर तिलमिला रहा होगा क्योंकि यह पाकिस्तान को शामिल करने वाले उसकी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का विकल्प है। लेकिन विडंबना है कि अमेरिका इस समझौते के खिलाफ भारत को चेतावनी दे रह है। ऐसे में भारतीय विदेश नीति की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा होगी। ऐसे में उम्मीद है कि 4 जून के बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली मजबूत केन्द्र सरकार चाबहार समझौते को लागू करने के मामले में भी अमेरिका को मनाने में सफल होगी।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

महिला उम्मीदवार

संसद में महिला आरक्षण कानून पास हो जाने के बाद भी देशभर की सभी पार्टियों ने 2024 के चुनाव में महिला उम्मीदवारों को 33 प्रतिशत तो दूर 15 प्रतिशत सीटें भी नहीं दी है। इसकी प्रमुख वजह यही हो सकती है कि सभी दलों में जिताऊ महिला उम्मीदवारों की कमी है। सिर्फ फिल्मी कलाकारों व नेताओं की उत्तराधिकारी महिलाओं को ही सीटें दी गई हैं। यदि राजनीतिक दल वास्तव में महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं तो पहले उनको पार्टी स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां देनी होंगी। इससे वह राजनीतिक प्रशिक्षण पाने के साथ-साथ जनता के बीच जाकर अपनी जुझारू व अधिकारियों से काम कराने वाली छवि बना सकें। इससे चुनावी टिकट पाने की उनकी दावेदारी आसान हो जाएगी। मतदान के चार चरणों में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया है और कई स्थानों पर तो उनकी संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक रही है। चुनाव के बाकी तीन चरणों में सभी राजनीतिक दलों को अपनी महिला उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए खास प्रयास करने चाहिए। ऐसा कर ही हम संसद से लेकर ग्राम पंचायतों तक में महिलाओं को समुचित स्थान दे सकेंगे।

–सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

चाबहार पर करार भारत की कूटनीतिक सफलता

चाबहार पोर्ट के विकास और प्रबंधन पर अगले दस वर्ष के लिए ईरान की सरकारी कंपनी से समझौता भारत को व्यापारिक-सामरिक लाभ देगा। जहां एक ओर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यह सही जवाब है, वहीं मध्य-एशिया के देशों के अलावा यूरोप से व्यापार का मार्ग खुल जाएगा। चूंकि अमेरिका का ईरान पर प्रतिबंध जारी है लिहाजा भारत के इस कदम पर दुनिया को दिखाने के लिए धमकी देना उसकी मजबूरी थी। भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को याद दिलाया कि उसने हाल ही में इस पोर्ट को विकसित करने में भारत की भूमिका की तारीफ की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि यह समझौता सभी के हित में है, लिहाजा अमेरिका को संकीर्ण दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। वैसे भी ट्रम्प के शासन काल में इस प्रतिबंध से भारत को मुक्त रखा गया था। अब इस नए समझौते के बाद अमेरिका को यह सोचना होगा कि वह दक्षिण और मध्य एशिया में चीन को पांव पसारने की खुली छूट देना चाहता है या भारत के जरिए उस पर अंकुश लगना चाहता है। चाबहार परियोजना उत्तर-दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ही हिस्सा है। उधर भारत-मध्यपूर्व-यूरोप -इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी सर्वसम्मत परिकल्पना नई दिल्ली की जी-20 बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने की थी, उसे भी अंजाम देने का रास्ता खुलेगा। भारत के लिए यह एक बड़ी राजनयिक सफलता है।

प्रेरणा

पचास साल की उम्र में हर मनुष्य के पास वह चेहरा होता है जिसमें उसकी आत्मा झलकती है। **-जॉर्ज ऑरवेल**

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

कामयाबी की दौड़ में अपनी खुशी न भूल जाएं

यह जबर्दस्त प्रतिभा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा का युग है। हर कोई, हर पल मौके और संबंधों को भुनाना चाहता है। जीना कोई नहीं चाहता। धीरे-धीरे सब कुछ व्यावसायिक होता जा रहा है। मुझे कुछ मिलेगा तो मैं किसी के लिए कुछ करूंगा या करूंगी। निकट से निकट के संबंध, वो भी परिवार में, सौदे के हिसाब से चलाए जा रहे हैं। प्रबंधन की दुनिया में एक शब्द चल रहा है मून लाइटिंग। इसका सीधा अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी को बिना बताए, दूसरे संस्थान के लिए भी काम करे। यानी एक साथ दो जगह काम करना। एक वर्ग कह रहा है कि यह नैतिकता के खिलाफ है। और दूसरा वर्ग कह रहा है अब यह मजबूरी और जरूरत है क्योंकि मैनेजमेंट काम करने वालों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता, उनका यंत्र की तरह इस्तेमाल करता है। और काम करने वाले निष्ठावान नहीं हैं। इसलिए तनाव तो आएगा पर इस सब में आप अपना निजी नुकसान न कर लें। नुकसान की शुरुआत मेंटल हेल्थ से होगी और भुगतेगी देह। और जब शरीर कीमत चुकाएगा तो कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए कामयाबी की दौड़ में अपनी खुशी को न भूल जाएं। • Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

नया विचार • किताबें छोड़कर वीडियो देखने का असर

क्या युवाओं का बौद्धिक विकास ठीक से हो रहा है?

चेतन भगत
अंग्रेजी के उपन्यासकार
chetan.bhagat@gmail.com

हाल ही में एक वीडियो बहुत चर्चित हुआ। एक निजी विश्वविद्यालय के बेखबर छात्र विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने चले आए थे। एक रिपोर्टर के साधारण से सवालों के जवाब में वे दो वाक्य भी नहीं बोल पा रहे थे। वीडियो देखकर कइयों की हंसी फूट पड़ी, लेकिन वह उतना ही दुःखद भी था। उसमें हमारे आज के औसत कॉलेज छात्रों का एक छोटा-सा नमूना नजर आया था। वे साधारण छात्र नहीं थे। उनके माता-पिता ने उन्हें अच्छी परवरिश दी थी और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में दाखिला दिलाया था। वे महंगे निजी विश्वविद्यालयों का खर्च उठाने में भी सक्षम थे। वे छात्र अच्छे कपड़े पहनते हैं और महंगे फोन रखते हैं। इसके बावजूद जब वे कुछ कहने के लिए मुंह खोलते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी पढ़ाई-लिखाई ठीक से नहीं हो सकी है।

यह एक गंभीर स्थिति है। इसका यह मतलब है कि हमारे मौजूदा स्नातकों और भावी स्नातकों का एक पूरा वर्ग- जो शायद लाखों में हैं- ऐसा है, जिसकी किसी चीज के बारे में सोचने, समझने, उसका विश्लेषण या समाधान करने की क्षमता शोचनीय है। स्कूल के बारह साल और कॉलेज के तीन या चार साल पूरे करने के बाद ये हालात हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पूरे देश की यात्राएं करता हूं और कॉलेज-छात्रों को संबोधित करता हूं। यह कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि औसत छात्र अयोग्यता का भयावह स्तर प्रदर्शित करते हैं। अगर युवा किसी भी चीज में दिमाग लगाने से ही इनकार कर देंगे तो हम विकसित कैसे बनेंगे?

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत में मेधावी छात्र नहीं हैं। भारत के छात्र ही यूनिकॉर्न के संस्थापक, इंवेंटर्स, शीर्ष वकील और सर्जन बने हैं। लेकिन, वे अपवाद हैं। जब 'सभी' छात्रों की बात आती है, तो चीजें इतनी उजली नहीं लगतीं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आधे से अधिक भारतीय स्नातक बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों है? हम अक्सर इसके लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को दोष देते हैं। शायद आंशिक रूप से वह हो भी। लेकिन वास्तविक कारण इससे गहरे हैं। तीन कारण देखें।

1. भारतीय परिवार, जिनमें साधन-संपन्न परिवार भी शामिल हैं, अपने बच्चों को पढ़ने, लिखने, सोचने, विश्लेषण करने, राय देने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। कितने मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे हैं, जो खाने की मेज पर किताबों, करंट अफेयर्स, वैश्विक चिंताओं आदि पर चर्चा करते हैं? इसके बजाय हम इस बारे में बात करना पसंद करते हैं कि खाना कैसा बना है, घी, अचार और गुड़ कितना अच्छा है, कौन किससे शादी कर रहा है, रियलिटी शो और क्रिकेट में क्या हो रहा है, कौन-सी वेब सीरीज देखनी है या कौन-सा बॉलीवुड स्टार विवाह कर रहा है। इससे भी बदतर यह है कि हम आजकल खाने की मेज पर भी फोन में लगे रहते हैं। दिमागी जड़ता वहीं से शुरू होती है। इसके लिए किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम या कॉलेज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

2. वीडियो देखना नया चलन बन गया है। किताबें पढ़ने को समय की बर्बादी माना जाता है। कई छात्र कहते पाए जाते हैं कि 'मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं तो वीडियो देखना पसंद करता हूं।' वास्तव में वो यह कहना चाह रहे होते हैं कि मैं पढ़ने के लिए जरूरी मानसिक प्रयास नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो देखने में दिमाग की कम कसरत होती है। जबकि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर पर भरोसा करेंगे जो कहता हो, 'मैंने कभी मेडिकल की किताबें नहीं पढ़ीं, लेकिन बहुत वीडियो जरूर देखे हैं?'

हमें सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों सरीखे फिजिकल-इंफ्रास्ट्रक्चर की ही नहीं, ह्यूमन-इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। हमें लाखों ऐसे युवा चाहिए, जिनमें सोचने-समझने की क्षमता, दूरदृष्टि और एक बेहतर कल के निर्माण की क्षमता हो।

3. एक औसत भारतीय छात्र अच्छा जीवन बिताना चाहता है। अच्छे जीवन से उसका आशय आईफोन, आकर्षक डेटिंग पार्टनर, महंगे कपड़े, ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रेंडी बार-रेस्तरां में जाना है। सोशल मीडिया फीड उसे यही सब दिखाकर उसकी इच्छाओं को बढ़ावा देती है। उसके दिमाग में अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने के लिए समय ही नहीं है। जब उससे करियर के लक्ष्यों के बारे में पूछा जाता है, तो वो बस इतना ही कहता है कि मुझे कोई अच्छी-सी नौकरी चाहिए। दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने, किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने या सार्थक जीवन जीने का जुनून उसमें नहीं होता। उनकी मानसिकता यह होती है कि चाहे जैसे हो, मुझे यह लाइफस्टाइल मिल जाए, फिर उसके लिए मां-पिता से ही मदद क्यों न लेनी पड़े। इससे बचें। हर उस चीज में ध्यान भटकाना बंद कर दें, जो आपको बौद्धिक रूप से जड़ बनाती हो। दुनिया के बारे में जानें। समाज के रचनात्मक-सदस्य के रूप में अपना स्थान खोजें। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करने पर ही फोकस करें। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

विमर्श • लोकसभा चुनावों में बहुत कुछ दांव पर

चुनावों के शोरगुल में जरूरी मुद्दों से ध्यान भटक रहा है

अश्विनी कुमार
पूर्व केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री

लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान के साथ ही 543 उम्मीदवारों में से 379 का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया। देश के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लाने वाले चुनाव के रूप में देखे जाने वाले इस निर्वाचन में इंडिया गठबंधन द्वारा मौजूदा सरकार को टक्कर दी जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ दल के पास अपने चुनाव अभियान की थीम तैयार करने को लेकर नवगठित विपक्षी गठजोड़ की तुलना में ज्यादा समय था। विपक्षी दलों का काउंटर-नैरेटिव संवैधानिक लोकतंत्र और उसके मूल्यों की रक्षा पर केंद्रित है। वे कहते हैं कि एक निरंकुश राज्यसत्ता उदार लोकतंत्र के प्राथमिक सिद्धांतों और देश के गणतंत्रीय चार्टर में निहित सत्ता के उत्तरदायित्व को नकारती है। विपक्ष द्वारा भारत भर में प्रमुख राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारियों, संवैधानिक संस्थानों में गिरावट, नौकरशाही की स्वायत्तता का क्षीण होना और मीडिया की आज्ञाकारिता का अपने मत के समर्थन में हवाला दिया जाता है। उसके सामने चुनौती यह है कि अपने इस नैरेटिव के लिए जनता की सहमति कैसे अर्जित करें।

लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के शोर-शराबे वाले चुनाव-अभियान ने वास्तविक मुद्दों को दबा दिया है। तर्क-वितर्क की जगह आक्षेपों और निंदा ने ले ली है। खुद से ऊपर उठ पाने में असमर्थ नेताओं द्वारा संचालित लोकतांत्रिक संवाद की विकृति एक कमजोर लोकतंत्र की पुष्टि करती है। सत्ता की खोज में अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत कम सम्मान और राजनीतिक आदर्शवाद के उपहास से लोकतंत्र की आड़ में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन ही दिखलाई देता है। अगर भाजपा और विपक्षी दल सच में ही इस चुनाव को एक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण क्षण मानते हैं- जो देश का भविष्य निर्धारित करेगा- तो उन्हें मुख्य मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

इंडिया गठबंधन में कई स्वर सम्मिलित हैं। लेकिन उसके अभियान की सफलता उसके मंतव्यों की स्पष्टता से ही तय होगी। अपने मुख्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने और प्रत्येक मतदाता को उससे अवगत कराने के अलावा वह वैकल्पिक नेतृत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न से बच नहीं सकता है। मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ने अपने मुख्य प्रचारक राहुल गांधी को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया है। कांग्रेस की जो भी स्थिति हो, नेतृत्व का प्रश्न उसके चुनाव-अभियान के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। विपक्षी एकता के आधार के रूप में खुद को पुनर्जीवित करने की आवश्यक शर्त के रूप में कांग्रेस को चापलूसी और वफादारी के बीच के अंतर को भी पहचानना होगा। अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली में 'छिपी हुई खामोशियों' को उदारतापूर्वक सुनना भी उसके लिए जरूरी है।

दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के मुख्य प्रचारक के रूप में 26 दलों के संयुक्त विपक्ष के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए इच्छाशक्ति की असाधारण दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने रणनीतिक रूप से अपनी पार्टी के अभियान को राष्ट्रीय गौरव और लोगों के भविष्य के लिए आशाओं के साथ आगे बढ़ाया है, और शायद वे लगातार तीसरा कार्यकाल जीत सकते हैं। लेकिन उन्हें भी यह ज्ञात होगा कि न्याय, गरिमा और स्वतंत्रता के विचार सत्ता के प्रलोभन से अधिक दीर्घकालीन होते हैं। अपनी विविधता से परिभाषित एक राष्ट्र के नेता के रूप में वे इससे भी अवगत होंगे कि उनका प्राथमिक दायित्व राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और असंख्य सामाजिक-राजनीतिक विभाजनों को पाटने के लिए एक एकीकृत राजनीति का पोषण करना है। चाहे

दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में दोनों पक्षों के शोर-शराबे वाले प्रचार-अभियान ने वास्तविक मुद्दों को दबा दिया है। तर्क-वितर्क की जगह आक्षेपों और निंदा ने ले ली है। जबकि कई जरूरी सवाल सामने खड़े हैं।

सरकार कोई भी बनाए, जीत उनकी होनी चाहिए जिनकी राजनीति न्याय और मानवीय गरिमा पर आधारित लोकतंत्र को कायम और मजबूत करती हो।

यह चुनाव समानतापूर्ण नागरिकता की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि जनता के नाम पर मांगी गई शक्ति का उपयोग उनके अंतर्निहित अधिकारों को आगे बढ़ाने में ही किया जाना उचित है। यह हमारे देश और उसके लोगों को भी परिभाषित करेगा, जिन्हें अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेना है, यह याद रखते हुए कि उनकी स्वतंत्रता लोकतंत्र के रक्षकों के नैतिक साहस, निडरता और उदारता पर निर्भर करती है। यह चुनाव किसी के निजी दृष्टिकोण के बारे में नहीं है। इसके बजाय, इसे हमारे सामाजिक ताने-बाने में गहराती दरारों को ठीक करने वाला होना चाहिए, ताकि हम दावा कर सकें कि भारतीय लोकतंत्र कोई भ्रामक सपना नहीं। और हम एक प्रबुद्ध देश के सशक्त नागरिकों के रूप में गर्व से अपना सिर उठा सकते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

हेल्थ & वेलनेस

https://t.me/AllNewsPaperPaid

वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को • दुनियाभर में करीब 130 करोड़ लोग हाइपरटेंशन के शिकार

हर चौथे व्यक्ति को हाइपरटेंशन, रोज दो फल, 200 ग्राम सब्जियां व 100 ग्राम साबुत अनाज घटाते हैं बीपी

डॉ. रमाकांत पांडा
चेयरमैन, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई

दुनियाभर में इस समय लगभग 130 करोड़ लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। इससे हृदय संबंधी रोग, स्ट्रोक और किडनी रोग जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि देश में हर चौथे व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। वहीं लगभग 46% लोगों को यह पता नहीं कि उन्हें इसकी समस्या है। दरअसल इसके कोई सामान्य लक्षण नजर नहीं आते हैं, जिसके चलते यह बीमारी और घातक हो जाती है। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। ऐसे में बीपी की जांच कराना ही इसे पता करने का एकमात्र उपाय है। हालांकि खान-पान में सुधार सहित कुछ बदलाव यदि जीवनशैली में लाए जाएं तो बीपी को नियंत्रित कर इसकी आशंका को कम कर सकते हैं।

बीपी यदि 140/90 तो हाइपरटेंशन

हाइपरटेंशन से जुड़ा सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है

हाइपरटेंशन क्या है?

धमनियां पूरे शरीर में दिल से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त ले जाती हैं। दिल शरीर के सभी हिस्सों तक रक्त पहुंचाने के लिए धमनियों के माध्यम से आवश्यक दबाव पैदा करता है। धमनियों की दीवारों पर लगने वाला यह दबाव ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। हाइपरटेंशन तब होता है जब यह दबाव लगातार बहुत अधिक हो।

यह क्यों होता है?

हाइपरटेंशन का कोई एक स्पष्ट कारण नहीं है बल्कि इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे फास्टफूड का अधिक सेवन (इनमें नमक अधिक होता है), धूम्रपान, किडनी से जुड़ी बीमारी व शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहना इसके प्रमुख कारण हैं। कुछ गर्भनिरोधक दवाइयों से भी बीपी बढ़ने की समस्या हो सकती है।

इसके लक्षण क्या हैं?

आमतौर पर, हाइपरटेंशन की शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। बीमारी जब गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है तब चक्कर आना, यूरीन में ब्लड आना, सिर में लगातार दर्द रहना, नाक से खून आना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होने जैसे लक्षण दिख सकते हैं। हाइपरटेंशन के साथ ही यदि गुस्सा भी आता है तो खतरा अधिक हो जाता है।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दो उपाय जो बीपी को 20 पॉइंट तक घटा सकते हैं

DASH डाइट *: डाइटरी एप्रोच टु स्टॉप हाइपरटेंशन यानी कि DASH डाइट हाइपरटेंशन को नियंत्रित में बेहद मददगार है। इससे 14 पॉइंट तक बीपी कम किया जा सकता है। इसके तहत रोज के भोजन में दो मध्यम आकार के फल जैसे सेब, केला, संतरा अथवा नाशपाती होने चाहिए। लगभग 200 ग्राम हरी सब्जियां, करीब 100 ग्राम साबुत अनाज, 100 ग्राम नट्स, बीज और बीन्स को शामिल करें। लो फैट डेयरी और पोल्ट्री प्रोटीन के लिए लें।*

वजन *: मोटापे से ग्रसित व्यक्ति यदि एक किलो वजन कम करता है तो एक पॉइंट तक बीपी कम हो जाता है। 5 किलो वजन घटाना बीपी में फायदेमंद।*

रिसर्च •

पेट पर ज्यादा चर्बी तो कमजोर याददाश्त का खतरा तीन गुना ज्यादा

पेट के आसपास की चर्बी लिवर से जुड़ी बीमारियों, डायबिटीज आदि के लिए तो जिम्मेदार है ही यह याददाश्त के लिए भी नुकसानदायक है। लाइव साइंस मैगजीन के अनुसार लिवर और मस्तिष्क में याददाश्त का मुख्य केंद्र हिप्पोकैंपस दोनों ही PPARalpha प्रोटीन का विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं। अधिक बेली फैट वाले लोगों में फैट को शरीर के उपयोग में लाने के लिए लिवर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में वह इस प्रोटीन का अधिक उपयोग कर लेता है। इसके बाद शरीर के विभिन्न हिस्सों में एकत्रित प्रोटीन का भी उपयोग करने लगता है। ऐसे में हिप्पोकैंपस को नुकसान पहुंचने लगता है। और याददाश्त कमजोर होने लगती है।

कोलेस्ट्रॉल •

कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक रूप से घटाने में मददगार हैं ये आसन

डॉ. हंसाजी योगेंद्र
डायरेक्टर, दि योगा इंस्टीट्यूट मुंबई

खराब कोलेस्ट्रॉल भारतीयों में तेजी से बढ़ती समस्या है। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि बिना पता चले यह धीरे-धीरे धमनियों की दीवारों पर जमा होता है। इससे प्लाक बनते हैं जो धमनियों को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे दिल और दिमाग में रक्त का प्रवाह बाधित होता है, जिससे दिल के रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का लगभग 20 प्रतिशत मस्तिष्क में होता है, जो शरीर के किसी अन्य टिशू की तुलना में अधिक है। खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए नुकसानदायक है। खान-पान में बदलाव करने के साथ ही अर्ध मत्स्येंद्रासन, आंजनेयासन और हस्तपादांगुष्ठासन आदि किए जाएं तो इसे प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं।

अर्ध मत्स्येन्द्रासन

पैर फैलाकर फर्श पर बैठ जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें। दाएं पैर को उठाएं और एड़ी को बाएं घुटने के पास रखें। धड़ को थोड़ा दाहिनी ओर मोड़ें और दाएं घुटने को बाएं हाथ की बगल से दबाते हुए दाएं टखने को पकड़ें। दाहिने हाथ को पीठ के पीछे से बाईं जांघ की ओर ले जाएं, हथेली बाहर की ओर हो। गर्दन को दाहिने कंधे की ओर मोड़ें। कुछ सेकंड रुकें। धड़ और गर्दन को सीधा करते हुए पूर्व स्थिति में आएं। अब बाईं ओर मुड़ने के लिए यही स्टेप्स दोहराएं।

सेहत का विज्ञान • शहद और गुड़ भी ब्लड शुगर के स्तर को उतना ही बढ़ाते हैं जितने कि चीनी से बने उत्पाद

डायबिटीज को नियंत्रित करने में बेहद असरदार हैं भोजन और जीवनशैली के ये बदलाव

रेणु रखेजा,
न्यूट्रिशनिस्ट एवं हेल्थ कोच
@consciouslivingtips

भारत को अक्सर दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। क्योंकि दुनियाभर के डायबिटीज के मरीजों में से लगभग 17 प्रतिशत यहीं हैं। डायबिटीज के जेनेटिक कारण भी हैं, लेकिन यह मुख्यत: जीवनशैली से जुड़ी बीमारी है। प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन, हाई कैलोरी डाइट, शारीरिक निष्क्रियता और गंभीर तनाव इस समस्या को और बढ़ाते हैं। इसके अलावा अधिक बॉडी फैट, खासकर पेट के आसपास अधिक चर्बी से भी डायबिटीज का खतरा बढ़ता है।

पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस व डायबिटीज को जानें

डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ब्लड शुगर के स्तर और इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना जरूरी है। भोजन के रूप में लिया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटकर रक्त प्रवाह में शामिल हो जाता है। इसके बाद पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है जो ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करने में शरीर की कोशिकाओं की मदद करता है। कोशिकाएं जब इंसुलिन के प्रति कम प्रतिक्रिया करने लगती हैं तब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। वे ग्लूकोज को ठीक से उपयोग नहीं कर पाती हैं। ब्लड शुगर का स्तर बढ़ा रहता है। डायबिटीज की आशंका बढ़ती है।

इन तरीकों से डायबिटीज को नियंत्रित करने के साथ ही उसे रिवर्स भी कर सकते हैं...

नाश्ते में प्रोटीन अधिक लें

हाई प्रोटीन नाश्ते से ब्लड शुगर का स्तर सुबह से ही स्थिर रहता है। मीठा खाने की इच्छा कम होती है। दरअसल प्रोटीन को पचने में अधिक समय लगता है इससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता।

पोहे की जगह मूंगदाल का चीला खाएं

उदाहरण के तौर पर पोहा अथवा पराठे की जगह मूंगदाल का चीला, पनीर भुर्जी या अंडा नाश्ते में लें। इनमें प्रोटीन अधिक होता है। इससे भूख पर नियंत्रण में मदद मिलती है। साथ ही यह दोपहर से पहले ब्लड शुगर के गिरने से अचानक होने वाली कमजोरी और थकान से बचा सकता है। शुगरी फूड खाने की आशंका कम होती है।

हाई फाइबर फूड पहले खाएं

सही फूड का चुनाव और उसका क्रम ब्लड शुगर को मैनेज करने में बेहद महत्वपूर्ण है। भोजन की शुरुआत हाई फाइबर फूड से करें। इसके बाद प्रोटीन वाले फूड लें। चावल या रोटी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को अंत में खाएं।

भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी

सबसे पहले सलाद या कम तेल में पकी हुई सब्जियां खाएं। इसके बाद चिकन/मछली/पनीर जैसे प्रोटीन वाले फूड लें। अंत में दाल और सब्जी के साथ थोड़े चावल/रोटी खाएं। इससे भोजन के दौरान ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथ ही पोषक एवं फाइबरयुक्त खाद्य पदार्थों की प्राथमिकता बढ़ती है।

भोजन से हाई शुगर फूड घटाएं

सफेद चावल, मैदे से बने उत्पाद, आलू, कॉर्नफ्लैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, मिठाई, शहद, गुड़, फ्रूट जूस और मीठे पेय का सेवन कम करें। ये ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाते हैं।

मिलेट्स, जौ का दलिया करें शामिल

साबुत मिलेट्स, जौ का दलिया अथवा क्विनोआ को चावल की जगह शामिल करें। सत्तू, रागी या अलसी को रोटियों में मिलाएं। साबुत फल खाएं। नमकीन नींबू पानी या सत्तू पीएं। इनमें हाई-फाइबर के साथ कम शुगर होती है। ब्लड ग्लूकोज को स्थिर रखने में मदद मिलती है।

अगले अंक में जानिए डायबिटीज को नियंत्रित करने वाले ऐसे ही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में।

नोट : इस लेख में दी गई जानकारी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जीवनशैली में सुधार के लिए है। अपनी डायबिटीज की दवाओं में कोई भी बदलाव करने से पहले स्वास्थ्य सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 77

लापरवाही का नमूना

मुंबई में एक बिलबोर्ड के गिरने से 14 लोगों की मौत और 75 लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले से यह बात एक बार फिर उजागर हो गई है कि देश के शहरों के नगर निकाय अधिकारियों में किस कदर लापरवाही घर कर चुकी है। जैसा कि जांच में सामने आ रहा है इस प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ है। तथाकथित उद्यमी जिसे भारतीय रेल तथा वृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) दोनों से होर्डिंग और बैनर लगाने का अनुबंध मिला है, उसे नियमों के उल्लंघन के लिए जाना जाता है। यहां तक कि उस पर होर्डिंग लगाने के लिए पेड़ों को काटने तक के इल्जाम हैं। वह राजनीति में आने का आकांक्षी है और उस पर बलात्कार का भी आरोप है। घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने की घटना उसके काम करने के तरीके का एक नमूना पेश करती है। यह 120 फुट गुना120 फुट का विशालकाय होर्डिंग था और उसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। वह बीएमसी के 40 गुना 40 के अधिकतम अधिकृत होर्डिंग की तुलना में तीन गुना बड़ा था। इगो मीडिया नामक इससे संबंधित कंपनी को लेकर मार्च 2023 में भी सवाल उठे थे। उस वक्त बीएमसी ने इगो मीडिया को 6.14 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क न चुकाने के लिए नोटिस दिया था। उसके बाद एक अन्य नोटिस इस वर्ष 2 मई को रेलवे पुलिस की ओर से दिया गया। रेलवे पुलिस उस जमीन का रखरखाव करती है जहां बिलबोर्ड खड़ा किया गया था। वहां यह होर्डिंग लगाने के लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया था। 13 मई को यानी घटना के दिन भी कंपनी को एक नोटिस दिया गया था जिसके मुताबिक बिलबोर्ड को बिना बीएमसी की समुचित स्वीकृति के खड़ा किया गया था।

इन नोटिसों से अफसरशाही की जरूरी खानापूर्ति हो सकती है लेकिन उनसे यह नहीं स्पष्ट होता है कि आखिर क्यों इस समस्या पर ध्यान जाने में करीब दो वर्ष का समय लगा और यह भी कि आखिर नोटिस देने के बाद भी कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। बिलबोर्ड अप्रैल 2022 से लगा हुआ था। कम से कम यह पूरा सिलसिला बीएमसी की कार्यक्षमता पर भी तो सवाल पैदा करता है। परंतु इन चीजों से कहीं अधिक धूल भरे तूफान के कारण हुई यह दुर्घटना बताती है कि नगर निकायों के अधिकारियों द्वारा कर्तव्यपालन में विफल रहने के कारण शहरों में रहने वाले नागरिक किस कदर मुश्किल में पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए 2017 में भी दक्षिण मुंबई से केवल 10 किलोमीटर दूर एक वाणिज्यिक परिसर में रूफटॉप रेस्टोरेंट में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में हुई जांच से पता चला कि रेस्टोरेंट में फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे, बुनियादी अग्निशमन उपकरण मसलन आग बुझाने वाले सिलिंडर और आग की स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते नहीं थे। इसके बावजूद अग्निशमन विभाग ने उसे तथा करीब स्थित एक अन्य खानपान की दुकान को समुचित ढंग से प्रमाणित किया था। हालांकि बाद में महानगरपालिका तथा अग्निशमन विभाग के कई संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई थी।

यह कहानी देश के तमाम शहरों की है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेड़ों के इर्दगिर्द बिना सोचे-समझे कंक्रीट बिछा दिया गया है जिससे उनकी जड़ें कमजोर हुई हैं। इससे हर वर्ष मॉनसून के पहले सैकड़ों पुराने पड़े उखड़ जाते हैं और लोगों की जान जाती है अथवा संपत्ति का नुकसान होता है। इसी तरह मॉनसून के पहले नालियों की सफाई जैसे कदम नहीं उठाने के कारण देश के कई शहरों में अक्सर बाढ़ आती है और पैदल चलने वाले तमाम लोगों को नंगे तारों के कारण बिजली के झटकों से जान गंवानी पड़ती है। शहरी नागरिकों को मौसमी मार का जितना खतरा है उतना ही खतरा उन्हें ऐसी इमारतों से भी है जिन्हें शिथिल अधिकारियों की वजह से नियामकीय मंजूरी मिली है लेकिन जो ढह रही हैं। जलवायु परिवर्तन ऐसे खतरों में इजाफा करता है।

अजय मोहंती

अर्थव्यवस्था के लिए सही लचीली विनिमय दर

अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाए रखने में लचीली विनिमय दर की अहम भूमिका होती है जो झटकों को बरदाश्त करने की काबिलियत रखती हो। बता रहे हैं अजय शाह

विनिमय दर का लचीलापन झटके को बरदाश्त करने में मददगार होता है। जब बाहरी या आंतरिक झटके लगते हैं तो इसका कुछ बोझ लचीली विनिमय दर भी वहन करती है। जब विनिमय दर का समायोजन नहीं होता है तो समायोजन का अधिक बोझ शेयर कीमतों, अचल संपत्ति की कीमतों और कंपनी की बुनियादी बातों पर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपया 2022 के अंत से कहीं अधिक नियंत्रित है। इससे हमें यह समझ बनाने में मदद मिलती है कि भविष्य में किस प्रकार के झटके देखने को मिल सकते हैं।

भारत दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही सीमा पार गतिविधियों को सीमित रखता आया है। आम जन से लेकर अर्थशास्त्र के विद्वानों और आय कर अधिकारियों तक ने आर्थिक आजादी और आत्मनिर्भरता को ही आधार बनाया। सन 1990 के दशक में जब पूंजी पर नियंत्रण कम होने लगा तो कई लोगों का प्राथमिक डर यही था कि पूंजी की आवक तो ठीक है लेकिन अगर सभी संस्थागत विदेशी निवेशक (एफआईआई) एक दिन बिकवाली करके चले गए तो क्या होगा?

न तो भारतीय और न ही एफआईआई कोई ऐसा समूह हैं जो अकेले दम पर कदम उठाएं। बाजार में हजारों कारोबारी हैं और एक ही समय में कई लोग खरीदने और बेचने का काम कर रहे होते हैं। जब बुरी खबरें आती हैं फिर चाहे वे भारत में हों या विदेश में, तो शेयर कीमतें या अचल संपत्ति की कीमतों में कमी आती है। परिसंपत्ति कीमतों की यह गिरावट खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आर्थिक समुदाय ने वर्षों के दौरान धीरे-धीरे इन सवालों को लेकर भरोसा हासिल किया और यह भय समाप्त हुआ कि विदेशी निवेशक एक दिन अचानक अपना निवेश निकाल लेंगे।

उसके बाद विनिमय दर की बात आती है। मान लेते हैं कि विदेशी निवेशक भारतीय परिसंपत्तियों की विशुद्ध रूप से बिकवाली करते हैं। उनकी प्राप्तियां रुपये में होती हैं और वे उन्हें अमेरिकी डॉलर में बदलने के लिए मुद्रा बाजार जाते हैं। अल्पावधि के पूंजी प्रवाह के लिए कमजोर रुपये की आवश्यकता होती है। वह विदेशी मुद्रा बाहर जा रहे विदेशियों को दे दी जाती है। भारत से बाहर जाने वाले विदेशियों को तब दो स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ता है: भारतीय परिसंपत्तियां कम कीमतों पर बिकती हैं और मुद्रा बाजार में भी कमजोर कीमत मिलती है।

अगर रुपये को कृत्रिम ढंग से स्थिर रखी जाए तो क्या होगा। अगर रुपया संकट के इस दौर में उछले नहीं तो क्या होगा? यह ऐसा होगा मानो भारतीय परिसंपत्तियों से बाहर जाने वाले विदेशियों के लिए लाल गलीचा बिछाया जा रहा हो। यह समझना मुश्किल है कि क्यों भारतीय राज्य को ऐसी जोखिम प्रबंधन सेवा विदेशियों को देनी चाहिए।

कीमतों का लचीलापन (शेयर कीमतें, बॉन्ड कीमतें, अचल संपत्ति कीमतें, विनिमय दर) वित्तीय व्यवस्था में झटके कम करता है। जब बुरी खबर आती है तो ये कीमतें प्रतिक्रिया देती हैं। वास्तविक अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम पाते हैं कि विनिमय दर में उतारचढ़ाव की दूसरी परत झटके सहने का काम करती है। जब बुरी खबर आती है तो रुपये का अवमूल्यन होता है। इससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और निर्यात कंपनियों के कारोबार का आकार भी बढ़ता है। आयात महंगा होता है जिससे उन कंपनियों को मदद मिलती है जिन्हें आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। वैश्वीकृत उत्पादों की कीमत कमजोर विनिमय दर के साथ ऊपर जाती है। इससे उन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों की कारोबारी हालत सुधरती है। मूल्य व्यवस्था में विनिमय दर सबसे अहम है। इसमें लचीलापन स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए अहम है।

जब हमारे पास लचीली विनिमय दर नहीं होती है तब ये सारे विचार उलटे साबित होते हैं। जब भारत सरकार खबरों को रोज विनिमय दर को आकार देने से रोकती है। जब बुरी खबरों के बीच वास्तविक अर्थव्यवस्था को कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन का साथ नहीं मिलता है। जब मुश्किल खबरों के बीच स्थिर विनिमय दर लाल गलीचे की तरह व्यवहार करती है और विदेशी निवेशकों को अपनी प्रतिभूतियों या अचल संपत्ति की बिकवाली करते समय लाभ होता है। यह बात वित्तीय बाजार कीमतों पर समायोजन का दबाव डालती है जो सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर अचल संपत्ति या प्रतिभूति में बड़ी गिरावट आती है।

अक्टूबर 2022 के आरंभ में अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया 82.8 तक पहुंच गया और तब से इसमें खास परिवर्तन नहीं आया है। हम डॉलर और रुपये की तयशुदा विनिमय दर के नए दौर में हैं। यह विनिमय दर व्यवस्था में एक अहम बदलाव था। उस समय इस निर्णय या इसके पीछे के तर्क को लेकर कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी। यह पता नहीं है कि मौद्रिक नीति समिति को इस बारे में बताया गया था अथवा नहीं।

किसी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह घरेलू चीजों पर केंद्रित मौद्रिक नीति, विनिमय दर नियंत्रण और खुले पूंजी खाते के रूप में तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकतीं। इन तीनों को साथ लाने की कोशिश एक वृहद आर्थिक मुश्किल पैदा करती है। बीते 20 महीनों में कई नीतिगत कदम एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के लिए हेजिंग अथवा एलआरएस पर रोक आदि रणनीतिक कदम उठाए गए हैं।

इसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा झटका सहन करने का एक उपाय गंवा देने का विचार हमें बीते 20 महीनों को समझने में मदद करता है। इस अवधि में मजबूत डॉलर के कारण रुपये में कुछ अवमूल्यन होता जिससे निर्यात क्षेत्र को मदद मिलती। विनिमय दर तमाम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय झटकों से राहत दिलाती है। उदाहरण के लिए शायद लाल सागर के मार्ग से व्यापार में कठिनाई के कारण लचीली विनिमय दर में मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। महामारी के बाद निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई लेकिन 2022 में उसका बढ़ना भी बंद हो गया। 2022 के बाद से प्रति माह करीब 55 अरब डॉलर का निर्यात हो रहा है। इसमें गैर तेल, गैर स्वर्ण वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात शामिल है।

कई बार चुनाव नतीजों ने भी परिसंपत्ति कीमतों को गति प्रदान की है। उदाहरण के लिए जब 2004 में कांग्रेस को जीत मिली थी तब शेयर कीमतों में गिरावट आई थी और 2009 में जब दोबारा पार्टी जीती तो बाजार में उछाल नजर आई। जब तक विनिमय दर ऐसी घटनाओं के समय स्थिर रहेगी, शेयर बाजार की अस्थिरता तेज रहेगी। लचीली और मजबूत अर्थव्यवस्था वही होती है जिसमें झटके सहन करने की शक्ति हो। जहां बुरी खबर से रुपये और शेयर कीमतों में गिरावट आए तथा अच्छी खबर से इसका उलटा हो।

(लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं)

गुणवत्ता वाली मानसिकता के अभाव की वजह?

दवा उद्योग कई वर्षों तक खराब वजहों से चर्चा में रहा और अब भारतीय दवा नियामक ने कदम उठाने का फैसला किया है।

दवा उद्योग नकली और घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं (एनएसक्यू) के घरेलू बाजार में खुलेआम बेचे जाने से लेकर भारतीय कंपनियों द्वारा निर्यात की गई दवाओं से कई देशों में सैकड़ों लोगों की मौत के चलते सुर्खियों में रहा।

वर्ष 2023 के अंत में सरकार और दवा नियामक, भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने यह आदेश दिया कि सभी दवा निर्माताओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की बेहतर विनिर्माण प्रक्रिया (जीएमपी) के मानकों का पालन करना होगा, चाहे उनका दायरा कैसा भी हो। दवा निर्माताओं को इस साल के अंत तक डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणन हासिल करने की आवश्यकता होगी।

इस बदलाव से पहले केवल अमेरिका या यूरोपीय देशों को भेजी जाने वाली भारतीय दवाओं के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि वे विकसित देशों के गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरती हैं। यूएस फूड ऐंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) भी उन भारतीय दवा निर्माताओं के दवा कारखाने का निरीक्षण करता था जो अपनी दवाओं का निर्यात अमेरिका में करना चाहते थे। इस प्रमाणन के बिना भारत के दवा निर्माता अमेरिका में दवा नहीं बेच सकते थे।

इस बीच, भारत का एक अन्य विनिर्माण क्षेत्र भी कुछ गलत वजहों से सुर्खियों में है। दरअसल सिंगापुर और हॉन्ग कॉन्ग ने हाल ही में एमडीएच और एवरेस्ट जैसे दो प्रमुख भारतीय मसाला ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि उनके मसाले में कार्सिनोजेन, एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) की मात्रा स्वीकार्य स्तर से कहीं अधिक है।

इस क्षेत्र के नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने तेजी से काम किया लेकिन इसकी कार्रवाईयों ने कई पेचीदा सवाल खड़े कर दिए। एफएसएसएआई ने देश में बनाए जाने वाले सभी मसालों के परीक्षण के आदेश दे दिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इसके मानकों का पालन करते हैं।

साथ ही मसाला बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि निर्यात वाले सभी मसालों के लिए ईटीओ के स्तर का परीक्षण किया जाए। यह अच्छी बात थी। हालांकि, जल्द ही बिज़नेस स्टैंडर्ड सहित कई समाचार पत्रों में बताया गया कि सिंगापुर और हॉन्ग कॉन्ग द्वारा एमडीएच और एवरेस्ट में ईटीओ के स्तर को लेकर चिंता जताए जाने से पहले एफएसएसएआई ने जड़ी बूटियों और मसालों में कीटनाशकों के अनुमति वाले मानकों में दस गुना की छूट दी थी। एफएसएसएआई ने अपने बचाव में कहा कि उसने विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही कीटनाशक की सीमा बढ़ाई। इसके अलावा, रिपोर्टों से पता चलता है कि नियामक भारत में बेचे जा रहे मसालों की ईटीओ सीमा के बारे में चिंतित हो यह जरूरी नहीं है बल्कि यह निर्यात किए जाने वाले मसालों के मामले में संभव हो सकता है।

प्रसेनजित दत्ता

तीसरे उद्योग में, वाहन उद्योग की बात की जा सकते हैं जिसमें भारत ने आखिरकार वैश्विक कार मूल्यांकन योजना के आधार पर भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनसीएपी) को लागू करने की दिशा में कदम उठाया। नई कारों का परीक्षण दुर्घटना की स्थिति में उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए किया जाएगा। ऐसा होने से पहले, भारतीय कार ग्राहकों को इस बात का उतना अंदाजा नहीं था कि उनकी कारें संरचनात्मक रूप से कितनी सुरक्षित हैं।

पिछले तीन दशकों में लगातार सरकारों के प्रयासों और योजनाओं के बावजूद, भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में नाकाम रहने के कई कारण बताए गए हैं। लॉजिस्टिक्स और बिजली लागत अधिक रहने, श्रम उत्पादकता कम होने और स्थानीय नियमन से जुड़े मुद्दों पर अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन कई भारतीय उत्पादों की निम्न गुणवत्ता मानक पर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता है।

केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के नियामकों ने भारत में बने और बेचे जा रहे सामान की गुणवत्ता पर या यहां तक कि लातिन अमेरिका, अफ्रीका या एशिया के कम विकसित देशों को निर्यात किए जा रहे सामानों पर भी अक्सर बहुत कम ध्यान दिया है।

ऐसा नहीं है कि भारतीय निर्माता उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद नहीं बना सकते हैं। किसी भी क्षेत्र की कोई भी विनिर्माण इकाई जो अमेरिका, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया आदि में निर्यात करती है, वह इन बाजारों के उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा करेगी। वे जिन सामान का निर्यात करते हैं उनकी गुणवत्ता, घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले सामानों की तुलना में काफी बेहतर होती है। ऐसा भी नहीं है कि भारत की नियमन प्रणाली हमेशा ढीली ही होती है लेकिन कई क्षेत्रों में ऐसा ही तस्वीर है। भारतीय नियामक आमतौर पर वैश्विक चलन और मानदंडों के आधार पर अपने नियमन की रूपरेखा तैयार करते हैं। हालांकि दवाओं या खाद्य पदार्थों से जुड़े कुछ भारतीय मानक, विकसित देशों के मानक जितने सख्त नहीं होते हैं लेकिन कुछ अन्य मानक उनकी तुलना में सख्त होते हैं।

असल समस्या, अक्सर संस्थागत क्षमता से जुड़ी होती है। ऐसे में सभी दवा कंपनियों को डब्ल्यूएचओ जीएमपी का पालन करने के लिए आदेश दिया जाना ज्यादा मददगार नहीं होता है। खासतौर पर तब जब आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि कंपनियां वास्तव में केवल प्रमाणन के वक्त पर नहीं बल्कि नियमित रूप से मानकों का पालन कर रही हैं।

इसी तरह, सिर्फ निर्यात वाले मसालों पर ही ईटीओ और कीटनाशकों जैसे अन्य दूषित तत्त्वों के लिए कड़ी जांच का कोई मतलब नहीं है जब घरेलू ग्राहकों को इसी तरह के उत्पादों का उपभोग करने दिया जाता है जो घटिया या दूषित होते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पास पूंजी और संसाधनों की कमी जैसे तर्क वास्तव में नीति निर्माताओं और नियामकों की निष्क्रियता और सोच-विचार में कमी का नतीजा है। पर्याप्त स्तर पर प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाएं स्थापित करना, पर्याप्त योग्य निरीक्षकों को काम पर रखना और छोटे उद्यमों को बेहतर गुणवत्ता वाला बनाने में मदद करना दरअसल सरकार और नियामकों का ही काम है।

यह तर्क भी ठीक नहीं है कि गुणवत्ता मानकों को पूरा करने से लागत बढ़ जाएगी। बिजली लागत और सरकारी करों को कम करके लागत प्रतिस्पर्धा लॉजिस्टिक्स में सुधार किया जा सकता है और इसके लिए गुणवत्ता मानकों से समझौता करने की भी जरूरत नहीं है।

सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों के कारण भारत में अधिकांश कारों की कीमत, विकसित बाजारों की तुलना में अधिक होती है। विदेशी बाजारों के ग्राहकों की तुलना में घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के मामले में नुकसान उठाना पड़ता है, भले ही समान विनिर्माण संयंत्र में दोनों बाजारों के लिए वाहन बनाए जा रहे हों।

हर वह देश जो एक बड़ी विनिर्माण शक्ति बना है, उसने अपने उत्पादों के गुणवत्ता मानक के स्तर को बढ़ाया है और यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू ग्राहकों को गुणवत्ता के मामले में नुकसान न उठाना पड़े।

भारतीय नीति निर्माताओं को इसे समझने की जरूरत है। इसी तरह, कॉरपोरेट जगत को भी यह समझने की जरूरत है कि गुणवत्ता से जुड़ी मानसिकता को अपनाए बिना वे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने की आकांक्षा कभी नहीं कर सकते हैं।

(लेखक बिज़नेस टुडे और बिज़नेस वर्ल्ड के पूर्व संपादक और संपादकीय परामर्श संस्था प्रोजैक व्यू के संस्थापक हैं)

आपका पक्ष

चाबहार बंदरगाह पर समझौते से होगा फायदा

भारत द्वारा ईरान के चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किया गया 10 वर्षीय समझौता उल्लेखनीय उपलब्धि है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले चाबहार बंदरगाह को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का माकूल जवाब है जिसे चीन और पाकिस्तान मिलकर तैयार कर रहा है। ग्वादर बंदरगाह चाबहार बंदरगाह से सड़क के रास्ते मात्र 400 किलोमीटर दूर है जबकि समुद्र के रास्ते इसकी दूरी केवल 100 किमी है। यह समझौता इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स ऐंड मैरीटाइम ऑर्गेना-इजेशन ऑफ ईरान के बीच हुआ है। इस समझौते से बंदरगाह में बड़े निवेश का रास्ता खुलेगा तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी इससे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के लिए भी रास्ते खुलेंगे। इस समझौते के लिए दोनों देशों के बीच पिछले तीन साल से वार्ता चल रही थी। यह बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी बेहद अहम है। चीन की अरब सागर में मौजूदगी को चुनौती देने के लिहाज से भी भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। रणनीतिक लिहाज से भी ग्वादर बंदरगाह में चीनी मौजूदगी भारत के लिए चुनौती है। ऐसे में चाबहार बंदरगाह में अपनी मौजूदगी भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस समझौते के तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड करीब 12 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद भारत का मध्य एशिया से सीधा संपर्क घट गया था। चाबहार के रास्ते भारत अब जरूरत पड़ने पर काबुल तक भी अपनी पहुंच बना पाएगा और साथ ही मध्य एशियाई देशों से व्यापार में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

विमलेश पगारिया, बदनावर

पिछले दिनों भारत ने ईरान के चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय समझौता किया

कचरे से अर्थव्यवस्था बढ़ाने में मिलेगी मदद

कचरा भारत की आर्थिक स्थिति और बेहतर करने में सहायक हो सकता है। बस हमें कचरे के निस्तारण की बेहतरीन व्यवस्था करनी होगी। हमें कचरा कम से कम उत्पन्न करने की आदत डालनी होगी। प्रत्येक जगह गीला या सूखा कचरा हमेशा अलग-अलग होगा तो कचरे के उपयोग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। दोनों प्रकार के कचरों की अलग-अलग व्यवस्था को नियमितता के साथ प्रभाव में लाने की आवश्यकता हैं। कूड़ा बीनने वालों के प्रति दृष्टि अच्छी रखें। देश का प्रत्येक काम कर सकते वाला व्यक्ति यदि रोजगार युक्त हो जाए, तो देश की आर्थिक उन्नति अवश्य होगी। सरकार समय-समय पर कचरा निस्तारण की कई योजनाएं चलाती हैं। हम सब को सामूहिक प्रयास करने होंगे। कचरे का प्रबंधन करके अच्छी कमाई की जा सकती है। कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक दिन हजारों टन कचरे के सही निस्तारण नहीं होने से चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय का इस विषय पर टिप्पणी इसकी गंभीर आवश्यकता को इंगित करता है।

इंदु, जयपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट बुधवार को जारी करने के साथ 14 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदनों पर ऑनलाइन मंजूरी के बाद 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे। इसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कोयला पर घटती निर्भरता

शेष विश्व की तरह भारत भी बिजली उत्पादन के लिए लंबे समय से कोयले पर निर्भर रहा है. तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन भी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति का बड़ा आधार रहे हैं. ये स्रोत बड़े पैमाने पर प्रदूषण के कारण रहे हैं. कोयले के खनन और ढुलाई से भी पर्यावरण को नुकसान होता है तथा तेल एवं गैस की खरीद पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है. देश में गैस और तेल उत्पादन से भी अनेक समस्याएं पैदा होती हैं. पर स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग में बढ़ोतरी से इनके उपयोग में उत्साहजनक कमी आने लगी है. साल 1966 के बाद यानी लगभग छह दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे आयी है. इस वर्ष जनवरी से मार्च की अवधि में देश में 13,669 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गयी है, जो एक रिकॉर्ड है. इस क्षमता में स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा 71.5 प्रतिशत है. स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है. इंस्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि भारत सरकार ने 2030 तक बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों के योगदान को 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया था. उस समय सीमा से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठोस आधार तैयार हो रहा है. यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी विकास आकांक्षाओं तथा बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए ऊर्जा की बड़ी आवश्यकता है. इस कारण जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता स्वाभाविक है तथा अभी कई वर्षों तक हमें उनकी जरूरत है. फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु संकट के समाधान के लिए स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहे हैं. यह बड़े संतोष की बात है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कोयले के इस्तेमाल का अनुपात घटता जा रहा है. जी-7 के देशों में पिछले साल कोयले की मांग 1900 के बाद सबसे कम रही. समूह में शामिल विकसित देशों ने बीते माह 2035 तक कोयले से बिजली उत्पादन को पूरी तरह बंद करने का संकल्प लिया है. धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित रखने के लिए उत्सर्जन अत्यंत निम्न स्तर पर लाना जरूरी है. इस दिशा में यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है. इस प्रक्रिया में भारत विश्व के समक्ष एक आदर्श उदाहरण के रूप में स्थापित हुआ है. सरकार स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए जहां आम लोगों को प्रोत्साहित कर रही है तथा घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सहयोग कर रही है, वहीं बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बड़ी परियोजनाओं को भी साकार किया जा रहा है.

साल 1966 के बाद यानी लगभग छह दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे आयी है.

बेहद महत्वपूर्ण है चाबहार समझौता

अनिल त्रिगुणायत
पूर्व राजदूत
amb.trigunayat@gmail.com

भारत पहले से ही रूस और ईरान के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए प्रयासरत है. इसी क्रम में चाबहार बंदरगाह की योजना बनी, जिस पर 2003 से काम चल रहा है. भारत ने उस बंदरगाह में शहीद बहिश्ती टर्मिनल को बनाया है और अनेक भारतीय कंपनियां संबंधित परियोजनाओं से जुड़ी हुई थीं. लेकिन काम अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा था क्योंकि ईरान पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगा दिये गये थे.

भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के संचालन और प्रबंधन तथा परियोजना के आगामी चरण के विकास के लिए हुआ दीर्घकालिक समझौता एक महत्वपूर्ण परिघटना है. यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहमियत रखता है. पाकिस्तान के साथ खराब संबंध के कारण अफगानिस्तान और मध्य एशिया से हमारा संपर्क एक तरह से पूरी तरह कट गया है. कुछ समय पहले जब भारत 50 हजार टन अनाज मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान भेजना चाहता था, तब पाकिस्तान ने बहुत दिनों तक रास्ता देने में कोताही की थी, जबकि उसका दावा है कि वह अफगानिस्तान का दोस्त है. ऐसे में हमारे लिए एक वैकल्पिक मार्ग आवश्यक हो जाता है. भारत पहले से ही रूस और ईरान के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए प्रयासरत है. इसी क्रम में चाबहार बंदरगाह की योजना बनी, जिस पर 2003 से काम चल रहा है. भारत ने उस बंदरगाह में शहीद बहिश्ती टर्मिनल को बनाया है और अनेक भारतीय कंपनियां संबंधित परियोजनाओं से जुड़ी हुई थीं. लेकिन काम अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा था क्योंकि ईरान पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगा दिये गये थे.

हालांकि चाबहार बंदरगाह परियोजना तकनीकी रूप से प्रतिबंधों के दायरे में नहीं थी, लेकिन अनेक कंपनियों ने अमेरिकी पाबंदियों की आशंका से काम की गति को बहुत धीमा कर दिया था. इसी बीच पाकिस्तान ने चाबहार के नजदीक ही चीन के सहयोग से ग्वादर बंदरगाह बनाने का काम प्रारंभ कर दिया. वह परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा योजना का हिस्सा है और उसमें सऊदी अरब का भी बहुत निवेश है. चाबहार में काम धीमा होने के बावजूद भारत और ईरान के बीच परियोजना के बारे में बातचीत होती रही थी. पहले हर साल समझौते का नवीनीकरण होता था तथा भारतीय कंपनी इंडिया ग्लोबल पोर्ट लिमिटेड शहीद बहिश्ती टर्मिनल को संभालती थी. लेकिन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक व्यवस्था की आवश्यकता थी. इस साल जनवरी में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान गये थे, तब इस मसले पर ईरानी राष्ट्रपति रईसी और संबंधित मंत्रियों से उनकी चर्चा हुई थी. उसी समय यह तय हुआ था कि ईरान पूरे चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन एवं संचालन का जिम्मा भारत को देगा. उस दौरे में भारत ने 120 मिलियन डॉलर के निवेश तथा 250 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण के लिए सहमति दी थी. दोनों देशों ने यह भी तय किया है कि यह बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर का हिस्सा भी होगा. इस बंदरगाह के माध्यम से हमारे लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का सरल रास्ता मिल जायेगा. अब इसके लिए हमें पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं होगी. उन देशों को भी भारतीय बाजार और हिंद महासागर से जुड़ने का अवसर मिल सकेगा.

यह बहुत अजीब बात है कि समझौते होने के साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग का एक बयान आ गया कि जो देश ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखेंगे, उन्हें भी प्रतिबंधों के दायरे में लाया जा सकता है. अमेरिका को यह अच्छी तरह से मालूम है कि अफगानिस्तान को मदद की दरकार है ताकि वह संकट और अस्थिरता से निजात पा सके. मध्य एशिया खुद अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह वहां पैठ बनाने की कोशिश भी कर रहा है. अगर वह भारत के साथ मिलकर मध्य एशिया से अपने जुड़ाव को बेहतर करता, तो वह अच्छी बात होती. चाबहार परियोजना में यदि वे भारत के लिए अवरोध पैदा करते हैं, तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित ही कहा जायेगा. पहले उसने चाबहार परियोजना को पाबंदियों के दायरे से बाहर रखा था. उसे आगे भी ऐसा ही रवैया अपनाना चाहिए. अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह जिस डाल पर बैठा हो, उसे ही काटने लगे. जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है, अमेरिका भी मानता रहा है कि चाबहार परियोजना पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद है. इसी समझ के कारण इसे प्रतिबंधों से अलग रखा गया था. अमेरिका के हालिया बयान से यही संकेत मिलता है कि वह इस परियोजना पर भी पाबंदी लगाने के चक्कर में है. अपने भू-राजनीतिक एजेंडे के तहत अगर अमेरिका ऐसा करता है, तो इससे भारत को नुकसान तो होगा, उसको भी कोई लाभ नहीं होगा.

अमेरिका चाहे जो कहे, भारत चाबहार बंदरगाह को लेकर गंभीर है. अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापक रणनीतिक समझौता है. इसके प्रावधानों और प्रक्रियाओं के तहत दोनों पक्षों में इस मसले पर बातचीत होगी. तब भारत उसके समक्ष इस परियोजना के बारे में समुचित जानकारी रखेगा और आशा है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक होगी. इस संबंध में भारत को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है. मूल बात यह है कि हमें अपने हितों को प्राथमिकता देनी है. मध्य एशिया से जुड़ाव और इंटरनेशनल कॉरिडोर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. इसमें चाबहार एक आवश्यक कड़ी है. अगर अमेरिका अपनी बात पर अड़ा भी रहता है, तब भी इस परियोजना से भारत के हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता. अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता एक जरूरी मुद्दा है. इसमें भारत उल्लेखनीय योगदान दे सकता है. मध्य एशिया के देश लंबे समय से चीन और रूस के बीच झूलते रहे हैं. उन्हें भी दूसरे देशों की जरूरत है. वे भारत से संबंध बढ़ाने के साथ-साथ तुर्की और अमेरिका से भी निकटता बढ़ा रहे हैं.

मेरा मानना है कि अमेरिका वैसे तो बयानबाजी करेगा, पर आखिरकार वह यह समझेगा कि उसने पहले चाबहार को महत्वपूर्ण क्यों कहा था और क्यों इसे पाबंदियों से अलग रखा था. यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि रूस और ईरान ऐसे देश हैं, जिन पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ढेरों प्रतिबंध लगाये हैं. इन देशों को अगर कोई फायदा होता दिखेगा, तो अमेरिका जरूर अड़ंगा लगाने की कोशिश करेगा. अनेक पाबंदियों का असर अन्य देशों पर भी होता है. यह पहलू एक बड़ी चुनौती है और हमें इसे लेकर सावधान रहना होगा. सरकार यह नहीं कहती कि उसे परेशानी है, लेकिन निजी कंपनियों को अपने नुकसान का अंदेशा रहता है. इसलिए वे दबाव की स्थिति में पीछे हट सकती हैं, जैसा हमने पहले देखा है. बहरहाल, चुनौतियों के बावजूद अभी यह उम्मीद बढ़ी है कि इस परियोजना का कामकाज तेजी से आगे बढ़ेगा तथा समूचे क्षेत्र को उसका फायदा मिलेगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

पीओके में बढ़ता जा रहा है जनता का गुस्सा

विवेक शुक्ला
वरिष्ठ पत्रकार
vivekshukladelhi@gmail.com

पाकिस्तान तो भारत के जम्मू-कश्मीर पर बार-बार अपना दावा करता है, पर दुनिया देख रही है कि उसके कब्जे वाला कश्मीर जल रहा है. पीओके का अवाम बिजली की भारी-भरकम बिलों और आटे के आसमान छूते दामों के कारण नाराज है.

जब हमारी कश्मीर घाटी में लोकसभा चुनाव का प्रचार जारी है, तब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के बहुत बड़े हिस्से में अवाम सड़कों पर है. जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से मात्र 130 किलोमीटर दूर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद और मीरपुर जैसे प्रमुख शहर में जनता सरकार से दो-दो हाथ करना चाहती है. जनता पीओके सरकार और देश की संघीय सरकारों से अपना हक मांग रही है. पीओके में जब आंदोलन चल रहा है, तब भारत के लोकसभा चुनाव की कैंपेन में पीओके का जिक्र हो रहा है. भाजपा नेता एवं गृहमंत्री अमित शाह ने बीते रविवार कहा कि पीओके भारत का है, हम उसे लेकर रहेंगे. पीओके को भारत में मिलाने को लेकर भारतीय संसद का एक अहम प्रस्ताव भी है.

पीओके की बिगड़ती स्थिति के कारण पाकिस्तान के रहनुमाओं की रातों की नींद उड़ गयी है. पाकिस्तान तो भारत के जम्मू-कश्मीर पर बार-बार अपना दावा करता है, पर दुनिया देख रही है कि उसके कब्जे वाला कश्मीर जल रहा है. पीओके का अवाम बिजली की भारी-भरकम बिलों और आटे के आसमान छूते दामों के कारण नाराज है. सोशल मीडिया के दौर में पीओके की जनता देख रही है कि भारत के कश्मीर के लोग कम से कम बिजली के बिलों या आटे की आसमान छूती कीमतों के कारण तो नाराज नहीं है. वहां अन्य मसले हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर जीवन सुकून भरा है. पीओके में ताजा हिंसक आंदोलन का तात्कालिक कारण है कि पाकिस्तान सरकार ने आटे की कीमतों को कम करने की मांग को मानने से इंकार कर दिया है. बिजली के बिल कम करने पर तो सरकार आंदोलनकारियों से बात करने को वैसे भी तैयार नहीं है. दरअसल, पीओके में बवाल तब शुरू हुआ जब अवामी एक्शन कमेटी ने आठ मई, 2023 को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किये थे. इससे पहले, बीते वर्ष अगस्त में बिजली बिल पर नये कर लगाने से स्थिति बिगड़ने लगी थी. करों के विरोध में मुजफ्फराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया जिन्हें स्थानीय व्यापारियों का समर्थन मिला. प्रदर्शन जल्दी ही रावलकोट और मीरपुर जिलों तक फैल गया. बीते वर्ष 17 सितंबर को मुजफ्फराबाद में एक बैठक के बाद आवामी एक्शन कमेटी ने आंदोलन को राज्यव्यापी करने का निर्णय लिया. इसके बाद पीओके में बिजली बिल जलाये जाने लगे. इससे नाराज सरकार ने कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया, पर जनता के दबाव में उन्हें रिहा कर दिया गया.

इसके बाद आंदोलनकारियों की तरफ से सरकार को 10 सूत्रीय मांगों की सूची सौंपी गयी. जिसमें आटे पर सब्सिडी और बिजली बिलों में कमी की मांगें शामिल थीं. पर सरकार इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हुई. इससे नाराज आवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद स्थित पीओके विधानसभा तक मार्च करने का आह्वान किया. नौ मई को डोडियाल में एक डिप्टी कमिश्नर पर उस समय हमला हुआ जब उन्होंने भीड़ को तितर-बितर करने के आदेश दिये. दस मई को पीओके के प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने निकले, जिससे गंभीर झड़पें हुईं. एक आला पुलिस अफसर की मौत हो गयी. इसके बाद से ही पीओके के मुख्यमंत्री अनवर उल हक सरकार को जनता के गुस्से से दो-चार होना पड़ रहा है. फिलहाल लगता तो यही है कि आवामी एक्शन कमेटी का अपनी मांगों के समर्थन में चल रहा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती. हां, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच रावलकोट में बातचीत फिर से शुरू जरूर हो गयी है. परंतु, यह देखने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान सरकार, जो पीओके सरकार के साथ खड़ी है, प्रदर्शनकारियों की मांगें स्वीकार करेगी? फिलहाल लगता तो नहीं है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेने के संकेत दे रहे हैं.

इस बीच, लगता है कि कांग्रेस नेता मणि शंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला को पीओके पर भारतीय संसद में पारित प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं है. बाइस फरवरी, 1994 विशिष्ट दिन है भारत की कश्मीर नीति की रोशनी में. उस दिन संसद ने एक प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर पीओके पर अपना अधिकार जताते हुए कहा था कि पीओके भारत का अटूट अंग है. पाकिस्तान को उसे छोड़ना होगा जिस पर उसने कब्जा जमाया हुआ है. यहां संसद के प्रस्ताव को संक्षिप्त रूप में लिखना सही रहेगा, 'सदन भारत की जनता की ओर से घोषणा करता है- (क) जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा. भारत के इस भाग को देश से अलग करने का हरसंभव तरीके से जवाब दिया जायेगा. (ख) भारत में इस बात की क्षमता और संकल्प है कि वह उन नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब दे जो देश की एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अंखडता के खिलाफ हों, और मांग करता है- (ग) पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के उन इलाकों को खाली करे जिसे उसने कब्जाया हुआ है.' बहरहाल, यह आने वाला समय ही बतायेगा कि पीओके में चल रहा आंदोलन शांत होता है या नहीं. इसके अतिरिक्त, पीओके का भारत में विलय किस तरह से होगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

निवेश के लिए सभी का एकजुट होना सकारात्मक संकेत

नेपाल के सात प्रमुख राजनीतिक दलों- सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों के वरिष्ठ नेताओं ने हाल ही में देश के निवेश और व्यापार माहौल को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता जतायी है. कांतिपुर आर्थिक शिखर सम्मेलन-2024 में नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा, सीपीएन-यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल, सीपीएन (माओवादी सेंटर) के उपाध्यक्ष पंपा भुसाल, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगडेन, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मुख्य सचेतक संतोष परियार, सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) के महासचिव घनश्याम भुसाल और जनमत पार्टी के अध्यक्ष सीके राउत ने निवेश को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक शक्तियों और अन्य हितधारकों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया. अभी दो सप्ताह पूर्व भी प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, मुख्य विपक्षी नेता नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा और प्रमुख गठबंधन सहयोगी सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित देश के शीर्ष नेताओं ने दो दिवसीय निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था. जिसमें नेपाल को निवेश-अनुकूल गंतव्य में बदलने की प्रतिबद्धता जतायी गयी थी. प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक शक्तियों द्वारा घरेलू व विदेशी निवेश और संयुक्त राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता का अहसास होना सकारात्मक संकेत है. हालांकि यह पर्याप्त नहीं है. क्योंकि नेपाली राजनेताओं ने बार-बार ऐसे वादे किये हैं, पर उनका कोई परिणाम नहीं निकला है. इसके लिए, नेपाल को अभी भी राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता तथा पूर्वानुमान की आवश्यकता है. कांतिपुर आर्थिक शिखर सम्मेलन में भी व्यापारिक समुदायों के प्रतिनिधियों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तविक निवेशक बड़ा निवेश करने से पहले नीतिगत पूर्वानुमान को पूर्व शर्त के रूप में चाहते हैं. यह एक वैध चिंता है. नीति निर्माताओं को इसे सुनिश्चित करना चाहिए.

THE KATHMANDU POST
WITHOUT FEAR OR FAVOUR

बोधि वृक्ष

तन सबल, मन निर्मल

कुछ लोग समझते हैं कि पहले धनोपार्जन कर लेंगे, फिर बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और अन्य सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर साधना में जुट जायेंगे. यह भी सोचते हैं, वृद्धावस्था आते-आते अंग-प्रत्यंग शिथिल होने लगेंगे, काम करने की शक्ति नहीं रह जायेगी. इसलिए शक्ति रहते जरूरत भर धन उपार्जन नहीं कर लेंगे, तो वृद्धावस्था में सुख से कैसे रहेंगे. इस चिंता से बेचैन मनुष्य अपने जीवन को पहले धनोपार्जन में लगाता है और वृद्धावस्था आते-आते जब शरीर काम करने लायक नहीं रहता है, तब भगवान के नाम का जाप करने लगता है. यदि वृद्धावस्था आने से पहले ही जीवन समाप्त हो जाए तो? यह तो सभी जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी तय है. पर यह पता नहीं, किसकी मृत्यु कब होगी. प्रत्येक मनुष्य वृद्धावस्था तक जियेगा, यह भी निश्चित नहीं है. फिर कुछ लोग जीवन के सबसे महान कार्य- आध्यात्मिक साधना- बचे हुए जीवन में क्यों संपन्न करना चाहते हैं, जब सामर्थ्य ही खत्म हो जाता है. सामान्य तौर पर मनुष्य मृत्यु के भय से ही वृद्धावस्था में भगवान को स्मरण करता है. पूरे जीवन में किये गये बुरे कार्यों के भय से भयभीत और असहाय होकर ऐसे लोग भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं. वे भगवान से यही निवेदन करते हैं कि उनके कृत कर्मों के पाप से भगवान उन्हें बचा लें. परंतु भगवान के सामने तो तुम बुढ़ापा के जीर्ण देह और थके हुए मन लेकर जाते हो. जब भगवान को हम ताजा पुष्प, ताजा प्रसाद अर्पण करते हैं, तो मुरझाये मन और अस्वस्थ तन को लेकर उनके पास जाने का क्या मतलब? एक तरफ मन मृत्यु के डर से घबराया हुआ है, दूसरी तरफ मन में अनेक दोष समाया हुआ है. जब तक मन निर्मल और तन सबल न हो, साधना कैसे होगी? निष्कर्ष यह है कि सामर्थ्य रहते हुए, मन के निर्मल और तन के तरोताजा रहते हुए, जीवन के अन्य कर्मों के साथ साधना की राह पकड़ लेने में ही भलाई है. कौन जाने कब बुलावा आ जाए और जीवन की यह महत्वपूर्ण योजना धरी रह जाए.

-श्री श्री आनंदमूर्ति

कुछ अलग

नासूर बन गया है शहरों में ट्रैफिक जाम

सुधीर कुमार
टिप्पणीकार
sudhirphd@bhu.ac.in

डच कंपनी टॉमटॉम के छह महादेश के 55 देशों के 387 शहरों के सर्वेक्षण पर आधारित ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट- 2023 से पता चलता है कि 2022 की तुलना में 2023 में 387 शहरों में से 228 में सड़कों पर वाहनों की औसत गति में कमी आयी है. यही नहीं, 60 प्रतिशत से अधिक शहरों में 2021-23 के बीच ईंधन के औसत बजट में 15 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि देखने को मिली है. रिपोर्ट बताती है कि लंदन दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला शहर है, जहां 10 किलोमीटर की दूरी औसतन 37 मिनट, 20 सेकेंड में तय की जाती है. वहीं इस मामले में बेंगलुरु और पुणे क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर हैं, जहां उतनी ही दूरी क्रमशः 28 मिनट, 10 सेकेंड तथा 27 मिनट, 50 सेकेंड में पूरी होती है. डबलिन, टोरंटो, मिलान तथा दिल्ली व मुंबई जैसे भारतीय शहर भी यातायात संकुलन की चपेट में हैं.

भारत की 'सिलिकॉन सिटी' बेंगलुरु दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में शामिल होती जा रही है. बेंगलुरु में सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना कठिनाई भरा साबित हो रहा है. गौरतलब है कि बेंगलुरु के इतिहास में 27 सितंबर, 2023 का दिन सबसे व्यस्त रहा, जब शहर के आउटर रिंग रोड इलाके में भीषण जाम देखने को मिला था. उस दिन जाम में लगभग साढ़े तीन लाख वाहन फंसे थे. वाहनों ने एक किलोमीटर का सफर दो घंटे में तय किये थे. आलम यह था कि स्कूल से छूटे बच्चे रात में अपने घर पहुंचे थे. आज देश के कमोबेश छोटे-बड़े सभी शहर जाम की समस्या का सामना कर रहे हैं. शहरी यातायात में जाम नासूर बन चुका है. यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है. जाम समय की बर्बादी के साथ-साथ मानव की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है. ट्रैफिक जाम ड्राइवरों, यात्रियों और प्रमुख सड़क मार्गों के पास रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न बीमारी और परेशानियां उत्पन्न करता है. यह लोगों में तनाव और चिड़चिड़ापन के साथ श्वसन संबंधी बीमारियों को भी जन्म देता है.

मोटर वाहन को दुनियाभर में वायु प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक माना जाता है. वाहनों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे गैस वायु को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं. यह शहरों का औसत तापमान बढ़ाने में सहायक हैं. इस तरह जाम जलवायु परिवर्तन के लिए खतरा बनते हैं. यातायात संकुलन को कम किये बिना सतत विकास लक्ष्यों का हासिल करना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इससे मानव का स्वास्थ्य और कल्याण प्रभावित होता है.

आपके पत्र

चुनाव में उदासीन दिख रहे वोटर

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव का काफी महत्व है. लेकिन, इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाता उदासीन दिख रहे हैं. इसको लेकर भाजपा, कांग्रेस के अन्य दल चिंतित हैं. हालांकि, मतदान प्रतिशत में कमी के कई कारण हैं. इस बार चुनाव प्रचार में आम मतदाताओं के मुद्दे गायब हैं. साथ ही चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए गलत तरीके अपनाये जाते हैं. पैसे से वोट खरीदने का चलन हो गया है. यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं में अधिक उदासीनता देखी जा रही है.

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

तीन किमी लंबी सड़क में15 गड्ढे

भागलपुर शहर से अलीगंज जानेवाली सड़क में तीन किलोमीटर में 15 गड्ढे हैं. रोड को काटकर पानी का पाइप बिछाया गया है. सड़क पर हुए गड्ढों से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. इस पथ से हजारों वाहन हर दिन गुजरते हैं. नगर निगम क्षेत्र में यह स्थिति काफी चिंताजनक है. वरीय प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी एक बार इस पथ से सफर करना चाहिए, जिससे उन्हें सच्चाई का पता चले. नगर निगम को भी सड़क पर हुए गड्ढों को जल्द भरने का प्रयास करना चाहिए.

मिथिलेश कुमार, भागलपुर

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 16 मई 2024

AI की संभावनाएं

OpenAI ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में नया धमाका करते हुए सोमवार को LLM का लेटेस्ट वर्जन जारी किया, जिसे GPT 4o नाम दिया गया है। अभी दुनिया जेनरेटिव AI के मौजूदा मॉडलों द्वारा किए जाने वाले कमालों से उपज रहे अवसरों और जोखिमों को ही समझने की कोशिश कर रही थी कि इस नए टूल ने संभावनाओं की एक बिल्कुल नई खिड़की खोल दी है।

AI Image

OpenAI का GPT 4o

जेनरेटिव AI का नया दौर | GPT 4o की खासियत है कि यह टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज तीनों फॉरमेट में निर्देश लेते हुए अभूतपूर्व तेजी से रेस्पॉन्स दे सकता है। यह चेहरे के भाव भी पढ़ सकता है और वातावरण की ध्वनियों को भी संज्ञान में लेते हुए उन्हें समझ सकता है। इन वजहों से GPT 4o अब तक के AI मॉडलों से कहीं आगे की चीज हो गया है।

कई भूमिकाएं | इसके साथ इंटरएक्शन की संभावनाओं पर विचार करें तो एक ट्रांसलेटर, एक टीचर, एक वर्क असिस्टेंट, एक टुअर गाइड और किसी दृष्टि बाधित व्यक्ति की आंख जैसी भूमिकाओं में इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। रियलटाइम ट्रांसलेशन इसकी एक अहम विशेषता है, जो अलग-अलग भाषा जानने वाले लोगों के बीच सहज बातचीत को संभव बना सकती है। साफ है कि आने वाले समय में हम वैश्विक स्तर पर संवाद प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव देख सकते हैं।

प्रॉडक्टिविटी पर असर | इस बात को लेकर आम राय रही है कि AI और जेनरेटिव AI का इस्तेमाल प्रॉडक्टिविटी बढ़ाता है। इस सिलसिले में माइक्रोसॉफ्ट की ओर से LLM बेस्ड कोडिंग असिस्टेंट Copilot का इस्तेमाल करने वाले वर्करों के बीच हाल में करवाया गया एक रिव्यू बताता है कि Copilot यूज करने वाले वर्कर नॉन-यूजर्स के मुकाबले 26-73% ज्यादा तेजी से काम पूरा करते हैं।

सहायक या प्रतिद्वंद्वी | बड़ी बात यह है कि जो AI अब तक इंसान के सहायक की भूमिका में था, वह तेजी से उसकी जगह लेता दिख रहा है। वह न केवल इंसान की तरह बल्कि उससे ज्यादा तेजी से और उससे ज्यादा सटीकता से सोच, समझ और फैसले ले सकता है। इंसान से निर्देश लेने की उसकी जरूरत भी लगातार कम होती जा रही है।

निष्कर्ष में जल्दबाजी नहीं | ध्यान रखना होगा कि GPT 4o भी इस फील्ड की एक शुरुआती छलांग ही है। जिस तरह के प्रयोग चल रहे हैं, वे आने वाले वर्षों में हमारी दुनिया को किन स्तरों पर और कितना बदलेंगे, इसका अभी सही ढंग से अंदाजा भी नहीं लग सकता। इसलिए संभल कर और सोच-समझकर कदम बढ़ाना होगा। भारत के लिए इस पूरे मामले में सबक ये है कि उसे भी तेजी से जेनरेटिव AI पर काम करने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका और चीन जैसे देशों की तुलना में वह इस तकनीक में काफी पीछे है।

साड्डी दिल्ली

यहां के हम सिकंदर

विवेक शुक्ला

अब सदर बाजार की बस्ती हरफूल सिंह या गोल मार्केट में कौन होगा, जो कभी सिकंदर बख्त का पड़ोसी रहा होगा! वह गोल मार्केट के हैवलॉक स्क्वेयर में रहते थे। अब भी कुछ लोग हैं, जिन्होंने सिकंदर बख्त को शिवाजी स्टेडियम में हॉकी खेलते हुए देखा था। वह तेज-तर्रार फॉरवर्ड थे। दिल्ली हॉकी लीग में इंडिपेंडेंट क्लब से लंबे समय तक खेले। मैच के बाद दोस्तों संग भगत सिंह मार्केट की मिठाई की दुकानों में लस्सी पीना उन्हें पसंद था।

Shital Verma

लोकसभा चुनाव के दौर में सिकंदर बख्त एक खास संदर्भ में याद आते हैं। इस बार भी BJP, कांग्रेस या आप ने किसी मुसलमान को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। बख्त राजधानी दिल्ली से लोकसभा के लिए चुने गए इकलौते मुस्लिम सांसद थे। देश में 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। सब विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। सिकंदर बख्त की कांग्रेस (O) का भी जनता पार्टी में विलय हुआ था। उन्हें जनता पार्टी ने चांदनी चौक सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इमरजेंसी लगाने के कारण माहौल कांग्रेस के खिलाफ था। सिकंदर बख्त को चांदनी चौक से सफलता मिली। चुनाव के बाद केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। उसमें सिकंदर बख्त को शहरी विकास मंत्रालय का कामकाज सौंपा गया। जनता पार्टी सरकार में दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। वह विदेश मंत्री बनाए गए। सिकंदर बख्त बहुत जोशीले भाषण देते थे। वह अपने भाषणों में शेर-ओ-शायरी भी करते थे। मगर जनता पार्टी सरकार अपने शिखर के नेताओं की रोज की किच-किच के कारण गिर गई। उसके बाद 1980 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। सिकंदर बख्त फिर से जनता पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से लड़े। इस बार वह कांग्रेस उम्मीदवार भीखूराम जैन से 18 हजार वोटों से हार गए। भीखूराम जैन के पुत्र नरेन कहते हैं कि बख्त साहब बहुत पढ़े-लिखे और निहायत जहीन किस्म के इंसान थे। सिकंदर बख्त और भीखूराम जैन एक दौर में कांग्रेस में थे। दोनों में याराना था। दोनों 1952 में दिल्ली नगर निगम के लिए चुने गए थे। कांग्रेस 1969 में टूटी तो सिकंदर बख्त कांग्रेस (O) के साथ जुड़ गए। भीखूराम जैन कांग्रेस में ही रहे। सिकंदर बख्त ने आगे चलकर BJP जॉइन कर ली। वह अटल बिहारी वाजपेयी की 1996 में बनी 13 दिन की सरकार में विदेश मंत्री भी बने। बाद में केरल के राज्यपाल भी रहे। सिकंदर बख्त मुसलमानों की कुरैशी बिरादरी से थे। उन्होंने विभाजन के तुरंत बाद राज शर्मा से विवाह किया। राज जी भी सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थीं। उस विषाक्त समय में भी दिल्ली में उस अंतरधार्मिक विवाह का कहीं विरोध नहीं हुआ था। इस बात की गवाही देने वाले तो अब भी राजधानी में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे।

एकदा

काम आई मां की सीख

सन 1839 में न्यू यॉर्क के रिचफर्ड में एक साधारण परिवार में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने अपनी मेहनत और ऊंची सोच के दम पर अपना और अपने परिवार का नाम अमेरिका के अमीर उद्योगपतियों में जोड़ लिया। रॉकफेलर परिवार तब आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पारिवारिक हालात पर बात करते हुए एक दिन बालक जॉन को मां ने समझाया, 'देखो बेटा, जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत, सहनशीलता और जरूरत भर ही खर्च करने की आदत मनुष्य को ऊंचे मुकाम पर ले जाती है।' जॉन ने मां की बात की गांठ बांध ली। वह जब 16 साल के हुए तो उन्हें पुस्तक बेचने का काम मिला। उन्होंने वहीं वित्त और व्यवसाय को अच्छी तरह से समझा। 1859 में उन्होंने तेल उद्योग में कदम रखा। अपनी व्यापारिक समझ और निरंतर प्रयासों के दम पर 1870 में उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई। वह कंपनी इतनी बड़ी थी कि 19वीं सदी के अंत तक देश के तेल उत्पादन और वितरण का लगभग 90 फीसदी हिस्सा उसके कब्जे में था। जीवन के अंतिम दिनों में रॉकफेलर को मां की यह सीख याद आई कि जरूरत भर ही अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि अपनी कमाई का अतिरिक्त हिस्सा दान किया करेंगे। जल्दी ही दुनिया के स्तर पर बड़े दानदाता के रूप में उनका नाम दर्ज हो गया। जॉन डी रॉकफेलर की कामयाबी अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है उनकी दानशीलता की वजह से।

Subrata Dhar

संकलन : **दिलीप लाल**

बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के कमजोर पड़ने से बदल चुकी है यूपी में दलित पॉलिटिक्स

राजनीति में अब भी क्यों भटक रहे दलित

सुधा पाई

यूपी में 90 के दशक में जिस दलित राजनीति का बोलबाला था, वह एक दलित पार्टी के इर्द-गिर्द घूमती थी। अब यह सामाजिक न्याय और आर्थिक तरक्की की व्यापक मांग कर रही है, खासकर गरीब गैर-जाटव दलितों के बीच। बहुत-से दलितों को लगता है कि मायावती उनकी आर्थिक उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं।

किसे होगा फायदा | BSP के खिलाफ असंतोष का सबसे ज्यादा फायदा BJP उठा रही है। हिंदुत्व के बैनर तले विकास और सांस्कृतिक पहचान के वादों के साथ BJP अपनी नई राजनीति से दलितों को लुभा रही है। इस बीच, कई नए स्थानीय आंबेडकरवादी संगठन भी उभरे, जैसे कि भीम आर्मी। कभी दलितों की सबसे बड़ी पार्टी रही BSP अब अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। दलितों की आवाज अब भी बुलंद है, लेकिन वर्ग, विचारधारा और क्षेत्र के आधार पर बंट चुकी है। कुछ आंबेडकरवादी BSP के पक्ष में हैं और कुछ हिंदुत्ववादी BJP के।

भीम आर्मी | 2015 में भीम आर्मी और 2020 में आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ। BSP के प्रति मोहभंग के चलते अस्तित्व में आए दलित संगठनों में ये अहम हैं। इन दोनों की स्थापना की है चंद्रशेखर आजाद ने। आजाद जाटव हैं। वह यूपी में नई दलित राजनीति का चेहरा हैं।

आजाद की सीमा | आजाद ने अत्याचारों के खिलाफ लड़कर, आंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए साइकल यात्राएं निकालकर और दलित बच्चों के लिए स्कूल खोलकर जाटव युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 उभरते नेताओं में शुमार किया है। हालांकि उनकी भीम आर्मी अभी केवल पश्चिमी यूपी तक सीमित है। इसी तरह पूर्वांचल में आंबेडकर जन मोर्चा बना, जिसकी अगुआई श्रवण कुमार निराला कर रहे हैं। बुंदेलखंड में दद्दू प्रसाद के नेतृत्व में बहुजन मुक्ति पार्टी शुरू हुई। ये दोनों ही BSP के नेता रह चुके हैं। दोनों संगठनों की सक्रियता सिर्फ स्थानीय स्तर पर है।

दलित वोटों की लड़ाई

- यूपी में उभरे नए क्षेत्रीय दलित संगठन
- कई धड़ों में बंट चुके हैं दलित वोटर
- इनका एक वर्ग आया BJP के साथ

BJP का गणित | जहां तक BJP का सवाल है तो उसे मिलने वाले दलित समर्थन की कहानी जटिल है। यह ऊंची जाति के अत्याचारों के विरोध के साथ-साथ व्यावहारिक पसंद से भी प्रभावित होती है। छोटी दलित जातियां लंबे समय से उन पार्टियों को पसंद करती रही हैं, जो स्थानीय दबंग जातियों से उनकी सुरक्षा कर सकें। 1990 के दशक में BSP ने प्रभावी ढंग से यह काम किया, लेकिन आज कई दलितों को लगता है कि BJP ही उनके हितों की सबसे अच्छी तरह से रक्षा कर सकती है।

AI Image

वोटों में बंटवारा | यूपी में BJP ऊंची जाति की पार्टी मानी जाती है। पर कई दलित अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए BJP के बजाय ऊंची जातियों को जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि सपा के शासनकाल में भी उन्हें वैसे ही अत्याचार झेलने पड़े। दूसरी ओर, BSP ने अत्याचारों के खिलाफ होने वाले विरोध-प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं लिया। इन सबका फायदा BJP को मिला।

दलितों का हिंदुत्वकरण | क्या BJP को दलितों का बढ़ता समर्थन सिर्फ रणनीतिक मामला है, क्योंकि BSP कमजोर पड़ रही है? या इसका मतलब यह है कि दलित आंदोलन अब हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है? यूपी में बाल्मीकि जैसी जातियों का हिंदुत्वकरण 19वीं सदी के आखिर से चल रहा है। आज यह एक खुला सामाजिक और राजनीतिक अभियान है, जो चुनाव नतीजों में साफ दिखता है।

नगीना का मुकाबला | इस बार I.N.D.I.A. गठबंधन ने यूपी में कांग्रेस और सपा को एक साथ ला दिया है। मायावती इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, जिससे मुकाबला कई-तरफा हो चला है। इससे BJP को मदद मिल रही है। पश्चिमी यूपी की नगीना सीट पर यह साफ दिखा। यहां पहले चरण में वोटिंग हुई थी। BJP, BSP और I.N.D.I.A. के बीच टक्कर है। साथ में, चंद्रशेखर आजाद भी खड़े हैं। 2019 में यह सीट BSP ने जीती थी, लेकिन तब उसका सपा के साथ गठबंधन था। इस बार क्या दलित फिर BSP का साथ देंगे? या BSP, BJP और आजाद के बीच दलित वोट बंट जाएंगे और इसका फायदा BJP को मिलेगा? या दलित 2012 की तरह मुसलमानों से हाथ मिला लेंगे और I.N.D.I.A. के साथ जाएंगे? क्या मुसलमानों की वजह से हिंदू एकजुट होंगे और दलित भी BJP को चुनेंगे?

डर और भरोसा | एक बात गौर करने लायक है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी के लिए खास उत्साह नहीं दिख रहा। स्थानीय मुद्दे ज्यादा अहम हो रहे हैं। यही वजह हो सकती है कि शुरुआती चरणों में वोटरों में अधिक जोश नहीं दिखा। दलितों में एक और बड़ा डर है कि कहीं संविधान में बदलाव करके आरक्षण और बाबा साहेब द्वारा दिलाए गए दूसरे फायदे छीन न लिए जाएं।

नए आंदोलन की मुश्किल | बहुजन समाज पार्टी के राज में थोड़ी पहचान और राजनीतिक ताकत पाकर दलित समाज अब अपने सियासी इरादे बड़े कर रहा है। लेकिन, पुरानी दलित पार्टियों या नए संगठनों के लिए आंदोलन खड़ा करने की जगह कम हो गई है। मोदी के नेतृत्व में BJP जितने दिन सत्ता में रहेगी, दलितों के हिंदुत्व में शामिल होने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन, अगर नई पीढ़ी के दलित नेता समुदाय के गुस्से को वोटों में बदल पाए तो दलित दावेदारी की एक नई लहर देख सकते हैं।

(लेखिका पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं)

हिमालय इतनी भीड़ के लिए नहीं है तैयार

महेश पाण्डेय

अक्षय तृतीया से शुरू हुई उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। 10 मई से यात्रा शुरू होने के बाद से 14 मई तक करीब पौने तीन लाख तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ का दौरा कर चुके हैं।

माणा तक लाइन | बढ़ती भीड़ के चलते जगह-जगह जाम लगा है तो मंदिरों में लंबी कतारें। बदरीनाथ मंदिर खुलने के पहले ही दिन दर्शन के लिए लगभग 4 किमी लाइन माणा गांव तक फैली हुई थी। चारधाम यात्रा के लिए 14 मई को चार बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों की संख्या 26,73,519 पहुंच चुकी थी। इसमें केदारनाथ जाने वाले 9 लाख से अधिक तो बदरीनाथ के लिए सवा आठ लाख से अधिक लोग थे। सवा चार लाख लोग यमुनोत्री जाना चाहते थे तो पौने पांच लाख गंगोत्री। बढ़ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के चलते पर्यटन विभाग ने ऑफलाइन पंजीकरण बुधवार और गुरुवार को बंद रखने का निर्णय लिया है।

सिस्टम की संवेदनहीनता | कहा जा रहा है कि यात्रा के शुरुआती शहरों हरिद्वार-ऋषिकेश से लेकर चारों धामों तक फैली अव्यवस्था बताती है कि सिस्टम में उच्च हिमालयी क्षेत्रों को लेकर संवेदनशीलता की कमी है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य तंज करते हैं कि चारों धाम में इवेंट मैनेजमेंट नहीं, बल्कि सुगम और सुरक्षित यात्रा चलाने की आवश्यकता है। सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हर धाम में प्रतिदिन कितने यात्रियों के रहने की व्यवस्था उसने बनाई हुई है। अव्यवस्था के कई और रूप दिखते हैं।

जाम की समस्या | मिसाल के तौर पर 'ऑल वेदर रोड' के नाम से प्रचारित चार धाम की सड़कें अभी भी पूरी तरह नहीं बन पाई हैं, इसलिए जाम की समस्या है। आमतौर पर जितनी दूरी तय करने में 2 घंटे लगते थे, अब 8-8 घंटे लग रहे हैं। यात्रा मार्ग पर पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से जगह-जगह गंदगी पवित्र नदियों में बहाई जा रही है।

स्थानीय लोग परेशान | केदारनाथ और बदरीनाथ में स्थानीय निवासियों के शुरुआती दौर में ही विरोध प्रदर्शन ने सिद्ध कर दिया है कि कहीं न कहीं सरकार असफल साबित हुई है। बदरीनाथ में जिला प्रशासन ने स्थानीय निवासियों की प्रसाद की सारी दुकानों को हटा दिया है। वर्षों से तुलसी माला बेचने वाली सैकड़ों स्थानीय महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। केदारनाथ में घोड़े-खच्चर वाले और स्थानीय दुकानदार अभी भी अपनी समस्याओं का समाधान न किए जाने से परेशान हैं।

कॉमन रूम

पहाड़ नहीं तैयार | इस वर्ष 80 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के यहां आने का अनुमान है। इतनी भारी भीड़ के लिए पहाड़ तैयार नहीं हैं। नीति-निर्माताओं को चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्था करते समय यात्रियों की संख्या में हो रही भारी वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा यह सब किसी आपदा को न्योता देने जैसा ही होगा।

जाम की यादें | यात्रा शुरू होने के दूसरे ही दिन यमुनोत्री मंदिर की ओर जाने वाले खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर भक्तों की भारी भीड़ दिखी। इसका विडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस को तीर्थयात्रियों से 'कम से कम एक दिन' के लिए मंदिर आने से बचने की अपील करनी पड़ी। ऐसे में तीर्थयात्री यहां से बुरी यादें लेकर जाएंगे। इससे पर्यटन स्थल के रूप में उत्तराखंड की छवि प्रभावित होगी।

बेहिसाब भीड़ | हालांकि, तमाम स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों के धरने-प्रदर्शन के बाद सरकार कुछ हरकत में आई है। सीएम ने अपने सचिव मीनाक्षी सुंदरम को उत्तरकाशी में कैंप करने को कहा है। इससे पूर्व, शासन व जिला स्तर पर तीन-तीन अधिकारियों को पहले ही चारधाम की व्यवस्था देखने के लिए तैनात किया गया है। फिर भी यह सवाल बना हुआ है कि इतनी बेहिसाब भीड़ को हिमालय में एडजस्ट करने की क्षमता कहां है?

टाइम मशीन

हकीम साहब ने आयुर्वेद को बचाया

मोहम्मद असगर

मोहम्मद अजमल खान के वालिद हकीम गुलाम महमूद खान अपने वक्त के मशहूर यूनानी फिजिशन थे। दादा शरीफ खान ने पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान स्थित अपने घर में क्लिनिक बना रखा था। यही क्लिनिक मोहम्मद अजमल खान को सौंपा गया, जो बाद में करोल बाग जाकर तिब्बिया कॉलेज बन गया।

AI Image

जादुई इलाज | मोहम्मद अजमल खान का जन्म 12 फरवरी 1863 को हुआ। यूनानी चिकित्सा की शिक्षा हासिल करने के बाद वह रामपुर के नवाब के मुख्य चिकित्सक नियुक्त हो गए। इलाज में कामयाबी पाने पर उनके बारे में मशहूर होने लगा था कि उनके पास जादुई दवा है, जिसका रहस्य सिर्फ हकीम ही जानते हैं।

गांधी से मुलाकात | हकीम अजमल खान ने आजादी की जंग में भी महात्मा गांधी का साथ पकड़ लिया था। उनकी गांधी जी से पहली मुलाकात 1919 में हुई। तभी वह असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उसी दौर का एक किस्सा है। वह एक राजा के महल में उसकी बीमार रानी को देखने पहुंचे थे। हकीम अजमल ने देखा कि रानी ने विदेशी कपड़े पहने हैं और पूरा कमरा विदेशी सामानों से भरा है। इस पर हकीम ने रानी की नब्ज देखते हुए कहा कि वक्त बदल रहा है, अब सिर्फ खादी इस्तेमाल करना चाहिए। रानी ने जवाब दिया कि 'पहनने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खादी खुरदुरी होती है और जिस्म में चुभती है।' हकीम यह सुनकर खफा हो गए और वहां से जाने लगे। उन्होंने कहा कि, 'मैं आपकी नब्ज नहीं देख पाऊंगा। जब खादी आपके जिस्म में चुभती है तो मेरी उंगली भी आपके हाथ में चुभती होगी, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूं।' यह सुनकर महाराज बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने हकीम साहब से माफी मांगी और वादा किया कि महल से विदेशी सामान बाहर निकलवा देंगे।

रिसर्च को बढ़ावा | हकीम अजमल खान यूनानी मेडिसिन में ख्याति हासिल करते जा रहे थे। उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद और यूनानी के विस्तार और विकास में खूब दिलचस्पी ली। तभी उन्होंने जामिया मिल्लिया की स्थापना की। इसके अलावा हिंदुस्तानी दवाखाना और आयुर्वेदिक रसायनशाला, आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हर्बल दवाओं पर अनुसंधान और विकास के लिए रिसर्च सेंटर खोला।

अंग्रेजों को सबक | महिलाओं के लिए दिल्ली की कासिम जान गली में हकीम अजमल खान ने मदरसा-ए-तिब्बिया जनाना की स्थापना की। इसका उद्घाटन 13 जनवरी 1909 को हुआ था। यह वही दौर था जब अंग्रेजों ने आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियों को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी थी। 1910 में अंग्रेजी हुकूमत ने हकीमों और वैद्यों की प्रफेशनल मान्यता को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। हकीम अजमल खान को लगा कि अंग्रेजों का यह फैसला भारत में रचे-बसे डॉक्टरी सिस्टम को खत्म कर देगा। उन्होंने देशभर के हकीमों और वैद्यों को सरकारी प्रस्ताव के खिलाफ एकजुट किया और आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। प्रस्ताव वापस हुआ।

उपाधियां लौटाईं | हकीम अजमल खान को 1908 में हाजिक-उल-मुल्क यानी राष्ट्र को मरहम लगाने वाला उपाधि दी गई थी। 1915 में ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। उन्होंने दोनों ही उपाधि लौटा दी। 29 दिसंबर 1927 को वह इस दुनिया से रुखसत हो गए।

पूर्वाग्रहों से सामना

प्रणव प्रियदर्शी

ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं कि किसी ने कोई खास कंपनी जॉइन की और 25 साल बाद भी वह उसी कंपनी में दिखे। इस अजूबे का जीता-जागता उदाहरण हैं राजलक्ष्मी श्रीनिवासन। गणित के पैशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिलचस्पी की बदौलत वह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ओर आकर्षित हुईं और 1999 में कॉलेज से निकलने के बाद बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोहो से जुड़ीं। आज इसी कंपनी में वह डायरेक्टर (प्रॉडक्ट मैनेजमेंट) की भूमिका निभा रही हैं। मगर एक कंपनी में रहने का मतलब यह नहीं है कि वह सीधी, सहज राह चलकर यहां पहुंची हैं। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए वह बताती हैं कि असम्पशन (पूर्वधारणा) और अनअवेयरनेस (अनभिज्ञता) सबसे बड़ी चुनौती हुआ करते थे। धीरे-धीरे उन्होंने इस पर काबू पाया। मगर ये तो हुई अपने अंदर की कमजोरी। बाहर की चुनौतियों का जहां तक सवाल है तो कई मौकों पर लगा कि उन्हें कम आंका जा रहा है। यही नहीं, कई मौकों पर जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की प्रवृत्ति से भी दो-चार होना पड़ा। उनके मुताबिक अच्छी बात यह रही कि जोहो के अंदर खुलकर बोलने का कल्चर था। खूबियों और खामियों पर खुलेपन के साथ बातचीत करके फैसले लिए जाते थे। इससे उनके लिए अपनी कमजोरियों पर काम करते हुए उन्हें दूर करते चलना और अपनी खूबियां निखारते रहना आसान हो गया। वह कहती हैं, टेक्नॉलजी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बेसिक्स को ठीक रखना और अपने स्किल को लगातार अपडेट करते रहना अहम है। यह याद रखना भी जरूरी है कि इस फील्ड में नई पीढ़ी हमेशा बेहतर और ज्यादा बुद्धिमान होती है। नए लोगों को भी उनका यही सुझाव है कि अपने सीनियर्स के अनुभव और टीम मेंबर्स की शार्पनेस का सम्मान करें लेकिन अपने बाद फील्ड में आए लोगों से भी मदद मांगने में हिचक न महसूस करें। यह आपकी अपेक्षा से ज्यादा फायदेमंद होता है।

राजलक्ष्मी श्रीनिवासन

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

बिना प्रेम अध्यात्म उस शरीर जैसा है जिसमें आत्मा नहीं

हफ़ीज़ किदवई

आध्यात्मिक शक्ति के विषय में बहुत कुछ विस्तार से बताया जाता रहा है। इसके साथ यह प्रश्न भी उठता है कि अध्यात्म को किस शक्ति की आवश्यकता होती है जिससे वह आध्यात्मिक शक्ति बन जाए? उस शक्ति का नाम है प्रेम। जब प्रेम हमारे अंदर अपना पहला कदम रखता है, तो हम एक परिवर्तन महसूस करते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसे देख नहीं सकते, पर उसका स्वाद, उसकी सुगंध, उसके रस हमें आनंदित करते हैं।

प्रेम ही अध्यात्म को पूर्ण करता है। बिना प्रेम अध्यात्म उस शरीर जैसा है, जिसमें आत्मा नहीं है। शरीर बहुत खूबसूरत हो, उसके हाथ पैर सुगठित हों, उसके चेहरे पर शांति भी हो, पर जब आत्मा नहीं होगी तो वह शरीर कैसा! एक प्रश्न तो यह भी उठता है कि प्रेम है क्या? इसका बड़ा सरल उत्तर है, आपके अंदर जो नहीं है उसे पूरा करने वाला ही प्रेम है। हम सब अधूरे हैं। जब हमें प्रेम होता है, तभी तो कहा जाता है कि हम पूरे हो गए। प्रेम हमें संपूर्णता का एहसास देता है। इसे यूं समझिए कि आपके पास सब कुछ है, बस दो बातें करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जो दो बात आपसे कर ले और उसकी बातें आपको प्रिय लगे, वही तो प्रेम है।

भक्तिमार्ग पर चलने वाले हर संत को देखिए। वह अपने अंदर के ईश्वर के साक्षात्कार को ही तो तड़पते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें एक पल के लिए ईश्वर अपना वह रूप दिखा दे, जो उन्होंने नहीं देखा। यही तो प्रेम है, जो उन्हें उस भक्ति की ओर ले जाता है। जो उनको पूर्णता देता है। हममें से कोई अधूरा नहीं रहना चाहता। बस सबकी पूर्णता अलग-अलग है और यह प्रेम से पूरी होती है। आपका जीवन जैसे एक खांचा है। उस खांचे को भरने वाला कोई दूसरा है। जैसे ही आपको उसमें इस खांचे की सूरत दिखती है, हृदय उधर झुक जाता है। सभी सूफियों ने प्रेम को प्रधानता दी है। वह अपने मुर्शिद यानी गुरु से प्रेम को ही पूर्णता मानते हैं। सूफी मार्ग में बिना प्रेम के वैसे भी कोई नहीं चल सकता। आध्यात्मिक संत शम्स तबरेज हों या फिर रूमी, इनके प्रेम ने आध्यात्मिक जगत को जो शक्ति दी है, वह अद्भुत है। प्रेम और अध्यात्म, ये दो विषय भले ही अलग मालूम पड़ें, पर ये एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

किसी ने पूछा कि सुदामा और कृष्ण में कैसा प्रेम था? वह एक दोस्त वाला प्रेम था। दोनों एक-दूसरे को पूर्णता देते थे। कृष्ण को गरीब सुदामा, या गरीब सुदामा को साधन संपन्न कृष्ण पूर्णता ही तो देते थे। कृष्ण सुदामा के पास बैठकर अपने दिल की बात कर सकते थे। उनके साथ गांव में घूमे अपने बचपन को याद करके रो भी सकते थे। कृष्ण के पास क्या नहीं था, पर जो उनके पास नहीं था, वह थे सुदामा। इसलिए वह उनके मित्र हुए और मित्रता की पहली शर्त ही प्रेम है।

प्रेम हमें पूर्णता देता है। जब हम पूर्ण होते हैं, तभी अध्यात्म की शक्ति समझ में आती है। इसीलिए कहा गया है, प्रेम और अध्यात्म एक-दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कहा जाता है कि हृदय में प्रेम का वास हो, तो सबके प्रति हमारी भावना पवित्र हो जाती है। हमें इंसान, जीव-जंतु, पेड़-पौधों, हवा-पानी- इन सबकी जरूरत है। इन सबके बिना हम अधूरे हैं। इन सबसे प्रेम कर हम आध्यात्मिक शक्ति को विस्तार दे सकते हैं।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ स्वतंत्र विदेश नीति

15 मई का संपादकीय 'दूरगामी समझौता' पढ़ा। 2016 से लंबित चाबहार पोर्ट का MOU ऐसे संवेदनशील समय में हस्ताक्षरित हुआ है जब ईरान और इस्राइल में तनाव बना हुआ है और पश्चिम एशिया संकटग्रस्त है। अमेरिका ने इस्राइल के पक्ष में ईरान पर नए सिरे से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। आशंका है कि ईरान से नजदीकी बढ़ाने वालों से अमेरिका दूरी बना लेगा। बावजूद इसके भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति पर चलने से गुरेज नहीं किया है। पाकिस्तान की वह हसरत अब ठंडी पड़ जाएगी जिसके तहत वह कराची पोर्ट के इस्तेमाल के लिए लिए मध्य एशियाई देशों को लुभाने की कोशिश कर रहा था।

मामचंद सागर, ई मेल से

■ व्यवस्था पर सवाल

14 मई के संपादकीय 'वोट की कीमत' में चुनाव के दौरान कैश बांटने की बड़ी समस्या को उजागर किया गया है। यह खेल इतने गोपनीय तरीके से होता है कि खबर फैलती नहीं है। हैरानी की बात है कि आंध्र प्रदेश के मतदाताओं ने डंके की चोट पर अपने वोट की कीमत मांगी। देखा जाए तो यह भी एक तरह से मतदाता की जागरूकता का ही उदाहरण है। उसे पता है कि नेता से अगर कुछ फायदा लिया जा सकता है तो वह चुनाव के दौरान ही संभव है। एक बार चुनाव हो जाए तो फिर नेता कहां नजर आता है। इस प्रकरण से मतदाताओं की मजबूरी और व्यवस्था की गड़बड़ी दोनों उजागर हो गई।

इन्द्र सिंह धिगान, किंग्जवे कैंप

■ प्रकृति से संतुलन जरूरी

केदारनाथ के पट खुलने के बाद जो विडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, वे चिंता बढ़ाने वाली हैं। तस्वीरों में काफी लोगों को विडियोग्राफी करते देखा गया। मंदिर के सामने इतनी बड़ी भीड़ कोई अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को भी इसमें पहल करने की जरूरत है ताकि सीमित संख्या में लोग पहुंचें। आस्था और श्रद्धा के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ देखने को मिल रहा है। लोग शायद भूल रहे हैं कि केदारनाथ की त्रासदी ने किस तरह से झकझोर कर रख दिया था।

करुणा नयन चतुर्वेदी, डीयू

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अचानक यूक्रेन गए – एक खबर

– ठंडे पड़ते युद्ध को फिर से हवा तो नहीं दी जा रही है!

रोहन श्रीवास्तव

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

क्रोध की अग्नि में व्यक्ति पहले स्वयं ही जलता है

राजमार्गों पर अतिक्रमण

यदि केंद्र सरकार ने राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्यों को फिर से चिट्ठी लिखी तो इसका मतलब है कि पहले जो चिट्ठियां लिखी गई थीं, उन पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर अतिक्रमण फौरी तौर पर ही हटाया गया। शायद यही कारण है कि इस बार लिखी गई चिट्ठी में यह कहा गया है कि जिम्मेदारी तय कर इसकी निगरानी की जाए कि राजमार्गों पर अतिक्रमण न होने पाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को पिछले दिशा-निर्देशों की भी याद दिलाई है। राजमार्गों पर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने के साथ दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बनने वाले अतिक्रमण को हटाना कोई ऐसा काम नहीं, जिसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशों की आवश्यकता हो, लेकिन अपने देश में जरूरी कामों और जोखिम से बचने के उपायों को लेकर भी निर्देश देने पड़ते हैं। इससे यही पता चलता है कि राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां राजमार्गों पर किए जाने वाले अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर नहीं। जब वे राजमार्गों पर सुगम यातायात को लेकर सजग नहीं तो फिर वे राज्य मार्गों यानी स्टेट हाईवे एवं अन्य सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए कितना तत्पर रहती होंगी। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में राजमार्गों से लेकर हर व्यस्त सड़क अतिक्रमण से ग्रस्त रहती है। इसके चलते न केवल आवागमन में बाधा पैदा होती है और जाम लगता है, बल्कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिनमें प्रति वर्ष डेढ़ लाख से अधिक लोग मरते हैं।

यह अच्छी बात नहीं कि राज्य सरकारों को बार-बार याद दिलाना पड़े कि राजमार्गों को अतिक्रमण से बचाने की जरूरत है। इसकी आवश्यकता तो राज्य सरकारों को स्वतः महसूस होनी चाहिए। राजमार्गों पर तय गति सीमा से वाहन न चल पाने, जाम लगने और दुर्घटनाओं का सिलसिला कायम रहने के बावजूद उन्हें अतिक्रमण से मुक्त नहीं किया जा पा रहा है। राजमार्गों के साथ उनसे जुड़ी सड़कें भी अतिक्रमण और जाम से अटी पड़ी रहती हैं। शहरी सीमा में तो राजमार्ग बिल्कुल आम सड़कों की तरह तब्दील हो जाते हैं। उनमें हर तरह के वाहन चलते नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखने को मिलता है कि उनमें यातायात नियमों का पालन नहीं होता। स्थिति यह है कि उलटी दिशा में भी वाहन चलते मिलते हैं। केंद्र सरकार को राज्यों को राजमार्गों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के दिशा-निर्देश देने के साथ यह भी देखना होगा कि उनमें यातायात पुलिस की उपस्थिति कैसे बढ़े और उनमें प्रकाश की समुचित व्यवस्था कैसे हो? चूंकि बरसात करीब आ रही है, इसलिए राजमार्गों में जल निकासी की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें गड्ढा मुक्त करने पर भी। इससे इन्कार नहीं कि देश में राजमार्ग तेजी से बन रहे हैं, लेकिन यह ठीक नहीं कि इसी के साथ वे समस्याओं से घिरते भी जा रहे हैं।

सतर्कता आवश्यक

पंजाब का माहौल खराब करने के लिए असामाजिक तत्वों की ओर से लगातार साजिश की जा रही है। जहां अलग-अलग जगहों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में आतंकी संगठन सिख फार जस्टिस से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक आतंकी माड्यूल का पर्दाफाश करते हुए चार सदस्यों को पकड़ा है। ये लोग टारगेट किलिंग को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। राज्य में चुनावी माहौल के बीच इस तरह की साजिश को गंभीरता से लेना होगा। आरोपितों के तार विदेश में छिपे आतंकियों से जुड़ रहे हैं। पंजाब में पहले भी कई गैंगस्टर एवं आतंकी पकड़े जा चुके हैं, जो टारगेट किलिंग के माध्यम से राज्य में अमन शांति को भंग करना चाहते थे। कुछ समय पहले रूपनगर के नंगल में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी की हत्या में भी विदेश में छिपे असामाजिक तत्वों से आरोपितों के संबंधों का पता चला था। आरोपितों को विदेश से फंडिंग हुई थी। फरीदकोट एवं अमृतसर में अलग-अलग धार्मिक संगठनों के नेताओं की हत्या में भी यह बात सामने आ चुकी है कि प्रदेश का माहौल करने के लिए साजिश रची गई थी। प्रदेश में एक जून को मतदान होना है। दो दिन बाद जब नामांकन वापसी हो जाएगी तब चुनावी माहौल गरमाएगा। बड़े नेताओं की रैलियां एवं जनसभाएं होंगी। इस दौरान राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि गैंगस्टरों एवं तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए। तस्करों, गैंगस्टरों एवं आतंकियों का गठजोड़ पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसे खत्म करना ही होगा। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

चुनावी माहौल के बीच अमन शांति भंग करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा बलों को ज्यादा चौकसी बरतनी होगी

मार्क्सवाद की खतरनाक खुराक

विकास सारस्वत

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इस समय विरोध-प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उससे भारत को सतर्क रहना होगा

अवधेश राजपूत

इन दिनों कई अमेरिकी और यूरोपीय विश्वविद्यालय इजरायल-फलस्तीन युद्ध का दूसरा मोर्चा बन चुके हैं। अमेरिका में तो उग्र प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए कैंपसों में पुलिस और सेना बुलानी पड़ी है। वहां सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि अमेरिकी संस्थान हथियार बनाने वाली कंपनियों और ऐसे व्यवसायों से अपना निवेश वापस लें, जो इजरायल को लाभ पहुंचाते हों। आंदोलन की आड़ में अराजकता और कैंपसों पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा भी चल रही है। अमेरिका के पिछले छात्र आंदोलनों की ही तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन प्रदर्शनों का केंद्र बनी हुई है। इस उत्पात में कई शिक्षकों का भी भरपूर सहयोग साफ दिखाई दे रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में करीब सौ प्राध्यापकों ने पत्र लिखकर न केवल हमास समर्थक छात्रों का बचाव किया था, बल्कि सात अक्टूबर के नरसंहार को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की सलाह भी दी थी। हमले के तुरंत बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने हमास, हिजबुल्ला और जिहाद के समर्थक मोहम्मद अब्दू की अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति की। इसी संस्थान के प्रोफेसर जोसफ मस्साद ने हमले को प्रशंसनीय बताया। साउथ कैलिफोर्निया के एक प्राध्यापक अब्दुल फतह अलनाजी को तो एक इजरायली प्रदर्शनकारी की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। हमास के नृशंस हमले के अगले ही दिन हार्वर्ड की फलस्तीन एकजुटता समिति ने इस हमले के लिए इजरायल को ही जिम्मेदार बताया था। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि हार्वर्ड अध्यक्ष क्लाडीन गे, यूनिवर्सिटी आफ पेंसिल्वेनिया की अध्यक्ष लिज मैगिल और एमआइटी अध्यक्ष सैली कार्नब्लथ ने अपने यहां यहूदी नरसंहार के नारों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बेशर्मी से बचाव किया।

अमेरिकी कैंपसों में साफ दिखाई दे रही यह शरिया-वामपंथ कट्टरता पिछले सात दशकों से वहां पनप रहे सांस्कृतिक मार्क्सवाद की देन है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित 'वैज्ञानिक समाजवाद' के अनुसार शोषित मजदूर वर्ग को पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति करनी थी, परंतु रूसी क्रांति किसानों द्वारा लाई गई। बोल्शेविक क्रांति के बाद यूरोप की तमाम कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियां मार्क्स द्वारा क्रांति के अवश्यंभावी होने की भविष्यवाणी पर आस लगाए बैठी रहीं, लेकिन क्रांति नहीं आई। हताश विचारकों ने मार्क्सवाद का नए सिरे से आकलन शुरू किया, जिसमें जर्मनी के गोएथे यूनिवर्सिटी स्थित इंस्टीट्यूट आफ सोशल रिसर्च ने अग्रणी भूमिका निभाई। ये बुद्धिजीवी खुद को सभी विचारधाराओं से असंबद्ध बताते हुए अपनी चेष्टा को आलोचनात्मक सिद्धांत कहते रहे, परंतु पूंजीवाद के विरोध एवं क्रांति के समर्थन में लगभग सभी एकमत थे। मार्क्सवाद की पुनर्समीक्षा में फ्रैंकफर्ट स्कूल के अलावा इतालवी मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्शी का बड़ा योगदान रहा। ग्राम्शी ने मजदूर और किसानों के अलावा भाषाई, नस्लीय और मजहबी अल्पसंख्यकों को शोषित वर्गों के रूप में चिह्नित किया और उनसे क्रांति की उम्मीद लगाई।

छह-सात दशक पहले छिड़े नारी मुक्ति आंदोलन और यौन क्रांति ने नारीवादियों और यौन अल्पसंख्यकों को भी शोषित वर्ग में जोड़ दिया। मार्क्सवाद और इस्लामियत में समान रूप से विद्यमान कट्टरता और मजहबी अल्पसंख्यकों का शोषित वर्ग के रूप में चिह्नीकरण इस्लामी कट्टरवादियों के लिए अनुकूल रहा। नए वामपंथी विचारकों के पास भी अब क्रांति के वाहक के रूप में बहुत से वर्गों का एक बड़ा समूह था। दूसरी तरफ हिटलर के डर से इंस्टीट्यूट आफ सोशल रिसर्च, फ्रैंकफर्ट से अमेरिका स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित हुआ, जहां यह संस्थान 1935 से 1953 तक बना रहा। इस दौरान यहां बहुत सा मार्क्सवादी साहित्य प्रकाशित हुआ। ग्राम्शी की जेल में लिखी लेखनी का प्रकाशन भी यहीं हुआ और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में वामपंथ का केंद्र बन गई। हथियारबंद क्रांति की आशा छोड़ नए वामपंथ ने विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया। ग्राम्शी ने मार्क्सवादियों से शैक्षणिक संस्थाओं में घुसपैठ बनाने का आह्वान किया और मार्क्यूज ने समाज में क्रांतिकारी चेतना को शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से संचारित करने की वकालत की। इसके साथ ही मार्क्यूज ने सहिष्णुता को ही दमनकारी बता दिया। मार्क्यूज ने कहा कि जब तक समाज में किसी भी प्रकार की वर्ग संरचना है तब तक बुर्जुआ वर्ग सहिष्णुता को अपना विशेषाधिकार और सत्ता बनाए रखने के लिए हथियार की तरह उपयोग करता रहेगा। इसलिए मार्क्यूज का विचार अल्पसंख्यकों, कट्टरपंथियों और अराजक तत्वों के प्रति सहिष्णुता का तो समर्थन करता है, परंतु बहुसंख्यकों और सरकारी तंत्र के प्रति सहिष्णुता का विरोध करता है।

तथ्यों को नकारने वाले सांस्कृतिक मार्क्सवाद ने न सिर्फ हर सामाजिक समस्या को समूह दृष्टि से देखने पर बल दिया, बल्कि पूरी दुनिया को शोषक और शोषित जैसे स्थायी वर्गों में बांट दिया। ऐसे में, इस विचारधारा ने कुछ समूहों का अंधा समर्थन और दूसरे समूहों के अंध विरोध को प्रोत्साहित किया। अपने मताग्रह के कारण सांस्कृतिक मार्क्सवाद उन तथ्यों की अनदेखी करता है जो उसकी विचारधारा के खिलाफ जाते हैं। उदाहरण के लिए इस विचारधारा के अनुसार बहुसंख्यक हमेशा शोषक और अल्पसंख्यक शोषित ही रह सकता है। जबकि भारत में ही देखें तो मजहबी और नस्लीय अल्पसंख्यकों ने लंबे समय तक बहुसंख्यकों पर शासन और उनका शोषण भी किया है। असहिष्णुता और कट्टरता को विचारधारा का लबादा ओढ़ाकर सांस्कृतिक मार्क्सवाद ने आज वह स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें यहूदी विद्यार्थी बैरीकेड लगाकर विश्वविद्यालयों में अपनी जान बचा रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया को लगा था कि वामपंथ खत्म हो गया, परंतु अमेरिकी विश्वविद्यालय इसके गवाह हैं कि मार्क्सवाद अपने परिवर्तित रूप में अब भी एक खतरा है और इस्लामी कट्टरपंथियों के साथ इसके गठजोड़ ने सभ्य समाज के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। यह चुनौती भारत में भी उभर रही है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इस समय जो कुछ हो रहा है, उससे भारत को सतर्क रहना होगा।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

समग्र विकास को समर्पित सरकार

हरदीप सिंह पुरी

मोदी सरकार की उपलब्धियां यही सिद्ध करती हैं कि सर्वसमावेशी नीतियों से ही विकसित भारत बनाया जा सकता है

नल से जल ने सुगम बनाया जीवन। फाइल

पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकल्प लिया कि वर्ष 2047 में जब देश स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा होगा तब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। दस वर्ष पहले तक यह दावा असंभव लगता। वर्ष 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 'फ्रैजाइल फाइव' करार देकर नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा। उसके उलट भारत अभी विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की राह पर है। यह कैसे संभव हुआ? पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और देश की उत्पादक क्षमता में सुधार लाना है। सरकार का दृष्टिकोण उसकी 'परिपूर्णता की राजनीति' में निहित है, जिसमें बुनियादी ढांचा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सामर्थ्य, हरित अर्थव्यवस्था, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन पर जोर है। योजना बनाना एक बात है और उसे धरातल पर उतारना दूसरी बात। मोदी सरकार इन दोनों ही मोर्चों पर खरी उतरी है। परिणामस्वरूप पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। 'मोदी की गारंटी' आम नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

इस सफलता में हमारे समाज के चार स्तंभों गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं का सशक्तीकरण महत्वपूर्ण रहा है। एक समय गरीबी के चलते पहचाना जाने वाला भारत अब समृद्धि की राह पर है। गरीबों की भलाई के लिए कोविड महामारी के समय मोदी सरकार ने 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देने की जो पहल की थी वह अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी। शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना ने उन स्ट्रीट वेंडरों को राहत प्रदान की, जिनके सामने एकाएक रोजगार की चुनौतियां आ गई थीं। इस योजना में अब तक 63 लाख से अधिक लाभार्थियों को 11,300 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है। साथ ही इसने शहरी गरीबों को डिजिटल रूप से साक्षर होने में भी सक्षम बनाया है। पीएम किसान और पीएम फसल बीमा जैसी योजनाओं से आज 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लैंगिक समानता को प्रमुखता दी जा रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और जल जीवन मिशन एवं अमृत मिशन के तहत लगभग 14 करोड़ नल-जल कनेक्शन दिए गए। एक दशक पहले तक नल से जल की पहुंच केवल 17 प्रतिशत परिवारों तक थी जो आंकड़ा बढ़कर अब 70 प्रतिशत तक हो गया है। पीएम आवास योजना के तहत लगभग चार करोड़ आवास निर्मित किए गए हैं। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में तीन करोड़ और नए घर बनाने का वादा किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन मंजूर किए जा चुके हैं, जिससे धुआं-रहित रसोई की सुविधा लगभग सभी तक पहुंच चुकी है, जो 2014 तक केवल 55.9 प्रतिशत परिवारों तक सीमित थी। महिलाएं इन योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी हैं, जिसने उनके जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से सुगमता प्रदान की है।

वहीं, आयुष्मान भारत जैसी योजना के माध्यम से स्वास्थ्य पर खर्च करीब 25 प्रतिशत कम हो गया है। निम्न-मध्यम वर्गीय भारतीयों को बीमारी के चलते गरीबी का दोहरा झटका झेलना पड़ता था, लेकिन इस योजना के जरिये प्रति वर्ष 55 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को पांच लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया गया है। 2013-14 की तुलना में पूंजीगत व्यय में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है, जो 3.92 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राजमार्गों की लंबाई 60 प्रतिशत बढ़ गई है। समूचे ग्रामीण इलाकों में करीब-करीब पक्की सड़कें बन गई हैं। सभी गांवों तक बिजली पहुंच गई है। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग चौगुना हो गया है। विश्व बैंक रैंकिंग के अनुसार हमारे लाजिस्टिक और औद्योगिक परिचालन में काफी सुधार हुआ है। देश में 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। सात नए आइआइएम और आइआइटी की स्थापना की गई है। एम्स की संख्या में तिगुनी वृद्धि हुई है। 51 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम के जरिये 33.43 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है। जीएसटी, आइबीसी, परिसंपत्ति मौद्रीकरण, श्रम कानून सुधार, स्टार्टअप इंडिया और पीएलआइ जैसी आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने वाली सिद्ध हुई हैं। प्रति व्यक्ति आय भी छह गुना बढ़कर 15,000 डालर तक पहुंचने की संभावना है। वैश्विक निवेशक भी इस आशावाद को साझा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत को रिकार्डतोड़ एफडीआइ प्राप्त हो रहा है। घरेलू शासन के साथ-साथ वैश्विक शासन के मामलों पर भी प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक कौशल और दूरदर्शिता को सार्वभौमिक प्रशंसा मिली है।

मोदी सरकार की उपलब्धियां यही सिद्ध करती हैं कि सामाजिक न्याय को चरितार्थ करने वाली सर्वसमावेशी नीति ही विकसित भारत के सपने को साकार करने में सक्षम है। हमें विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए देशहित में सक्रिय रहना होगा। 'राष्ट्र प्रथम' हमारे लिए सर्वोच्च मंत्र है।

(लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम एवं शहरी कार्य मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

कर्तव्य और अधिकार

कर्तव्य के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि जिसे करने के लिए कर्ता स्वाधीन हो, जिससे किसी का अहित न हो, वही कर्तव्य है। वस्तुतः, कर्तव्य से दूसरों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसी कारण किसी का अहित नहीं होता। किसी व्यक्ति में जैसे-जैसे कर्तव्यपरायणता सुदृढ़ होती जाती है, वैसे-वैसे उसकी परतंत्रता स्वतंत्रता में बदल जाती है। यदि हम गहनता से विचार करें तो देखेंगे कि पराधीनता का जन्म एकमात्र अकर्तव्य से ही होता है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति किसी का ऋणी नहीं रहता। उसकी प्रसन्नता किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। वह प्रत्येक परिस्थिति में पूरी तरह संतुलित रहकर अपने जीवन से प्रसन्न एवं संतुष्ट रहता है। प्रत्येक मानव में विवेक शक्ति, भाव शक्ति एवं क्रिया शक्ति उपस्थित रहती है। मनुष्य अपने विवेक के प्रकाश में कर्तव्य का दर्शन करता है। इसके पश्चात भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, इसी विवेक शक्ति के अधीन हो जाती है। जो मनुष्य इस प्राप्त विवेक का आदर नहीं करता, वह स्वाधीनतापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्धारण भी नहीं कर पाता। प्रायः कर्तव्य के निर्णय के लिए मनुष्य के स्वयं के आत्मज्ञान, विवेकपूर्ण व्यक्तियों के सत्संग और सद्ग्रंथों के अनुशीलन की आवश्यकता होती है।

कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से गुंथे हुए होते हैं। एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार और दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य पहले व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे व्यक्ति का कर्तव्य समाज का अधिकार और समाज का कर्तव्य व्यक्ति का अधिकार। राष्ट्र का कर्तव्य प्रजा का अधिकार और प्रजा का कर्तव्य राष्ट्र का अधिकार।

इस प्रकार एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के सम्यक् परिपालन से दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। निष्कर्षतः, यह कहा जा सकता है कि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करके ही सभी के अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं।

डा. प्रशांत अग्निहोत्री

परिवार को जोड़ते परंपरागत आयोजन

डा. मोनिका शर्मा

दिखावे से दूर मन को जोड़ने वाले रीति-रिवाजों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए विवाह करना परिवार की नींव को भी मजबूती देता है

भारतीय समाज में पारिवारिक मेलमिलाप का सबसे मुफीद अवसर वैवाहिक समारोह होते हैं। दूर-दराज के सगे-संबंधियों से लेकर करीबी रिश्तेदारों तक विवाह आयोजनों के सुखद अवसर का हिस्सा बनने की रीत रही है। अपनेपन और भागीदारी की इन परंपराओं ने पारिवारिक व्यवस्था को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। बावजूद इसके शादी समारोह अब नए ही रंग-ढंग में रंगे दिखते हैं। वैवाहिक आयोजनों में हावी होते दिखावे और धूम धड़ाके के बीच गुम हो रहे परंपरागत रिवाजों को लेकर उच्चतम न्यायालय ने विचारणीय टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जिसकी अपनी पवित्रता है। इसीलिए युवाओं को विवाह से पहले संस्था की पवित्रता ध्यान में रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हिंदू विवाह की पवित्र संस्था को केवल गीत, नृत्य और शराब पीने और खाने के लिए आयोजित सामाजिक कार्यक्रम के रूप में महत्वहीन नहीं बनाया जाना चाहिए। हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए उचित संस्कारों और रीतियों का निष्ठापूर्वक पालन होना चाहिए।

ध्यातव्य है कि न्यायालय ने युवाओं से कहा है कि विवाह को फिजूलखर्ची के अवसर के रूप में या दहेज-उपहार मांगने के साधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण, गंभीर और आवश्यक कार्यक्रम है। इसे महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जो एक पुरुष और एक महिला के बीच आजीवन बंधन स्थापित करता है। एक परिवार की नींव बनाता है, जो भारतीय समाज की मौलिक इकाई है।

समझना मुश्किल नहीं कि न्यायालय की यह टिप्पणी शादी समारोहों के माध्यम से परिवार के जुड़ाव, परंपराओं के पोषण, समाज की भागीदारी और संस्कारों के निर्वहन को लेकर एक प्रतिबद्धता तय करने का भाव लिए है। दायित्वबोध को बल देने की सोच को पोषित करती है। पारिवारिक बिखराव के बढ़ते आंकड़ों, वैवाहिक जीवन में बढ़ते अपराधों एवं जीवनसाथी के प्रति उपेक्षा और असंवेदशीलता के बर्ताव पर लगाम लगाने का उद्देश्य लिए है। भविष्य में आर्थिक परेशानियों से जूझने के हालात बनाने वाले महंगे आयोजनों के बजाय सोच समझकर खर्च करने की बात लिए है। चिंतनीय है कि कुछ परिवारों की यह फिजूलखर्ची और चमक दमक देश के आम परिवारों की मुश्किलें बढ़ाती है। बेवजह की धूमधाम के लिए सामाजिक-मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है, जो कि भेदभाव बढ़ाकर परिवार की रूपरेखा को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में दिखावे से दूर मन को जोड़ने वाले रीति-रिवाजों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए विवाह करना परिवार की नींव को मजबूती देता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

चुनाव एवं राजनीतिक सुधार आवश्यक

'घटते मतदान के लिए नेता भी जिम्मेदार' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में शंकर शरण ने परिपक्व लोकतंत्र के पक्ष में प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए हैं। उनका यह कहना यथार्थ ही है कि अनिवार्य मतदान किसी प्रकार से सार्थक समाधान नहीं है। आखिर मतदाताओं की असहमति भी तो एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। यह सही है कि नोटा जैसे विकल्प की पहल हुई है, लेकिन वह सकारात्मक नहीं है। उसका अभी तक कोई व्यापक प्रभाव भी नहीं दिखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि घटते मतदान के रुझान को लेकर राजनीतिक दल भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि न केवल सार्थक चुनाव सुधारों की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए जाएं, बल्कि राजनीतिक दलों को भी अधिक जिम्मेदार बनाते हुए उन पर अपने भीतर लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए दबाव बनाया जाए। प्रमुख राजनीतिक दल यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में टिकट देने से पहले ही एक प्रकार का चुनाव कराएं, जिसमें जनता या पार्टी कार्यकर्ताओं की किसी प्रकार की भागीदारी संभव हो तो कहीं अधिक लोकप्रिय प्रत्याशी सामने आ सकते हैं। लेखक महोदय का यह सुझाव भी सही है कि ऐसे चुनाव सुधार समय की आवश्यकता हो चले हैं, जिसमें चुनावी प्रक्रिया आकर्षक बन सके। इसके लिए चुनावों में चल निकली बेतहाशा खर्च की परंपरा पर भी किसी प्रकार का अंकुश लगाया जाए, क्योंकि इसके चलते सीमित संसाधनों वाले योग्य लोगों के लिए चुनाव लड़ना संभव नहीं रह गया है। यह भी लोकतंत्र के परिदृश्य को बिगाड़ता है।

गुंजन शर्मा, कमला नगर-नई दिल्ली

रेमिटेंस से चमकी भारतीय अर्थव्यवस्था

'आर्थिकी का सहारा बने प्रवासी भारतीय' शीर्षक आलेख में डा. जयंतीलाल भंडारी ने भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजे गए रेमिटेंस को भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भूमिका के बारे में बता रहे हैं। हाल में जारी की गई यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रवासियों द्वारा वर्ष 2022 में भेजा गया रेमिटेंस दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह बात भारतीय प्रवासियों के परिश्रम, दक्षता और मातृभूमि के प्रति स्नेह को दर्शाती है। एक आम भारतीय नागरिक के नजरिये से यह स्पष्ट है कि हमारे प्रवासी भाई-बहनों का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे प्रवासी भाई-बहन सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें, ताकि वे भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर सकें। सरकार प्रवासी भारतीयों के साथ स्नेह एवं सहभागिता बनाए रखे। तभी हम विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

awanishg30@gmail.com

मतदान से दूरी क्यों?

शंकर शरण का आलेख ''घटते मतदान के लिए नेता भी जिम्मेदार'' एक दम सटीक प्रतीत होता है। अब भारत में साक्षरता तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आम भारतीय अपने हितों के अनुकूल शासन चाहता है, जबकि नेताओं की भाषा अमर्यादित होती जा रही है। उस पर बिना किसी तथ्य के सरकारी रेवड़ी बांटने के वादे भारतीय मानस का मतदान से मोह भंग का कारण बन रहे हैं। एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान से चुनाव लड़ सके, जीतने के बाद अपनी मर्जी से दूसरे दल में शामिल न हो सके इसका प्रविधान कानून में होना चाहिए। चुनाव प्रचार में धर्म, जाति, किसी खास वर्ग विशेष को लक्ष्य कर भाषण पर प्रतिबंध होना चाहिए। नेताओं द्वारा सत्ता में आने के बाद अपने किए गए गए वादे निभाने के सतत प्रयास किए जाने चाहिए। जिस प्रकार उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण अनिवार्य कर दिया गया है, उसी प्रकार उनके सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों का विवरण भी मीडिया में प्रकाशित किया जाना चाहिए। सभी चुनावों में स्वस्थ गतिविधियों, जिम्मेदार एवं सकारात्मक सोच वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। vashishatha1967@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

क्रोध की अग्नि में व्यक्ति पहले स्वयं ही जलता है

राजमार्गों पर अतिक्रमण

यदि केंद्र सरकार ने राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्यों को फिर से चिट्ठी लिखी तो इसका मतलब है कि पहले जो चिट्ठियां लिखी गई थीं, उन पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर अतिक्रमण फौरी तौर पर ही हटाया गया। शायद यही कारण है कि इस बार लिखी गई चिट्ठी में यह कहा गया है कि जिम्मेदारी तय कर इसकी निगरानी की जाए कि राजमार्गों पर अतिक्रमण न होने पाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को पिछले दिशा-निर्देशों की भी याद दिलाई है। राजमार्गों पर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने के साथ दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बनने वाले अतिक्रमण को हटाना कोई ऐसा काम नहीं, जिसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशों की आवश्यकता हो, लेकिन अपने देश में जरूरी कामों और जोखिम से बचने के उपायों को लेकर भी निर्देश देने पड़ते हैं। इससे यही पता चलता है कि राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां राजमार्गों पर किए जाने वाले अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर नहीं। जब वे राजमार्गों पर सुगम यातायात को लेकर सजग नहीं तो फिर वे राज्य मार्गों यानी स्टेट हाईवे एवं अन्य सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए कितना तत्पर रहती होंगी। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में राजमार्गों से लेकर हर व्यस्त सड़क अतिक्रमण से ग्रस्त रहती है। इसके चलते न केवल आवागमन में बाधा पैदा होती है और जाम लगता है, बल्कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिनमें प्रति वर्ष डेढ़ लाख से अधिक लोग मरते हैं। यह अच्छी बात नहीं कि राज्य सरकारों को बार-बार याद दिलाना पड़े कि राजमार्गों को अतिक्रमण से बचाने की जरूरत है। इसकी आवश्यकता तो राज्य सरकारों को स्वतः महसूस होनी चाहिए। राजमार्गों पर तय गति सीमा से वाहन न चल पाने, जाम लगने और दुर्घटनाओं का सिलसिला कायम रहने के बावजूद उन्हें अतिक्रमण से मुक्त नहीं किया जा पा रहा है। राजमार्गों के साथ उनसे जुड़ी सड़कें भी अतिक्रमण और जाम से अटी पड़ी रहती हैं। शहरी सीमा में तो राजमार्ग बिल्कुल आम सड़कों की तरह तब्दील हो जाते हैं। उनमें हर तरह के वाहन चलते नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखने को मिलता है कि उनमें यातायात नियमों का पालन नहीं होता। स्थिति यह है कि उलटी दिशा में भी वाहन चलते मिलते हैं। केंद्र सरकार को राज्यों को राजमार्गों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के दिशा-निर्देश देने के साथ यह भी देखना होगा कि उनमें यातायात पुलिस की उपस्थिति कैसे बढ़े और उनमें प्रकाश की समुचित व्यवस्था कैसे हो? चूंकि बरसात करीब आ रही है, इसलिए राजमार्गों में जल निकासी की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें गड्ढा मुक्त करने पर भी। इससे इन्कार नहीं कि देश में राजमार्ग तेजी से बन रहे हैं, लेकिन यह ठीक नहीं कि इसी के साथ वे समस्याओं से घिरते भी जा रहे हैं।

निगरानी की जरूरत

यह राहत की बात है कि राज्य सरकार मानसून से पहले बाढ़ जैसी आपदा से बचाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। बांधों की मजबूती और उनकी देखरेख पर करीब दो सौ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान बताया जा रहा है। इस राशि से बांधों के साथ स्लूस गेटों की मरम्मत होगी और बाढ़ से बचाव वाली वस्तुओं का भंडारण किया जाएगा। सरकार हर वर्ष मानसून से पहले इस तरह की तैयारी करती है, लेकिन इसके बावजूद बारिश के बाद बांधों के टूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि इसकी जिम्मेदारी तय हो। योजनाओं की सख्त मानीटरिंग की जाए, ताकि काम पर कोई सवाल नहीं उठे। पहले ही वैसे कमजोर तटबंधों का सर्वे करा लिया जाए जिसके टूटने की आशंका है। ऐसे बांधों को प्राथमिकता में रखा जाए और इसपर पहले काम शुरू हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ से बचाव के लिए अभी राज्य में 225 योजनाओं पर काम चल रहा है। इन योजनाओं पर अभी से नजर रखी जाए, ताकि कोई कमी न रह जाए। हालांकि, यह व्यवस्था पहले से बनी हुई है कि जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता की उपस्थिति में बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित काम होंगे। कार्यपालक अभियंता निरीक्षण रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे। कंक्रीट आदि के नमूने लेकर काम की जांच होगी। कोई गड़बड़ी पाए जाने पर कार्यपालक अभियंता ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। अब सरकार की इस व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत है, ताकि ठेकेदार कोई लापरवाही न कर सकें। ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरों में भी जलजमाव से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। राज्य सरकार के आदेश के बाद भी मुजफ्फरपुर, दरभंगा जैसे शहरों में नाले की उड़ाही का काम शुरू नहीं हो सका है। अगर यह काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो शहर के लोग जलजमाव से जूझेंगे।

मानसून से पहले बाढ़ जैसी आपदा से बचाव की तैयारी शुरू होने की सूचना राहत देने वाली है। शहरों में भी नालों की उड़ाही जैसे काम शीघ्र शुरू करने की जरूरत है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या मतदाताओं की उदासीनता के लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं?

आज का सवाल
क्या टीम इंडिया के कोच के लिए विदेशी क्रिकेटर को प्राथमिकता देनी चाहिए?

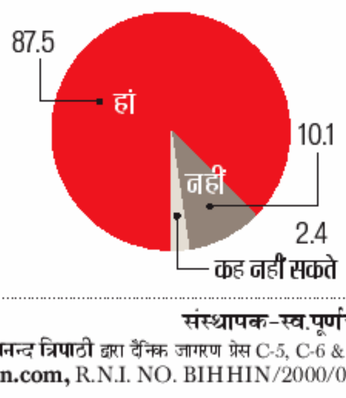

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

मार्क्सवाद की खतरनाक खुराक

विकास सारस्वत

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इस समय विरोध-प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उससे भारत को सतर्क रहना होगा

इन दिनों कई अमेरिकी और यूरोपीय विश्वविद्यालय इजरायल-फलस्तीन युद्ध का दूसरा मोर्चा बन चुके हैं। अमेरिका में तो उग्र प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए कैंपसों में पुलिस और सेना बुलानी पड़ी है। वहां सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि अमेरिकी संस्थान हथियार बनाने वाली कंपनियों और ऐसे व्यवसायों से अपना निवेश वापस लें, जो इजरायल को लाभ पहुंचाते हों। आंदोलन की आड़ में अराजकता और कैंपसों पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा भी चल रही है। अमेरिका के पिछले छात्र आंदोलनों की ही तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन प्रदर्शनों का केंद्र बनी हुई है। इस उत्पात में कई शिक्षकों का भी भरपूर सहयोग साफ दिखाई दे रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में करीब सौ प्राध्यापकों ने पत्र लिखकर न केवल हमास समर्थक छात्रों का बचाव किया था, बल्कि सात अक्टूबर के नरसंहार को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की सलाह भी दी थी। हमले के तुरंत बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने हमास, हिजबुल्ला और जिहाद के समर्थक मोहम्मद अब्दू की अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति की। इसी संस्थान के प्रोफेसर जोसफ मस्साद ने हमले को प्रशंसनीय बताया। साउथ कैलिफोर्निया के एक प्राध्यापक अब्दुल फतह अलनाजी को तो एक इजरायली प्रदर्शनकारी की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। हमास के नृशंस हमले के अगले ही दिन हार्वर्ड की फलस्तीन एकजुटता समिति ने इस हमले के लिए इजरायल को ही जिम्मेदार बताया था। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि हार्वर्ड अध्यक्ष क्लाडीन गे, यूनिवर्सिटी आफ पेंसिल्वेनिया की अध्यक्ष लिज मैगिल और एमआइटी अध्यक्ष सैली कार्नब्लथ ने अपने यहां यहूदी नरसंहार के नारों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बेशर्मी से बचाव किया।

अमेरिकी कैंपसों में साफ दिखाई दे रही यह शरिया-वामपंथ कट्टरता पिछले सात दशकों से वहां पनप रहे सांस्कृतिक मार्क्सवाद की देन है। वैचारिक कट्टरता के इस पहलू की कभी गहन समीक्षा नहीं हुई। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित 'वैज्ञानिक समाजवाद' के अनुसार शोषित मजदूर वर्ग को पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति करनी थी, परंतु रूसी क्रांति किसानों द्वारा लाई गई। बोल्शेविक क्रांति के बाद यूरोप की तमाम कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियां मार्क्स द्वारा क्रांति के अवश्यंभावी होने की भविष्यवाणी पर आस लगाए बैठी रहीं, लेकिन क्रांति नहीं आई। हताश विचारकों ने मार्क्सवाद का नए सिरे से आकलन शुरू किया, जिसमें जर्मनी के गोएथे यूनिवर्सिटी स्थित इंस्टीट्यूट आफ सोशल रिसर्च ने अग्रणी भूमिका निभाई। चूंकि यह विश्वविद्यालय फ्रैंकफर्ट में स्थित था इसलिए इस मतांतरित विचार को फ्रैंकफर्ट स्कूल आफ थाट के नाम से जाना गया। ये बुद्धिजीवी खुद को सभी विचारधाराओं से असंबद्ध बताते हुए अपनी चेष्टा को आलोचनात्मक सिद्धांत कहते रहे, परंतु पूंजीवाद के विरोध एवं क्रांति के समर्थन में लगभग सभी एकमत थे। मार्क्सवाद की पुनर्समीक्षा में फ्रैंकफर्ट स्कूल के अलावा इतालवी मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्शी का बड़ा योगदान रहा। ग्राम्शी ने मजदूर और किसानों के अलावा भाषाई, नस्लीय और मजहबी अल्पसंख्यकों को शोषित वर्गों के रूप में चिह्नित किया और उनसे क्रांति की उम्मीद लगाई।

करीब छह-सात दशक पहले छिड़े नारी मुक्ति आंदोलन और यौन क्रांति ने नारीवादियों और यौन अल्पसंख्यकों को भी शोषित वर्ग में जोड़ दिया। मार्क्सवाद और इस्लामियत में समान रूप से विद्यमान कट्टरता और मजहबी अल्पसंख्यकों का शोषित वर्ग के रूप में चिह्नीकरण इस्लामी कट्टरवादियों के लिए अनुकूल रहा। नए वामपंथी विचारकों के पास भी अब क्रांति के वाहक के रूप में बहुत से वर्गों का एक बड़ा समूह था। दूसरी तरफ हिटलर के डर से इंस्टीट्यूट आफ सोशल रिसर्च, फ्रैंकफर्ट से अमेरिका स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित हुआ, जहां यह संस्थान 1935 से 1953 तक बना रहा। इस दौरान यहां बहुत सा मार्क्सवादी साहित्य प्रकाशित हुआ। ग्राम्शी की जेल में लिखी लेखनी का प्रकाशन भी यहीं हुआ और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में वामपंथ का केंद्र बन गई। हथियारबंद क्रांति की आशा छोड़ नए वामपंथ ने विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया। ग्राम्शी ने मार्क्सवादियों से शैक्षणिक संस्थाओं में घुसपैठ बनाने का आह्वान किया और मार्क्यूज ने समाज में क्रांतिकारी चेतना को शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से संचारित करने की वकालत की। इसके साथ ही मार्क्यूज ने सहिष्णुता को ही दमनकारी बता दिया। मार्क्यूज ने कहा कि जब तक समाज में किसी भी प्रकार की वर्ग संरचना है तब तक बुर्जुआ वर्ग सहिष्णुता को अपना विशेषाधिकार और सत्ता बनाए रखने के लिए हथियार की तरह उपयोग करता रहेगा। इसलिए मार्क्यूज का विचार अल्पसंख्यकों, कट्टरपंथियों और अराजक तत्वों के प्रति सहिष्णुता का तो समर्थन करता है, परंतु बहुसंख्यकों और सरकारी तंत्र के प्रति सहिष्णुता का विरोध करता है।

अवधेश राजपूत

तथ्यों को नकारने वाले सांस्कृतिक मार्क्सवाद ने न सिर्फ हर सामाजिक समस्या को समूह दृष्टि से देखने पर बल दिया, बल्कि पूरी दुनिया को शोषक और शोषित जैसे स्थायी वर्गों में बांट दिया। ऐसे में, इस विचारधारा ने कुछ समूहों का अंधा समर्थन और दूसरे समूहों के अंध विरोध को प्रोत्साहित किया। अपने मताग्रह के कारण सांस्कृतिक मार्क्सवाद उन तथ्यों की अनदेखी करता है जो उसकी विचारधारा के खिलाफ जाते हैं। उदाहरण के लिए इस विचारधारा के अनुसार बहुसंख्यक हमेशा शोषक और अल्पसंख्यक शोषित ही रह सकता है। जबकि भारत में ही देखें तो मजहबी और नस्लीय अल्पसंख्यकों ने लंबे समय तक बहुसंख्यकों पर शासन और उनका शोषण भी किया है। असहिष्णुता और कट्टरता को विचारधारा का लबादा ओढ़ाकर सांस्कृतिक मार्क्सवाद ने आज वह स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें यहूदी विद्यार्थी बैरीकेड लगाकर विश्वविद्यालयों में अपनी जान बचा रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया को लगा था कि वामपंथ खत्म हो गया, परंतु अमेरिकी विश्वविद्यालय इसके गवाह हैं कि मार्क्सवाद अपने परिवर्तित रूप में अब भी एक खतरा है और इस्लामी कट्टरपंथियों के साथ इसके गठजोड़ ने सभ्य समाज के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। यह चुनौती भारत में भी उभर रही है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इस समय जो कुछ हो रहा है, उससे भारत को सतर्क रहना होगा।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

समग्र विकास को समर्पित सरकार

हरदीप सिंह पुरी

मोदी सरकार की उपलब्धियां यही सिद्ध करती हैं कि सर्वसमावेशी नीतियों से ही विकसित भारत बनाया जा सकता है

पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकल्प लिया कि वर्ष 2047 में जब देश स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा होगा तब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। दस वर्ष पहले तक यह दावा असंभव लगता। वर्ष 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 'फ्रैजाइल फाइव' करार देकर नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा। उसके उलट भारत अभी विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की राह पर है। यह कैसे संभव हुआ? पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और देश की उत्पादक क्षमता में सुधार लाना है। सरकार का दृष्टिकोण उसकी 'परिपूर्णता की राजनीति' में निहित है, जिसमें बुनियादी ढांचा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सामर्थ्य, हरित अर्थव्यवस्था, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन पर जोर है। योजना बनाना एक बात है और उसे धरातल पर उतारना दूसरी बात। मोदी सरकार इन दोनों ही मोर्चों पर खरी उतरी है। परिणामस्वरूप पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। 'मोदी की गारंटी' आम नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

इस सफलता में हमारे समाज के चार स्तंभों गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं का सशक्तीकरण महत्वपूर्ण रहा है। एक समय गरीबी के चलते पहचाना जाने वाला भारत अब समृद्धि की राह पर है। गरीबों की भलाई के लिए कोविड महामारी के समय मोदी सरकार ने 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देने की जो पहल की थी वह अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी। शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना ने उन स्ट्रीट वेंडरों को राहत प्रदान की, जिनके सामने एकाएक रोजगार की चुनौतियां आ गई थीं। इस योजना में अब तक 63 लाख से अधिक लाभार्थियों को 11,300 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है। साथ ही इसने शहरी गरीबों को डिजिटल रूप से साक्षर होने में भी सक्षम बनाया है। पीएम किसान और पीएम फसल बीमा जैसी योजनाओं से आज 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लैंगिक समानता को प्रमुखता दी जा रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होना महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और जल जीवन मिशन एवं अमृत मिशन के तहत लगभग 14 करोड़ नल-जल कनेक्शन दिए गए। एक दशक पहले तक नल से जल की पहुंच केवल 17 प्रतिशत परिवारों तक थी जो आंकड़ा बढ़कर अब 70 प्रतिशत तक हो गया है। पीएम आवास योजना के तहत लगभग चार करोड़ आवास निर्मित किए गए हैं। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में तीन करोड़ और नए घर बनाने का वादा किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन मंजूर किए जा चुके हैं, जिससे धुआं-रहित रसोई की सुविधा लगभग सभी तक पहुंच चुकी है, जो 2014 तक केवल 55.9 प्रतिशत परिवारों तक सीमित थी। महिलाएं इन योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी हैं, जिसने उनके जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से सुगमता प्रदान की है।

नल से जल ने सुगम बनाया जीवन ● फाइल

वहीं, आयुष्मान भारत जैसी योजना के माध्यम से स्वास्थ्य पर खर्च करीब 25 प्रतिशत कम हो गया है। निम्न-मध्यम वर्गीय भारतीयों को बीमारी के चलते गरीबी का दोहरा झटका झेलना पड़ता था, लेकिन इस योजना के जरिये प्रति वर्ष 55 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को पांच लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इससे भारतीय परिवारों को सालाना लगभग 60,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया गया है। 2013-14 की तुलना में पूंजीगत व्यय में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है, जो 3.92 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राजमार्गों की लंबाई 60 प्रतिशत बढ़ गई है। समूचे ग्रामीण इलाकों में करीब-करीब पक्की सड़कें बन गई हैं। सभी गांवों तक बिजली पहुंच गई है। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग चौगुना हो गया है। विश्व बैंक रैंकिंग के अनुसार हमारे लाजिस्टिक और औद्योगिक परिचालन में काफी सुधार हुआ है। देश में 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। सात नए आइआइएम और आइआइटी की स्थापना की गई है। एम्स की संख्या में तिगुनी वृद्धि हुई है। 51 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम के जरिये 33.43 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है। जीएसटी, आइबीसी, परिसंपत्ति मौद्रीकरण, श्रम कानून सुधार, स्टार्टअप इंडिया और पीएलआइ जैसी आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने वाली सिद्ध हुई हैं। प्रति व्यक्ति आय भी छह गुना बढ़कर 15,000 डालर तक पहुंचने की संभावना है। वैश्विक निवेशक भी इस आशावाद को साझा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत को रिकार्डतोड़ एफडीआइ प्राप्त हो रहा है। घरेलू शासन के साथ-साथ वैश्विक शासन के मामलों पर भी प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक कौशल और दूरदर्शिता को सार्वभौमिक प्रशंसा मिली है।

मोदी सरकार की उपलब्धियां यही सिद्ध करती हैं कि सामाजिक न्याय को चरितार्थ करने वाली सर्वसमावेशी नीति ही विकसित भारत के सपने को साकार करने में सक्षम है। हमें विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए देशहित में सक्रिय रहना होगा। 'राष्ट्र प्रथम' हमारे लिए सर्वोच्च मंत्र है।

(लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम एवं शहरी कार्य मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

कर्तव्य और अधिकार

कर्तव्य के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि जिसे करने के लिए कर्ता स्वाधीन हो, जिससे किसी का अहित न हो, वही कर्तव्य है। वस्तुतः, कर्तव्य से दूसरों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसी कारण किसी का अहित नहीं होता। किसी व्यक्ति में जैसे-जैसे कर्तव्यपरायणता सुदृढ़ होती जाती है, वैसे-वैसे उसकी परतंत्रता स्वतंत्रता में बदल जाती है। यदि हम गहनता से विचार करें तो देखेंगे कि पराधीनता का जन्म एकमात्र अकर्तव्य से ही होता है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति किसी का ऋणी नहीं रहता। उसकी प्रसन्नता किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती। वह प्रत्येक परिस्थिति में पूरी तरह संतुलित रहकर अपने जीवन से प्रसन्न एवं संतुष्ट रहता है।

प्रत्येक मानव में विवेक शक्ति, भाव शक्ति एवं क्रिया शक्ति उपस्थित रहती है। मनुष्य अपने विवेक के प्रकाश में कर्तव्य का दर्शन करता है। इसके पश्चात भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, इसी विवेक शक्ति के अधीन हो जाती है। जो मनुष्य इस प्राप्त विवेक का आदर नहीं करता, वह स्वाधीनतापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्धारण भी नहीं कर पाता। प्रायः कर्तव्य के निर्णय के लिए मनुष्य के स्वयं के आत्मज्ञान, विवेकपूर्ण व्यक्तियों के सत्संग और सद्ग्रंथों के अनुशीलन की आवश्यकता होती है।

कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से गुंथे हुए होते हैं। एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार और दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य पहले व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे व्यक्ति का कर्तव्य समाज का अधिकार और समाज का कर्तव्य व्यक्ति का अधिकार। राष्ट्र का कर्तव्य प्रजा का अधिकार और प्रजा का कर्तव्य राष्ट्र का अधिकार। विद्यार्थी का कर्तव्य आचार्य का अधिकार और आचार्य का कर्तव्य विद्यार्थी का अधिकार होता है।

इस प्रकार एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के सम्यक् परिपालन से दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। निष्कर्षतः, यह कहा जा सकता है कि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करके ही सभी के अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं।

डा. प्रशांत अग्निहोत्री

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

चुनाव एवं राजनीतिक सुधार आवश्यक

'घटते मतदान के लिए नेता भी जिम्मेदार' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में शंकर शरण ने परिपक्व लोकतंत्र के पक्ष में प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए हैं। उनका यह कहना यथार्थ ही है कि अनिवार्य मतदान किसी प्रकार से सार्थक समाधान नहीं है। आखिर मतदाताओं की असहमति भी तो एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। यह सही है कि नोटा जैसे विकल्प की पहल हुई है, लेकिन वह सकारात्मक नहीं है। उसका अभी तक कोई व्यापक प्रभाव भी नहीं दिखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि घटते मतदान के रुझान को लेकर राजनीतिक दल भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि न केवल सार्थक चुनाव सुधारों की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए जाएं, बल्कि राजनीतिक दलों को भी अधिक जिम्मेदार बनाते हुए उन पर अपने भीतर लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए दबाव बनाया जाए। प्रमुख राजनीतिक दल यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में टिकट देने से पहले ही एक प्रकार का चुनाव कराएं, जिसमें जनता या पार्टी कार्यकर्ताओं की किसी प्रकार की भागीदारी संभव हो तो कहीं अधिक लोकप्रिय प्रत्याशी सामने आ सकते हैं। लेखक महोदय का यह सुझाव भी सही है कि ऐसे चुनाव सुधार समय की आवश्यकता हो चले हैं, जिसमें चुनावी प्रक्रिया आकर्षक बन सके। इसके लिए चुनावों में चल निकली बेतहाशा खर्च की परंपरा पर भी किसी प्रकार का अंकुश लगाया जाए, क्योंकि इसके चलते सीमित संसाधनों वाले योग्य लोगों के लिए चुनाव लड़ना संभव नहीं रह गया है। यह भी लोकतंत्र के परिदृश्य को बिगाड़ता है।

गुंजन शर्मा, कमला नगर-नई दिल्ली

सरल व सस्ती हो चुनाव प्रक्रिया

शंकर शरण द्वारा लिखित आलेख 'घटते मतदान के लिए नेता भी जिम्मेदार' पढ़ा। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं जागरूकता अभियान को देखते हुए मतदान में वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक संपन्न हुए चार चरणों के चुनाव में पूर्व की तुलना में मतदान में कमी आई है। मतदान में कमी कई सवालों को जन्म दे रही है। यह चुनावी प्रक्रिया के प्रति मतदाताओं की उदासीनता का प्रतीक है। आज की चुनावी प्रक्रिया महंगी होती जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा एक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 95 लाख खर्च करने की सीमा निर्धारित की है। यह रकम भी आम लोगों की पहुंच से बाहर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार को कई करोड़ का खर्च आता है। कई बार राजनीतिक दलों द्वारा टिकट बेचने की खबरें सामने आती हैं। चुनावों में काले धन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बढ़ते चुनावी खर्च ने योग्य कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने से दूर कर दिया है। एक दौर में उम्मीदवार लोगों से चवन्नी-अठन्नी का सहयोग लिया करते थे, लेकिन आज निर्धन कार्यकर्ताओं के लिए पंचायत चुनाव लड़ना भी सपना हो चुका है। राजनीति में बढ़ता वंशवाद और परिवारवाद लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। प्रचंड गर्मी भी मतदाताओं के उत्साह को ठंडा कर रही है। मतदान में कमी के लिए संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया जिम्मेदार है। सभी राजनीतिक दलों को मिलकर चुनावी प्रक्रिया को सरल, सस्ता और लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना चाहिए।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

निवेश से ज्यादा प्रवासियों की भेजी रकम

'आर्थिकी का सहारा बने प्रवासी भारतीय' शीर्षक लेख में डा. जयंतीलाल भंडारी भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई रकम की भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भूमिका बता रहे हैं। हाल ही में जारी की गई यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रवासियों द्वारा वर्ष 2022 में भेजा गया रेमिटेंस दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह बात भारतीय प्रवासियों के परिश्रम, दक्षता और मातृभूमि के प्रति स्नेह को दर्शाती है। उनके द्वारा भेजी गई 111 अरब डालर की राशि ने देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत विश्व का पहला देश बन गया है, जहां प्रवासियों द्वारा एक साल में 100 अरब डालर से अधिक की रकम भेजी गई है। यह रकम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी ज्यादा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। इसके बावजूद प्रवासी भारतीयों को विदेश में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इजरायल-हमास संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियानों ने यह सिद्ध किया कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके लिए एक स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है, जो प्रवासी भारतीयों की चिंताओं को समझे और उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाए। ताकि वे भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर सकें।

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

पोस्ट

यह समझ नहीं आ रहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार स्वाति मालीवाल के साथ हुई अभद्रता को लेकर मौन क्यों हैं? मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

इस समय शेयर बाजार को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं। मोदी सरकार ने इससे जुड़ी शंकाओं को दूर करने के लिए अंग्रेजी में माहिर एवं तार्किक रूप से अपनी बात रखने वाले मंत्रियों निर्मला सीतारमण और एस. जयशंकर को मोर्चे पर लगाया है।

शेखर गुप्ता@ShekharGupta

दस किलो राशन की बात करके कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अभी तक इनके पास एक मुद्दा तो होता बोलने के लिए, लेकिन यह मुद्दा खुद ही गंवा दिया। अब पांच साल आगे कभी नहीं बोल पाएंगे फ्री राशन क्यों? कहेंगे तो लोग याद दिलाएंगे कि आपने तो दस किलो का वादा किया था। लाला@Lala_The_Don

मोदी सरकार पहले से पांच किलो राशन दे रही है और अब कांग्रेस ने भी दस किलो देने का वादा किया है। क्या विपक्ष की आंखें देर से खुलीं? मैं पहले से कहता रहा हूं कि यह मुफ्त राशन का चुनाव है। लोग नेताओं के बड़े-बड़े वादों से पक चुके हैं। अब उनका ध्यान बुनियादी जरूरतों की पूर्ति पर ही लगा है। राजदीप सरदेसाई@sardesairajdeep

जनपथ

प्रकरण मालीवाल पर दिखे मुदई सुस्त,
क्या कर लेगी पुलिस भी हो करके अब चुस्त।
हो करके अब चुस्त जिन्हें अपनों ने मारा,
वो जब खुद है चुप्प लगेगी कैसे धारा??
स्वयं पूर्व अध्यक्ष न लड़ पातीं हैं जब रण,
तो आखिर किस भांति प्रेरणा दे यह प्रकरण!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 34

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ बृहस्पतिवार, 16 मई 2024

उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए।
-सुभाष चंद्र बोस

भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने से चारधाम यात्रा के दौरान कुछ लोगों के मरने की खबर निश्चित रूप से दुखद है। प्रशासन को जहां भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सक्रियता दिखानी होगी, वहीं श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि नवंबर तक चलने वाली यात्रा के लिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।

थोड़ा धीरज रखिए

अक्षय तृतीया के दिन दस मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से शुरू हुई और बारह मई को बदरीधाम के कपाट खुलने के बाद पूरी तरह संचालित हो रही चारधाम यात्रा पर भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने से सरकारी व्यवस्थाएं तो ध्वस्त हुई ही हैं, यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि यात्रा के पहले तीन दिन में ही पिछले वर्ष की तुलना में 61 फीसदी (केदारनाथ में 67 फीसदी) ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके थे। आलम यह है कि पहले पांच दिनों में ढाई लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, जबकि 27 लाख से ज्यादा अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। जबकि पिछले साल पहले पांच दिनों में महज 52 हजार लोग ही पहुंचे थे। पारिस्थितिक रूप से अस्थिर उच्च हिमालयी क्षेत्र में एकाएक इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने से हालत यह हो गई है कि हरिद्वार से आगे बढ़ते ही कई किलोमीटर लंबे जाम में लोग बीस से पच्चीस घंटों तक फंसे रहे और अब तक दस लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। परेशान हाल लोग प्रशासन की बदइंतजामी को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। मगर नहीं भूलना चाहिए कि सरकार के जो भी इंतजाम थे, वे 2023 में यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखकर किए गए थे। कई लोग तो बगैर रजिस्ट्रेशन भी पहुंच रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस वर्ष करीब 80 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या स्थानीय बुनियादी ढांचा इसको संभालने के लिए तैयार है। 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चारधाम राजमार्ग विकास योजना, जिसे चारधाम ऑल वेदर सड़क परियोजना भी कहा जाता है, की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना। सिर्फ चारधाम ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण इस परियोजना में पिछले वर्ष उत्तरकाशी के सुरंग हादसे से भले कुछ देरी हुई, लेकिन अब यह पूरा होने के कगार पर है। इसके अतिरिक्त

चारों धामों को जोड़ने वाली रेलवे की चारधाम परियोजना के भी अगले वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है। लिहाजा आने वाले वर्षों में इस यात्रा में निश्चित ही दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन फिलहाल चारधाम यात्रा के जो निराशाजनक दृश्य दिख रहे हैं, उनसे निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को तो अतिरिक्त सक्रियता दिखानी ही होगी, लोगों को भी समझना होगा कि यात्रा नवंबर तक चलेगी, ऐसे में, किसी तरह की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।

जैव विविधता का मूल्य समझें

हाल ही में जैव विविधता दिवस चुपचाप बीत गया, लेकिन उसके मूल्य को तभी समझा जा सकता है, जब हम ऐसे परिदृश्य पर विचार करें, जहां जीवन केवल एक ही प्रजाति के रूप में हो। ऐसा जीवन अनिश्चित-सा होगा और ऐसे में पृथ्वी कभी भी दुर्भिक्ष या किसी महामारी के कारण जीवन-विहीन हो सकती है।

जैव विविधता के गॉडफादर के रूप में लोकप्रिय अमेरिकी पारिस्थितिकी विज्ञानी थॉमस ई. लवजॉय की एक मार्मिक टिप्पणी है, 'जैविक विकास की अंतिम विडंबना यह हो सकती है कि मनुष्य के मस्तिष्क के माध्यम से आत्म-समझ प्राप्त करने के तुरंत बाद जीवन ने अपनी सबसे सुंदर रचनाओं को नष्ट कर दिया होगा।' जीवन की विविधता के मूल में एक मूलभूत सत्य निहित है : जगत में सबकुछ अंतर्संबंधों से बंधा है। जैव विविधता जीवन के स्थायित्व और चिरंजीविता के केंद्र में है, किंतु जैव विविधता के योग से भी परे अस्तित्व से आलोक से सराबोर जीवन स्वयं में नैसर्गिक विकास (इवोल्यूशन) की एक मनोरम गाथा का प्रतीक है। जैव विविधता ही जीवन की नैया की खेवनहार है। जितनी अधिक जैव विविधता, उतना ही अधिक जीवन का उत्कर्ष, उतना ही प्रबल जीवनगामी पृथ्वी का ब्रह्मांड में साम्राज्य!

वीर सिंह

जैव विविधता जीवन की शाश्वतता की अनंत कथा है। जैव विविधता प्रकाश की जीवंत कहानी है, जिसे सूर्य का प्रकाश प्रकाश-संश्लेषण के माध्यम से जीवन ऊर्जा के अनंत रूपों में खिलकर आकाशगंगाओं को सुनाता है। प्रकाश की सृजनात्मक क्षमता असीमित है। पेड़-पौधों के पर्णहरित से अठखेलियां कर प्राकृतिक विकास के नवाचारों के झरोखे खोलता प्रकाश अनंत जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों को निरंतर पोषित करता है। जीवन कथा को अमर बनाए रखने के लिए समय की धारा के साथ नई प्रजातियां और उनके आनुवंशिक रूप जीवन को समृद्धि और आनंद का उपहार देते रहते हैं।

एक बहती नदी के समान ऊर्जा जीवन के विभिन्न माध्यमों से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। पदार्थ निष्क्रिय होता है, ऊर्जा क्रियाशील। पदार्थ की क्रियाशीलता ऊर्जा के कारण ही होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिशीलता का स्रोत ऊर्जा ही है। मुक्तावस्था में ऊर्जा विध्वंसक रूप ले सकती है, जिसे एन्ट्रॉपी कहते हैं। असंख्य जीव-वाहिकाओं में प्रकाश

संश्लेषण के माध्यम से प्रवेश कर सौर ऊर्जा एक रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करती है। सभी जीवधारियों का व्यवहार और उनके कार्य-कलाप उसी ऊर्जा की रचनात्मक अभिव्यक्तियां हैं। मुक्तावस्था में यही ऊर्जा अराजक हो सकती थी। ऊर्जा जीवन की जितनी विविधता में क्रियाशील होगी, उतनी ही सृजनशीलता और संतुलन की अवस्था में होगी।

इसी प्रकार, पृथ्वी की भी ब्रह्मांड के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रह्मांड की एन्ट्रॉपी को नियंत्रित कर एक ब्रह्मांडीय संतुलन स्थापित करना ही जैव विविधता-भरी पृथ्वी का अनुष्ठान है। पृथ्वी पर जीवन केवल पृथ्वी का ही नहीं, ब्रह्मांड का एक उपादान है। पृथ्वी का उदय ब्रह्मांड के विकास की अनवरत यात्रा का एक लक्ष्य रहा होगा। ब्रह्मांड में 'बिग बैंग' की घटना से कालांतर में पृथ्वी-रूपी अमृत निकला, जैव विविधता जिसकी बूंदें हैं!

ऐसे परिदृश्य पर विचार करें, जहां जीवन केवल एक ही प्रजाति के रूप में हो। ऐसा जीवन निरा अनिश्चित-सा होगा और ऐसी दशा में पृथ्वी कभी भी दुर्भिक्ष या किसी महामारी के कारण जीवन-विहीन हो सकती है। जीवों की घनी विविधता ने ऐसी संभावनाओं को क्षीण कर दिया। जीवन की स्थिरता, गतिशीलता और निरंतरता उसकी विविधता पर निर्भर है। जैव विविधता जीवन को जलवायु संबंधी अनियमितताओं के प्रति लचीला बनाती है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम जीव समुदायों को पोषित करती है। विविधता स्वयं जीव समुदाय के लिए अस्तित्व का कारक है। जैव विविधता का समृद्ध भंडार जैव-रासायनिक चक्रों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है और जैवमंडल के जीवन-निर्वाह को संरक्षित करती है।

जैव विविधता हमारे जिंदा ग्रह को जीवन-शक्ति प्रदान करती है। इस अद्भुत विविधता के जागरूक प्रबंधक के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन के बहुरूप दर्शन को संरक्षित करना हमारा परम दायित्व है। पारिस्थितिक दार्शनिक हेनरिक स्कोलिमोस्की ने अस्तित्व संरक्षण के लिए जैव विविधता के आंतरिक मोल पर जोर देते हुए मानवता और प्रकृति के बीच गहन अंतर्संबंध को गहराई से स्पष्ट किया है। जीवों के पारस्परिक तालमेल और मानव सहित संपूर्ण जीवन के अस्तित्व के लिए जैव विविधता जीवन के मूल सार का प्रतीक है।

जैव विविधता जीवन की रचनात्मकता की असंख्य अभिव्यक्तियों को दर्शाती है, जिसमें प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्र और आनुवंशिक विविधता का समृद्ध स्पेक्ट्रम सम्मिलित है और जो हमारे ग्रह पर स्वयं हमारी प्रजाति के अस्तित्व के पहले से निवास करते हैं। स्कोलिमोस्की की पारिस्थितिक दर्शन की अंतर्दृष्टि हमें जैव विविधता को केवल दोहन किए जाने वाले संसाधन के रूप में नहीं, वरन एक पवित्र विरासत के रूप में समझने के लिए प्रेरित करती है। सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय रेडवुड तक, प्रत्येक जीव पारिस्थितिक संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जीवन की जटिल प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं। स्कोलिमोस्की की दृष्टि में, जैव विविधता जीवित पृथ्वी की परम आत्मा का प्रतीक है, जिसके बल पर हमारा जैव मंडल जीवन-शक्ति और संतुलन के साथ स्पंदित होता है।

अभूतपूर्व पर्यावरण चुनौतियों के युग में जैव विविधता जीवन के अस्तित्व की कुंजी है। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है और पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है, पारिस्थितिक दर्शन से मिला ज्ञान हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्तों को फिर से जागृत करने और पारिस्थितिक प्रबंधन के प्रतिमान को अपनाने का आग्रह करता है। जैव विविधता से भावी पीढ़ियों के लिए सुख, समृद्धि और संतोष की विरासत सुनिश्चित होती है। हेनरिक स्कोलिमोस्की का पारिस्थितिक-दर्शन अस्तित्व के ब्रह्मांडीय स्पंदन के भीतर जैव विविधता के मोल का गहरा प्रमाण प्रस्तुत करता है। जैव विविधता को एक पवित्र विरासत के रूप में अपनाकर हम अपने ग्रह पर संपूर्ण जीवन के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक रास्ता बना सकते हैं।

-प्रो. एमेरिटस, पर्यावरण विज्ञान, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
edit@amarujala.com

जीवन धारा

एपीजे अब्दुल कलाम

रचनात्मक व्यक्ति कुछ न कुछ करने की इच्छाशक्ति से प्रेरित होता है। आप जो भी करते हैं, वह आपके कौशल और ताकत का हिस्सा बन जाता है, जो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

बिना इच्छाशक्ति के जीवन कैसे बढ़ेगा

सभी मनुष्यों के भीतर तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली हमारी प्रेरणाएं, दूसरी प्रवृत्तियां और तीसरी इच्छाशक्ति। ये तीनों शक्तियां मिलकर जीवन को आगे ले जाने का काम करती हैं। इनमें भी इच्छाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यह तस्वीर कुल मिलाकर वैसी ही बनती है, जैसे एक धनुर्धर के कंधे पर लटका तरकश का तीर, जो हमारे भीतर की प्रेरणा और आवेग का प्रतिनिधित्व करता है। तीरंदाज ने अभी-अभी अपने धनुष से जो तीर छोड़ा, वह उसकी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और तीर छोड़े जाने वाला वह क्षण विशेष उस तीरंदाज की इच्छाशक्ति के साथ कुछ करने की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। हो सकता है कि वह तीर न चलाने का फैसला भी कर लेता। इस प्रकार प्रकृति वह चीज है, जिसे न तो बदला जा सकता है और न उसके प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इच्छाशक्ति अनुसार कुछ करने की आजादी हमेशा रहती है। अगर प्रेरणा और नजरिया पहले से मौजूद है, तो हम इच्छाशक्ति से क्या नहीं कर सकते! व्यक्ति की स्थिति के ये दो पहलू- प्रवृत्ति और इच्छाशक्ति, कैंची के दो हिस्सों की तरह होते हैं। एक हिस्सा इच्छाशक्ति से कार्य करने की स्वतंत्रता है, तो दूसरा हिस्सा प्रेरणा और सहजवृत्ति को बताता है। जब दोनों हिस्से साथ चलते हैं, तो कैंची अपना काम करती है। आप कैंची के सिर्फ एक हिस्से से कपड़ा नहीं काट सकते। इसी प्रकार, किसी कार्य के लिए प्रेरणा, वृत्ति और इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता जरूरी हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। प्रत्येक विचार, भावना, इच्छा और कर्म एक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो अच्छा और बुरा, दोनों ही प्रभाव हम पर डालती है। इसलिए हम अपनी परिस्थितियों, आंतरिक प्रेरणाओं और प्रवृत्तियों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया कैसे करें, कैसे इनमें सामंजस्य बिठाएं, यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। रचनात्मक व्यक्ति कुछ न कुछ करने की इच्छाशक्ति से प्रेरित होता है। आप जो भी करते हैं, वह आपके कौशल और ताकत का हिस्सा बन जाता है, जो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

इन सब के साथ एक और जो बात आती है, वह है हमसे होने वाली गलतियां। मैं आपसे कहता हूं कि गलतियां होना कोई बुरी बात या अपराध नहीं है। गलतियों से ही हम सीखते हैं, गिरकर उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप कई सफल लोगों को यह खुलासा करते देखेंगे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी एक गलती बड़ा कारण रही। अगर वह गलती नहीं होती, तो शायद कामयाबी हासिल नहीं होती। लोग यह सोचकर गलती करने से डरते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सही मायने में देखें, तो गलतियां हमारी यात्रा का हिस्सा हैं। ये हमारी जीवनयात्रा को सुधारने और आगे ले जाने का एक जरिया भी बनती हैं। गलतियां ही हमें बताती हैं कि हमारे भीतर ज्ञान की कमी कहां है। अगर हम ज्ञान बढ़ाएं, मानवता के रास्ते पर चलें, जीवन और व्यवहार में लचीलापन रखें और समझदारी का परिचय दें, तो फिर गलतियों के लिए जगह ही कहां रह जाएगी!

गलतियों से ही सीख मिलती है

सूत्र

यदि हम गलतियां करना बंद कर देंगे तो हम सीखना बंद कर देंगे। गलतियों के बारे में खूबसूरत बात यह है कि हम उन्हें हमेशा सुधार सकते हैं। गलतियां हमें एक सीमित दायरे से बाहर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आपने जो गलती की, वह आपका निर्णायक कारक नहीं है, बल्कि आप उससे कैसे सीखते हैं और कैसे उबरते हैं, यह आपको परिभाषित करता है।

स्मृति

नोबेलजयी कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का 13 मई को निधन हो गया। प्रस्तुत हैं, उनकी स्मृति के अंश...

हम गरीब थे, लेकिन हमारे आसपास हमेशा किताबें थीं

मुझे इस विश्वास के साथ बड़ा किया गया कि सबसे बुरी चीज 'अपने ऊपर ध्यान देना' है या 'खुद को स्मार्ट समझना' है। यह नियम हमारे जैसे देहाती लोगों के लिए था, शहरी लोगों के लिए नहीं। मैंने हमेशा एक स्वीकार्य और निजी जीवन जीने की कोशिश की और ज्यादातर मैं ऐसा करने में सफल रही।

मेरी मां इसका अपवाद थीं, हालांकि शुरू में ही वह पार्किंसंस रोग का शिकार हो गई थीं। मेरी मां अब भी मेरे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनका जीवन बहुत दुखद और अन्यायपूर्ण था। वह बहुत बहादुर थीं। उन्होंने सात साल की उम्र से ही मुझे स्कूल में रविवार को काव्य पाठ करने लायक बनाने के लिए संघर्ष किया।

एलिस मुनरो
(10.07.1931-13.05.2024)

शुरू में मैंने उन चीजों के बारे में लिखा, जो हैरान करती थीं-मृत्यु, प्रेम, चिंताएं, जो जीवन भर भ्रमित करती हैं। जीवन के बारे में लिखने से मेरे लिए जीना सहज हो गया।

मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती थी, जो कॉलेज जाती हो। कॉलेज जाने वाले लड़के भी बहुत कम थे। मुझे केवल दो वर्षों के लिए छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन तब मैं एक लड़के से प्रेम करने लगी थी, जो मुझसे शादी करना चाहता था और मुझे वेस्ट कोस्ट ले जाना चाहता था। अब मैं हर समय लिख सकती थी। लिखने का इरादा मेरा तभी से था, जब मैं घर पर रहती थी। हम लोग गरीब थे, पर हमारे आसपास हमेशा किताबें रहती थीं।

ऐसा नहीं था कि घर के काम या बच्चों के कारण मैं लिख नहीं पाती थी। मैंने जीवन भर घर का काम किया है। हमारे समाज में एक नियम था कि जो महिलाएं लिखने जैसा कुछ अजीब काम करना चाहती थीं, उन्हें गलत माना जाता था और उनकी उपेक्षा की जाती थी। हालांकि मैंने ऐसा किया और ऐसी कई महिलाएं मेरी दोस्त बनीं, जो मजाक करती थीं और छिप-छिपकर पढ़ती थीं। हमने बहुत अच्छा समय बिताया। वास्तव में समस्या मेरे लेखन में ही थी, जो अक्सर अच्छा नहीं होता था। मैं सीखने के दौर से गुजर रही थी। सौभाग्य से उसी समय इस बात का बड़ा शोर मचा कि हमारा कनाडाई साहित्य कहां है। टोरंटो में कुछ लोगों का ध्यान मेरे असहज लेखन पर गया। उन्होंने मेरी मदद की। मैंने अपने लेखन में हमेशा अपने जीवन के कुछ अंशों का उपयोग किया है। कहना चाहिए कि *द व्यू फ्रॉम कैसल रॉक* मेरे अपने परिवार की ही कहानी है।

लेखन की शुरुआत में मैंने उन चीजों के बारे में लिखा, जो मुझे हैरान करती थीं-मृत्यु, प्रेम, हर तरह की चिंताएं, जो हमें जीवन भर भ्रमित करती हैं। जीवन के बारे में लिखने से मेरे लिए जीना सहज हो गया। हालांकि मैं अब भी हैरान हूं, मुझे एहसास है कि जो प्रश्न हम पूछते हैं, वे हमारे द्वारा दिए गए उत्तरों की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प हैं। मुझे यकीन है कि मेरी कहानियों में सामाजिक और राजनीतिक सामग्री है, कम से कम उन शब्दों के व्यापक अर्थ में। जाहिर है कि प्रत्येक मानवीय क्रिया का कोई न कोई राजनीतिक आवेग और सामाजिक परिणाम होता है। लेकिन मैं अपने काम में इन उद्देश्यों की व्याख्या पाठकों या आलोचकों पर छोड़ना चाहूंगी। मुझे अपने साहित्य में किसी संदेश का पैबंद लगाना पसंद नहीं है।

आंकड़े

विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई

अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के बीच विनिर्माण उद्योग में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आया है।

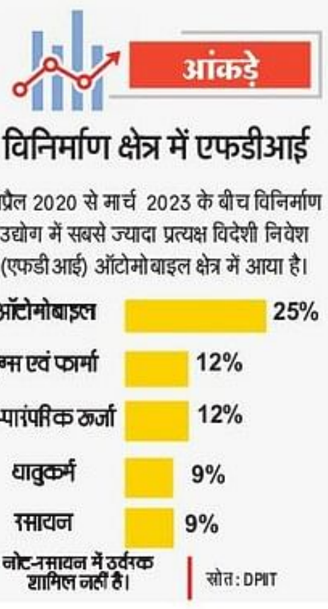

नोट-रसायन में उर्वरक शामिल नहीं है। स्रोत: DPIIT

सच को लाख छिपाओ, वह छिप नहीं सकता है। एक न एक दिन सामने आ ही जाता है।

सामने आई सच्चाई

अंतर्यात्रा
संकलित

एक राजकुमारी को संगीत की शिक्षा देनी थी। वीणा-वादन और संगीत के लिए दूसरे राज्य के राजकुमार उदयन उपयुक्त थे। राजा ने कूटनीति से उन्हें बुलवा लिया। पर राजा दोनों को एक-दूसरे से संपर्क नहीं करने देना चाहता था। इसलिए दोनों के बीच में पर्दा लगा दिया। उदयन से कहा गया कि राजकुमारी दृष्टिबाधित है और राजकुमारी को बताया गया कि उदयन कुष्ठ रोग से पीड़ित है।

शिक्षा शुरू हुई और कई दिनों तक यह क्रम चला। एक दिन उदयन संगीत का अभ्यास करा रहा था। राजकुमारी बार-बार गलतियां कर रही थी। उदयन ने कई बार टोका, फिर भी राजकुमारी उसके स्वरों को पकड़ नहीं सकी। उदयन ने नाराज होकर कहा, कितनी बार बता दिया, फिर भी ध्यान नहीं देती हो। आखिर दृष्टिबाधित जो हो। राजकुमारी ने भी आवेश में कहा-जरा संभलकर बोलो, तुम्हारी तरह कुष्ठ रोगी नहीं हूं। उदयन ने सोचा, मैं कुष्ठ रोगी तो नहीं हूं, फिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों कहा? राजकुमारी ने भी इसी तरह सोचा कि मैं दृष्टिबाधित नहीं हूं, फिर उदयन ने क्यों कहा? सच्चाई जानने के लिए दोनों ने पर्दा उठाया, तो पाया कि दोनों में कोई दोष नहीं है। आवरण हटते ही दोनों के सामने सच्चाई आ गई। इसलिए कहा जाता है कि सच को लाख छिपाओ, वह छिप नहीं सकता है। एक न एक दिन सामने आ ही जाता है।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 09 मई, 1977

उत्पादन कर में कमी के बावजूद चीनी के भाव बढ़े

उत्पादन कर में कमी के बावजूद चीनी के भाव बढ़े

उपभोक्ता क्षेत्रों में खांडसारी की आवक कमजोर होने तथा उत्पादन कर में कमी होने के बावजूद चीनी मिलों द्वारा भाव बढ़ा दिए जाने से गत सप्ताह चीनी के भाव सुधर गए। गुड व खांडसारी में भी मजबूती रही।

जोखिम तो हर टीके में होते हैं

टीकों के बारे में ईमानदार संवाद के साथ जनता को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था उन्हें निराश नहीं करेगी।

पत्रलेखा चटर्जी

स्वास्थ्य

जैसे ही एंग्लो-स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश अदालत में यह स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कुछ दुर्लभ मामलों में टीटीएस (थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम) का कारण बन सकती है, भारत में खलबली मच गई। इसे स्वास्थ्य एवं विज्ञान की कम समझ रखने वाले सोशल मीडिया एन्फ्लुएंसर ने और तेजी से बढ़ाया। टीटीएस की वजह से लोगों में रक्त के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स में भी कमी आती है। ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे कोविशील्ड नाम दिया गया था, को भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया और बेचा था।

चूंकि देश में इन दिनों चुनावी मौसम है, इसलिए अचानक ही यह मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक खेल का हिस्सा बन गया। एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से अपने कोविड-19 टीके को वापस मंगवाने की पहल की। लेकिन यह मुद्दा खबरों में

बना हुआ है। थाईलैंड के अनुसार देश भर में दी गई 4.87 करोड़ खुराक में से केवल सात मामलों में टीटीएस के संदिग्ध मामले पाए गए, जो खतरे की दर को कम दर्शाता है। भारत में इसके प्रति घबराहट का एक मुख्य कारण घरेलू राजनीति है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया, जो मुख्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा। अब सत्ताधारी पार्टी को घेरने वाले सोशल मीडिया एन्फ्लुएंसर और विपक्षी नेता एस्ट्राजेनेका वैक्सीन विवाद में कूदकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

अब तक हम जानते हैं कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के दुष्प्रभाव बहुत ही दुर्लभ हैं। 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी इसका समर्थन किया। अप्रैल 2021 में डब्ल्यूएचओ ने कहा था, 'नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वैक्सजेवरिया और कोविशील्ड टीकों के साथ टीटीएस का जोखिम नगण्य जान पड़ता है। ब्रिटेन के आंकड़ों से पता चलता है कि टीका लगवाने वाले दस लाख वयस्कों में से चार मामलों में टीटीएस का जोखिम था। यानी ढाई लाख पर एक मामला, जबकि यूरोपीय संघ में यह दर अनुमानित रूप से एक लाख पर एक मामला है। कोविड-19 टीकाकरण के बाद टीटीएस जोखिम को लेकर देशों को इसके हानि-लाभ का विश्लेषण करना चाहिए, जो स्थानीय महामारी विज्ञान, टीकाकरण के लिए लक्षित आयु वर्ग और वैकल्पिक टीकों की उपलब्धता पर विचार करता हो। इन दुर्लभ दुष्प्रभावों के जोखिम में भौगोलिक आधार पर भिन्नता हो सकती है। इसलिए सभी देशों में टीटीएस के संभावित मामलों का आकलन महत्वपूर्ण है।'

साक्ष्यों से पता चलता है कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने के कुछ दिनों या हफ्तों बाद टीटीएस के लक्षण सामने आते हैं, न कि वर्षों बाद। यदि वैज्ञानिक समुदाय को कोविशील्ड वैक्सीन के संभावित दुर्लभ दुष्प्रभावों के बारे में पता था, तो फिर लोगों में इतनी दहशत क्यों है? इसका मुख्य कारण है कि टीका संबंधी प्रभावी संदेश के प्रसार के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। प्रत्येक टीके के कुछ जोखिम होते हैं, लंबे समय से प्रचलित टीके के भी। लेकिन गंभीर दुष्प्रभाव दुर्लभ हैं। इसके अलावा दुष्प्रभावों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने का तंत्र भी पारदर्शी नहीं था और टीकाकरण के बाद के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना प्राथमिकता में नहीं था। इससे गलतफहमी पैदा हुई। हम चिंताओं को नकार नहीं सकते। कोविशील्ड समेत हरेक टीके के दुष्प्रभाव होते हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।

लोगों का विश्वास कायम करना जरूरी है, जो टीकाकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य का आधार है। भारत में कोई संगठित टीका विरोधी आंदोलन नहीं है, फिर भी भारत को पोलियो मुक्त होने में कई दशक लगे। मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में छोटे बच्चों में टीका लगवाने को लेकर आपत्ति थी। उनके भय को दूर करने के लिए काफी प्रयास करने पड़े थे। एनएफएचएस-5 (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे) 2019-21 के अनुसार, देश में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 76.1 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि चार में से एक बच्चा जरूरी टीकों से वंचित है। टीके के बारे में एक खुले ईमानदार संवाद की सख्त जरूरत है। जनता के भय को दूर कर यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि स्वास्थ्य व्यवस्था उन्हें निराश नहीं करेगी।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

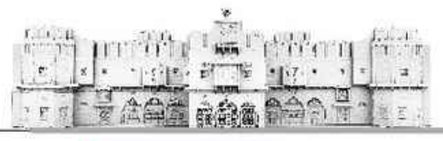

बदइंतजामी से बढ़ीं चार धाम यात्रा में परेशानियां

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ व यात्रा मार्ग में लगे जाम को देखते हुए प्रशासन ने दो दिन के लिए चार धाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करते हुए श्रद्धालुओं से यह भी आग्रह किया है कि वे हालात सामान्य होने तक चार धाम के लिए अपने आगे की यात्रा को फिलहाल रोकें। चार धाम यात्रा में यात्रियों की परेशानियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दो दिन से हजारों यात्री बीच में फंसे वाहनों में ही रात बिताने को मजबूर हैं। गंगोत्री-यमुनोत्री मार्ग पर वाहनों की रेलमपेल के कारण पुलिस ने कई जगह आवागमन को डाइवर्ट भी किया है।

समूचे यात्रा मार्ग में यात्रियों के बीच में फंसे होने और सड़कों पर लगे जाम की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे चिंताजनक और डराने वाली हैं। चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ कोई अचानक उमड़ी हो, ऐसी बात भी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले तुलना करें तो इस यात्रा के पहले दो दिन में ही चालीस फीसदी से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए आए हैं। जाहिर है कि भीड़ प्रबंधन को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए थी, वह समुचित रूप से नहीं की गई। असल में इस पर खास ध्यान ही नहीं दिया गया। चार धाम यात्रा के लिए जाने के इच्छुक श्रद्धालु जिस तरह से पंजीकरण करा रहे हैं, उससे भी लगता है कि इस बार पिछले सालों का रेकॉर्ड टूट सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गांव-कस्बों की अपनी क्षमताएं हैं। यह बात सही है कि चार धाम यात्रा के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं लेकिन यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं की वजह से परेशानियां झेलने को मजबूर होना पड़े तो उसमें प्रशासन की नाकामी ही झलकती है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित किया जाना चाहिए। क्षमता से अधिक लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। रही बात वाहनों के कारण बाधित होने वाले यातायात की, तो यह भी एक तथ्य है कि बड़ी संख्या में निजी साधनों से जाने वाले यात्रियों के कारण वाहनों की रेलमपेल बढ़ती है। सरकारी स्तर पर सार्वजनिक परिवहन का पुख्ता प्रबंध हो तो संकट कम हो सकता है।

चार धाम की इस यात्रा में बदइंतजामी के और भी कई कारण हैं। यात्रा मार्गों को समय पर दुरुस्त नहीं करना भी प्रशासन की बड़ी नाकामी है। अब गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। ऐसे में चार धाम के लिए यात्रियों की आवक और बढ़ने वाली है। वाहनों की बेतरतीब पार्किंग भी संकट बढ़ाने वाली है। यह बात सही है कि धार्मिक पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी संबल देता है लेकिन यात्री सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा।

कल्याण सीट न मिलने से भाजपा नेताओं के मन में खटास, मन से जुड़ेंगे या नहीं यह बड़ा सवाल

सीएम पुत्र के भाग्य के साथ असली व नकली शिवसेना का फैसला भी करेगा मतदाता

मुंबई से
दौलत सिंह चौहान

शिवसेना तोड़ कर भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के डॉक्टर पुत्र श्रीकांत शिंदे तीसरी बार कल्याण लोकसभा सीट से मैदान में हैं। पिछले दो चुनाव उन्होंने शिवसेना से जीते, जो अब टूट चुकी है। यह सीट महाराष्ट्र की उन 13 सीटों में से एक है, जहां दोनों शिवसेना आपस में भिड़ रही हैं। मराठी बहुल कल्याण सीट के मतदाता फैसला करेंगे कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत के हकदार उद्धव ठाकरे हैं या एकनाथ शिंदे।

ठाणे लोकसभा सीट से टूट कर 2009 में बनी कल्याण लोकसभा सीट पर अब तक हुए तीन चुनावों में शिवसेना (टूटने से पहले वाली) ने लगातार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को हराया। एनसीपी भी अब दो टुकड़ों में बंट चुकी है। कांग्रेस का इस सीट पर प्रभाव नजर नहीं आया। सीएम पुत्र के सामने शिवसेना (उद्धव) ने वैशाली दरेकर राणे को मैदान में उतारा है। इस लोकसभा क्षेत्र में गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन जीत-हार का फैसला मराठियों के हाथ में है। भाजपा का प्रभाव इस क्षेत्र में खास कर गुजराती और राजस्थानी मतदाताओं पर है। लेकिन भाजपा की शिंदे के बेटे के साथ लंबे समय से पटरी नहीं बैठ रही है। इस सीट में पड़ने वाली 6 विधानसभा सीटों में से आधी उल्हासनगर, कल्याण पूर्व और डोंबिवली पर भाजपा का कब्जा है, जबकि शिवसेना के पास केवल एक अंबरनाथ सीट ही है। कल्याण ग्रामीण सीट महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और मुस्लिम बहुल मुंब्रा-कलवा एनसीपी शरद पवार गुट के पास है। तीन विधायक होने से भाजपा का दावा इस बार कल्याण सीट पर था और मामला काफी गरम हो गया था। अंततः भाजपा आलाकमान के दखल से फैसला शिंदे के बेटे के पक्ष में हुआ। महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो उत्तेजित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए यह स्पष्टीकरण तक दिया कि कल्याण सीट भाजपा ने इसलिए छोड़ी क्योंकि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपमानित नहीं करना चाहती। इसके बावजूद धरातल पर भाजपा के टिकट के दावेदार नेताओं और उनके समर्थकों का शिंदे के बेटे के लिए मन से जुड़ना बड़ा सवाल बना हुआ है।

डोंबिवली में शिवेसना उद्धव की प्रत्याशी वैशाली राणे का चुनाव कार्यालय।

डोंबिवली में शिवेसना शिंदे के प्रत्याशी श्रीकांत शिंदे का चुनाव कार्यालय।

राज ने बढ़ाई श्रीकांत की मुश्किलें

कल्याण ग्रामीण से मनसे का विधायक है और मनसे प्रमुख महायुती का समर्थन कर रहे हैं। ठाणे और कल्याण लोकसभा सीटों पर महायुती के उम्मीदवारों से समर्थन आयोजित रैली में प्रथम बार मंच पर आए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर बाहरी के खिलाफ आवाज उठा कर शिंदे और भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। गुजराती, राजस्थानी और उत्तर भारतीय संगठनों के नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति उठाते हुए कहा कि भाजपा को हमारे वोट भी चाहिए और वह हमारी पिटाई करने वालों और हमें दुत्कारने वालों से हाथ भी मिलाती है। ये कैसे चलेगा? भाजपा नेता भी उनके सुर में सुर मिला कर खुल कर कह रहे हैं कि देश में कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है, कारोबार या नौकरी कर सकता है। कांग्रेस ने भाजपा पर वार करते हुए कहा है कि राज ठाकरे के बयान पर भाजपा को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

छह लाख वोटों से जीत का दावा

शिवसेना शिंदे के डोंबिवली स्थित मुख्य चुनाव कार्यालय के प्रमुख सागर बापट हालांकि दावा करते हैं कि इस बार श्रीकांत साहेब 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे एक बार क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। शिंदे सरकार में केबिनेट मंत्री रविंद्र चह्वाण, जो डोंबिवली से भाजपा विधायक हैं, श्रीकांत शिंदे के लिए हालांकि दिन-रात काम कर रहे हैं।

कड़ी टक्कर दे रहीं वैशाली

महाविकास अघाड़ी की प्रत्याशी वैशाली राणे कल्याण लोकसभा सीट के डोम्बिवली इलाके की रहने वाली हैं। संगठन पर पकड़ रखने वाली वैशाली तीन बार ठाणे नगर निगम का चुनाव जीत चुकी हैं। एनसीपी टूटने के बाद शरद पवार गुट के प्रमुख नेता बने जितेंद्र अव्हाड़ मुस्लिम बहुल मुंब्रा-कलवा सीट से विधायक हैं, जो महाविकास अघाड़ी के साझीदार के रूप में शिवसेना उद्धव की प्रत्याशी वैशाली के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव के डोंबिवली स्थित मुख्य चुनाव कार्यालय में मिले सह सम्पर्क प्रमुख अरविंद बिरमोल के अनुसार वैशाली लोगों से सीधा संवाद कर रही हैं। वे बोले, पिछले 10 साल में एमपी ने किया क्या है। रेल नेटवर्क का विस्तार न होने से अंबरनाथ से लेकर कलवा तक के उपनगरीय स्टेशनों पर भीड़ में आए दिन ट्रेन से गिरने से लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। शिंदे और भाजपा मेट्रो के झूठे सपने दिखा कर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं।

मतदाता का मानस

कल्याण स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे सुशील कुमार से बात हुई। उनका कहना था कि दिल्ली के चुनाव बड़े और राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। हम वोट भी उसी आधार पर करते हैं, लेकिन यदि स्थानीय और बाहरी की बात करने वालों को तवज्जो दी जाती है तो चिंता तो होती है। फिर जनता काम भी देखती है। मुंब्रा में मोहम्मद इस्माइल नामक युवक से चाय की थड़ी पर बात हुई। वो बोले हमें नहीं पता कौन जीतेगा, पर कोई जीते हारे हमारे यहां के हालात तो सुधरने वाले हैं नहीं। कल्याण में फुटपाथ पर रेडिमेड कपड़े बेच रहे अनमोल से पूछा, उन्होंने कहा कि श्रीकांत साहेब का ही माहौल है। अब तो उनके पिता सीएम हैं तो उम्मीद है कल्याण का भी 'कल्याण' होगा। कलवा के बाजार में महिला सुरेखा ने बताया कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहां की समस्याओं को कोई हल नहीं कर रहा।

समाज भी निभाए जिम्मेदारी

अदालत ने समझाया सप्तपदी का महत्त्व

अदालती निर्णय कई बार सामाजिक सुधारों की पीठिका तैयार करते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रेल 2024 को एक निर्णय के माध्यम से ऐसा ही किया। न्यायाधीश नागरत्ना तथा न्यायाधीश जॉर्ज मसीह की पीठ का निर्णय मूलतः हिन्दू धर्म के विवाह में सप्तपदी तथा दूसरे संस्कारों के महत्त्व के बारे में था किन्तु इस निर्णय में न्यायालय ने मौजूदा समाज की विसंगतियों और उनसे पैदा होने वाली जटिलताओं को उजागर करते हुए अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। डॉली रानी बनाम मनीष का मौजूदा मुकदमा ऐसे दम्पती का था जिसमें दोनों प्रशिक्षित पायलट थे। दोनों ने 2021 के मार्च महीने में सगाई की तथा उसके बाद जुलाई में एक मंदिर में जाकर तथाकथित रूप से विवाह करके एक प्रमाणपत्र ले लिया और फिर उसके आधार पर विवाह का पंजीकरण करा लिया। दोनों के परिवार ने उनकी शादी हिन्दू रीति रिवाजों से करने के लिए 25 अक्टूबर 2024 की तिथि तय की किन्तु आपसी मतभेद इतने बढ़ गए कि वह विवाह विच्छेद के मुकदमे तक आ गया। इस तथाकथित विवाह में सप्तपदी का संस्कार नहीं किया गया था।

प्रो. हरबंश दीक्षित
डीन, विधि संकाय,
तीर्थंकर महावीर विवि
@patrika.com

अन्य बातों के आलावा अदालत के सामने प्रश्न यह था कि क्या सप्तपदी के बिना कोई हिन्दू विवाह को वैधानिक मान्यता दी जा सकती है? इसका उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू विवाह के अनुष्ठानों और उसके कानूनी और सामाजिक सामाजिक प्रभावों की व्यापक विवेचना की। अदालत ने कहा की हिन्दू विवाह एक संस्कार है और हिन्दू विवाह के अंतर्गत उसे तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक की सभी अनुष्ठानों का पालन न कर लिया गया हो। अदालत ने आगे कहा कि भारतीय समाज में हिन्दू विवाह को बहुत सम्मान से देखा जाता है और युवा लोगों को वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले उस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करना चाहिए। इस मामले में सप्तपदी के अनुष्ठान का पालन नहीं किया गया था। इस मामले की खासियत यह है कि अदालत ने अपने को केवल कानून के तकनीकी पहलुओं तक सीमित रखने की बजाय सामाजिक पहलुओं पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह जैसी महत्त्वपूर्ण संस्था को बहुत हल्के में लेने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा विवाह कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है। यह उपहारों और अन्य आर्थिक लेन-देन का माध्यम नहीं है अपितु यह एक पवित्र बंधन है। इसे वर-वधू को सामाजिक मान्यता देकर पति और पत्नी जैसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। अदालत ने कहा कि विवाह केवल नाचने और जश्न का मौका नहीं होता अपितु यह पवित्र वैवाहिक संबंधों कि आधारशिला होती है। इसलिए युवक युवतियों को इसे बहुत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। समाज सुधार के मामलों में अदालतों की भूमिका बहुत सीमित होती है। इसलिए अब समाज की जिम्मेदारी है कि वह इस पहल को अंजाम तक पहुंचाए।

'नेताजी के तारे-सितारे'

अपनी जय-जयकार से घमंड में चूर मत होना

लोकसभा चुनाव के चार चरण पूरे हो चुके हैं। प्रचार में राष्ट्रीय स्तर के नेता पूरे देश में घूम -घूम कर अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इससे स्थानीय नेताओं को अपनी जीत का भरोसा हो रहा है। वे अपने ग्रह-नक्षत्रों पर भी नजर जमाए हुए हैं। देखते हैं कि आज उनके सितारे क्या कह रहे हैं - अज़हर हाशमी

मेष- आज आपकी राशि में पांचवां चन्द्रमा बहुत शुभ है। प्रचार में पंच तत्व 'क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर' स्वयं आपका सपोर्ट करेंगे। वाह।

वृषभ- आज आपके गोचर में चौथा चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं है। प्रचार पर निकलने से पूर्व अपना सिर चार बार 'खुजाएं'। लाभ होगा।

मिथुन- आपकी राशि में गोचर में तीसरा चंद्रमा है, जो कि शुभ है। आप प्रचार में तर्कों से प्रतिद्वंद्वी की बखिया उधेड़ देंगे। वह तिलमिला कर रह जाएगा।

कर्क- आज आपकी राशि में गोचर में दूसरा चंद्रमा शुभ है। प्रचार में आज *'हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा'* होगा।

सिंह- आपकी राशि में गोचर में चंद्रमा आपकी ही राशि में है। आज प्रचार में आप प्रतिद्वंद्वी को 'नानी-दादी' याद दिला देंगे।

कन्या- आज राशि में 12वां चंद्रमा आपके 'बारह' बजा सकता है। प्रचार पर निकलने से पहले प्रतिद्वंद्वी के चमचों को गन्ने का रस पिलाएं।

तुला- आज ग्यारहवां चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद है। आज प्रचार में आपकी ही 'तूती 'बोलेगी। जिससे प्रतिद्वंद्वी की 'नैया 'डोलेगी।

वृश्चिक- आज गोचर में दसवां चंद्रमा शुभ है। दसों दिशाओं में प्रचार में आपकी ही जय-जयकार होगी। आप भी घमण्ड से अकड़ना मत।

धनु- आज आपकी राशि में गोचर में नौवां चंद्रमा अनुकूल है। आपके समक्ष प्रचार में प्रतिद्वंद्वी का 'पटाखा' फुस्स हो जाएगा। बधाई ।

मकर- आज आपकी राशि में आठवां चंद्रमा अशुभ है। अशुभता दूर करने के लिए आठ बार 'नाक भौं सिकोड़ें।' लाभ होगा।

कुंभ- आज गोचर में सातवां चंद्रमा बहुत शुभ है। प्रतिद्वंद्वी के पांव तले धरती' खिसक जाएगी। आज आप छाए रहेंगे। वाह।

मीन- आज गोचर में छठा चंद्रमा अनुकूल नहीं है। आज आपकी जुबान फिसल सकती है। अपनी जुबान को फिसलपट्टी न बनाएं। सावधान

अगला राशिफल सोमवार के अंक में

अमेठी : कार्यकर्ताओं के बीच प्रियंका गांधी

पिता की याद में भावुक संबोधन

उत्तर प्रदेश के अमेठी में पिछले सप्ताह कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते समय प्रियंका गांधी ने अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अमेठी से जुड़ी यादों और अमेठी के साथ गांधी परिवार के रिश्तों का भावुक होते हुए जिक्र किया था। अमेठी व रायबरेली में पार्टी के प्रचार अभियान को पर्दे के पीछे रहकर संभाल रहे कांग्रेस से जुड़े और जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके लेखक ने भाषण से जुड़े पहलुओं को इस दौरान वहां बने माहौल का जिक्र करते हुए समेटा है।

संदीप सिंह
पूर्व छात्रसंघ
अध्यक्ष, जेएनयू
@patrika.com

कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। उस दिन, जब मैं फुर्सतगंज के पास बीच रास्ते में प्रियंका जी से मिला तो उन्होंने कहा था कि पिता जी (राजीव गांधी) के बारे में बोलने का मन है। दिमाग में कमोबेश यही छवि उभरी कि एक राजनीतिक भाषण होगा जिसमें अमेठी से राजीव जी के लगाव और अपनापे का जिक्र होगा। उस दिन का यह आखिरी कार्यक्रम था। रात के लगभग नौ बज रहे थे। रायबरेली में 15 नुक्कड़ सभाओं के बाद अमेठी के कार्यकर्ताओं के बीच उनका यह भाषण था।

अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने भी संक्षेप में भाषण दिया और प्रियंका माइक पकड़ कर खड़ी हो गईं। शुरू के एक दो मिनट हम जैसे लोगों का ध्यान भी नहीं जा पाया कि बोल क्या रही हैं। पिता की जीप में शरारत करते दो बच्चे। वो राजीव जी के बारे में बोल रही थीं। जीप चलाकर अमेठी के गांव-गांव में जाना, जनता से राजीव जी का रिश्ता, उनकी नेकदिली और साहस के साथ साधनों के अभाव व सड़क-खरंजे का जिक्र। हल्का सा एक चित्र उभर रहा था। दिन भर की थकावट के बाद उनकी भरभरा गई आवाज में अचानक एक वाक्य तीर की तरह कान में घुसा। एक किशोर लड़की की घबराहट सुनाई देने लगी।

आगे का भाषण एक लड़की दे रही थी, जो अपने पिता की सलामती के लिए व्रत और उपवास रख रही थी और जिसकी रोज की नींद को देर रात घर लौट रहे पिता की पदचाप का इंतजार रहता था। फिर एक फोन की घंटी बजने का जिक्र आया और मैंने उस पूरी सभा में सन्नाटा पसरते देखा जैसे वह घटना ठीक अभी-अभी घट रही हो। एक बेटी अपनी मां को उसके पति के नहीं रहने की सूचना देने जा रही थी। घड़ी की सुई दस की ओर बढ़ रही थी। उस दिन भी यही समय रहा होगा। उन्नीस बरस की लड़की को, ऐसी स्त्री को उसके प्रेमी की मृत्यु की सूचना देनी थी जिसके लिए वह सात समुन्दर पार अपना सब कुछ छोड़कर भारत चली आई थी।

फिर उन्होंने अपनी मां की आंखों के सामने छाने वाले अंधेरे का जब जिक्र किया तो पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। कई की आंखें नम हो गईं। वे उस हंसी के बारे में भी बोल रही थीं, जो राजीव गांधी के जाने के बाद, उन्होंने उस स्त्री की आंखों में, जिसे वे अपनी मां कहती हैं- दुबारा कभी नहीं देखी। सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। सभा, राजनीति, चुनाव, उसका तनाव सब गायब होने लगा। जब मां द्वारा अमेठी से चुनाव लड़ने के फैसले का जिक्र आया, वर्षों से गुमसुम, विरह में टूटी हुई एक स्त्री के चट्टानी संकल्प का चित्र भी उभर रहा था। भीड़ में से नारा गूंजा ' राजीव भैया अमर रहे'। मैंने चारों तरफ देखा। लोग रो रहे थे। दिल्ली से प्रयागराज जा रही ट्रेन में अपने शहीद पिता की अस्थियों के साथ बैठी एक बेटी के दुःख और क्रोध के पहाड़ को मैंने अमेठी के रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों के आंसुओं की गर्माहट में पिघलते हुए देखा। मैंने उस रात आंसुओं के समंदर में एक लड़की को जीवन का, परिवार का, जनता से एक नेता के सच्चे प्रेम और आदर का अर्थ पाते हुए देखा। तब मेरी उमर आठ-नौ बरस भी नहीं रही होगी, न मैं वहां था, मगर मुझे ऐसे लग रहा था कि यह सब मेरे सामने घटित हो रहा है। मैंने उन्नीस बरस की एक लड़की में अपने देश की महान परंपरा का बीज पड़ते देखा।

मैंने अपनी कल्पना में जनता के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला, एक नेता पैदा होते हुए देखा। लोगों की भीड़ में बैठे पुराने कार्यकर्ताओं का नाम लेकर जिक्र होने लगा और धीरे-धीरे हम सब भावनाओं के ज्वार से उतरने लगे। गर्मियों में अक्सर लग जाने वाली आग में एक किसान का घर स्वाह हो गया था। उसकी मुट्ठी में बेटी की शादी के लिए बचाकर रखे अधजले नोटों की राख थी। भीड़ में सामने खड़ी जामों कस्बे की रमाकांति को जब उन्होंने रोते हुए देखा तो उसकी कहानी सुनाने लगीं और रोने से मना करते हुए उन्होंने कहा 'रोओ मत, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे हिम्मत दी है।' उन्होंने रमाकांति को अपने पास बुला लिया। राजीव भैया की बिटिया का भाषण अमेठी की जनता से रिश्ते की कहानी कहता गया। बोलीं- अगर अपने जीवन में किसी इंसान को पूजा तो वे मेरे पिताजी थे। अमेठी मेरे पिताजी की कर्मभूमि है। मैं इस भूमि को भी पूजती हूं। ये मेरे लिए व राहुल के लिए पवित्र भूमि है। प्रियंका ने लंबा भाषण दिया। फर्क करना मुश्किल था कि कौन बोल रहा है। महज एक बेटी या कांग्रेस पार्टी की एक नेता।

शी जिनपिंग की यात्रा

यूरोपीय देशों को लुभाने की चीन की कोशिश

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया यूरोपीय यात्रा खूब सुर्खियां बटोर रही है। पांच साल में यूरोप की अपनी पहली यात्रा को शी जिनपिंग ने चीन की विदेश नीति की जड़ें फिर से जमाने के लिए इस्तेमाल किया है। पिछले पांच सालों में दुनिया बहुत बदल गई है, खासकर यूरोप महाद्वीप। इस दौरान चीन की आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई है, । चीन ने यूक्रेन युद्ध में रूस का मौन समर्थन करके पश्चिमी जगत को चिढ़ाने का काम किया है और अमरीका के साथ चीन का सामरिक तनाव बढ़ा है। ऐसे में वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए यूरोपीय देशों को लुभाने की चीन की कोशिश कितना रंग लाती है, वह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत को सजग रहने की आवश्यकता है।

विनय कौड़ा
अंतरराष्ट्रीय मामलों
के जानकार
@patrika.com

यूक्रेन में रूस की आक्रामक सैन्य कार्रवाई, अमरीका में डॉनल्ड ट्रम्प की संभावित वापसी और चीन के बढ़ते आर्थिक दबाव ने यूरोप के भू-राजनीतिक परिदृश्य को बेहद जटिल बना दिया है। कई यूरोपीय नेताओं ने शी जिनपिंग से यूक्रेन युद्ध के खात्मे के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया है। हालांकि तेजी से बदली वैश्विक परिस्थितियों में यूरोपीय संघ ने अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीतियों की घोषणा की है, जिसे चीन अपने खिलाफ मानने लगा है। इस पृष्ठभूमि में शी की यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को मजबूत करके यूरोप के साथ राजनयिक संबंधों को स्थिर करना है।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्रांस, सर्बिया और हंगरी का दौरा किया। चीनी रणनीतिकारों ने इन तीन देशों का चयन भी कूटनीतिक नजरिए से किया। शी ने उन यूरोपीय नेताओं को गले लगाने में वक्त बिताया जिनकी गिनती नाटो या यूरोपीय संघ को परेशान करने वालों के तौर पर होती है। यह सही है कि यूरोप, भारत का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है, जो वैश्विक व्यवस्था में उसके रुख का कई मायनों में समर्थन करता है। एकजुट यूरोप वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए भी आवश्यक है, जिससे चीन अपनी शक्ति में इजाफा न कर पाए। इसके लिए यह जरूरी है कि यूरोप के साथ भारत के रिश्तों में और गहराई एवं गंभीरता आए। मुक्त व्यापार समझौते पर लंबे समय से रुकी हुई बातचीत में तेजी लाने की आवश्यकता है।

आज का सवाल

खनन क्षेत्र में हादसों को कैसे रोका जा सकता है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

कीटनाशक भी वजह

खेती में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे कैंसर बढ़ रहा है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का सीमित प्रयोग होना चाहिए।
-प्रेम कुमार पटेल, दमोह , मध्य प्रदेश

नशा भी है कारण

खाद्य एवं पेय पदार्थों में केमिकल का उपयोग, पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का ज्यादा इस्तेमाल, अनियमित जीवनशैली और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण कैंसर बढ़ रहा है।
-डॉ. शिशिर मिश्रा, सीधी, मध्य प्रदेश

तंबाकू से होता है कैंसर

कैंसर के बढ़ते मामलों का कारण खाने की चीजों में मिलाए जाने वाले कृत्रिम रसायन हैं। तंबाकू की लत से भी कैंसर फैलता है। ऐसी चीजों के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए।
-नितेश पाठक, सोडाला, जयपुर

खराब जीवनशैली से हानि

स्वस्थ जीवन शैली व सात्विक आहार-विहार का ध्यान नहीं रखने से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। जंक फूड के अत्यधिक सेवन से भी कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं।
-लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, ' देश में कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? पाठकों की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

rb.gy/p78lgh

चिंतन

भीषण गर्मी व प्रचंड लू से बढ़ रही मौतें चिंताजनक

चुनावी गर्मी के साथ मौसम की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी इस बार प्रचंड गर्मी पड़ने की है। अप्रैल में ही इसकी वानगी हम देख चुके हैं, बीते कुछेक वर्षों की तुलना में इस बार अप्रैल माह अधिक गर्म बीता है। वर्ष दर वर्ष दुनिया भर में तापमान में वृद्धि हो रही है। अत्यधिक गर्मी से भारत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, गर्मी जनित रोग बढ़ रहे हैं, लोगों की मौतें गर्मी से हो रही हैं। भीषण गर्मी व प्रचंड लू से दिन ब दिन बढ़ रही मौतें चिंताजनक हैं। ताजा अध्ययन के मुताबिक, दुनिया भर में प्रति वर्ष 1.53 लाख से अधिक मौतें भीषण गर्मी या लू के कारण होती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 20 फीसदी मौतें भारत में होती हैं। पिछले 30 वर्षों से अधिक के आंकड़ों के आधार पर यह अध्ययन किया गया है। भारत के बाद चीन और रूस का स्थान है, जिनमें से प्रत्येक में क्रमशः लगभग 14 फीसदी और 8 फीसदी मौतें भीषण गर्मी से जुड़ी होती हैं। मोनाश विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में पाया गया कि लू से जुड़ी मौतें गर्मी से संबंधित सभी मौतों का लगभग एक तिहाई और वैश्विक स्तर पर कुल मौतों का एक प्रतिशत है। हर वर्ष गर्मियों में होने वाली कुल डेढ़ लाख से अधिक अतिरिक्त मौतों में से लगभग आधी एशिया में और 30 प्रतिशत से अधिक यूरोप में होती हैं। सबसे बड़ी अनुमानित मृत्यु दर (जनसंख्या के अनुपात में मृत्यु) शुष्क जलवायु और निम्न-मध्यम आय वाले क्षेत्रों में देखी गई। यह अध्ययन 'पीएलओएस मेडिसिन' में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में 2019 तक के दशक की तुलना 1999 तक के दशक से करने पर, दुनिया भर में हर साल भीषण गर्मी की अवधि औसतन 13.4 से 13.7 दिनों तक बढ़ी हुई पाई गई, जिसमें हर दशक में वातावरण का औसत तापमान 0.35 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योग, चिमनियां, वाहनों से निकलने वाले धुएं, अत्यधिक आबादी के चलते कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन, जंगलों में आग, ज्वालामुखी विस्फोट आदि अनेक कारण हैं, जिनसे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। सूर्य से निकलने वाली पराबैगनी किरणों के चलते बने ब्लैक होल से भी धरती पर उत्यधिक उष्मा पहुंच रही है। गर्मी के मौसम में तापमान इतना अधिक बढ़ जा रहा है कि वह लोगों के लिए असह्य हो रहा है। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण चुनाव का प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाता है, शायद इसलिए सरकार इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर एजेंडा तैयार नहीं करती है। 'वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन' (डब्ल्यूडब्ल्यूए) समूह नामक वैज्ञानिकों की टीम ने इस बार अप्रैल में लगातार 17 दिनों तक अत्यधिक गर्मी को खतरे के संकेत के तौर पर लिया है। इस टीम के मुताबिक, इसी तरह की भीषण गर्मी का सामना प्रत्येक 30 साल में एक बार करना पड़ सकता है और जलवायु परिवर्तन के कारण पहले से ही इसकी संभावना लगभग 45 गुना अधिक हो गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रचंड लू पूरे एशिया में गरीबी में रहने वाले लोगों के जीवन को और अधिक मुश्किल बना रही है। भीषण गर्मी व प्रचंड लू के चलते स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है। आज जरूरत जलवायु परिर्तन के असर को कमतर करने के लिए हरित पर्यावरण, प्राकृतिक रहन-सहन व खान-पान, भीषण गर्मी की चेतावनी प्रणाली, हरित विकास व स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच आदि के क्षेत्र में समग्रता से काम करने की जरूरत है।

विश्लेषण

प्रमोद भार्गव

पाक के खिलाफ खौल रहा पीओके

पीओके में लगातार विद्रोह की आग सुलग रही है, यहां तक कि हालात बेकाबू हो गए हैं और पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। समूचे पाक अधिकृत कश्मीर में धारा-144 लागू होने के साथ मोबाइल-इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। महंगाई, बिजली और आटे पर सब्सिडी की छूट के चलते यह आंदोलन इतना आगे बढ़ गया है कि एक पुलिस अधिकारी की गुस्साए लोगों ने हत्या कर दी। पीओके में कुल 10 जिले हैं। यह आंदोलन भींबर से शुरू हुआ और सभी जिलों में फैल गया। आंदोलन का संचालन करने के लिए एक नया संगठन 'ज्वांइट अवामी एक्शन कमेठी' बनाया है, जिसमें सभी जिलों के लोग भागीदार है। अब पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में लगातार विद्रोह की आग सुलग रही है, यहां तक कि हालात बेकाबू हो गए हैं और पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। समूचे पाक अधिकृत कश्मीर में धारा-144 लागू होने के साथ मोबाइल-इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। महंगाई, बिजली और आटे पर सब्सिडी की छूट के चलते यह आंदोलन इतना आगे बढ़ गया है कि एक पुलिस अधिकारी की गुस्साए लोगों ने हत्या कर दी। पीओके में कुल 10 जिले हैं। यह आंदोलन भींबर से शुरू हुआ और सभी जिलों में फैल गया। आंदोलन का संचालन करने के लिए एक नया संगठन 'ज्वांइट अवामी एक्शन कमेठी' बनाया है, जिसमें सभी जिलों के लोग भागीदार है। शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलनकारियों की मांग है कि पाकिस्तान सरकार की भ्रष्ट शासन-प्रणाली से वे तंग आ चुके हैं, अतएव पाक के साथ रहना नहीं चाहते हैं। हमें इससे आजादी चाहिए। घबराई शहबाज शरीफ सरकार ने हुए नुकसान को नियंत्रित करने की दृष्टि से 23 अरब का बजट प्रावधान पीओके के लिए किया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जो मांगें उन्होंने रखी हैं, वे सभी मान्य की जाएं। अन्यथा वे प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी समय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एक दिन हम पीओके पर अवैध कब्जे को समाप्त करेंगे और पीओके वापस भारत के साथ जुड़ जाएगा।

पीओके के लोगों के साथ वाकई अन्याय हो रहा है। यहां के लोगों को उत्पादन लागत पर बिजली नहीं मिल रही है। जो बिजली पीओके में बनाई जाती है, उसे सरकार पीओके से दो रुपये प्रति यूनिट लेती है और फिर यहीं के लोगों को महंगी दरों पर बेचती है। पीओके में रहने वाले लोगों को सब्सिडी पर आटा देना रोक दिया है, जबकि आटा पेट की भूख मिटाने की बुनियादी जरूरत है। आटा समेत अन्य 30 वस्तुओं पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। लोगों ने यह भी मांग की है कि पीओके की अफसरशाही और 53 मंत्रियों को मिलने वाली विलासी सुविधाएं बंद की जाएं। इन्हें सरकार की ओर से महंगी व लग्जरी गाड़ियां और घर के साथ टीए-डीए मिल रहे हैं। इन्हें बंद किया जाए। यही नहीं इनके जो सहायक है, उन्हें भी ऐसे ही सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कतई उचित नहीं है। इन्हें बंद किया जाए। हालांकि पीओके में पाक से अलगाव का संकट इतना बढ़ गया है कि अब समझौते कि दूर-दूर तक कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है।

शायद इस स्थिति का पूर्वाभास करने के बाद ही जयशंकर ने जल्द पीओके का भारत में विलय होने का दावा किया है। यही नहीं उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर इसका विलय होगा। क्योंकि वहां के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी तरसने को मजबूर हो रहे हैं। तिस पर भी राहत देने की बजाय पाकिस्तानी सेना अत्याचार पर आमादा है। लोग पाक सेना से आजादी और भारत में शामिल होने के लिए नारे लगा रहे हैं। गुलाम जम्मू-कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर यह पहली उच्च स्तरीय प्रतिक्रिया हैं। इस परिप्रेक्ष्य में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अतएव अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार

की पीओके के संदर्भ में कोई न कोई ऐसी रणनीति अवश्य चल रही है, जो विलय की दिशा में बढ़ रही है।

दूसरी तरफ जिस आतंकवाद का जनक पाकिस्तान रहा है, वही आतंकवाद अब उसके लिए पीओके में चुनौती बनकर सामने आ रहा है। पाक में आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ माह पहले ही बलूचिस्तान प्रांत के तुरबाद नगर में नौसैनिक अड्डे पर आतंकवादियों ने गोली बरसाते हुए हमला किया था। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा इलाके में चीनी नागरिकों के एक काफिले पर हमला बोल दिया था। इसमें पांच चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। ये इंजीनियर दासू हाइड्रोप्रोजेक्ट के निर्माण में लगे थे। इन हमलों की जुम्मे वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) की मजीद ब्रिगेड ने ली हुई है। इस्लामाबाद से 200 किमी दूर स्थित दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण चीनी कंपनी कर रही है। 2021 में भी इस परियोजना पर काम कर रहे नौ चीनी इंजीनियरों सहित 13 लोगों को बलूच हमलावरों ने मार गिराया था। पाकिस्तान में अकेले फरवरी माह में हुए 97 हमलों में 118 लोग मारे जा चुके हैं। 20 मार्च को ग्वादर बंदरगाह पर भी आतंकी हमला हो चुका है। इस हमले की जिम्मेदारी भी बलूचों ने ली है। इन हमलों के चलते पाक में नई बनी शाहबाज सरकार मुसीबतों से घिर गई है। दरअसल बलूचिस्तान प्रांत के नागरिक मानते हैं कि पाक सरकार उनके प्रांत के हितों की लंबे समय से अनदेखी कर रही है। यहां के लोग इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप का भी विरोध कर रहे हैं। दासू हाइड्रोप्रेजेक्ट और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के निर्माण के अंतर्गत कई परियोजनाएं पीओके में निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का विरोध लगातार हो रहा है, लेकिन पाक सरकार धन के लालच में चीन के सुरसा मुख में फंस चुकी है। देश में चल रही आर्थिक बदहाली के कारण भी सरकार चीन का दामन नहीं छोड़ पा रही है। चीन से उसकी मित्रता का कारण धन का लालच तो है ही, भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते भी हैं। पाक की तरह चीन से भी भारत का सीमा पर निरंतर तनाव बना हुआ है। अब पीओके में आतंकी शक्तियां इतनी मजबूत हो गई हैं कि पाक का अफगानिस्तान व ईरान से भी मधुर संबंध बनाए रखना मुश्किल हो रहा है।

पीओके की परिधि में आने वाले गिलगिट-बाल्टिस्तान वास्तव में भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य के हिस्सा हैं। बावजूद 4 नबंवर 1947 से पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं, लेकिन यहां के नागरिकों ने इस बलात कब्जे को कभी नहीं स्वीकारा। यहां तभी से राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आवाजें उठ रही हैं और पाक सरकार इन लोगों पर दमन और अत्याचार का सिलसिला जारी रखे हुए है। साफ है, पाक की आजादी के साथ गिलगिट-बाल्टिस्तान का मुद्दा जुड़ा हुआ है। पाक की कुल भूमि का 40 फीसदी हिस्सा यहीं है, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच हैं, इसलिए इसे गिलगिट-बलूचिस्ताल भी कहा जाता है। पाक और बलूचिस्तान के बीच संघर्ष 1945, 1958, 1962-63, 1973-77 में होता रहा है। 77 में पाक द्वारा दमन के बाद करीब 2 दशक तक यहां शांति रही, लेकिन 1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और फिर से संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगावावादी आंदोलन वजूद में आए, इनमें प्रमुख बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। निर्वाचन की प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद भी यहां की विधानसभा को अपने बूते कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। सारे फैसले एक परिषद लेती है, जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। लिहाजा चुनाव के बावजूद भी यहां विद्रोह की आग सुलगी रहती है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस

योगेश कुमार गोयल

वर्ष दर वर्ष जानलेवा होता डेंगू

अन्य घातक बीमारियों के साथ-साथ डेंगू भी अब ऐसी गंभीर बीमारी बन चुका है, जिसके जोखिम को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। प्रतिवर्ष डेंगू के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। डेंगू उन घातक बीमारियों में से एक है, जिसका यदि समय से इलाज नहीं मिले तो यह जानलेवा हो सकता है। भारत में प्रायः जून से अक्तूबर के दौरान डेंगू के सर्वाधिक मामले सामने आते हैं। अब तो स्थिति यह है कि देशभर में डेंगू की भयावहता को लेकर हर साल हाहाकार सा मचा नजर आता है। डेंगू से बचाव को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ही प्रतिवर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विशेष थीम के साथ 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस 'डेंगू रोकथामः सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी' विषय के साथ मनाया जा रहा है। मानसून के साथ डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों के पनपने का मौसम शुरू होता है, इसीलिए इस बीमारी को लेकर लोगों में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा इसके लिए 16 मई का दिन निर्धारित किया गया।

डेंगू के लगातार सामने आते मामलों को देखते हुए डेंगू से बचाव को लेकर अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अभी तक इसकी कोई वेक्सीन नहीं बनी है, इसलिए डेंगू से बचाव के उपाय ही सबसे अहम हैं। वर्ष 2018 में भारत में एक लाख से भी ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए थे और एम्स द्वारा डेंगू के दस वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह तथ्य भी सामने आया था कि केवल एम्स में ही डेंगू से मृत्युदर 7-10 फीसदी थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2023 में देश में डेंगू के मामलों की संख्या करीब ढ़ाई लाख थी। माना जाता रहा है कि अक्तूबर माह के बाद रात के तापमान में गिरावट आने पर डेंगू के मच्छर स्वतः ही खत्म हो जाते हैं लेकिन समय के साथ-साथ स्थिति खतरनाक होती जा रही है और डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का प्रकोप अब सर्दी के मौसम में भी शांत नहीं होता। डेंगू अब साल-दर-साल इतना जानलेवा होता जा रहा है कि मौसम में बदलाव के बावजूद सर्द मौसम में डेंगू के सैंकड़ों मरीज सामने आने लगे हैं।

डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को प्रायः तेज सिरदर्द होता है और लगातार बुखार आता है, जो 100 डिग्री के आसपास बना रहता है लेकिन डेंगू के मरीजों के मामलों में कुछ समय से यह चिंताजनक स्थिति भी देखी जाने लगी है कि बहुत से मरीज अब ऐसे भी सामने आते हैं, जिनमें बुखार तथा सिरदर्द जैसे लक्षण नदारद होते हैं और केवल शारीरिक कमजोरी तथा प्लेटलेट्स कम होने जैसे लक्षण ही देखने को मिलते हैं। सिर्फ थकान और कमजोरी की शिकायत करने वाले ऐसे मरीजों में डेंगू की पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है। रक्त जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर ही उनमें डेंगू की पुष्टि की जा सकती है। डेंगू के लक्षणों में आए इस बड़े बदलाव को लेकर किए गए अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि एडीस मच्छर के वायरस और स्ट्रेन में बदलाव के कारण ही ऐसा हो रहा है। हालांकि चिकित्सक इस बदलाव को जानलेवा तो नहीं किन्तु चिंताजनक अवश्य मानते हैं।

वायरस संक्रमण के कारण डेंगू होता है, जो मादा एडीस मच्छर के काटने से होता है। केवल मादा मच्छर में ही डेंगू का वायरस होता है और यह मच्छर दिन में ही काटता है। एडीस मच्छर के काटने के करीब 3-5 दिनों बाद डेंगू के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वायरस संक्रमण श्वेत रक्त कोशिकाओं पर धावा बोलता है, जिससे डेंगू पीड़ित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर हो जाती है। प्लेटलेट्स कम होने पर शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। इलाज सही मिले तो स्थिति जल्द नियंत्रित हो सकती है अन्यथा डेंगू जानलेवा साबित हो सकता है। जब डेंगू अपनी खतरनाक अवस्था में पहुंचता है तो जानलेवा हो जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में रोगी की प्लेटलेट्स बेहद कम हो जाती है, उसका रक्तचाप तेजी से नीचे गिरता है और शरीर के अंदरूनी अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। डेंगू के प्रमुख लक्षणों में लगातार बुखार रहने के साथ-साथ सिरदर्द, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण देखे जाते हैं। इसके अलावा बुखार के साथ नाक बहना, खांसी, आखों के पीछे दर्द, त्वचा पर हल्के रैशेज, भूख कम होना, कमजोरी जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं और कुछ लोगों में लाल व सफेद निशानों के साथ पेट खराब होने, जी मिचलाने, उल्टी लगने जैसे लक्षण भी सामने आते हैं। व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद आज भी बहुत से लोग यही मानते हैं कि डेंगू का मच्छर गंदी नालियों या दूषित जल में ही पनपता है जबकि वास्तव में वायरस जनित यह खतरनाक बीमारी साफ-सुथरे पानी में पनपने वाले एडीज मच्छरों के काटने से फैलती है। डेंगू के मच्छर प्रायः मानसून के बाद ठहरे हुए साफ पानी में पैदा होते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शिव के अंश से जन्म पर मनुष्य ज्ञानी होता है

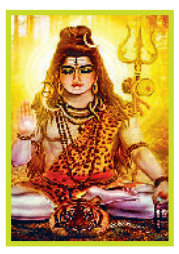

संकलित

दर्शन

साधक दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के साधक का स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह होता है, दूसरे प्रकार के साधक का स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है, पर बिल्ली का बच्चा स्वयं मां को नहीं पकड़ता, मां उसे जहां छोड़ दे, वहीं पड़ा रहता है। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़े रहता है, इसलिए अगर कभी उसका हाथ छूट जाए तो वह गिर पड़ता है और उसे चोट पहुंचती है। पर बिल्ली के बच्चे को यह भय नहीं है, क्योंकि उसे उसकी मां स्वयं पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसी प्रकार, ज्ञानयोगी या कर्मयोगी साधक बंदर के बच्चे की तरह स्वयं के प्रयत्न से मुक्तिलाभ करने का प्रयास करता है, परंतु भक्त साधक ईश्वर को ही एकमात्र कर्ता जानकर बिल्ली के बच्चे की तरह उन्हीं के चरणों में निर्भय होकर निश्चित पड़ा रहता है। ज्ञानी कहता है सोहम। मैं ही वह शुद्ध आत्मा हूं। परंतु भक्त कहता है, अहा, यह सब उनकी ही महिमा है। यह सब कुछ मैं हूं, यह सब कुछ तुम हो, तुम स्वामी हो, मैं सेवक-इन तीन भावों में से किसी भी एक में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित होने पर ही भगवत्प्राप्ति होती है। शिव के अंश से जन्म होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। विष्णु के अंश से जन्म हो तो प्रेम-भक्ति होती है। उसके मन से प्रेम-भक्ति कभी नहीं जाती। बहुत ज्ञान विचार करने के बाद यदि किसी समय यह प्रेम-भक्ति कुछ कम भी हो जाए तो फिर और एक समय यह यदुवंश का ध्वंस करने वाले मूसल की तरह देखते-देखते बढ़ भी जाती है।

राजा हैं, फिर भी घमंडी ना बनें

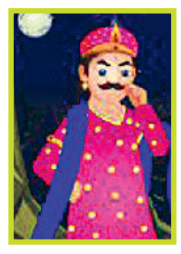

संकलित

प्रेरणा

एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत घमंडी था। उसके घमंड के चलते आस पास के राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार उस गाँव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की सोची।साधु तेजी से राजमहल की ओर गए और बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से में भर गया। राजा बोलाः ये क्या उदण्डता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दियाः मैं आज रात इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी वो बोलाः महात्मा जी ये मेरा राज महल है कोई सराय नहीं, कहीं और जाइये। साधु ने कहाः हे राजा, तुमसे पहले ये राजमहल किसका था? राजाः मेरे पिताजी का, साधुः तुम्हारे पिताजी से पहले ये किसका था? राजाः मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्करा कर कहाः हे राजा, जिस तरह लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते है वैसे ही ये तुम्हारा राज महल भी है जो कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है ये एक सराय ही है जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। साधु की बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट, मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ा।

अंतर्मन

आज की पाती

बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं की जड़

हमारा देश विकास और अन्य बहुत से अच्छे कामों में दुनिया भर में नंबर वन पर है और आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में भी हमारा देश दुनिया भर में एक नंबर पर पहुंच चुका है। इस मामले में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गई है और भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। अगर भारत सरकार और देश का आमजन बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए गंभीरता दिखाए तो भारत जनसंख्या वृद्धि के मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकना नितांत आवश्यक है क्योंकि इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं।

–मनीष पांडे, जगदलपुर

ट्रेंड

जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे

ओड़िशा में भाजपा सरकार बनने पर 6 दिन के अंदर श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी से संबंधित जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। हम श्री जगन्नाथ भक्तों के लिए मंदिर के सभी चारों द्वारों को खोलकर मंदिर की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे।

-अमित शाह, केंद्रीय मंत्री

सच्चाई नहीं दिखती

प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में बोला कि मैं यहां का प्याज खाकर और यहां के कपास से बने हुए कपड़े पहनकर बड़ा हुआ हूं। वो ये भी कहते है मैंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारा। उनकी एक भी बात में सच्चाई नहीं दिखती।

-मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष

जनता का पैसा

भाजपा ने गूगल पर 100 करोड़ का प्रचार करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये जनता का पैसा है, जो चुनावी चंदे के रूप में कंपनियों से बटोरा है और जनता से वसूला है और दूसरी तरफ़ कोरोना के दौरान घपले वाला केयर फंड बनाकर भाजपा ने जनता से सीधे भी वसूला है।

-अखिलेश यादव, सपा नेता

एआई सीखेंगे

अगली पीढ़ी के फिल्म निर्माता फिल्म स्कूलों में नहीं जाएंगे। वे सीखेंगे कि एआई सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी फिल्म को कैसे 'प्रॉम्प्ट' किया जाए। क्या मैंने अगली पीढ़ी कहा? हम अगले साल इस बार एआई जेनरेट फिल्में बनाएंगे।

-शेखर कपूर, फिल्म निर्माता

करंट अफेयर

तीसरी बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी

पाकिस्तान मूल के एक प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक मजबूत नेता हैं जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बाल्टीमोर निवासी पाकिस्तानी अमेरिकी कारोबारी साजिद तरार ने कहा कि मोदी न केवल भारत के लिए अच्छे हैं बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी अच्छे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान को भी उनके जैसा कोई नेता मिलेगा। तरार ने कहा, 'मोदी एक शानदार नेता हैं। वह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान का दौरा किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मोदी जी पाकिस्तान के साथ संवाद और व्यापार शुरू करेंगे।' एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'भारत के लिए भी शांतिपूर्ण पाकिस्तान अच्छा होगा।' उन्होंने कहा कि हर जगह यही कहा जा रहा है कि 'मोदी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे'। तरार 1990 के दशक में अमेरिका आकर बस गए थे और पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों से उनके अच्छे संपर्क हैं। उन्होंने कहा, 'यह चमत्कार से कम नहीं है कि भारत में 97 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं वहां मोदी जी की लोकप्रियता देख रहा हूं और 2024 में भारत का शानदार उदय होते देख रहा हूं।

ऑफ बीट

धार्मिक अनुभव बदल सकता है मेटावर्स

नई तकनीकें हमेशा हमारे धार्मिक अनुभवों में नयापन और बदलाव लेकर आई हैं। 1880 के दशक में रेडियो सुनना कई लोगों की नजर में धार्मिक महत्व रखता था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि रेडियो में सुनाई दे रही आवाज किसी और लोक से आ रही है। उस दौरान प्रेतात्माओं से संवाद करने के लिए होने वाली सभाएं काफी लोकप्रिय हो गई थीं क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि रेडियो ने आध्यात्मिक दुनिया के लिए एक द्वार खोल दिया है। भले ही दुनिया के कुछ हिस्सों में औपचारिक धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी में कमी देखी जा रही है, लेकिन नयी तकनीकें हमारे आध्यात्मिक जीवन में नयापन लाती रहेंगी। हमारे समय का सबसे नया माध्यम मेटावर्स एक सूचनात्मक और अनुभवात्मक तकनीक है, जहां उपयोगकर्ता आभासी वास्तविकता (वीआर) में बनाए गए सामाजिक वातावरण में बातचीत कर सकते हैं। मेटावर्स को पहले से मौजूद तकनीकों का उपयोग करके व्यवस्थित और निर्मित किया जा रहा है। इसके पूर्ण रूप और विकास के लिए उन तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता होगी जो अभी तक मौजूद नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मौजूदा तकनीक का उपयोग करके 3डी ऑनलाइन स्पेस में तेजी से प्रतिपादन या कंप्यूटिंग संभव नहीं है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://epaper.haribhoomi.com

कल्पमेधा

क्रोध करने का मतलब है, दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना; जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करो।

– कन्फ्यूशियस

महंगाई का रुख

सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए कई वर्ष से प्रयास कर रही है, मगर इसमें स्थिरता नहीं आ पा रही। रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई पांच फीसद के नीचे रखने की मंशा से कई बार बैंक दरों में बढ़ोतरी की और अभी तक वह उनमें कटौती करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा। खुदरा महंगाई पिछले महीने बढ़ कर 7.74 फीसद पर पहुंच गई। अब थोक महंगाई अपने तेरह महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। पिछले महीने यह 1.26 फीसद दर्ज हुई। पिछले वर्ष मार्च में यह 1.41 फीसद थी। थोक महंगाई पिछले दो महीने से लगातार बढ़ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कहना है कि अप्रैल महीने में खाद्य वस्तुओं, बिजली, कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस, खाद्य उत्पाद विनिर्माण और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से थोक महंगाई बढ़ी है। इस स्थिति में कब तक सुधार की संभावना है, इसे लेकर कोई आकलन पेश नहीं किया गया है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में कब नरमी दर्ज होगी, कहना मुश्किल है। विश्व में जिस तरह संघर्ष की स्थितियां और मंदी का दौर है, उसमें कीमतों में कमी को लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता।

विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में महंगाई बढ़ने की वजहें भी साफ हैं। कोयला उत्पादन क्षेत्र में विकास दर सुस्त बनी हुई है। कोयला आयात बढ़ा है। ऐसे में बिजली उत्पादन पर असर पड़ना स्वाभाविक है। विनिर्माण में लागत पर खुदरा महंगाई का भी असर होता है। कोयला और बिजली की कीमतें बढ़ने से भी इस क्षेत्र में महंगाई बढ़ती है। इससे जाहिर है कि अभी आने वाले समय में जल्दी इस स्थिति में किसी सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। महंगाई का एक बड़ा कारण विकास दर में असंतुलन भी है। कुछ क्षेत्रों में विकास दर काफी ऊंची है, तो कुछ में नीचे का रुख बना हुआ है। थोक महंगाई बढ़ने का अर्थ है कि खुदरा महंगाई पर उसका सीधा असर पड़ेगा। अगर वस्तुओं के उत्पादन पर लागत बढ़ेगी, तो खुदरा वस्तुओं की कीमतें उसके अनुपात में कहीं अधिक बढ़ी हुई दर्ज होंगी। फिर, चूंकि महंगाई का आकलन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है, वास्तविक महंगाई उससे कहीं अधिक होती है। इसीलिए अक्सर जब सरकारी आंकड़ों में महंगाई का स्तर घटा हुआ दर्ज होता है, तब भी आम उपभोक्ता कोई राहत महसूस नहीं करता।

आम चुनाव की सरगर्मी में विपक्षी दलों ने महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है। इसलिए थोक महंगाई के ताजा आंकड़े एक बार फिर उन्हें सत्तापक्ष की आलोचना का अवसर देंगे। यह एक अजीब तरह का असंतुलन है कि देश की अर्थव्यवस्था का रुख ऊपर की तरफ है, जबकि महंगाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसकी कुछ वजहें साफ हैं। महंगाई को सहनशील स्तर पर लाने के लिए जरूरी है कि बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़े, मगर बेरोजगारी बढ़ने, प्रति व्यक्ति आय घटने और क्रयशक्ति छीजती जाने की वजह से बाजार में संतुलन नहीं बन पा रहा। जिस मौसम में नई फसल की आवक तेज होती है, उसमें भी खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें ऊंची रहती हैं। दूसरी तरफ किसान फसलों की वाजिब कीमत न मिल पाने से परेशान दिखते हैं। जब तक अर्थव्यवस्था में कायम असंतुलन दूर करने का प्रयास नहीं होता, महंगाई पर काबू पाना कठिन ही बना रहेगा।

सुशील मोदी

वे बिहार में भाजपा का प्रमुख चेहरा थे। यह उनके मिलनसार, भरोसेमंद व्यक्तित्व और राजनीतिक कुशलता का ही नतीजा था कि बहुमत हासिल न कर पाने के बावजूद भाजपा बिहार में कई बार सत्ता में रही। सुशील मोदी की नीतीश कुमार से गहरी दोस्ती थी। हालांकि दोनों के दलों की वैचारिक पृष्ठभूमि अलग थी, पर सुशील मोदी पर नीतीश कुमार का भरोसा इतना दृढ़ था कि वे भाजपा के साथ गठबंधन करने को तैयार हुए। यहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल कर चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के बाद भी उन्होंने उसका साथ छोड़ा और भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। सुशील मोदी जयप्रकाश नारायण के प्रभाव में राजनीति में आए थे। फिर वे भाजपा के साथ हो गए और आजीवन उससे जुड़े रहे। वे प्रबुद्ध राजनीतिकों में से थे। हर वक्त देश-दुनिया की घटनाओं पर नजर रखते थे। वित्तीय मामलों की उन्हें गहरी समझ थी। यही वजह है कि नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें वित्त मंत्रालय का भार भी सौंपा गया था। वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने कई उल्लेखनीय काम किए। जिस समय जीएसटी की रूपरेखा तैयार हो रही थी, सुशील मोदी को राज्यों के वित्तमंत्रियों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।

करीब पचास वर्ष वे राजनीति में रहे। अलग-अलग समय में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदनों के लिए वे निर्वाचित हुए। उपमुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य राजनीतिक पदों पर रहते भी उनका व्यक्तित्व सदा बेदाग रहा। उन पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मृदुभाषी थे। अपने विरोधियों के बारे में भी वे कभी तल्ख नहीं देखे गए। बहुत सोच-समझ कर और अर्थपूर्ण टिप्पणी करते थे। वे बिहार के लोकप्रिय नेताओं में थे। बिहार में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण हैं, उसमें भाजपा को मजबूत स्थिति में खड़ा करने में सुशील मोदी का बड़ा योगदान था। हालांकि भाजपा को यह मलाल है कि अभी तक वह अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। मगर जिस तरह सुशील मोदी ने एनडीए को वहां कामयाबी दिलाई थी, वह उनके बाद की पीढ़ी के नेताओं के सामने एक बड़ी लकीर है। उनका जाना भाजपा ही नहीं, बिहार की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है।

युवाओं में बढ़ती आत्मघाती प्रवृत्ति

भारत में युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ काफी ज्यादा है। परीक्षाओं में सफलता का अत्यधिक दबाव, अभिभावकों और शिक्षकों की अपेक्षाएं और विफलता का डर युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल सकता है।

रंजना मिश्रा

भारत के युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति न केवल सामाजिक चिंता का विषय, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की ताजा रपट के आंकड़े भारत में आत्महत्या की गंभीर स्थिति को उजागर करते हैं। रपट के अनुसार, 2022 में भारत में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा चिंताजनक है, खासकर जब हम यह जानते हैं कि भारत में आत्महत्या के मामलों की वास्तविक संख्या दर्ज संख्या से कहीं अधिक हो सकती है। अपर्याप्त पंजीकरण प्रणाली, मृत्यु के चिकित्सा प्रमाणन की कमी और आत्महत्या से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण कई मामलों का पता तक नहीं चल पाता है। रपट में यह भी सामने आया है कि 41 फीसद आत्महत्याएं 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं द्वारा की जाती हैं।

इसके पीछे अनेक जटिल कारण हैं, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शैक्षणिक दबाव, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, प्रेम संबंधों में विफलता, व्यसन और घरेलू हिंसा आदि प्रमुख हैं। भारत में युवाओं पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ काफी ज्यादा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसका उपचार नहीं कराते। परीक्षाओं में सफलता का अत्यधिक दबाव, अभिभावकों और शिक्षकों की अपेक्षाएं और विफलता का डर युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल सकता है। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, और परिवार में तनाव भी आत्महत्या के लिए जोखिम का कारक बन सकते हैं। युवाओं के बीच इंटरनेट के उपयोग में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि भी आत्महत्या में प्रमुख भूमिका अदा करती है। इसके कुछ अन्य कारकों में साइबरबुलिंग, लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और सामाजिक मूल्यों में गिरावट भी शामिल हो सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आत्महत्या का एक बड़ा कारण हैं। भारत में लगभग 54 फीसद आत्महत्याएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती हैं। पढ़ाई के दबाव यानी शैक्षणिक तनाव से होने वाली आत्महत्याओं के मामले लगभग 23 फीसद पाए गए हैं। इसी प्रकार भारत में होने वाली आत्महत्याओं में सामाजिक तथा जीवन शैली कारकों का लगभग 20 फीसद और हिंसा का 22 फीसद योगदान रहता है। इसके अलावा आर्थिक संकट के कारण 9.1 फीसद और संबंधों की वजह से लगभग 9 फीसद आत्महत्याएं भारत में देखी गई हैं। युवा लड़कियों और महिलाओं में कम उम्र में विवाह, कम उम्र में मां बनना, निम्न सामाजिक स्थिति, घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता और लैंगिक भेदभाव भी आत्महत्या के महत्त्वपूर्ण कारक हैं। आत्महत्या के आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2022 में परीक्षा में विफलता के कारण 2095 लोगों ने आत्महत्या की थी।

इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार, शैक्षणिक प्रणाली में सुधार, सामाजिक-आर्थिक सहायता, प्रेम संबंधों में परामर्श, व्यसन से मुक्ति, हेल्पलाइन और सहायता समूह, मीडिया की जिम्मेदारी और सामुदायिक जागरूकता शामिल हैं। इसके लिए सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और समुदायों को मिलकर कदम उठाने होंगे। युवाओं को

यह जानकारी देनी आवश्यक है कि वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनका वैकल्पिक और उचित समाधान मौजूद है। अगर इस प्रकार समस्याओं से परेशान युवाओं से लगातार बातचीत की जाए और उन्हें अच्छी प्रकार समझाया जाए, तो आत्महत्या जैसे बड़े संकट से उन्हें बचाया जा सकता है।

भारत में लगभग 54 फीसद आत्महत्याएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती हैं। पढ़ाई के दबाव यानी शैक्षणिक तनाव से होने वाली आत्महत्याओं के मामले लगभग 23 फीसद पाए गए हैं। इसी प्रकार भारत में होने वाली आत्महत्याओं में सामाजिक तथा जीवनशैली कारकों का लगभग 20 फीसद और हिंसा का 22 फीसद योगदान रहता है। इसके अलावा आर्थिक संकट के कारण 9.1 फीसद और संबंधों की वजह से लगभग 9 फीसद आत्महत्याएं भारत में देखी गई हैं। युवा लड़कियों और महिलाओं में कम उम्र में विवाह, कम उम्र में मां बनना, निम्न सामाजिक स्थिति, घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता और लैंगिक भेदभाव भी आत्महत्या के महत्त्वपूर्ण कारक हैं।

युवाओं को आत्महत्या से बचाने के लिए, उनकी मानसिक परेशानियों की शीघ्र पहचान करनी होगी और अनुकूल वातावरण में उनकी देखभाल के समुचित प्रावधान होने चाहिए। इस प्रवृत्ति को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना और उन्हें सस्ती दर पर उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाकर परीक्षाओं में सफलता के दबाव को कम करना और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। नशे से ग्रस्त युवाओं के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए और उन्हें उपचार प्रदान करना चाहिए।

अगर कोई युवा आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है, तो उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करनी चाहिए जैसे परिवार के सदस्य, दोस्त से या चिकित्सक से। आत्महत्या जैसी घातक प्रवृत्ति से बचने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवनशैली के अंतर्गत, पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और तनाव को कम करने के लिए स्वस्थ मनोरंजन करें। इसके अलावा सदैव सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। उन्हें ऐसे लोगों से मित्रता या निकटता रखनी चाहिए, जो उन्हें सही सलाह दें और उनके मानसिक बल को बढ़ाएं।

मानसिक समस्याओं से जूझ रहे युवाओं के पारिवारिक माहौल को सुधारने का भी भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे सामाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर या लैंगिक आधार पर भेदभाव न किया जाए। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, अंतर क्षेत्रीय सहयोग और सामाजिक तथा सामुदायिक भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, ताकि किसी भी व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याएं उत्पन्न न हों और न ही उनमें आत्मघाती प्रवृत्तियां विकसित हो सकें। गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आत्महत्या रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए।

आत्महत्या के कारणों और इससे निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों के बारे में अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। सरकार को इस दिशा में अधिक निवेश करना चाहिए और विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही आत्महत्या रोकथाम को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त बजट आबंटित किया जाना चाहिए। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय रणनीति विकसित करनी चाहिए और इसके कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए।

युवाओं का जीवन अमूल्य है और उनके पास इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हों, उन्हें उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए और समस्याओं से हार न मानकर बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आत्महत्या कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज हमारे देश के युवाओं में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जागरूकता, रोकथाम रणनीति और सामाजिक प्रयासों द्वारा मिलकर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और युवाओं को बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान कर सकते हैं।

किसी भी देश के युवा उस देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के रीढ़ की हड्डी होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो उस देश का राष्ट्रीय धन होते हैं। उनका इस प्रकार आत्महत्या करना देश का बहुत बड़ा नुकसान है। हमें हर हाल में इस आत्मघाती प्रवृत्ति को समूल नष्ट करना होगा और अपने देश की युवा शक्ति को बचाकर उन्हें देश के नवनिर्माण में लगाना होगा।

बदलते जमाने की चुनौतियां

आशुतोष कुमार

जमाना बदलने के साथ-साथ परिवेश और लोग भी बदल गए दिखते हैं। इन बदलावों के बीच प्रकृति अछूती कैसे रह सकती है। यह सही है कि आज प्रकृति के कोप का सामना मनुष्य को करना पड़ सकता है, मगर अपने कुत्सित प्रयासों से मनुष्य ने जिस तरह प्रकृति की गति को भी प्रभावित किया है, उसके नतीजे तो आने ही हैं। मई-जून के महीनों में अब उच्च स्तर पर तापमान को लेकर चिंताएं उभर रही हैं। मगर हालत यह है कि मार्च बीतते ही भीषण गर्मी लोगों को झुलसाने लगती है। अक्तूबर तक गर्मी की स्थिति कमोबेश ऐसी ही रहती है। बरसात भी कहीं अधिक मेहरबान रहती है, तो बारिश कहीं से बिल्कुल रूठी दिखती है। नतीजतन, कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पैर पसारती गर्मी के आगे बरसात और शरद हाशिए पर दिखते हैं। प्रकृति में यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। हां, यह जरूर है कि इस परिवर्तन को लोग आज ज्यादा महसूस कर रहे हैं, जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया।

प्रकृति की विकृति सिर्फ नगर और शहर में नहीं, गांव में भी दिखती है। गांव में भले ही बड़े-बड़े वाहन नहीं चलते, उपरिपुल और ऊंची रिहाइशी इमारतों या अपार्टमेंट के निर्माण कार्य नहीं होते। लेकिन वहां दूसरी तरह की समस्याएं हैं। इन नई समस्याओं को सामाजिक बदलाव से जोड़कर देखा जा सकता है। आज से पच्चीस-तीस साल पहले के उस जमाने को याद किया जा सकता है जब खलिहानों में एक खंभे से बैलों को जोतकर दौनी की जाती थी। एक खंभे के चारों तरफ बैल घूमते थे। दौनी के दौरान बैलों का मुंह बांधना मना था। बैल अपने संगी के साथ घूमते और जब मन हुआ, अनाजयुक्त भूंसे में मुंह लगा कर कुछ खा लेते। बैलों के पीछे घूमने वाला किसान या हलवाहा बैलों की इस शरारत को नजरअंदाज करता था। बैलों का यह हक समझा जाता था कि वह जितना चाहे, अनाजयुक्त भूंसे को खाए। तब बैल और गाय-भैंस भी एक कृषक परिवार के सदस्य होते थे। होली-दिवाली में जब घर में पकवान बनते थे, तब अनिवार्य रूप से बैलों को भी पकवान खिलाए जाते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है।

मशीनीकरण के इस युग में बैल गांव से विलुप्त हो गए हैं। पशुपालन अब गृहस्थ जीवन से हटकर व्यवसाय बन गया। पूजा-पाठ में गोबर गणेश के लिए गोबर बड़ी मुश्किल से मिलता है। आज बच्चे गाय को जरूर जानते और पहचानते हैं। संभव है वे सांड को भी समझ पाएं, लेकिन बैल के बारे में नहीं जानते। नए जमाने में बैल का कोई सरोकार और औचित्य भी नहीं रहा। बैल क्या होता है, बच्चे को समझा पाना भी जरा कठिन है। बहरहाल, अब गांव भी पहले जैसे नहीं रहे। कटनी के बाद रबी फसलों को खलिहान में पहले भी रखा जाता था, अब भी रखा जाता है। मगर अब फसलों के सूखे डंठलों से अनाज दौनी से नहीं, थ्रेसर से निकाले जाते हैं। थ्रेसर चलाने के समय गांव की आबोहवा शहरों से भी खराब हो जाती है। अप्रैल से जून तक गांवों में भी प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा रहता है। इसके कारण उड़ते भूसे के छोटे कण तेज हवा के साथ मिलकर पूरे इलाके के वायु को प्रदूषित कर देते हैं। यह प्रदूषण इतना खतरनाक होता है कि कई लोग सांस और फेफड़े संबंधी बीमारी के शिकार हो जाते हैं।

तात्पर्य है कि आज प्रदूषण की जद में सिर्फ बड़े नगर ही नहीं, गांव भी हैं। प्रकृति अब न शहर में महफूज है, न ही गांवों में। यह किसी एक प्रदेश या देश की नहीं, बल्कि वैश्विक समस्या है। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एवं जलवायु एजंसी की रपट के मुताबिक, एशियाई देशों में लू का प्रभाव अत्यधिक गंभीर होता जा रहा और ग्लेशियरों के पिघलने से आनेवाले दिनों में क्षेत्र में भीषण जल संकट पैदा होने का खतरा पैदा हो जाएगा। एशियाई देशों में पिछले कुछ वर्षों में लगातार लू का असर बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघलने के कारण भविष्य में जल सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। एशियाई देशों का पिछले साल तापमान 1961 से 1990 के औसत से लगभग दो डिग्री सेल्सियस अधिक था। पिछले साल एशिया दुनिया का सबसे अधिक आपदा प्रभावित क्षेत्र था।

दक्षिण-पश्चिम चीन वर्षा का स्तर कम होने से सूखे से पीड़ित है। तिब्बती पठार पर केंद्रित उच्च-पर्वतीय एशिया क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर बर्फ की सबसे बड़ी मात्रा मौजूद है। इस क्षेत्र के बाईस ग्लेशियरों में से बीस को पिछले साल लगातार बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। 2023 में उत्तर-पश्चिम प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान रिकार्ड पर सबसे अधिक था। एशिया में अस्सी फीसद से अधिक बाढ़ और तूफान सहित उनासी आपदाएं दर्ज की गईं। इससे करीब नब्बे लाख लोग प्रभावित हुए। सवाल यह है कि इसके लिए दोषी कौन है? यह तय है कि इसके लिए किसी एक देश या किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इसके लिए कोई देश या व्यक्ति दोषमुक्त भी नहीं है। आज प्रकृति खतरे में है, इसके लिए हम सभी कठघरे में हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति को ओर लौटने की जिम्मेवारी हम सबकी है। जब हम प्रकृति के करीब जाएंगे, प्रकृति से जुड़ने की हममें प्रवृत्ति जाग्रत होगी। तभी हम प्रकृति के कोप से बचेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आधुनिकता और मशीनीकरण के इस युग में यह भी ध्यान रहे कि हम कुछ ऐसा न करें, जिससे पर्यावरण दूषित हो।

दुनिया मेरे आगे

आज प्रकृति खतरे में है, इसके लिए हम सभी कठघरे में हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की ओर लौटने की जिम्मेवारी हम सबकी है। जब हम प्रकृति के करीब जाएंगे, प्रकृति से जुड़ने की हममें प्रवृत्ति जाग्रत होगी। तभी हम प्रकृति के कोप से बचेंगे।

स्वच्छता के कदम

गर्मी के दिनों में पानी का महत्त्व कितना होता है, इससे सब परिचित हैं। कई स्थानों पर पानी की समस्या वहां स्रोतों के अभाव में बनी रहती है। जहां जल के स्रोत हैं, वहां ज्यादा समस्या नहीं होती। कई स्थानों पर कुएं, बावड़ी बने हुए हैं, उसमें पानी है, लेकिन उसकी सफाई न होने से, उसके ऊपर जाली नहीं ढंकी होने से धूल, कचरा आदि पड़े होते हैं। अगर संबंधित संस्था, आम लोग या उसके मालिक सफाई पर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर पानी को पीने योग्य बनाया जाकर स्वच्छ जल की प्राप्ति क्षेत्र के रहवासियों को प्राप्त हो सकती है। ऐसी ही समस्या नदियों की भी है। स्थानीय स्तर पर गांव, शहर समीप से बहने वाली नदियों की भी है। उसमें गंदे नालों का अपशिष्ट समाहित होता है। नदियों में काई, विसर्जन की सामग्री आदि भी पड़ी दिखाई देती हैं। उस पानी से नहाने, आचमन करने से श्रद्धालु परहेज करने लगे हैं। गंदा हुए पानी से अनेक बीमारियां उत्पन्न होने का अंदेशा बना रहता है। स्वच्छ जल प्राप्ति के लिए स्थानीय स्तर पर रूपरेखा बनाई जाकर स्थानों को चिह्नित कर सफाई का कार्य किया जाना चाहिए, ताकि स्वच्छ जगहों पर स्वच्छता का इजाफा हो सके।

– संजय वर्मा 'दृष्टि', धार, मप्र

जीवनशैली का नतीजा

शरीर को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आहार से मिलती है। आहार स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, ताकि तन-मन सुचारु रूप से चलता रहे। भोजन बनने तक की प्रक्रिया में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्त्व मिलते रहते हैं। कच्ची सामग्री लें या पैक किए हुए खाद्य पदार्थ या ओवन में पकने वाला खाद्य, सभी में शुद्धता और आवश्यक पौष्टिक तत्त्वों का समावेश होना कठिन होता जा रहा है। खाने वाले अधिक हैं और उगाने वाले या भोजन निर्माण करने वाले कम हैं। अधिक से अधिक उत्पादन करना खाद्यान्न उद्योग का ध्येय हो गया है। गुणवत्ता कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इससे कभी न कभी मनुष्य बीमारियों से घिर ही जाता है। ऊपर से बिगड़ी हुई जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ाने में सहायक होती है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर और खुले में खानपान का कम उपयोग करके स्वस्थ रहा जा सकता है। थोड़ा श्रम लगेगा इन सबको व्यवस्थित करने में, पर हम कर लेंगे।

– इंदु मणि, राजसमंद

सेहत के लिए सतर्कता

'बीमारी का आहार' (संपादकीय, 11 अप्रैल) में यह बिल्कुल सही कहा गया है कि जीवनशैली में बदलाव के लिए आजकल का खानपान दोषी है। हरेक आदमी की जिंदगी, पैसे कमाने और काम में व्यस्त रहने की वजह से घड़ी की सुईयों की तरह घूमने लगी है, जिसकी वजह से जीवनशैली में परिवर्तन आ गया है। बीमारियां न तो अकेले संक्रमण से फैलती हैं और न ही आनुवंशिक होती हैं। शारीरिक सक्रियता की कमी, कार्य के दबाव से तनाव के बढ़ते स्तर, जंक फूड का अत्यधिक उपयोग, गजटों का निरंतर प्रयोग और नींद के पर्याप्त न होने से बीमारियों में बेहिसाब वृद्धि हो रही है। पहले जिन बीमारियों को वयस्कों की बीमारी माना जाता था, वे अब बड़े-बूढ़ों, युवाओं को ही नहीं, बच्चों को भी अपनी लपेट में ले रही हैं। उच्च रक्त दाब, हृदयाघात, मधुमेह, अवसाद जैसी बीमारियां जो पहले के समय सुनने को नहीं मिलती थीं, वे अब बहुत ज्यादा सुनाई पड़ने लगी हैं।

– नरेश कानूनगो, देवास

असुविधा की पटरी

जरूरत के समय शौचालय का उपयोग प्रत्येक महिला और पुरुष की एक अनिवार्य प्राकृतिक आवश्यकता है और इसका महत्त्व समझते हुए हाल के कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में इससे जुड़ी समस्या के समाधान के लिए कई प्रकार के प्रबंध किए गए हैं। इस संदर्भ में ट्रेनों के लोको पायलटों और गार्डों के केबिन में शौचालयों की कमी खलने वाली है। महिला ट्रेन चालकों को इस सुविधा का उपयोग करने के लिए 'वाशरूम ब्रेक' लेना होता है, जिसके लिए उन्हें वाकी-टाकी पर संदेश भेजना पड़ता है जो स्टेशन मास्टर से लेकर नियंत्रण कक्ष तक कई लोगों तक पहुंचता है। फिर किसी उपयुक्त स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर उन्हें शौचालय की सुविधा मिल पाती है। रेलवे द्वारा लगभग अनौपचारिक तौर पर अपनाई जा रही यह व्यवस्था महिला चालकों के लिए कभी-कभी बहुत असहज परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

https://t.me/AllNewspaperPdf

www.readwhere.com